413

विशेष संदर्भ सं। 1/1964

30 सितंबर, 1964।

(न्यायमूर्तिगण पी. बी. राजेंद्रगढ़कर, सी. जे., ए. के. सारकर, के. सुब्बा राव, के. एन. वांचू, एम. हिदायतुल्ला, जे. सी. शाह और एन. राजगोपाला अयंगर)

भारत का संविधान, अनुच्छेद। 143 (1) -के तहत संदर्भ, क्या आवश्यक है

संविधान के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित मामलों से संबंधित-जब उचित हो तो जवाब देने से इनकार करना।

भारत का संविधान, अनुच्छेद। 194 (3) -हाउस ऑफ कॉम के विशेषाधिकार

भारतीय राज्य विधानमंडलों को प्रदत्त अधिकार-निर्णायक सामान्य वारंट द्वारा प्रलोभन के लिए प्रतिबद्ध होने की शक्ति कि क्या ऐसे विशेषाधिकारों में से कोई एक विशेषाधिकार देता है, चाहे वह संविधान के प्रावधानों और मौलिक अधिकारों के अधीन हो-विशेषाधिकारों का दायरा निर्धारित करने की शक्ति चाहे वह पूरी तरह से न्यायालयों के बहिष्कार के लिए विधानमंडलों के पास हो।

भारत का संविधान, अनुच्छेद। 32 , 226 - उच्चतम न्यायालय की शक्ति और

उच्च न्यायालय राज्य विधानमंडलों द्वारा अवमानना के लिए समितियों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करेंगे-मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोप में हस्तक्षेप करने की शक्ति।

भारत का संविधान, अनुच्छेद। 211 - चाहे निर्देशिका हो या अनिवार्य

अनुच्छेद पर इसका प्रभाव। 194 (3) .

उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा ने वचन दिया

एक केशव सिंह, जो इसके सदस्यों में से एक नहीं थे, को इसकी अवमानना के लिए जेल भेजा गया। समादेश के वारंट में कथित अवमानना को दर्शाने वाले तथ्य नहीं थे। अपराध के लिए कारावास की सजा काटते हुए, केशव सिंह ने अपने वकील के माध्यम से अनुच्छेद के तहत एक याचिका दायर की। 226 संविधान और एस। 491 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रो सेडचोर ने उनके समर्पण को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी; उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए भी अनुरोध किया। उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) ने सरकारी वकील को नोटिस दिया,

जिन्होंने विधानसभा सहित सभी प्रतिवादियों की ओर से इसे स्वीकार कर लिया। जमानत याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित समय पर सरकारी वकील पेश नहीं हुए। बेग और सघल जे. जे. जिन्होंने आवेदन को सुना और आदेश दिया कि केशव सिंह को अनुच्छेद के तहत उनकी याचिका के निर्णय तक जमानत पर रिहा किया जाए। 226. विधानसभा ने पाया कि केशव सिंह और उनके वकील ने उच्च न्यायालय का रुख करते हुए, और उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने याचिका पर विचार करने और जमानत देने में विधानसभा की अवमानना की थी, और एक प्रस्ताव पारित किया कि उन सभी को हिरासत में उसके सामने पेश किया जाए। इसके बाद न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं ने अल्लाहा बाद में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं और उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने उनकी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ विधानसभा के प्रस्ताव के निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसके बाद विधानसभा ने एक स्पष्टीकरण प्रस्ताव पारित किया जिसने अपने पहले के रुख को संशोधित किया। न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को हिरासत में पेश किए जाने के बजाय सदन के समक्ष उपस्थित होने और प्रस्ताव देने के लिए कहा गया

उनकी व्याख्या।

इस स्तर पर भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद के तहत एक संदर्भ दिया।

143 (1) जिस संविधान में उच्च न्यायालय और राज्य विधानमंडल के बीच स्थायी संबंध के बारे में पूरा विवाद है, जिसमें यह प्रश्न भी शामिल है कि क्या मामले के तथ्यों पर केशव सिंह [1965] 1 एस. सी. आर.

उनके अधिवक्ता और दोनों न्यायाधीश, अपने-अपने कृत्यों से, राज्य विधानमंडल की अवमानना के दोषी थे, उनकी राय और रिपोर्ट के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया था।

संदर्भ की सुनवाई में बिहार के महाधिवक्ता की ओर से संदर्भ की क्षमता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति इस आधार पर उठाई गई थी कि यह संविधान के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों के दायरे में आने वाले किसी भी मामले से संबंधित नहीं है। यह भी आग्रह किया गया कि भले ही संदर्भ सक्षम हो, लेकिन न्यायालय को इसका जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, और इसके द्वारा दिए गए उत्तर राष्ट्रपति को उन किसी भी कठिनाई को हल करने में मदद नहीं करेंगे जिनका सामना उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में करना पड़ सकता है। न्यायालय ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और समान संबंधों की सुनवाई के लिए आगे बढ़ा, जो मोटे तौर पर दो समूहों में गिर गए-विधानसभा का समर्थन करने वाले और उच्च न्यायालय का समर्थन करने वाले।

विधानसभा की ओर से यह आग्रह किया गया था कि अनुच्छेद के आधार पर। 194 (3) संविधान के अनुसार यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स की सभी शक्तियां, विशेषाधिकार

और उन्मुक्ति इसे प्रदान की गई थी। यह अपने विशेषाधिकारों का एकमात्र न्यायाधीश था और न्यायालयों को उनके प्रयोग में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। वैकल्पिक रूप से, यह था

तर्क दिया कि इंग्लैंड में अदालतों ने कभी भी किसी समर्पण में हस्तक्षेप नहीं किया

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अवमानना के लिए जब समर्पण एक सामान्य वारंट द्वारा किया गया था, यानी एक वारंट जो अवमानना का गठन करने वाले तथ्यों को नहीं बताता था, और इसलिए भारत में न्यायालयों को भी राज्य विधानमंडलों के सामान्य वारंटों की वैधता की जांच करने से रोक दिया गया था। इसलिए, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय में कार्यवाही विधायिका की अवमानना में थी।

उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए रुख का समर्थन करने वालों ने आग्रह किया कि विधानमंडलों को संविधान के प्रावधानों और मौलिक अधिकारों के अधीन हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां प्राप्त हों, कि सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होने की शक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों में से एक नहीं थी, कि अनुच्छेद 226 और 32 के आधार पर, नागरिक को अदालतों में जाने का अधिकार था जब उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, और वह अनुच्छेद के प्रावधानों के कारण था। 211 , विधायिका को न्यायाधीशों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। हेल्ड (प्रति पी. बी. गजेंद्रगडकर सी. जे., के. सुब्बा राव, के. एन. वांचू, एम. हिदायतुल्ला, जे. सी. शाह और एन. राजागोपाला अय्यंगार, जे. जे.) - अनुच्छेद की शर्तें। 143 (1) वे बहुत व्यापक हैं और वे केवल इतना चाहते हैं कि राष्ट्रपति को संतुष्ट होना चाहिए कि संदर्भित किए जाने वाले प्रश्न इस तरह के प्रकृति के और इतने सार्वजनिक महत्व के हैं कि उन पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन होगा। वर्तमान संदर्भ बनाने वाले प्रेसी डेंट के आदेश से पता चलता है कि वह इतने संतुष्ट थे, और इसलिए संदर्भ सक्षम था। तर्क कि अनुच्छेद के तहत एक संदर्भ। 143 (1) संविधान के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों से सीधे जुड़े मामलों पर ही हो सकता था

गलत धारणा है। [431 ई-एफ; 432 ई-एफ]। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद के तहत किए गए पूर्व संदर्भ। 143 (1) कोई समान पैटर्न नहीं दिखाया और यह व्यापक और चौड़े के अनुरूप था

अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द। 143 (1) . [433 सी-डी]।

पुनः में - दिल्ली विधि अधिनियम, 1912, [1951] एस. सी. आर. 747, पुनः: केरल शिक्षा विधेयक, 1957, [1959] एस. सी. आर. 995, पुनः: बेरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एन्क्लेव्स, [1960] 3 एस. सी. आर. 250 और पुनः: समुद्री सीमा शुल्क

अधिनियम, [1964] 3 एस. सी. आर. 787, संदर्भित।

उच्चतम न्यायालय पर किसी संदर्भ का उत्तर देना अनिवार्य नहीं है।

अनुच्छेद के तहत। 143 (1) -उस अनुच्छेद में उपयोग किया गया शब्द 'मई' होने के कारण, 'शब्द' के साथ अनुच्छेद में उपयोग किया जाएगा। 143 (2) . एक रिपोर्ट विशेष संदर्भ बनाने से इनकार

हालाँकि, निर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर देना केवल पर्याप्त और संतोषजनक कारणों के लिए उचित होगा, उदाहरण के लिए, जिन प्रश्नों का उल्लेख किया गया है वे विशुद्ध रूप से सामाजिक-आर्थिक या राजनीतिक चरित्र के हैं जिनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।

किसी भी मायने में। वर्तमान संदर्भ ने गंभीर संवैधानिक महत्व के सवाल उठाए और न्यायालय द्वारा दिए गए जवाब राष्ट्रपति को केंद्र और राज्य सरकारों को उपयुक्त विधायी या कार्यकारी कार्रवाई करने की सलाह देने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इसका जवाब देना अदालत का कर्तव्य था, [434 बी-डी; 433 जी-एचजे।

वर्तमान संदर्भ में न्यायालय द्वारा दी गई सलाहकार राय कार्यवाहियाँ उचित रूप से तथाकथित न्यायनिर्णयन नहीं थीं, और इस तरह किसी भी पक्ष को बाध्य नहीं करती थीं। [446 एच; 447 ए]।

((ii) भारत में राज्य विधानमंडल अनुच्छेद के आधार पर ऐसा नहीं कर सकते थे।

194 (3) अपनी शक्तियों और विशेषाधिकारों के एकमात्र न्यायाधीश होने का दावा करते हैं

न्यायालयों का बहिष्करण। उनकी शक्तियों और विशेषाधिकारों को अनुच्छेद में पाया जाना था। 194 (3) अकेले और कहीं और, और उस अनुच्छेद की व्याख्या करने की शक्ति भारतीय संविधान की योजना के तहत निहित थी, विशेष रूप से इस देश की न्यायपालिका के साथ। (संविधान की योजना को रद्द कर दिया गया)। [444 जी-एच; 446 जी-एच]।

भारत में संविधान को कायम रखने का इरादा नहीं था

'द्वैतवाद' जिसने 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड में सार्वजनिक जीवन को बुरी तरह से बाधित किया। संविधान निर्माताओं को पता था

न्यायपालिका और संसद के सदनों के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई कई अप्रिय स्थितियों में से, और यह दिखाया कि इरादा इस तरह के संघर्ष से बचने का था देश। [454 ए-बी; 455 सी-ई]। अनुच्छेद 211 जो प्रदान करता है कि विधानमंडल चर्चा नहीं कर

सकते थे न्यायाधीश का अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण अनिवार्य था। [457 जी-एचआई।

यू. पी. बनाम राज्य मनबोधन लाल श्रीवास्तव, [1958] एस. सी. आर. 533 और मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम नॉरमैंडिन, एल. आर. [1917]। ए. सी

170 , संदर्भित किया गया। ((ग) यद्यपि अनुच्छेद। 194 (3) स्पष्ट रूप से विषय नहीं बनाया गया है

संविधान के प्रावधानों के लिए, यह अनुचित होगा यदि वैध कारणों से वे थे तो अन्य प्रावधानों की उपेक्षा करने के लिए इसे तैयार करना।प्रासंगिक और लागू पाया गया। इसलिए जहाँ भी यह प्रकट हुआ कि अनुच्छेद के प्रावधानों के बीच टकराव था। 194 (3) और

मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान, एक प्रयास किया जाना था

सौहार्दपूर्ण नियम को अपनाकर उक्त संघर्ष को हल करने के लिए निर्माण जैसा कि शर्मा के मामले में किया गया था। [443 सी-ई]}।

पंडित एम. एस. एम. शर्मा बनाम श्री श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य, [1959] सप. 1 एससीआर 806।

((iv) शर्मा के मामले में इस न्यायालय के बहुमत ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद. 21 अनुच्छेद की सामग्री पर लागू होता था। 194 (3) हालांकि अनुच्छेद।

19 (1) नहीं था। अल्पमत का दृष्टिकोण यह था कि अनुच्छेद। 194 (3) के अधीन था

सभी मौलिक अधिकार। [451 बी-सी]।

यह नहीं कहा जा सकता कि शर्मा के मामले में बहुमत ने उस अनुच्छेद को माना था।94 (3) सरल के लिए सभी मौलिक अधिकारों से स्वतंत्र था इसका कारण यह है कि इसे अनुच्छेद माना जाता था। 21 लागू था, हालांकि मामले के तथ्यों में इसके प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाया गया।

उस मामले में याचिकाकर्ता ने सामान्य मुद्दा नहीं उठाया था अनुच्छेद के लिए प्रयोज्यता और प्रासंगिकता। 194 (3) सभी मूलभूत

भाग III में अधिकार, और इसलिए यह न्यायालय के लिए अनावश्यक था

उस सामान्य मुद्दे पर चर्चा करें और निर्णय लें। उनका दावा आवेदन [1965] 1 एस. सी. आर. पर आधारित था।

केवल दो अनुच्छेदों की क्षमता अर्थात अनुच्छेद 21 और 19 (1) (ए)। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पहला लागू था और दूसरा लागू नहीं था। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि यह शर्मा के मामले में सुलझा लिया गया था। [451 सी-एफ]।

लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि शर्मा के मामले ने इस मुद्दे को सुलझा लिया है या नहीं।

अनुच्छेद. 22 (2) अनुच्छेद पर लागू होता था। 194 (3) या नहीं। [रेड्डी के मामले में निर्णय की शुद्धता के बारे में उसमें बहुमत की टिप्पणियाँ

जो उस अनुच्छेद के आधार पर तय किया गया था। 22 (2) लागू किया गया था, आज्ञाकारी माना गया]। [452 डी-ई]।

पंडित एम. एस. एम. शर्मा बनाम श्री श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य,

[1959] सप. 1 एस. सी. आर. 806 और गुणुपति केशवरम रेड्डी बनाम। नफीसुल

हसन और उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 636 पर चर्चा की गई।

(v) शर्मा के मामले में लिया गया दृष्टिकोण कि परिभाषित करने वाले कानून

अनुच्छेद के प्रथम भाग के अधीन विधानमंडलों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार। 194 (3) अनुच्छेद के अधीन होगा। 13 और इसलिए मौलिक अधिकारों के लिए पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं थी। [453 जी)।

अनंत कृष्णन बनाम। मद्रास राज्य, ए. आई. आर. 1952 मैड। 395 , कोन

पक्षपाती हो गए।

((vi) अनुच्छेद का पहला भाग। 194 (3) राज्य विधानमंडलों को सशक्त बनाता है

कानून द्वारा अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं को परिभाषित करना। अनुच्छेद के दूसरे भाग में कहा गया है कि जब तक वे उपरोक्त तरीके से अपनी शक्तियों आदि को परिभाषित नहीं करते हैं, तब तक उनकी शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की होंगी। दूसरा भाग स्पष्ट रूप से अंतरिम अवधि के लिए प्रदान करने के लिए था जब तक कि पहले भाग के तहत कानून नहीं बनाए गए थे, वे आनुषंगिक विशेषाधिकार और उन्मुक्ति जो प्रत्येक कानून निर्माता के पास होनी चाहिए ताकि वह प्रभावी ढंग से काम कर सके। [442 सी-ई]।

इस खंड द्वारा प्रदत्त हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियाँ हैं -

वे जो 26 जनवरी, 1950 के संविधान के प्रारंभ में भी अस्तित्व में थे, न कि वे जो अस्वीकृत हो गए थे या जिनके संबंध में दावा छोड़ दिया गया था। इसके अलावा, केवल उन्हीं शक्तियों को प्रदान किया गया माना जा सकता है जिन पर न केवल हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किया गया था, बल्कि ब्रिटिश न्यायालयों द्वारा भी मान्यता प्राप्त थी। [442 एफ-एच]।

(vii) यह दावा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉम की सभी शक्तियाँ

अनुच्छेद के आधार पर मोन भारतीय विधानमंडलों में निहित हो गए। 194 (3) इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स की कई शक्तियां हैं-जैसे कि संप्रभु तक पहुंच का अधिकार, प्राप्तकर्ता के अधिनियमों को पारित करना, महाभियोग, अपने स्वयं के संविधान का निर्धारण करना आदि जिनका संभवतः भारतीय विधानमंडलों द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। [448 डी-जी]।

मे 'ज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, 16 वीं संस्करण। पी। 86 , संदर्भित किया गया।

(viii) अनुच्छेद। 194 (3) भारतीय राज्य विधानमंडलों को प्रदान नहीं किया

एक सामान्य वारंट द्वारा अवमानना के लिए प्रतिबद्ध होने का अधिकार जिसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में अदालतों द्वारा इसकी वैधता के लिए जांच नहीं की जा सकी। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में अपने सामान्य वारंट की जांच न करने का दावा किया गया अधिकार, इस धारणा पर आधारित था कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक उच्च न्यायालय की स्थिति में था और उसे अन्य उच्च न्यायालयों की तरह अवमानना के दोषी पाए गए व्यक्तियों की प्रतिबद्धता के लिए एक सामान्य वारंट जारी करने का अधिकार था। इंग्लैंड में एक परंपरा थी जिसके तहत एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी अवमानना के लिए सामान्य वारंट की अन्य अदालतों द्वारा जांच नहीं की जाती थी। विशेषाधिकार के आधार पर नहीं बल्कि इसी आधार पर हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी किए गए सामान्य वारंटों को अदालतों द्वारा जांच से परे माना गया था। [482 बी-डी; 496 एफ]।

विशेष संदर्भ

417

मे 'ज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, 16 वीं संस्करण। पर भरोसा किया।

एशबी वी। व्हाइट, एल. जे. (1701-05) 714, अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी का मामला,

86 ई. आर. 792, ब्रैडलॉफ बनाम। गोसेट, एल. आर. बारहवीं क्यू. बी. डी. 271,12 स्टेट ट्र.

822 , सर फ्रांसिस बर्डेट, एबॉट, 104 ई. आर. 501, स्टॉकडेल बनाम। हंसार्ड,

अन्य, 92 ई. आर., 232, मर्रे का मामला, 95 ई. आर. 629, ब्रास क्रॉस्बी, 95 ई. आर. 1005 , बर्डेट वी। एबॉट 3 ई. आर. 1289, मिडिलसेक्स के शेरिफ, 113 ई. आर.

419 और हावर्ड वी। गोसेट, 116 ई. आर. 139, ने चर्चा की और उस पर भरोसा किया।

ब्रैडलॉफ वी. गोसेट, एल. आर. XII क्यू. बी. डी. 271, लागू नहीं हुआ।

विक्टोरिया की विधान सभा के अध्यक्ष बनाम। ह्यूग ग्लास,

(1869-71) III एल. आर., पी. सी. 560, फील्डिंग और अन्य 'वी। थॉमस, 1896,

एल. आर., ए. सी., 600, द क्वीन बनाम रिचर्ड्स, 92 सी. एल. आर. 157 और डिल बनाम।

मर्फी, (1864) 1 मू। पी. सी (एन. एस.) 487 (15 ई. आर. 784), अनुसरण नहीं किया गया।

मध्य प्रांत और बरार अधिनियम में ग्वायर सी. जे. के अवलोकन

नहीं। 1938 का XIV [1939] एफ. सी. आर. 18 इस प्रभाव के लिए कि निर्णय

अन्य संविधानों के अनुच्छेद को तब भी सुरक्षित रूप से लागू नहीं किया जा सका जब

व्याख्या किए गए प्रावधान समान हैं, जिन पर भरोसा किया जाता है।

पार्कर जे. के अवलोकनः हंट का मामला [1959] 1 क्यू. बी. डी.

378 , के रूप में संदर्भित है कि के लिए एक प्रतिबद्धता के संबंध में भी अभिलेख के एक उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना, न्यायालय अपने न्यायशास्त्र का प्रयोग करते हुए

बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए दायर याचिका पर सुनवाई उक्त अवमानना की वैधता पर विचार करने के लिए सक्षम होगी, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिबद्धता के लिए वारंट सामान्य या स्पष्ट था।

भारतीय राज्य विधानमंडल अपने इतिहास में कभी नहीं थे,

या तो संविधान अधिनियम, 1935 के तहत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत

डेन्स एक्ट, 1947, जिसका उद्देश्य अभिलेख न्यायालय होना था। अनुच्छेद में कानूनी कथा। 194 (3) इंग्लैंड के इतिहास को भारत को हस्तांतरित नहीं कर सके और भारतीय राज्य विधानमंडलों को अभिलेख के वरिष्ठ न्यायालयों का दर्जा प्रदान नहीं कर सके। इस प्रकार जिस आधार पर अंग्रेजी अदालतें हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी एक सामान्य वारंट को इस आधार पर मानने के लिए सहमत हुईं कि यह एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया वारंट था, उनके मामले में अनुपस्थित था, और इसलिए, यह तर्क देना अनुचित होगा कि सामान्य वारंट के लिए एक निर्णायक चरित्र का दावा करने की प्रासंगिक शक्ति जिसे समझौते द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स के पास माना गया था, भारतीय विधानमंडलों में निहित हो गया। मामले के इस दृष्टिकोण पर उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा किए गए दावे को खारिज करना पड़ा। [492 ए-बी]।

(ix) भले ही गैर-परीक्षण योग्य सामान्य युद्ध द्वारा करने की शक्ति हो

राग को हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों का एक अभिन्न अंग माना जाता था-यह नहीं होगा कि भारतीय राज्य विधान मंडल अनुच्छेद के आधार पर उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। 194 (3) . [495 - एच]।

अनुच्छेद के तहत न्यायालयों की शक्तियों का अस्तित्व। 226 और

32 अनिवार्य रूप से नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार निहित है। (वर्तमान विवाद वास्तव में एक नागरिक और विधानमंडल के बीच था, न कि उच्च न्यायालय और विधानमंडल के बीच)। [494 ए-बी]।

यदि कोई नागरिक इस अदालत में जाता है और शिकायत करता है कि उसका मौलिक

अनुच्छेद के ठीक नीचे। 21 [अनुच्छेद पर लागू होने के लिए आयोजित। 194 (3) शर्मा के मामले में] या किसी अन्य लागू अधिकार का उल्लंघन किया गया था, यह स्पष्ट रूप से इस न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह उक्त उल्लेख के गुणागुण की जांच करे। ऐसे मामले में यह कहना कोई जवाब नहीं होगा कि नागरिक के खिलाफ जारी वारंट एक सामान्य वारंट था और एक सामान्य वारंट को आगे की सभी न्यायिक जांच और जांच को रोकना चाहिए। [1965] 1 एस. सी. आर. का प्रभाव

भारतीय नागरिक को अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। 32 अनुच्छेद के अंतिम भाग के निर्माण पर। 194 (3) यह निर्णायक रूप से इस दृष्टिकोण के खिलाफ था कि सदन द्वारा किसी शक्ति या विशेषाधिकार का दावा किया जा सकता है, हालांकि यह अनुच्छेद के साथ असंगत हो सकता है। 21. इस संबंध में यह स्मरण रखना प्रासंगिक था कि सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने के नियम ए. आर. के तहत संविधान के प्रावधान के अधीन थे। . 208 (1) . [493 डी-ई)।

साइमंड्स जे. के अवलोकन, इन रीः संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम, 1770, [1958] ए. सी. 331 और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का संकल्प, सी. जे. 1702-04 , पीपी। 555 , 560 , (मई 16 में उद्धृत एडन. पी. 47), संदर्भित।

यह अजीब होगा अगर वह सदन जो अनुच्छेद के कारण अक्षम था। 211 अपने कर्तव्यों के निर्वहन में न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने के लिए, उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में की गई कथित अवमानना के लिए हिरासत में बुलाने की शक्ति होनी चाहिए। यदि सदन के दावे को बरकरार रखा जाता है तो इसका मतलब होगा कि सदन किसी न्यायाधीश के खिलाफ सामान्य वारंट जारी कर सकता है और ऐसे वारंट की वैधता के संबंध में कोई न्यायिक जांच नहीं की जा सकती है। यह न्यायिक स्वतंत्रता की बुनियादी अवधारणा को गंभीर खतरे में डाल देगा। [493 ई-एच)।

यह भी संदेहपूर्ण था कि क्या एक सामान्य अप-स्पीकिंग वारंट जारी करने की शक्ति एस के अनुरूप थी। 554 (2) (बी) और एस। 555 दंड प्रक्रिया संहिता [496 ई-एफ]।

अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30 सभी अधिवक्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में वकालत करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करती है।

किसी भी न्यायाधिकरण या साक्षय लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति के समक्ष, और किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष, जिसके समक्ष ऐसा अधिवक्ता उस समय किसी कानून द्वारा या उसके तहत वकालत करने का हकदार है। बार काउंसिल अधिनियम की धारा 14 इसी तरह के अधिकार को मान्यता देती है। जिस प्रकार अनुच्छेद के अधीन उनके समक्ष मामलों से निपटने के लिए न्यायपालिका के अधिकार। 226 या अनुच्छेद। 32 की शक्तियों और विशेषाधिकारों के अधीन नहीं किया जा सकता

अनुच्छेद के तहत घर। 194 (3) , अतः न्यायपालिका को स्थानांतरित करने के लिए नागरिक के अधिकार और उस प्रक्रिया में सहायता करने के लिए अधिवक्ताओं के अधिकार को अनुच्छेद द्वारा अनियंत्रित रहना चाहिए। 194 (3) . यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और इस देश में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक एकीकृत योजना है। इसलिए एक निर्णायक

सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होने का अधिकार, जिसे राज्य विधानसभा अपनी शक्तियों या विशेषाधिकारों का एक अभिन्न अंग होने का दावा करती है, संविधान के भौतिक प्रावधानों के साथ असंगत था और इसे अनुच्छेद के बाद के भाग के तहत शामिल नहीं माना जा सकता था। 194 (3) . [495 ई-एच)।

सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होने की शक्ति इसके अलावा विधानमंडल के सदन के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक नहीं थी। अमेरिका कैन कांग्रेस इस तरह की शक्ति के बिना प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

[497 बी-ई]। भारत में संसद के सदनों के अलावा 14 राज्य विधानमंडल हैं। यदि यू. पी. विधानसभा द्वारा दावा की गई शक्ति को सौंप दिया जाता है, तो यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि इसके प्रयोग से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जब एक विधानमंडल का कोई सदस्य अपने ही विधानमंडल में दिए गए भाषण के कारण दूसरे विधानमंडल द्वारा जारी सामान्य वारंट द्वारा अवमानना के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। [497 ई-एफ)। (x) यह अनुच्छेद के तहत अपनी याचिका में केशव सिंह के लिए खुला था। 226 सदन को इस आधार पर आरोपित करना कि उनकी प्रतिबद्धता किस पर आधारित थी

सदन द्वारा पारित आदेश, और उस अर्थ में सदन इसके लिए उत्तरदायी था, और उसकी प्रतिबद्धता पर उसका नियंत्रण था। [496 बी-सी]। राजा वी। द अर्ल ऑफ क्रेव एक्स पार्टी सेक्गोम। [1910] 2 के. बी. डी. 576 और द किंग बनाम गृह मामलों के राज्य सचिव ओ 'ब्रायन, [1923] 2 के. बी. डी. 361, का उल्लेख किया गया है।

विशेष संदर्भ

419

(xi) हालांकि इंग्लैंड में दल जो संघ के लिए प्रतिबद्ध हैं

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्रलोभन अदालतों द्वारा जमानत के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है,

भारत में स्थिति अलग है। अगर अनुच्छेद। 226 अधिकारिता प्रदान करता है

अदालत प्रतिबद्धता के आदेश की वैधता से निपटने के लिए भले ही

प्रतिबद्धता सदन द्वारा आदेश दिया गया है, यह इस प्रकार है कि

न्यायालय के पास ऐसी कार्यवाहियों में अंतरिम आदेश देने का अधिकार क्षेत्र है।

[498 एफ-एचआई।

उड़ीसा राज्य बनाम। मदन गोपाल रूंगटा और अन्य, [1952] एस. सी. आर.

28 और क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल, 11 वीं संस्करण। पी। 350 , भरोसा किया पर।

लाला जयराम दास और अन्य और राजा सम्राट, 72 आई. ए. 120

अप्रयोज्य।

(xii) मामले के तथ्यों पर उच्च न्यायालय सक्षम था -

केशव सिंह की याचिका पर विचार करना और उन्हें लंबित जमानत देना।

आवेदन को आगे बढ़ाने में केशव सिंह या उनके वकील द्वारा प्रतिबद्ध अनुच्छेद के तहत। 226 , या उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका पर विचार करने में

और जमानत देना। यह विधान सभा के लिए सक्षम नहीं था।

हिरासत में रखने से पहले या उनके आचरण के लिए उनके स्पष्टीकरण की मांग करना। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के लिए सक्षम था

उक्त दो माननीय न्यायाधीशों की याचिकाओं पर विचार करना और उनसे निपटना और

अधिवक्ता, और अध्यक्ष को रोकने वाले अंतरिम आदेश पारित करने के लिए यू. पी. विधानसभा और अन्य प्रत्यर्थियों ने उक्त याचिकाओं के लिए आवेग से

न्यायालय जो किसी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करता है या उस पर विचार करता है या उस पर कोई दंड अधिरोपित करने वाले विधानमंडल का निर्णय

याचिकाक

र्ता

(जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है) या उसके विरुद्ध कोई प्रक्रिया जारी करना

याचिकाकर्ता की अवमानना (कथित अवमानना सदन की चार दीवारों के बाहर की गई है), या इसके उल्लंघन के लिए इसके विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, या जो ऐसी याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, वह उक्त विधानमंडल की कोई अवमानना नहीं करता है, और उक्त

विधायिका अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं के प्रयोग और प्रवर्तन में ऐसे न्यायाधीश के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है।

[502 ए; 503 सी]।

(xiii) यह याद रखना आवश्यक है कि स्थिति, गरिमा और महत्व

दो संस्थानों, विधानमंडल और न्यायपालिका की स्थिति मुख्य रूप से इन संस्थाओं की स्थिति, गरिमा और महत्व से प्राप्त होती है।

संबंधित कारण जो संविधान द्वारा उनके प्रभार को सौंपे गए हैं। इन दोनों निकायों के साथ-साथ कार्यपालिका, जो एक लोकतांत्रिक राज्य का एक महत्वपूर्ण घटक है, को लोकतांत्रिक राज्य के तीन घटकों के इस तरह के सामंजस्यपूर्ण कार्य के लिए न तो विरोध में और न ही शत्रुता की भावना से काम करना चाहिए, बल्कि अपने-अपने क्षेत्रों में तर्कसंगत, सामंजस्यपूर्ण और समझ की भावना से काम करना चाहिए।

अकेले इस देश में लोकतांत्रिक जीवन शैली के शांतिपूर्ण विकास, विकास और स्थिरीकरण में मदद करेगा, [447 डी-ई]।

(xiv) अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति जितनी बड़ी है, हमेशा होनी चाहिए।

सावधानी से, बुद्धिमानी से और सावधानी के साथ व्यायाम करें। क्रोध या चिड़चिड़ापन में इस शक्ति का बार-बार या अंधाधुंध उपयोग अदालत की गरिमा को बनाए रखने में मदद नहीं करेगा, लेकिन कभी-कभी यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। बुद्धिमान न्यायाधीश यह कभी नहीं भूलते कि अपने पद की गरिमा और स्थिति को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे अपने निर्णयों की गुणवत्ता, निडरता, निष्पक्षता और अपने दृष्टिकोण की वस्तुनिष्ठता और अपने न्यायिक आचरण में संयम, गरिमा और शिष्टाचार का पालन करके बड़े पैमाने पर जनता से सम्मान के पात्र हों। हम यह सोचने का साहस करते हैं कि न्यायपालिका के बारे में जो सच है वह विधानमंडल के बारे में भी उतना ही सच है। [501 एफ-जीजे।

आंद्रे पॉल बनाम में लॉर्ड एटकिन के अवलोकन। के महान्यायवादी

त्रिनिदाद, ए. आई. आर. 1936, पी. सी. 141, संदर्भित।

प्रति सरकार जे. (i) यह निस्संदेह न्यायालयों के लिए है कि वे व्याख्या करें

संविधान और इसलिए अनुच्छेद। 194 (3) . यह इस प्रकार है कि जब इस देश में यह प्रश्न उठता है कि क्या संविधान के प्रारंभ में हाउस ऑफ कॉमन्स को कोई विशेष विशेषाधिकार प्राप्त था, तो उस प्रश्न का निपटारा केवल अदालतों द्वारा किया जाना चाहिए। भयानक द्वैतवाद के यहाँ प्रकट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी अदालतें किसी विधानमंडल के सदन के साथ विवाद में पड़ जाती हैं कि उसके विशेषाधिकार क्या हैं। [509 ए-बी]।

((ii) अनुच्छेद में दिखाई देने वाले शब्द। 194 (3) शक्तियाँ, विशेषाधिकार हैं

और किसी सदन की उन्मुक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स की होगी। इससे अधिक सरल भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है। उस लेन गेज का केवल एक ही अर्थ हो सकता है और वह यह है कि इसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं को वे शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान करना था जो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के पास थी। शक्तियों के विभाजन के एक कथित सिद्धांत के प्रति निष्ठा का दावा करके शब्दों को उनके स्पष्ट अर्थ से इनकार करने में चतुराई का कोई अवसर नहीं है। [511 ए-बी]।

ब्रैडलॉफ वी. गोसेट, (1884) 12 Q.B.D.271, बर्डेट बनाम। एबट। (1811)

14 पूर्व 1, पुनः: दिल्ली कानून, [1951] एस. सी. आर. 747। पं. एम एस एम शर्मा बनाम श्री श्री कृष्ण सिन्हा। [1959] सप. 1 एस. सी. आर. 806, विक्टोरिया बनाम की लेजिस लेटिव असेंबली के अध्यक्ष। ग्लास (1871) एल. आर. 3. पी. सी. ऐप। 560

रानी वी। रिचर्ड्स, 92 सी. एल. आर. 157, क्वीन बनाम। रिचर्ड्स, 92 सी. एल. आर. 171 और फील्डिंग बनाम। थॉमस, [1896] ए. सी. 660, संदर्भित।

(iii) एक सामान्य वारंट द्वारा करने की शक्ति जिसके परिणामस्वरूप

अदालतों के अधिकार क्षेत्र से वंचित करना, हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों में से एक था। यह विशेषाधिकार अनुच्छेद के आधार पर यू. पी. विधानसभा के पास था। 194 (3) संविधान से। [524 सी-डी)।

यह दिखाने का कोई अधिकार नहीं है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास था

एक सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होने की शक्तियाँ क्योंकि यह एक उच्चतर अभिलेख न्यायालय था। न तो सदन का इतिहास और न ही अंग्रेजी मामलों के निर्णय इस तर्क का समर्थन करते हैं।

अदालतों ने केवल सदन को उच्च न्यायालय के समान सम्मान का हकदार माना। उन्होंने यह नहीं कहा कि सदन एक उच्च न्यायालय था। [513 बी-सी, 522 बी]।

मे 'ज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, 16 वीं संस्करण। पॉटर की कानूनी रूपरेखाएँ

इतिहास, (1958 एडन।) संविधान का एनसन का कानून। 6 टी एडन। खण्ड. 1 , संदर्भित किया गया।

ब्रैडलॉफ वी. गोसेट, (1884) 12 क्यू. बी. डी. 271 बर्डेट बनाम। एबॉट, 5

डाउ 165, मिडलसेक्स के शेरिफ, (1840) 11 ए और ई 272। स्टॉकडेल बनाम. हंसार्ड, (1839) 9 ईस्वी और एल और हावर्ड बनाम। गोसेट, (1874) 10 क्यू. बी. 359, पर भरोसा किया।

यह कहना गलत है कि सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होने का अधिकार

हाउस ऑफ कॉमन्स के पास अदालतों के सामूहिकता के कुछ नियमों, या अनुमानित साक्षय, या कानून की अदालतों और सदन के बीच एक समझौते से, या अंत में, पूर्व द्वारा बाद वाले को दी गई कुछ रियायतों से उत्पन्न होता है। [522 ई-एफ]।

हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी विशेषाधिकार कानून पर आधारित हैं। वह कानून

इसे लेक्स पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। वह कानून किसी भी अन्य कानून की तरह देश का एक कानून है जिसे अदालतें प्रशासित करने की हकदार हैं। { 522 एफ-जी]।

यह हमारे लिए नहीं है कि हम सदन के विशेषाधिकारों के बारे में नए विचार शुरू करें

कॉमन्स, ऐसे विचार जिनकी कल्पना इंग्लैंड में कभी नहीं की गई थी। उस अवधि के बारे में शोध जब ये विशेषाधिकार आकार ले रहे थे, वहन कर सकते हैं

1950 में उनकी सामग्री और प्रकृति का कोई जवाब नहीं। [523 जी-एच; 524 आर-सी]।

विशेष संदर्भ

421

निस्संदेह अधिकार के लेखकों के साथ-साथ कुछ हाल के निर्णय

न्यायिक समिति ने एक निर्णायक सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होने की शक्ति को सदन के विशेषाधिकार के मामले के रूप में माना है न कि एक उच्च न्यायालय के रूप में उसके अधिकार के रूप में। [515 जी-एच]।

मे 'ज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, 16 वीं संस्करण। संवैधानिक कानून पर मामले

कीर और लॉसन द्वारा, हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल्यूम। 28 , 467 , डाइसी का संवैधानिक कानून, 10 वीं संस्करण। , संदर्भित किया गया।

विक्टोरिया की विधान सभा के अध्यक्ष बनाम। ग्लास, फील्डिंग बनाम।

थॉमस और मिडिलसेक्स के शेरिफ ने भरोसा किया।

((iv) न्यायिक समिति के निर्णय बाध्यकारी नहीं हो सकते हैं -

भारतीय अदालतें लेकिन उनका उच्च प्रेरक मूल्य है, जब तक कि उन्हें नहीं दिखाया जाता है

गलत है। सवाल यह है कि क्या हाउस ऑफ कॉमन्स के पास एक निश्चित था

विशेषाधिकार। यदि विशेषाधिकार का न्यायिक नोटिस लेना है, तो इसके तहत एस। 57 साक्षय अधिनियम, के अधिकृत कानून रिपोर्टों का एक संदर्भ

इंग्लैंड वैध होगा, और यदि विशेषाधिकार का अस्तित्व है

विदेशी कानून के मामले के रूप में निर्णय लिया जाना, फिर से एस के तहत। 38 उस में से

इन रिपोर्टों के संदर्भ में कार्य करना उचित होगा। और तब से वे

इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालयों में से एक के निर्णय शामिल हैं, हम नहीं हैं

यह कहने का अधिकार है कि जिसे वे हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार कहते हैं

उनका देश एक विशेषाधिकार नहीं है, जब तक कि कुछ समान रूप से उच्च अधिकारी नहीं लेते हैं

इसके विपरीत दृष्टिकोण सामने आ रहा है। [517 डी-एफ]।

(v) यह नहीं कहा जा सकता है कि विचाराधीन विशेषाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।

भारतीय राज्य विधानमंडलों द्वारा केवल मौलिक अधिकारों के अधीन

संविधान द्वारा गारंटीकृत नागरिक। शर्मा के मामले में यह अदालत

यह निर्धारित किया कि हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार जो थे

राज्य विधानमंडल के सदन को अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया। 194 (3) पहले से लें मौलिक अधिकारों पर जोर देना। यह निर्णय सही था और नहीं

पुनर्विचार की आवश्यकता है। [524 ई-एफ; 525 बी-सी, एफ]।

पुनः में - दिल्ली विधि अधिनियम, 1950, [1951] एस. सी. आर. 747, निर्दिष्ट।

शर्मा के मामले में यह नहीं माना गया था कि आर्ट। 21 प्राथमिकता लेता है

अनुच्छेद में विशेषाधिकार। 194 (3) . दास सी. जे. ने निस्संदेह कहा कि कोई नहीं था

अनुच्छेद का उल्लंघन। 21 उस मामले में क्योंकि स्वतंत्रता से वंचित था

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। लेकिन यह केवल एक बदलाव था।

मूल कारण वह धारण कर सकते थे-जैसा कि उन्होंने अनुच्छेद के मामले में किया था। 19 (1) (क)-वह अनुच्छेद। 21 एक सामान्य प्रावधान और अनुच्छेद होना। 194 (3) होने के नाते

विशेष रूप से, पहले वाले को बाद वाले के आगे झुकना चाहिए। [531 ई-एफ; 532 बी-ई]।

यह कहने का एक और कारण है कि दास सी. जे. उस अनुच्छेद को नहीं मानते थे। 21

एक सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होने के विशेषाधिकार पर प्राथमिकता ली गई है तथ्य यह है कि उनका मानना था कि रेड्डी के मामले का गलत निर्णय लिया गया था। वह मामला

उस अनुच्छेद को धारण किया था। 22 समर्पण के विशेषाधिकार पर वरीयता थी।

अगर अनुच्छेद। 22 प्राथमिकता नहीं थी, जैसा कि दास सी. जे. ने तब से रखा होगा

उन्होंने रेड्डी के मामले की शुद्धता को स्वीकार नहीं किया, वे और नहीं कर सकते थे

उस अनुच्छेद को धारण किया। 21 करने के विशेषाधिकार पर वरीयता होगी

अपमान के लिए। [532 ई-एफ]।

(vi) शर्मा के मामले में बहुमत ने बिना चर्चा के कहा।

कि अनुच्छेद के तहत कानून। 194 (3) सभी मौलिक अधिकारों के अधीन होगा,

लेकिन ऐसा केवल अनुच्छेद के कारण है। 13 ऐसा कहते हैं। [528 सी-डी]।

अनुच्छेद 13 किसी कानून को बुरा बनाता है यदि वह मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करता है।

यह अनुच्छेद के रूप में नहीं कहा जा सकता है। 13 सी. एल. के तहत बनाए गए कानून बना सकते हैं। (3)

अनुच्छेद की। 194 शून्य, दूसरे भाग द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों को भी होना चाहिए शून्य हो जाओ। संविधान के प्रावधानों पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होता है।

टचूशन स्वयं। यह केवल राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को नियंत्रित करता है जो अनुच्छेद. 194 (3) नहीं है। तथ्य यह है कि सीएल में। (1) अनुच्छेद की। 194 शब्द हैं।

आ

ई [1965] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

422

' संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए 'होते हैं, जबकि उन्हें सी. एल. से हटा दिया जाता है। (3) यह एक मजबूत संकेत है कि बाद वाला खंड इस तरह के विषय होने का इरादा नहीं था। [528 ई-एच)।

((vii) जब किसी को दिए गए विशेषाधिकार के बीच टकराव होता है।

अनुच्छेद के दूसरे भाग द्वारा घर। 194 (3) और एक मौलिक अधिकार है कि टकराव को दोनों प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करके शर्मा के मामले की तरह हल किया जाना चाहिए। सामंजस्यपूर्ण निर्माण का अर्थ है कि दोनों प्रावधानों को अधिकतम प्रभाव दिया जाना चाहिए, बिना उनमें से एक को दूसरे को मिटा दिए। तत्काल मामले में टकराव सदन के विशेषाधिकार के बीच था कि वह किसी व्यक्ति को अवमानना के लिए प्रतिबद्ध करता है, बिना उस समर्पण के जिसकी अदालत द्वारा जांच की जानी चाहिए, और एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत है। 21 और अनुच्छेद के तहत उस अधिकार के प्रवर्तन में अदालतों को स्थानांतरित करने का अधिकार। 32 या अनुच्छेद। 226. यदि मौलिक अधिकार के प्रवर्तन

में अदालतों में जाने का अधिकार दिया जाता है, तो वह विशेषाधिकार जो प्रदान करता है कि यदि कोई सदन किसी व्यक्ति द्वारा

एक सामान्य वारंट कि समर्पण की अदालतों द्वारा समीक्षा नहीं की जाएगी, अपना सारा प्रभाव खो देगा और यह ऐसा होगा जैसे विशेषाधिकार नहीं था

अनुच्छेद के दूसरे भाग द्वारा एक सदन को प्रदान किया गया। 194 (3) . यह सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं था। ऐसा होने पर, यह होगा कि जब कोई सदन किसी व्यक्ति को सामान्य वारंट द्वारा अवमानना के लिए प्रतिबद्ध करता है तो उस व्यक्ति को अदालतों में जाने का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही अदालतें इसमें बैठ सकती हैं।

समर्पण के ऐसे आदेश पर निर्णय। [533 जी-एच, 534 ए-सी]।

बर्डेट बनाम में लॉर्ड एलेनबरो सी. जे. का अवलोकन। एबॉट, संदर्भित

नियम के संभावित अपवादों के लिए। [534 सी-डी]।

(viii) लखनऊ पीठ को इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया था कि

उसने कहा कि उसके पास अनुच्छेद के तहत याचिका से निपटने की पूरी क्षमता थी। 226 . वर्तमान संदर्भ में प्रश्न का निर्णय लेना आवश्यक नहीं था।

क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में जहां प्रतिबद्धता प्रत्यर्पण के लिए है

प्रलोभन कानून जमानत पर रिहाई की अनुमति देता है, क्योंकि संदर्भ नहीं था

इसका मतलब उस सवाल का जवाब खोजना था। कोई अवमानना नहीं की गई।

संबंधित के लिए माननीय न्यायाधीशों या बी. सोलोमन या केशव सिंह द्वारा

याचिका के संबंध में उनके द्वारा लिए गए भाग क्योंकि वे प्रकट नहीं हुए थे

कि उन व्यक्तियों में से कोई भी जानता था कि प्रतिबद्धता एक सामान्य के तहत थी

चूँकि वे दोषी नहीं थे, यह इसके लिए सक्षम नहीं था

विधानसभा ने उन्हें हिरासत में पेश करने का आदेश दिया। कड़ाई से बोलते हुए, सदन के समक्ष उन्हें हिरासत में लाने का सवाल नहीं उठाया गया

मामले के तथ्यों पर उत्पन्न होता है क्योंकि विधानसभा ने अपने प्रस्ताव को संशोधित किया था

इस संबंध में। विधानसभा स्पष्टीकरण मांगने के लिए सक्षम थी।

दो न्यायाधीशों और बी. सोलोमन से। के रूप में यह करने के लिए करने की शक्ति थी

अवमानना यह आवश्यक रूप से धोखाधड़ी से संबंधित तथ्यों का पता लगाने की शक्ति थी

प्रलोभन। पूर्ण पीठ याचिका पर विचार करने के लिए सक्षम थी

दो न्यायाधीश और बी. सोलोमन अधिवक्ता यदि मामले के तथ्यों पर वे

उसे दोषी नहीं कहा जा सकता था। यह होगा कि पूर्ण पीठ के पास था

अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति। मामले के तथ्यों पर,

उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो किसी याचिका को चुनौती देता है या उससे निपटता है उस पर कोई दंड अधिरोपित करने वाला विधानमंडल का कोई आदेश या निर्णय

याचिकाकर्ता या उसकी अवमानना के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रक्रिया जारी करना

या इसके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं के उल्लंघन के लिए या जो किसी भी

ऐसी याचिका पर आदेश उक्त विधानमंडल की अवमानना नहीं करता है, और उक्त विधानमंडल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है।

अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों के प्रयोग और प्रवर्तन में एक न्यायाधीश और

प्रतिरक्षाएँ। [534 डी; 537 डी]।

(ix) चौदह वर्षों के दौरान जब संविधान लागू हुआ है

राशन, विधानमंडलों ने इस विचार को सही ठहराने के लिए कुछ नहीं किया है

कि वे सत्ता पर भरोसा करने के लायक नहीं हैं। हालांकि अनुच्छेद।

211 विशेष संदर्भ है

423

लागू करने योग्य नहीं होने के कारण विधानमंडलों ने एक सराहनीय भावना दिखाई है

अभ्यास करें और इन सभी वर्षों में एक बार भी आचरण पर चर्चा नहीं की है

न्यायाधीशों का। हमें अपने लोगों में विश्वास नहीं खोना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि

विधानमंडल संविधान द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे।

न्याय या सुरक्षा न्यायिक सुधार में निहित है। इस तरह के सुधार कर सकते हैं

अच्छे से ज्यादा नुकसान। एक आधुनिक राज्य में यह अक्सर आवश्यक है

देश की भलाई है कि समानांतर शक्तियाँ अलग-अलग रूप में मौजूद होनी चाहिए

रियायतें। यह अपरिहार्य नहीं है कि ऐसी शक्तियों का टकराव होगा। [541 सी-ई]।

सलाहकार न्यायनिर्णय: 1964 का विशेष संदर्भ सं. 1।

अनुच्छेद के तहत विशेष संदर्भ। 143 के संविधान से

भारत।

सी. के. डाफ्टरी, अटॉर्नी-जनरल, एच. एन. सान्याल, सॉलिसिटर

जनरल, एस. वी. गुप्ते, एडिशनल। सॉलिसिटर-जनरल, बी. आर. एल. अयंगर और आर. एच. ढेबर, भारत संघ के लिए।

एम. सी. सीतलवाड़, जी. एस. पाठक, जगदीश स्वरूप, एस. एन. एंडली,

पी. एल. वोहरा, रामेश्वर नाथ, महिंदर नारायण, हरश के. पुरी और सुरेश वोहरा, माननीय मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के लिए

इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

जी. एस. पाठक, जगदीश स्वरूप, बिशुन सिंह, गोपाल बिहारी,

जे. एस. त्रिवेदी, एस. एन. पावनीकर, एस. एन. एंडली, पी. एल. वोहरा और

रामेश्वर नाथ, माननीय न्यायमूर्ति एन. यू. बेग के लिए।

एन. सी. चटर्जी, आसिफ अंसारी, एम. के. राममूर्ति और आर. के.

गर्ग माननीय न्यायमूर्ति जी. डी. सहगल के लिए।

एच. एम. सीरवई, महाधिवक्ता, महाराष्ट्र, टी. आर. अंध्या

रुजिना और एस. पी. वर्मा, यू. पी. विधानसभा के लिए।

एन. ए. पालखीवाला, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. माथुर और रविंदर नारायण, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के लिए।

जे. एम. ठाकुर, महाधिवक्ता, गुजरात, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. माथुर और रविंदर नारायण, माननीय मुख्य न्यायाधीश के लिए, गुजरात उच्च न्यायालय।

डी. नरसाराजू, एन. रामदार, ओ. पी. मल्होत्रा, बी. पार्थसारथी, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. माथुर और रविंदर नारायण, माननीय के लिए मुख्य न्यायाधीश, उड़ीसा उच्च न्यायालय।

मुरली मनोहर व्यास, एस. मूर्ति, बी. एन. कृपाल, बी. एल. खन्ना, के. के. जैन, चितले और एम. एस. गुप्ता, माननीय मुख्य न्यायाधीश के लिए, राजस्थान उच्च न्यायालय।

मुरली मनोहर, एस. मूर्ति, बी. एन. कृपाल, बी. एल. खन्ना, के. के. जैन, चितले और एम. एस. गुप्ता, माननीय मुख्य न्यायाधीश के लिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय।

डी पी सिंह, एस बालकृष्णन, शांति भटनागर और लाल नारायण सिंह, पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के लिए।

पी।

C.I

./65-2 [1965] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

424

ए. सी. मित्रा और डी. एन. मुखर्जी, माननीय अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए। एस. एस. सान्याल, एस. के. आचार्य और डी. एन. मुखर्जी, माननीय अध्यक्ष के लिए, W.B.L.C।

एच. एम. सीरवई, महाधिवक्ता, महाराष्ट्र, टी. आर. आनंद

यरुजिना, आर. ए. गागराट और वी. जे. मर्चेंट, माननीय के लिए

अध्यक्ष/अध्यक्ष महाराष्ट्र एल. ए. और एल. सी.

जी. एन. जोशी, अतीकुर रहमान और के. एल. हाथी, माननीय के लिए

अध्यक्ष, गुजरात एल. ए.

अध्यक्ष के लिए अतीकुर रहमान और के. एल. हाथी,

हिमाचल प्रदेश विधानसभा।

बी. सी. बरुआ, महाधिवक्ता, असम और नौनीत लाल, के लिए

माननीय अध्यक्ष जी, असम विधान सभा।

डी. एम. सेन, महाधिवक्ता, नागालैंड और नौनीत लाल, के लिए

नागालैंड विधान सभा।

बी. पी. झा, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद के लिए

और बिहार विधान सभा के अध्यक्ष महोदय।

के. एल. मिश्रा, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, बी. सी. मिश्र,

महाधिवक्ता की ओर से डी. डी. चौधरी और सी. पी. लाल

उत्तर प्रदेश राज्य।

एम. अधिकारी, महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश और आई. एन. श्रॉफ, महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश राज्य के लिए।

एन. कृष्णास्वामी रेड्डी, महाधिवक्ता, मद्रास, वी. रामास्वामी और ए. वी. रंगम, महाधिवक्ता के लिए

मद्रास राज्य।

अधिवक्ता की ओर से आंध्र प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता बी. वी. सुब्रमण्यम, एम. जगनाधा राव और टी. वी. आर. टाटाचारी

केट-आंध्र प्रदेश राज्य के लिए सामान्य।

महाधिवक्ता की ओर से बी. सेन, एस. सी. बोस और पी. के. बोस

पश्चिम बंगाल राज्य के लिए।

जी. सी. कासलीवाल, महाधिवक्ता, राजस्थान राज्य, एम. वी.

गोस्वामी, राजस्थान राज्य के लिए।

एस. पी. वर्मा, बिहार राज्य के अधिवक्ता के लिए।

जे. पी. गोयल, मेसर्स के लिए। केशव सिंह और बी. सोलोमन।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए एम. के. नाम्ब्यार और एन. एन. केसवानी।

अवध बार एसोसिएशन के लिए एम. के. नाम्बयार, चौधरी हैदर हुसैन, बी. के. धवन, बिशुन सिंह, शिव शास्त्री और एस. एस. शुक्ला

यह।

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

425

आर. जेठमलानी, पी. के. कपिला और ए. के. नाग, पश्चिमी के लिए

इंडिया एडवोकेट्स एसोसिएशन (मध्यस्थ)।

एस. एन. काकर, सी. एस. सरन, जी. पी. गुप्ता और एस. सी. अग्रवाल,

इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (मध्यस्थ) के लिए।

बार एसोसिया के लिए एम. के. नाम्ब्यार और वी. ए. सईद मुहम्मद

भारत का राष्ट्र (मध्यस्थ)।

आर. वी. एस. मणि, शौकत हुसैन, ई. सी. अग्रवाल, शहज़ादी

मोहिउद्दीन और पी. सी. अग्रवाल, आवेदकों के लिए-हस्तक्षेपकर्ताः (क) लोक रक्षा समाज (सेवक), (ख) अखिल भारतीय नागरिक स्वतंत्रता परिषद (ग) सप्रू लॉ सोसाइटी।

राममूर्ति, आर. के. गर्ग, डी. पी. सिंह और एस. सी. आगर

वाल फॉर एप्लिकेंट-इंटरवेनर दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स।

के. राजेंद्र चौधरी और के. आर. चौधरी, आवेदक के लिए

-हस्तक्षेपकर्ता, बिहार कार्यशील पत्रकार संघ।

चिंता सुब्बा राव, आवेदक-मध्यस्थ, संस्थान के लिए

जनमत।

गजेन्द्रगढ़कर सी. जे. ने उनकी ओर से राय दी

सुब्बा राव, वांचू,। हिदायतुल्ला, शाह और राजगोपाला

आयंगर जे. और खुद भी। जे. एस. ए. आर. के. जे. ने एक अलग प्रस्तुति दी।

राय दें।

गजेंद्रगडकर सी. जे. यह 1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1 है।

जिसके द्वारा राष्ट्रपति ने ओपीआई के लिए पाँच प्रश्न तैयार किए

संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत इस न्यायालय का गठन। द.

अनुच्छेद राष्ट्रपति को इस न्यायालय के प्रश्नों को संदर्भित करने के लिए अधिकृत करता है।

कानून या तथ्य जो उसे उत्पन्न हुआ या होने की संभावना प्रतीत होती है

उत्पन्न होना और जो ऐसी प्रकृति के हैं और ऐसे सार्वजनिक आई. एम.

संकेत है कि सर्वोच्च की राय प्राप्त करना समीचीन है

ऐसी सुनवाई के बाद, जो वह उचित समझे, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे सकता है उस पर राय। 26 मार्च को दिए गए अपने ऑर्डर ऑफ रेफरेंस में,

1964 , राष्ट्रपति ने अपना निष्कर्ष व्यक्त किया है कि संदर्भ आदेश में निर्धारित कानून की प्रकृति ऐसी है

और इस तरह के सार्वजनिक महत्व के कि यह समीचीन है कि राय

उस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त किया जाना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि 14 मार्च, 1964 को विधान सभा के अध्यक्ष ने

उत्तर प्रदेश की विधानसभा, के नाम से प्रशासित और

विधान सभा के आदेशों के तहत (इसके बाद संदर्भित)

"सदन" के रूप में), केशव सिंह के लिए एक फटकार, जो एक रेसी हैं सदन की अवमानना करने के लिए गोरखपुर का दंश

और नर के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए भी

सिंह नारायण पांडे, सदन के सदस्य।

अव

मानना और [1965] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

426

विचाराधीन विशेषाधिकारों का उल्लंघन एक पर्चे के कारण हुआ जो मुद्रित और प्रकाशित किया गया था और जिस पर अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर के साथ केशव सिंह के हस्ताक्षर थे। में।

उसी दिन बाद में सदन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि केशव सिंह को सदन में एक और अवमानना करने के लिए जेल भेजा जाए, जब उन्हें उपरोक्त फटकार प्राप्त करने के लिए बुलाया गया था और इससे पहले सदन के अध्यक्ष को एक अपमानजनक पत्र लिखने के लिए। इस आदेश के अनुसार, एक वारंट था

सदन के अध्यक्ष श्री वर्मा के हस्ताक्षर पर जारी किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि केशव सिंह को जिला जेल में रखा जाए।

लखनऊ, सात दिनों की अवधि के लिए, और वारंट के निष्पादन में केशव सिंह को जेल में रखा गया था।

19 मार्च, 1964 को श्री बी. सोलोमन, एक अधिवक्ता, जो प्रैक्टिस कर रहे थे

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष, केशव सिंह की ओर से उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 491 के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। इस याचिका पर आई. एम.

सदन के अध्यक्ष, सदन, मुख्यमंत्री से अनुरोध किया

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और जिला जेल के अधीक्षक,

लखनऊ, जहाँ केशव सिंह सजा काट रहे थे

प्रतिवेदियों के रूप में सदन द्वारा उन पर अधिरोपित कारावास

4 क्रमशः। इस प्रकार केशव की ओर से याचिका प्रस्तुत की गई

सिंह ने आरोप लगाया कि जेल में उनकी नजरबंदी कई मामलों में अवैध थी आधार। याचिका के अनुसार, केशव सिंह ने

प्रशासन द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद जेल जाने का आदेश दिया गया था उसके पास गया, और जिसने कारावास के आदेश को अवैध बना दिया और

बिना किसी अधिकार के। याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि केशव

सिंह को अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया गया था और कि उनकी नजरबंदी दुर्भावनापूर्ण थी और सिद्धांतों के खिलाफ थी

प्राकृतिक न्याय। यह भी उनका मामला था कि उत्तरदाता 1 से 3

उसे जिला जेल, लखनऊ भेजने का कोई अधिकार नहीं था, और जिससे जेल में उनकी नजरबंदी अवैध हो गई।

उक्त याचिका के लखनऊ पीठ के समक्ष दायर किए जाने के बाद

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता दोनों के लिए

पक्षकार बेग और सबगल जे. जे. के सामने पेश हुए। दोपहर 2 बजे और

एक दिन। श्री सोलोमन ने केशव सिंह और श्री के. एन. का प्रतिनिधित्व किया। सहायक सरकारी अधिवक्ता कपूर सभी पक्षकारों की ओर से पेश हुए।

चिंतनशील। तदनुसार, याचिका के समक्ष लिया गया था

इस अवसर पर दोपहर 3 बजे श्री सोलोमन अदालत में पेश हुए।

याचिकाकर्ता लेकिन श्री कपूर अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने

फिर एक आदेश पारित किया कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

427

रुपये की राशि में दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर। 1,000 जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ की संतुष्टि के लिए समान राशि में प्रत्येक और प्रति सोनल बॉन्ड। न्यायालय के उप-पंजीयक थे आदेश के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि आवेदक उपस्थित रहेगा।

भविष्य में मामले की हर सुनवाई पर अदालत। इस प्रकार, याचिका को स्वीकार कर लिया गया और जवाब देने वालों को इस अतिरिक्त निर्देश के साथ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया कि मामले को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। यह 19 मार्च को दोपहर 3 बजे हुआ।

20 मार्च, 1964 को श्री श्री राम, सरकारी अधिवक्ता

केट ने उत्तर प्रदेश सरकार के न्यायिक विभाग, लखनऊ के सचिव श्री निगम को पत्र लिखकर उन्हें आदेश के बारे में जानकारी दी

केशव सिंह के आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया। इस पत्र में श्री राम ने कहा है कि दोपहर 2 बजे अदालत में मामले का उल्लेख किए जाने के बाद पक्षों के अनुरोध पर इसे दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

श्री निगम से फोन पर संपर्क किया गया, लेकिन जब बातचीत चल रही थी, अदालत ने दोपहर 3 बजे मामले को उठाया और आदेश पारित कर केशव सिंह को शर्तों और शर्तों पर रिहा करने का निर्देश दिया।

जिनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। श्री श्री राम ने भेजा

श्री निगम को केशव द्वारा किए गए आवेदन की तीन प्रतियाँ

सिंह और सुझाव दिया कि बनाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए

संबंधित व्यक्तियों का एक उपयुक्त शपथ पत्र। उन्होंने यह भी बताया कि

श्री निगम ने कहा कि आवेदन को सुनवाई के लिए बहुत जल्द सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।

सरकार द्वारा किए गए अनुरोध का पालन करने के बजाय

अधिवक्ता को निर्देश देना और उसे आवेदन में विवरणी दाखिल करने का निर्देश देना। केशव सिंह द्वारा किए गए निर्णय पर सदन ने कार्रवाई शुरू की

केशव पर आदेश पारित करने वाले दो विद्वान न्यायाधीशों के खिलाफ

20 तारीख को सदन के अध्यक्ष के ध्यान में लाया गया मार्च के संबंध में अदालत के समक्ष क्या हुआ था

केशव सिंह द्वारा किया गया आवेदन। आदेश का संज्ञान लेना

केशव सिंह की याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित, सदन

21 मार्च, 1964 को एक प्रस्ताव पारित करने के लिए आगे बढ़े। यह संकल्प

उन्होंने कहा कि सदन का निश्चित दृष्टिकोण था कि एम/एस। जी. डी. सहगल, एन. यू. बेग, केशव सिंह और बी. सोलोमन ने अपराध किया था।

सदन की अवमानना और इसलिए, यह आदेश दिया गया कि केशव

सिंह को तुरंत हिरासत में लिया जाना चाहिए और कैद में रखा जाना चाहिए।

जिला जेल, लखनऊ में, अपने कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सोनमेंट और एम/एस। एन. यू. बेग, जी. डी. सहगल और बी. सोलोमन को [1965] 1 एस. सी. आर. होना चाहिए।

सदन के समक्ष अभिरक्षा में लाया जाए। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि केशव सिंह के कारावास का कार्यकाल पूरा करने के बाद, उन्हें 19 मार्च, 1964 को फिर से सदन की अवमानना करने के लिए सदन के समक्ष लाया जाना चाहिए।

दोनों न्यायाधीशों ने इस संकल्प के बारे में कड़ी मेहनत की

21 मार्च की शाम को रेडियो पर, और 22 मार्च, 1964 को प्रकाशित उत्तर भारत पत्रिका के सुबह के संस्करण में इसके बारे में पढ़ा। यही कारण है कि वे अनुच्छेद के तहत अलग-अलग याचिकाओं के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए। 226 संविधान से। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि सदन द्वारा पारित विवादित प्रस्ताव पूरी तरह से असंवैधानिक था और अनुच्छेद के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। 211 संविधान से। याचिकाओं के अनुसार, अनुच्छेद के तहत केशव सिंह द्वारा किया गया आवेदन। 226 न्यायाधीश सक्षम थे और केशव सिंह को रिहा करने का आदेश देते हुए, अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र और अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। 226. उनका तर्क था कि सदन द्वारा पारित प्रस्ताव न्यायालय की अवमानना के बराबर है, और चूंकि यह पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है, इसलिए इसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और एक अंतरिम आदेश द्वारा इसके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी जानी चाहिए। इन याचिकाओं पर उत्तरदाता के रूप में श्री वर्मा, अध्यक्ष, विधानसभा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य और मार शाल, विधानसभा को शामिल किया गया था। ये याचिकाएँ 23 मार्च, 1964 को दायर की गई थीं।

आशंका है कि इन घटनाओं ने एक को जन्म दिया था

बहुत गंभीर समस्या, 28 न्यायाधीशों वाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने उसी दिन लखनऊ में उनके दो सहयोगियों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं पर विचार किया, निर्देश दिया कि उक्त याचिकाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उत्तरदाताओं के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

21 मार्च, 1964 को उन्हें दिया गया आवास, और यदि पहले से ही वारंट जारी किया जा चुका है, तो उसे हटाने और उत्तर प्रदेश सरकार और सदन के मार्शल को वारंट को निष्पादित करने से रोकने के लिए।

इस बीच, 25 मार्च, 1964 को विद्वान श्री सोलोमन

केशव सिंह के अधिवक्ता ने अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में इसी तरह की याचिका प्रस्तुत की। 226. उन्होंने दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दायर याचिकाओं की तर्ज पर अनिवार्य रिट के लिए प्रार्थना की, और उन्होंने आग्रह किया कि सदन के खिलाफ उपयुक्त आदेश पारित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने न्यायालय की अवमानना की थी। अपनी याचिका के लिए श्री सोलोमन ने सात उत्तरदाताओं को शामिल किया था; वे थे: सदन के अध्यक्ष श्री वर्मा: विधान सभा, यू. पी. ; यू. पी. विधान सभा के मार्शल; विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

429

श्री सरन और श्री अहमद, विधान सभा के सदस्य, यू. पी., जिन्होंने उच्च न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा पारित आदेशों को सदन के ध्यान में लाया; और उत्तर प्रदेश राज्य।

इस आवेदन पर 28 सदस्यीय पूर्ण पीठ ने फिर से सुनवाई की।

25 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने याचिका स्वीकार करने के बाद एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी वैधता को याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी। इस याचिका की प्रारंभिक सुनवाई में अदालत में मौजूद वरिष्ठ स्थायी वकील को नोटिस दिया गया था। उन्होंने अदालत से कहा कि उस समय उनके पास आवेदन का विरोध करने का कोई निर्देश नहीं था। यही कारण है कि न्यायालय ने आवेदन का नोटिस जारी किया और जो उचित आदेश होगा उसे पारित किया।

उसी दिन सदन ने एक स्पष्टीकरण प्रस्ताव पारित किया।

यह संकल्प इस कथन के साथ शुरू हुआ कि ए। सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के संबंध में गलतफहमी व्यक्त की जा रही थी कि इसे संबंधित व्यक्तियों को स्पष्टीकरण के अवसर से वंचित करने के रूप में माना जा सकता है, और इसमें कहा गया कि यह सदन का कभी भी इरादा नहीं था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ विशेषाधिकार का उल्लंघन या सदन की अवमानना करने के आरोप का निपटारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए विशेषाधिकार या अवमानना के उस शासी उल्लंघन से अलग तरीके से किया जाए। अत: सदन ने संकल्प लिया कि अवमानना के प्रश्न का निर्णय नियमों के अनुसार 20 मार्च, 1964 के मूल प्रस्ताव में नामित व्यक्तियों को पूर्व निर्णय का अवसर देने के बाद किया जा सकता है।

इस संकल्प के परिणामस्वरूप, के लिए जारी किए गए वारंट

दो विद्वान न्यायाधीशों और श्री सोलोमन की गिरफ्तारी ड्रॉ के साथ हुई, जिसके परिणामस्वरूप दो विद्वान न्यायाधीशों और श्री सोलोमन को सदन के समक्ष उपस्थित होने और अपना स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य किया गया कि सदन को उनकी कथित अवमानना के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करनी चाहिए।

जब घटनाएँ जो इतनी तेजी से हुईं

19 मार्च से 25 मार्च, 1964 तक इस स्तर पर पहुँचने के बाद राष्ट्रपति ने अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय को संदर्भित करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लिया। 143 (1) 26 मार्च, 1964 को संविधान का। संदर्भ आदेश से पता चलता है कि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विचाराधीन घटनाओं ने उच्च न्यायालय और राज्य विधानमंडल के बीच एक गंभीर संघर्ष को जन्म दिया था, जिसने उच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के बारे में कानून के महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्नों को राज्य विधानमंडल और उसके अधिकारियों को और [1965] 1 एस. सी. आर. के संबंध में प्रस्तुत किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

430

अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों के संबंध में राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। राष्ट्रपति इस बात से भी संतुष्ट थे कि उनके संदर्भ आदेश में निर्धारित कानून के प्रश्न इस तरह के थे और इतने सार्वजनिक महत्व के थे कि उन पर इस न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन था। यही वर्तमान संदर्भ की उत्पत्ति है।

इस संदर्भ के तहत इस न्यायालय को भेजे गए प्रश्न

इस प्रकार पढ़िए:

(1) चाहे, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर

मामले में, यह लखनऊ पीठ के लिए सक्षम था

उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय से मिलकर

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. यू. बेग और माननीय श्री

न्यायमूर्ति जी. डी. सहगल, का मनोरंजन करने और उनसे निपटने के लिए

श्री केशव सिंह की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका उसके द्वारा अधिरोपित कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश की विधान सभा अपने संघ के लिए

प्रलोभन और इसके विशेषाधिकारों के उल्लंघन और पारित करने के लिए

श्री केशव सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश

उसकी उक्त याचिका का निपटान;

(2) चाहे, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर

मामले के श्री केशव सिंह ने याचिका दायर की

उसकी ओर से उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना उत्तर प्रदेश, जैसा कि उपरोक्त है, श्री बी. सोलोमन, अधिवक्ता,

उक्त याचिका और उक्त दोनों माननीयों को प्रस्तुत करके

न्यायाधीश उक्त पेटी का मनोरंजन करते हुए और उससे निपटते हुए

श्री केशव सिंह की रिहाई का आदेश की गई उक्त याचिका के निपटारे तक जमानत

उत्तर प्रदेश विधान सभा की अवमानना

देश;

(3) चाहे, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर

मामले में, यह विधायी सभा के लिए सक्षम था

उत्तर प्रदेश का उत्पादन का निर्देशन करने के लिए

दो माननीय न्यायाधीशों और श्री बी. सोलोमन, अधिवक्ता ने कहा

केट, उससे पहले हिरासत में या उनके स्पष्टीकरण के लिए बुलाने के लिए

इसकी अवमानना के लिए;

(4) चाहे, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर

मामले में, यह पूर्ण पीठ के लिए सक्षम था

उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय मनोरंजन और सौदा करने के लिए

उक्त दो माननीय न्यायाधीशों की याचिकाओं के साथ और

श्री बी. सोलोमन, अधिवक्ता और अंतरिम आदेश पारित करने के लिए

विधानसभा के अध्यक्ष को विशेष संदर्भ (गजेंद्रगढ़कर सी. जे.)

431

उत्तर प्रदेश और उक्त के अन्य उत्तरदाताओं

उपरोक्त निर्देश को लागू करने की याचिकाएँ उक्त विधान सभा; और

(5) चाहे वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो जो

किसी भी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करता है या उससे निपटता है

या कोई दंड अधिरोपित करने वाले विधानमंडल का निर्णय

याचिकाकर्ता या पेटी के खिलाफ कोई प्रक्रिया जारी करना

इसकी अवमानना या इसकी गोपनीयता के उल्लंघन के लिए

कानून और प्रतिरक्षा या जो इस पर कोई आदेश पारित करता है

याचिका उक्त विधानमंडल की अवमानना करती है और क्या उक्त विधानमंडल प्रो लेने के लिए सक्षम है

अभ्यास में ऐसे न्यायाधीश के खिलाफ सीडिंग और अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं का प्रवर्तन।

इस संदर्भ की सुनवाई में, श्री वर्मा ने एक मुद्दा उठाया है

बिहार के महाधिवक्ता की ओर से प्रारंभिक आपत्ति। उनका तर्क है कि वर्तमान संदर्भ अनुच्छेद के तहत अमान्य है।

143 (1) क्योंकि इस न्यायालय को निर्दिष्ट प्रश्न सूची I और III में किसी भी प्रविष्टि से संबंधित नहीं हैं और इसलिए उन्हें संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त किसी भी शक्ति, कर्तव्यों या कार्यों से संबंधित नहीं कहा जा सकता है। तर्क यह प्रतीत होता है कि यह केवल राष्ट्रपति की शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों के भीतर आने वाले मामलों के संबंध में है कि वह अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय की सलाहकार राय के लिए प्रश्न तैयार करने में सक्षम होगा। 143 (1) . हमारी राय में, यह तर्क पूरी तरह से गलत है। अनुच्छेद के शब्द। 143 (1) राष्ट्रपति को अपनी सलाहकार राय के लिए इस न्यायालय को भेजने का अधिकार देने के लिए काफी व्यापक हैं

कानून या तथ्य का प्रश्न जो उत्पन्न हुआ है या जिसके उत्पन्न होने की संभावना है, बशर्ते कि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि ऐसा प्रश्न ऐसी प्रकृति का है या ऐसा सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर इस न्यायालय की राय प्राप्त करना अपेक्षित है। यह बिल्कुल सच है कि अनुच्छेद के तहत। 143 (1) भले ही इस न्यायालय को उसकी सलाहकार राय के लिए प्रश्न भेजे जाते हैं, यह न्यायालय हर मामले में ऐसी सलाहकार राय देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद. 143 (1) बशर्ते कि राष्ट्रपति द्वारा तैयार किए गए प्रश्न इस न्यायालय द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद, वह ऐसी सुनवाई के बाद, जो वह उचित समझे, राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है। अनुच्छेद द्वारा निर्धारित प्रावधान में "होगा" शब्द के उपयोग के विपरीत "हो सकता है" शब्द का उपयोग। 143 (2) इस तथ्य को स्पष्ट रूप से सामने लाता है कि किसी मामले में, यह न्यायालय सम्मानपूर्वक अपनी सलाहकार राय व्यक्त करने से इनकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि उसे भेजे गए प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और अन्य प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। अनुच्छेद. 143 (2)

[

1965] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

432

उन मामलों से संबंधित है जिनमें राष्ट्रपति अनुच्छेद के परंतुक द्वारा निर्धारित निषेध के बावजूद इस न्यायालय को विवाद भेज सकता है। 131 , और यह जोड़ता है कि जब ऐसा निर्देश दिया जाता है, तो न्यायालय, ऐसी सुनवाई के बाद, जो वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय बताएगा। दूसरे शब्दों में, जबकि अनुच्छेद के तहत किए गए संदर्भ के मामले में। 143 (2) यह इस न्यायालय का संवैधानिक दायित्व है कि वह अनुच्छेद के तहत दिए गए संदर्भ में अपनी सलाहकार राय को शामिल करते हुए उस संदर्भ पर एक रिपोर्ट बनाए। 143 (1) ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इस संदर्भ के बाद के वर्ग से निपटने में, इस न्यायालय के लिए यह विचार करने के लिए खुला है कि क्या उसे अपनी सलाहकार राय देते हुए राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देनी चाहिए। संदर्भ के तहत प्रश्नों पर।

हालाँकि, इस स्थिति का उठाए गए प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं है

श्री वर्मा द्वारा। श्री वर्मा द्वारा उठाई गई आपत्ति की वैधता को अनुच्छेद के शब्दों के आलोक में आंका जाना चाहिए। 143 (1) स्वयं और ये शब्द इतने व्यापक आयाम के हैं कि इस तर्क को स्वीकार करना असंभव होगा कि श्री वर्मा द्वारा सुझाए गए संकीर्ण परीक्षण को संदर्भ की वैधता निर्धारित करने में ही लागू करना होगा। क्या अनुच्छेद है। 143 (1) आवश्यकता यह है कि राष्ट्रपति को संतुष्ट होना चाहिए कि कानून या तथ्य का प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है। उसे यह भी संतोष होना चाहिए कि ऐसा प्रश्न ऐसी प्रकृति का और इतना सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर इस न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है। प्रथम दृष्टया, इन दोनों मामलों पर राष्ट्रपति की संतुष्टि संदर्भ को उचित ठहराएगी, और यह केवल वहीं है जहां इस न्यायालय को लगता है कि उसके लिए अपनी सलाह व्यक्त करना अनुचित होगा।

इस पर खराब राय है कि यह सम्मानपूर्वक किसी भी राय को व्यक्त करने से इनकार कर सकता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वर्तमान मामले में यह सुझाव देना असंभव होगा कि तथ्य और कानून के प्रश्न जो इस न्यायालय को भेजे गए हैं, वे उत्पन्न नहीं हुए हैं और वे काफी सार्वजनिक महत्व के नहीं हैं। इसलिए, हमें नहीं लगता कि श्री वर्मा द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में कोई सार है।

संविधान के बाद से इस न्यायालय को दिए गए संदर्भ थे

1950 में अपनाया गया यह दर्शाता है कि संदर्भ की वैधता या वैधता निर्धारित करने में श्री वर्मा द्वारा सुझाए गए संकीर्ण परीक्षण को लागू करना कैसे अनुचित होगा। 1951 का पहला विशेष संदर्भ संख्या 1 इस न्यायालय को वैधता के बारे में प्रश्न पर इस न्यायालय की सलाहकार राय प्राप्त करने के लिए दिया गया था और

दिल्ली विधि अधिनियम, 1912, अजमेर-मेरवाड़ा (विधियों का विस्तार) अधिनियम, 1947 और भाग सी राज्य (विधि) अधिनियम, 1951 (1) के भौतिक प्रावधानों की संवैधानिकता। दूसरा विशेष

(1) पुनः में - दिल्ली विधि अधिनियम, 1912, [1951] एस. सी. आर. 747।

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

433

संदर्भ (1) 1958 में दिया गया था। इसमें केरल शिक्षा विधेयक, 1957 के कुछ प्रावधानों की वैधता का संदर्भ था, जिसे केरल विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा गया था। तीसरा विशेष संदर्भ (2) 1959 में दिया गया था। और इसने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच एक समझौते के भौतिक प्रावधानों की वैधता के संबंध में इस न्यायालय की सलाहकार राय आमंत्रित की, जिसे भारत-पाकिस्तान समझौते के रूप में वर्णित किया गया था। चौथा विशेष संदर्भ (3) 1962 में दिया गया था। इस संदर्भ में, राष्ट्रपति ने समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के उद्देश्य से संसद में पेश किए जाने वाले एक मसौदा विधेयक के प्रासंगिक प्रावधानों की वैधता के संबंध में इस अदालत की सलाहकार राय के लिए प्रश्न भेजे। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा अब तक अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय की सलाहकार राय के लिए भेजे गए प्रश्न। 143 (1) एक समान पैटर्न का खुलासा न करें और यह अनुच्छेद में उपयोग किए जाने वाले व्यापक और व्यापक शब्दों के साथ स्पष्ट रूप से सुसंगत है। 143 (1) .

इस बात पर जोर देने की शायद ही आवश्यकता है कि कानून के प्रश्न

जो वर्तमान अवसर पर इस न्यायालय को भेजे गए हैं, वे बहुत बड़े संवैधानिक महत्व के हैं। जिन घटनाओं ने इस संदर्भ को जन्म दिया है, उन्होंने एक बहुत ही कठिन समस्या उत्पन्न कर दी है और जब तक कि दो प्रतिष्ठित निकायों द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में आगे के विकास को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक वे एक बहुत ही गंभीर और कठिन स्थिति का कारण बन सकते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रपति ने यह विचार रखा कि इस न्यायालय की सलाहकार राय के लिए संदर्भ के लिए एक मामला स्थापित किया गया है और उन्होंने तदनुसार पांच प्रश्न तैयार किए हैं और उन्हें हमारी सलाहकार राय के लिए हमें भेज दिया है। अनुच्छेद के तहत। 143 (1) राष्ट्रपति के लिए यह सक्षम हो सकता है कि वह इस न्यायालय की सलाहकार राय के लिए

मौजूदा कानूनों के विवादित प्रावधानों की वैधता से संबंधित तथ्य और कानून के प्रश्नों को तैयार करे; उसके लिए यह खुला हो सकता है कि वह उन विधेयकों में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रावधानों की वैधता के संबंध में प्रश्न तैयार करे जो विधानमंडलों के समक्ष आएंगे; उसके लिए यह भी खुला हो सकता है कि वह इस न्यायालय की सलाहकार राय के लिए संवैधानिक प्रावधानों के प्रश्नों को तैयार करे।

वर्तमान की तरह संकेत; और यह हो सकता है कि राष्ट्रपति, हमारे उत्तर प्राप्त करने पर विचार कर सकते हैं कि क्या संघ सरकार

या राज्य सरकार से किसी भी उपयुक्त या उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाना चाहिए, या तो विधायी या कार्यपालिका में

(1) पुनः में - केरल शिक्षा विधेयक, 1957, एस. सी. आर. 995। (2) पुनः में - बेरूबरी संघ, [1960] 3 एस. सी. आर. 250।

(3) पुनः में - समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम आदि में संशोधन के लिए विधेयक [1964] 3 एस. सी. आर. 787.

इस न्यायालय द्वारा व्यक्त राय के अनुसार। यही कारण है कि हमें यह मानने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है कि वर्तमान संदर्भ

सक्षम।

जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, जब कोई संदर्भ प्राप्त होता है

अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय द्वारा। 143 (1) , यह न्यायालय, किसी मामले में, पर्याप्त और संतोषजनक कारणों से, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए प्रश्नों पर अपने उत्तरों वाली रिपोर्ट बनाने से सम्मानपूर्वक इनकार कर सकता है; ऐसी स्थिति शायद उत्पन्न हो सकती है यदि इस न्यायालय की सलाहकार राय के लिए तैयार किए गए प्रश्न विशुद्ध रूप से हैं।

सामाजिक-आर्थिक या राजनीतिक प्रश्न जिनका संविधान के किसी भी प्रावधान से कोई संबंध नहीं है, या अन्यथा जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। इस न्यायालय को इस तरह के मजबूत और सम्मोहक कारणों से प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करने की दृष्टि से संविधान ने अनुच्छेद में 'मे' शब्द का उपयोग किया है। 143 (1) अनुच्छेद से अलग। 143 (2) जहाँ प्रयुक्त शब्द 'होगा' है। इस मामले में हम

स्पष्ट रूप से यह राय है कि हमारी सलाहकार राय के लिए तैयार किए गए प्रश्न गंभीर संवैधानिक महत्व और महत्व के प्रश्न हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्रपति को उनके द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों के हमारे उत्तरों को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट दें।

यह हमें द्वारा प्रकट किए गए विवाद के गुणों की ओर ले जाता है

राष्ट्रपति द्वारा हमारे सलाहकार दृष्टिकोण के लिए तैयार किए गए प्रश्न। इस संदर्भ पर हमारे सामने विस्तार से तर्क दिया गया है। विद्वान महान्यायवादी ने हमारे सामने कार्यवाही शुरू की और संदर्भ की ओर ले जाने वाले प्रासंगिक तथ्यों को बताया, और व्यापक रूप से प्रतिद्वंद्वी दलीलों को इंगित किया जिन्हें सदन और उच्च न्यायालय ने मामले के बयानों द्वारा हमारे सामने उठाना चाहा।

उनकी ओर से दायर किया गया। श्री सीरवई, महाराष्ट्र के विद्वान महाधिवक्ता, सदन की ओर से पेश हुए और न्यायालय के समक्ष एक बहुत ही विद्वान, प्रभावशाली और विस्तृत तर्क प्रस्तुत किया। उनके बाद कई विद्वान वकील आए जिन्होंने मोटे तौर पर सदन द्वारा लिए गए रुख का समर्थन किया। श्री सीतलवाड़, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की ओर से पेश हुए, ने अपनी विशिष्ट संक्षिप्तता और स्पष्टता के साथ हमें एक बहुत ही सक्षम तर्क संबोधित किया; और उनके बाद कई विद्वान वकील थे जो न्यायाधीशों द्वारा लिए गए रुख का समर्थन करते दिखाई दिए। बहस के दौरान, हमारे सामने कई प्रस्तावों का प्रचार किया गया और संवैधानिक कानून के एक बहुत बड़े क्षेत्र को शामिल किया गया। इसलिए, हमें शुरुआत में ही यह स्पष्ट करना चाहिए कि वर्तमान संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों के अपने उत्तर तैयार करने में, हम केवल ऐसे बिंदुओं पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं, जो हमारी राय में, "समस्या पर प्रत्यक्ष और भौतिक असर डालते हैं।

उक्त प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत लीम्स। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि संवैधानिक मामलों से निपटने में, न्यायालय विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

उन प्रश्नों से निपटने में धीमी गति से होना चाहिए जो सख्ती से उत्पन्न नहीं होते हैं। अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय को दिए गए निर्देश से निपटने के लिए यह सावधानी और भी आवश्यक है। 143 (1) .

आइए हम मुख्य तर्कों को व्यापक रूप से बताते हुए शुरू करें।

सदन की ओर से और न्यायाधीशों और अधिवक्ता की ओर से आग्रह किया गया। श्री सीरवई ने इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं कि अनुच्छेद के तहत संदर्भ से निपटने में। 143 (1) , न्यायालय उसका प्रयोग नहीं कर रहा है जिसे उसका न्यायिक कार्य कहा जा सकता है।

कार्य. इस तरह के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष कोई पक्ष नहीं हैं।

एनस और कोई लिस नहीं है। न्यायालय द्वारा व्यक्त राय

इसलिए, संदर्भ पर सलाह है; और इसलिए, वह तर्क देता है कि

यद्यपि वह वर्तमान संदर्भ में हमारी ओर से उपस्थित होता है।

सदन का, वह यह स्पष्ट करना चाहता है कि सदन नहीं करता है

इस संबंध में किसी भी तरह से इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करें

प्रश्नों द्वारा कवर किए गए विवाद के क्षेत्र का। अन्य में

शब्दों में, उन्होंने कहा कि हमारे सामने उनकी उपस्थिति पूर्व के बिना थी

उनके मुख्य तर्क का न्याय करें कि अस्तित्व के बारे में सवाल

और सदन की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का विस्तार, साथ ही शक्तियों और प्राथमिकताओं के प्रयोग के बारे में सवाल

विलेज पूरी तरह से और विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र के भीतर थे

सदन; और यह न्यायालय जो कुछ भी कहे, वह इस पर रोक नहीं लगाएगा कि सदन अपने लिए इस के तहत हमें संदर्भित बिंदुओं को तय करने से

संदर्भ. यह रुख इस आधार पर आधारित था कि राय

हमारे द्वारा व्यक्त किया जाना सलाहकारी है और न्यायिक प्रकृति का नहीं है। न्यायालय के समक्ष पक्षों के बीच इस प्रकार का निर्णय।

श्री सीरवई ने भी अनुच्छेद के संबंध में यही रुख अपनाया था।

और उसके सदस्यों और समितियों से। हमारे पास ओक्का होगा इस अनुच्छेद के प्रावधानों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसके लिए

वर्तमान में, यह कहना पर्याप्त है कि श्री सीरवई के अनुसार, यह है के सुसंगत प्रावधानों का अर्थ लगाने के लिए सदन का विशेषाधिकार

अनुच्छेद. 194 (3) और अपने लिए निर्धारित करें कि इसकी शक्तियाँ, विशेषाधिकार क्या हैं

और प्रतिरक्षण हैं, और ऐसा होने पर, राय व्यक्त की गई है

अस्तित्व और विस्तार से संबंधित प्रश्नों पर यह न्यायालय।

विचारों से मुक्त अपने लिए एक ही प्रश्न का निर्धारण करना इस न्यायालय से।

इस प्रकार दावे के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए

जिसे सदन अपनी शक्तियों के संबंध में बनाने का प्रस्ताव करता है और

विशेषाधिकार, श्री सीरवई ने तर्क दिया कि इंग्लैंड में भी यह

जूडिका द्वारा दावा किए गए दो प्रतिद्वंद्वी क्षेत्राधिकारों के बीच द्वैतवाद

शासन और संसद हमेशा से अस्तित्व में रही है और यह अभी भी जारी है (1965) 1 एस. सी. आर.

अनसुलझा होना। कुछ मौकों पर, न्यायपालिका और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच विवाद बहुत कड़वा हो गया है।

रूप और इसने एक पूर्ण एंटीनोमी का खुलासा किया है। या। दोनों संबंधित प्रतिष्ठित निकायों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में विरोधाभास। अदालतों ने दावा किया कि उन्हें विचाराधीन शक्तियों और विशेषाधिकारों के अस्तित्व और विस्तार के बारे में सवाल का फैसला करने का अधिकार है और संसद ने 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान इस संबंध में अदालतों के अधिकार क्षेत्र को मान्यता देने से लगातार इनकार कर दिया। संसद मान गई कि वह कोई नया विशेषाधिकार नहीं बना सकती, लेकिन उसने खुद को मौजूदा विशेषाधिकारों के एकमात्र और अनन्य न्यायाधीश के रूप में मानने पर जोर दिया और यह निर्धारित करने के लिए अपने अधिकार से अलग होने के लिए तैयार नहीं था कि वे क्या थे, या उनके उल्लंघन से निपटने के लिए, और अपराधी नागरिकों को कैसे दंडित किया जाए। दूसरी ओर, अदालतों ने विशेषाधिकार के उल्लंघन के आधार पर संसद द्वारा पारित आदेशों की वैधता की जांच करने पर जोर दिया, और इस प्रकार प्रकट द्वैतवाद कई वर्षों तक बना रहा।

श्री सीरवई का तर्क है कि जिस सदन के लिए वे उपस्थित होते हैं

उस रुख का पालन करता है जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स ने समान रूप से लिया था। डी. विवाद, जिसके कारण अतीत में कई अवसरों पर न्यायपालिका और स्वयं के बीच संघर्ष हुआ। इस रवैये के अनुरूप, वह केशव सिंह द्वारा अपनी रिट याचिका में उठाए गए बिंदुओं से निपटने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से इनकार करते हैं। तार्किक रूप से, उनका तर्क है कि केशव सिंह और उनके अधिवक्ता द्वारा याचिका प्रस्तुत करना ई की अवमानना के बराबर है।

सदन, और जब विद्वान न्यायाधीशों ने याचिका पर विचार किया और उस पर एक अंतरिम आदेश पारित किया, तो उन्होंने सदन की अवमानना की। यह सदन द्वारा लिया गया दृष्टिकोण है और इस दृष्टिकोण की औचित्य, शुद्धता या वैधता इस देश में न्यायपालिका द्वारा जांची नहीं जा सकती है।

वैकल्पिक रूप से, श्री सीरवई ने अपने तर्क को थोड़ा अलग आधार पर रखा। उन्होंने स्वीकार किया कि एक शताब्दी से अधिक समय पहले, इंग्लैंड में, इस विवाद को न्यायपालिका और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच समझौते द्वारा काफी हद तक सुलझा लिया गया था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा यह मान्यता दी गई है कि विशेषाधिकार के अस्तित्व और विस्तार की अदालतों द्वारा जांच की जा सकती है। यह हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भी मान्यता प्राप्त प्रतीत होता है कि यदि। किसी व्यक्ति को उसकी अवमानना के लिए दंडित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह एक बोलने वाला वारंट जारी करता है, यह अदालत के लिए इस बात पर विचार करने के लिए खुला होगा कि वारंट में बताए गए कारण अवमानना के बराबर हैं या नहीं। इस सीमित सीमा तक, पिछली शताब्दी से न्यायपालिका की अधिकारिता को मान्यता दी गई है और लगातार, जब भी उसकी अवमानना के लिए उसके द्वारा पारित आदेशों को उचित ठहराना आवश्यक हुआ है, तो एक वापसी हमेशा विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.) रही है।

अदालतों में दायर किया गया। श्री सीरवई, हालांकि, इस तथ्य पर जोर देते हैं कि विशेषाधिकार की प्रकृति और सीमा के बारे में प्रश्न पर न्यायपालिका और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच इस बड़े पैमाने पर समझौते के परिणामस्वरूप भी, यह तय माना जाता है कि यदि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित करने के लिए एक स्पष्ट या सामान्य वारंट जारी किया जाता है जो इसकी अवमानना का दोषी है, तो अदालतें हमेशा उक्त सामान्य वारंट को निष्कर्ष के रूप में मानेंगी और सदन द्वारा पारित आदेश की वैधता की जांच नहीं करेंगी। वर्तमान मामले में, श्री सीरवई के अनुसार, सदन द्वारा दो विद्वान न्यायाधीशों के साथ-साथ श्री सोलोमन के खिलाफ पारित किया गया प्रस्ताव एक सामान्य प्रस्ताव की प्रकृति का है और हालांकि उनके खिलाफ जारी वारंट

न्यायाधीशों को वापस ले लिया गया है, यह स्पष्ट है कि सदन और वारंट जिन्हें शुरू में जारी करने का आदेश दिया गया था

उक्त संकल्प के अनुसरण में, सामान्य की प्रकृति में थे

समाधान और सामान्य वारंट, और इसलिए, यह इसके लिए खुला नहीं होगा

यह न्यायालय उन कारणों की जांच करने के लिए जिनके लिए उक्त वारंट थे

जारी किया गया। विचाराधीन प्रस्ताव और वारंट जारी किए गए

वर्तमान संदर्भ के तहत, हमें इस स्थिति को प्रभावी बनाना चाहिए जो किसी प्रकार के निहित द्वारा विकसित हुआ प्रतीत होता है

न्यायपालिका और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच समझौता।

यह समझौता दर्शाता है कि प्रश्नों को निर्धारित करने का अधिकार

अवमानना और उक्त के लिए सजा की पर्याप्तता तय करना।

अवमानना विशेष रूप से सदन की है, और यदि इसके अनुसरण में

उक्त अनन्य शक्ति, एक सामान्य वारंट जारी किया जाता है, सदन

उत्पत्ति या कारणों की व्याख्या करने के लिए कभी नहीं कहा जा सकता है

उक्त आदेश। यह अपने आप में विशेषाधिकारों का एक अभिन्न अंग है

और सदन की शक्तियाँ, और यह अभिन्न भाग, के अनुसार

घर, अनुच्छेद के परिणामस्वरूप भारत में लाया गया है। 194 (3) से

द. संविधान। दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि भले ही

इस न्यायालय के पास इसका दायरा और प्रभाव निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है

अनुच्छेद. 194 (3) , यह इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि यह विशेष

एक अनकही सामान्य वारंट जारी करने और उस पर जोर देने की शक्ति

उक्त वारंट को निर्णायक मानने वाली न्यायपालिका, इसका एक हिस्सा है -

जिन विशेषाधिकारों को अनुच्छेद का अंतिम भाग देता है। 194 (3) संदर्भित करता है। यह है।

इस व्यापक आधार पर कि श्री सीरवई चाहते थे कि हम अपने

उन प्रश्नों के उत्तर जो विषय वस्तु हैं

संदर्भ.

दूसरी ओर, न्यायाधीशों की ओर से श्री सीतलवाड़ तर्क देते हैं

कि हमारे संविधान में आयात करने की कोई गुंजाइश नहीं है

द्वैतवाद जो न्यायपालिका और न्यायपालिका के बीच इंग्लैंड में मौजूद था

हाउस ऑफ कॉमन्स। उनका तर्क है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता [1965] 1 एस. सी. आर.

यह अनुच्छेद के निर्माण का सवाल है। 194 (3) यह इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अपवादात्मक अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है और यह कि वह निर्माण जो यह न्यायालय अनुच्छेद के उत्तरार्ध में उपयोग किए गए प्रासंगिक शब्दों पर रखेगा। 194 (3) अंत में विचाराधीन विशेषाधिकारों का दायरा, विस्तार और चरित्र निर्धारित किया जाएगा।

श्री सीतलवाड़ के अनुसार, अनुच्छेद। 194 (3) इसे पृथक राष्ट्र में नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसे इसके संदर्भ में और अनुच्छेद जैसे अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। 32 , 211 और 226। जब अनुच्छेद का भौतिक भाग। 194 (3) इस प्रकार पढ़ा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान प्रश्नों को जन्म देने वाले मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय और सदन की शक्तियों के बीच किसी भी विरोधाभास या द्वैतवाद को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे आग्रह किया कि सदन के लिए एक ऐसा रवैया अपनाना बेकार होगा जिसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स ने 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में अपनाया था जब उक्त सदन और संसद के बीच संघर्ष पैदा हुआ था।

न्यायपालिका। श्री सीतलवाड़ कहते हैं कि एक सदी से अधिक समय से हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा यह तर्क देने का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि यदि कोई नागरिक जिसे सदन द्वारा उसके द्वारा की गई कथित अवमानना के लिए दंडित किया जाता है, तो वह एक और अवमानना का दोषी होगा यदि वह अदालत को उसके बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार क्षेत्र में ले जाता है, और न ही हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इस अवधि के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले वकील के खिलाफ या ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई प्रयास किया गया है; और इसलिए, तर्क यह है कि हमें वर्तमान विवाद से उस सामान्य समझौते के आधार पर निपटना चाहिए जो परंपरा के अनुसार, दो महान और शक्तिशाली संस्थानों, न्यायिक और विधानमंडल के बीच विकसित किया गया है।

श्री सीतलवाड़ ने स्वीकार किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बैठक हुई है

अंग्रेजी अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त जिसके द्वारा वे एक जनरल के साथ व्यवहार करते हैं

या आम तौर पर निर्णायक के रूप में सदन द्वारा जारी गैर-मौखिक वारंट;

लेकिन उनके अनुसार मामले का यह पहलू परंपरा या सौहार्द का परिणाम है और इसे एक अभिन्न अंग के रूप में नहीं माना जा सकता है।

स्वयं सदन के विशेषाधिकार का। इसे विकसित करने का आधार

कन्वेंशन इंग्लैंड के इतिहास में निहित है, क्योंकि पार्लिया

यह एक समय में सर्वोच्च न्यायालय था और यह है इस इतिहास के कारण कि हाउस ऑफ कॉमन्स भी आया था

एक उच्च न्यायालय के रूप में माना जाए। ऐसी धारणा

वर्तमान कार्यवाही में सदन के संबंध में नहीं किया जा सकता है

िंग्स। इसके अलावा, के प्रभाव के बारे में सवाल से निपटने में एक सामान्य वारंट, न्यायालय के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकता है

अनुच्छेदएँ। 32 , 211 और संविधान की धारा 226। खुद को आधार बनाते हुए

मोटे तौर पर इन तर्कों पर श्री सीतलवाड़ का तर्क है कि कॉन विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.) द्वारा हमारे देश में द्वैतवाद की समस्या का समाधान किया गया है।

439

उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करना

नागरिकों द्वारा किए गए दावों से निपटने के लिए जिनके मौलिक अधिकार हैं

आक्रमण किया गया है, और इसका मतलब है कि इस देश में, अगर एक

आदेश की वैधता की जांच करने के लिए यह न्यायालय या उच्च न्यायालय विधानमंडल सहित किसी भी प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया, और वह

अनिवार्य रूप से इस परिणाम को शामिल करता है कि एक अनकहा वारंट

निर्णायकता के विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते। कि, संक्षेप में,

इसकी व्यापक विशेषताएँ श्री सीतलवाड़ द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण है। हमारे सामने।

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि मुख्य विवाद का खुलासा

राष्ट्रपति द्वारा तैयार किए गए पाँच प्रश्न अंततः इसके अंतर्गत आते हैं।

एक बहुत ही संकीर्ण कम्पास। क्या सदन एकमात्र और अनन्य न्यायाधीश है?

इस मुद्दे की कि क्या इसकी अवमानना कहाँ की गई है

कथित अवमानना चार दीवारों के बाहर हुई है

घर का? क्या सदन इसका एकमात्र और अनन्य न्यायाधीश है?

दंड जो उस पक्ष पर लगाया जाना चाहिए जिसके पास है इसकी अवमानना का दोषी पाया गया? और, यदि प्रवर्तन में

इसका निर्णय सदन एक सामान्य या अनकहा वारंट जारी करता है,

उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करने का हकदार है

सजा पाए व्यक्ति की नजरबंदी की वैधता को चुनौती देना घर से? श्री सीरवई की ओर से तर्क का आग्रह किया गया

सदन यह है कि एक सामान्य वारंट के मामले में, उच्च न्यायालय

वारंट के पीछे जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है; और वर्तमान में

मामला, क्योंकि इसने याचिका पर विचार किया है और एक आदेश पारित किया है

वारंट की जांच किए बिना केशव सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

और उत्तरदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल किए जाने से पहले ही इसने कार्रवाई की है

अवैध रूप से और अधिकार क्षेत्र के बिना, और इसलिए, के विद्वान न्यायाधीश

उच्च न्यायालय, वकील और पक्षकार सभी अपराध के दोषी हैं।

घर का प्रलोभन। श्री सीरवई आग्रह करते हैं कि किसी भी मामले में बंदीवास में

इस चरित्र की कॉर्पस कार्यवाही, उच्च न्यायालय का कोई न्यायशास्त्र नहीं था अंतरिम जमानत देने के लिए शब्दकोष।

श्री सीतलवाड़ इस बात पर गंभीर रूप से विवादित नहीं हैं कि सदन ने

यह जाँचने की शक्ति कि क्या इसकी अवमानना की गई है

इसकी चार दीवारों के बाहर भी किसी के द्वारा और उसे थोपने की शक्ति है

इस तरह की अवमानना के लिए सजा; लेकिन उनका तर्क है कि

हमारे संविधान के भौतिक प्रावधानों के संबंध में, यह होगा यह दावा करने के लिए सदन के लिए खुला नहीं है कि इसका सामान्य वारंट है

इसे निर्णायक माना जाना चाहिए। हर मामले में जहाँ एक पक्ष है

सदन द्वारा अवमानना के लिए सजा सुनाई गई और हिरासत में लिया गया, यह होगा

उचित राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए तैयार रहें

अनुच्छेद के तहत। 226 और उच्च न्यायालय जाँच करने का हकदार होगा

उसकी दलीलों के गुण, भले ही वारंट सामान्य हो सकता है

पी।

C

.I./65-3 [1965] 1 एस. सी. आर.

440

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या बोलती नहीं है। श्री सीतलवाड़ के अनुसार, चूंकि उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। 226 , इसके पास अंतरिम जमानत का आदेश पारित करने की भी शक्ति है। इस प्रकार, विवाद वास्तव में उन मामलों में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के आसपास केंद्रित है जहां सदन द्वारा अवमानना में पक्ष को हिरासत में रखने का निर्देश देते हुए एक सामान्य या गैर-मौखिक वारंट जारी किया गया है।

यद्यपि द्वारा उत्पन्न समस्या का अंतिम समाधान

अनुच्छेद में निहित प्रावधानों के आलोक में निर्णय लिया जाना। 194 (3) संविधान की, और उस अर्थ में, अनुच्छेद की व्याख्या। 194 (3) यह वास्तव में मामले का सार है। इस स्तर पर इसकी आवश्यकता है। अनुच्छेद 194 पढ़िए:

" 194. (1) इसके प्रावधानों के अधीन रहते हुए

संविधान और नियमों और स्थायी आदेशों के लिए

विधान-मंडल की प्रक्रिया को निर्धारित करते हुए, वहाँ होगा प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में बोलने की स्वतंत्रता।

(2) किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य

के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा

विधान में उसके द्वारा कुछ भी कहा गया या कोई वोट दिया गया

या उसकी कोई समिति, और कोई भी व्यक्ति नहीं होगा

द्वारा या उसके अधीन प्रकाशन के संबंध में उत्तरदायी

ऐसे विधानमंडल के किसी सदन का किसी प्रतिवेदन का प्राधिकार,

कागज, वोट या कार्यवाही।

(3) अन्य मामलों में, शक्तियाँ, विशेषाधिकार और

किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की उन्मुक्ति, और किसी सदन के सदस्यों और समितियों के

ऐसा विधानमंडल ऐसा होगा जो समय-समय पर हो सके

विधान-मंडल द्वारा विधि द्वारा परिभाषित किया जाएगा, और, जब तक कि

परिभाषित, पार के हाउस ऑफ कॉमन्स के होंगे

यूनाइटेड किंगडम और उसके सदस्यों का दायित्व और समितियाँ, इस संविधान के प्रारंभ में।

(4) खंड (1), (2) और (3) के प्रावधान

उन व्यक्तियों के संबंध में लागू होगा जो इस आधार पर

संविधान को बोलने का अधिकार है, और अन्यथा

विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए

किसी राज्य या उसकी किसी समिति की प्रकृति जो वे लागू करते हैं।

उस विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में "। विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

441

यह ध्यान दिया जाएगा कि अनुच्छेद के पहले तीन भौतिक खंड।

194 तीन अलग-अलग विषयों से निपटें। खंड (1) यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में बोलने की स्वतंत्रता, जिसे वह निर्धारित करता है, संविधान के प्रावधानों और विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन है। इस खंड की व्याख्या करते समय, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि संविधान के वे प्रावधान जिनके अधीन विधायकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, संविधान के सामान्य प्रावधान नहीं हैं, बल्कि उनमें से केवल वे हैं जो विधानमंडल की प्रक्रिया के विनियमन से संबंधित हैं। नियम और स्थायी आदेश विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित कर सकते हैं और संविधान के कुछ प्रावधान भी इसे विनियमित करने के लिए अभिप्रेत हो सकते हैं; उदाहरण के लिए, ये अनुच्छेद 208 और 211 हैं। विशेषण खंड "विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित करने वाला" दोनों पूर्ववर्ती खंडों को नियंत्रित करता है।

"संविधान के प्रावधानों" और "नियमों और स्थायी आदेशों" से संबंधित। इसलिए, खंड (1) विधान मंडल को विशेष रूप से उसके पहले भाग द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि इस खंड को केवल संविधान के निर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन करके, संविधान निर्माता यह स्पष्ट करना चाहते थे कि उन्होंने विधायक को अलग से और एक अर्थ में, अनुच्छेद से स्वतंत्र रूप से बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक समझा। 19 (1) (ए)। यदि सभी विधायक दावा करने के हकदार थे

अनुच्छेद में निहित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 (1) (क) समान अधिकार विशेष रूप से प्रदान करना अनावश्यक होता।

अनुच्छेद द्वारा अपनाए गए तरीके से। 194 (1) ; और इसलिए, यह वैध होगा

यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि अनुच्छेद। 19 (1) (क) संविधान के प्रावधानों में से एक नहीं है जो संविधान के खंड (1) के पहले भाग को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद. 194 .

विधायिकाओं को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद, खंड

(2) इस तथ्य पर जोर देता है कि उक्त स्वतंत्रता का उद्देश्य होना है

पूर्ण और निरंकुश। इसी तरह की स्वतंत्रता की गारंटी है

विधायक उन मतों के संबंध में जो वे विधान में दे सकते हैं

इसकी प्रक्रिया या कोई समिति। दूसरे शब्दों में, भले ही एक लेजिस

लैटर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का उल्लंघन करते हुए प्रयोग करता है, कहते हैं,

अनुच्छेद की। 211 , वह किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसी तरह, यदि विधायक पर अपने भाषण या वोट से आरोप लगाया जाता है कि

भाग III द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है।

विधान सभा में संविधान के, वह नहीं होगा

किसी भी न्यायालय में उक्त उल्लंघन के लिए जवाबदेह होगा। अगर

आक्षेपित भाषण मानहानि के बराबर होता है या कार्रवाई योग्य या अभियोग बन जाता है

कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत सक्षम, प्रतिरक्षा का प्रावधान किया गया है।

इस खंड द्वारा किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्रवाई से उस पर आरोपित किया गया।

उन्

होंने [1965] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

442

ऐसे भाषण के लिए सदन जवाबदेह हो सकता है और अध्यक्ष इसके संबंध में उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है; लेकिन वह एक अलग मामला है। यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माता

विधायी कक्षों के भीतर बहस में पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता को इतना महत्व दिया कि उन्होंने सोचा कि खंड (2) द्वारा निर्धारित व्यापक शर्तों में विधायी कक्षों में अपने भाषणों के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई से विधायकों को पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करना आवश्यक

है। इस प्रकार, खंड (1) विधायी कक्ष के भीतर विधायकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और खंड (2) यह स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता शाब्दिक रूप से पूर्ण और निरंकुश है।

यह हमें खंड (3) पर ले जाता है। इस खंड का पहला भाग

राज्यों के विधानमंडलों को अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करने वाले कानून बनाने का अधिकार देता है; बाद वाले भाग में प्रावधान है कि जब तक ऐसे कानून नहीं बनाए जाते हैं, तब तक संबंधित विधानमंडलों को वही शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी जो संविधान के प्रारंभ में हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त थीं। संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि विधानसभाओं को अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति के संबंध में कानून बनाने में कुछ समय लगेगा। अंतराल के दौरान, उन्हें आवश्यक शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान करना स्पष्ट रूप से आवश्यक था। इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सी. एल. द्वारा जिन शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं पर विचार किया गया है। (3) , आनुषंगिक शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं जो प्रत्येक विधानमंडल के पास होनी चाहिए ताकि वह प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम हो सके, और जो खंड (3) के उत्तरार्द्ध भाग के उद्देश्य की व्याख्या करता है।

इस खंड के लिए आवश्यक है कि शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा

सदन द्वारा जिन संबंधों का दावा किया जाता है, उन्हें संविधान के प्रारंभ में, यानी 26 जनवरी, 1950 को अस्तित्व में नहीं दिखाया जाना चाहिए। यह सर्वविदित है कि बड़ी संख्या में प्रिवी

मान्यता के लिए अपने कड़वे संघर्ष के दिनों के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स ने जिन कानूनों और शक्तियों का दावा किया था, उनमें से कुछ को समय के साथ छोड़ दिया गया था, और कुछ वस्तुतः अस्वीकृति से समाप्त हो गए थे।

और इसलिए, हर मामले में जहां एक शक्ति का दावा किया जाता है, यह आवश्यक है

यह पूछताछ करने के लिए कि क्या यह प्रासंगिक समय पर एक मौजूदा शक्ति थी। यह भी प्रतीत होना चाहिए कि उक्त शक्ति का दावा न केवल द्वारा किया गया था

हाउस ऑफ कॉमन्स, लेकिन अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। यह स्पष्ट रूप से यह तर्क देना बेकार होगा कि यदि कोई विशेष शक्ति

जिसका सदन द्वारा दावा किया जाता है, सदन द्वारा दावा किया गया था

कॉमन्स लेकिन अंग्रेजी अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था, फिर भी इसे केवल खंड (3) के बाद के भाग के तहत बरकरार रखा जाएगा

यह आधार है कि यह वास्तव में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किया गया था। में। दूसरे शब्दों में, इस खंड द्वारा निर्धारित जांच है:

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

443

प्रश्नगत शक्ति प्रासंगिक समय पर हाउस ऑफ कॉमन्स में दिखाई गई या साबित हुई?

खंड (4) तीन पूर्व-खंडों द्वारा निर्धारित प्रावधानों का विस्तार करता है।

उसमें वर्णित कुछ व्यक्तियों को खंड सौंपना।

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि अनुच्छेद के सभी चार खंड। 194 हैं।

भाग III में निहित प्रावधानों के अधीन किए गए शब्दों में नहीं।

वास्तव में, खंड (2) को इतने व्यापक शब्दों में जोड़ा गया है कि सी. एल. द्वारा उन्हें प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करने में। (1) , यदि विधायक अपने भाषणों द्वारा भाग III द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, तो वे किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। फिर भी, यदि अन्य वैध विचारों के लिए, यह प्रतीत होता है कि सी. एल. की सामग्री। (3) संविधान के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर नहीं किया जा सकता है, यह सुझाव देना उचित नहीं होगा कि उन प्रावधानों को केवल इसलिए नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि उक्त खंड "संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन" शब्दों के साथ नहीं खुलता है। सीएल में निहित प्रावधानों के प्रभाव से निपटने में। (3) अनुच्छेद की। 194 , जहाँ भी यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रावधानों और मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों के बीच टकराव है, वहाँ सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को अपनाकर उक्त संघर्ष को हल करने का प्रयास करना होगा। इस तरह के नियम को अपनाने का क्या परिणाम होगा, हमें इस स्तर पर विचार करने के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। हम इसका उल्लेख बाद में करेंगे जब हम पंडित एम. एस. एम. शर्मा बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करेंगे। श्री श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य (1)।

तथापि, खंड (3) के प्रथम भाग के निहितार्थ,

इस स्तर पर जांच की जाए। सवाल यह है कि क्या किसी राज्य का विधानमंडल कोई कानून बनाता है जो अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और विशेषाधिकारों को निर्धारित करता है।

उन्मुक्ति, क्या यह कानून अनुच्छेद के अधीन होगा। 13 या नहीं? यह याद किया जा सकता है कि अनुच्छेद। 13 यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून अमान्य होंगे। अनुच्छेद का खंड (1)। 13 उस संबंध में भारत के क्षेत्र में प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू कानूनों को संदर्भित करता है

संविधान और खंड (2) उन कानूनों को संदर्भित करता है जो राज्य भविष्य में बनाएगा। प्रथम दृष्टया, यदि किसी राज्य का विधानमंडल खंड (3) द्वारा उसे प्रदत्त प्राधिकरण के अनुसरण में कोई कानून बनाता है, तो यह अनुच्छेद के अर्थ के भीतर कानून होगा। 13 और अनुच्छेद का खंड (2)। 13 यदि यह भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या उन्हें कम करता है तो यह अमान्य हो जाएगा। जैसा कि हम वर्तमान में इंगित करेंगे, यह पंडित शर्मा के (1) मामले में इस न्यायालय के फैसले का प्रभाव है। दूसरे शब्दों में, अब इसे तय माना जाना चाहिए।

(1) [1959] सप. 1 एससीआर 806।

कि यदि कोई कानून शक्ति के कथित प्रयोग के तहत बनाया गया है

खंड (3) के पहले भाग द्वारा प्रदत्त, इसे अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों द्वारा निर्धारित परीक्षण को पूरा करना होगा। यदि ऐसा है, तो यह तुरंत यह पूछताछ करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या संविधान निर्माताओं ने वास्तव में यह इरादा किया था कि मौलिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाएं, जिनके अधीन अकेले किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं को निर्धारित करने के लिए एक कानून बनाया जा सकता है, उक्त खंड के बाद के भाग का अर्थ लगाने में अप्रासंगिक माना जाना चाहिए। उसी बिंदु को आसानी से दूसरे रूप में रखा जा सकता है। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि सदन द्वारा दावा की गई कोई भी शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, तो संघर्ष कैसे हल होने वाला है। क्या संविधान का इरादा शक्तियों, विशेषाधिकारों को स्थापित करना था

और सी. एल. के उत्तरार्द्ध भाग में निर्दिष्ट प्रतिरक्षण। (3) उस कानून की तुलना में बहुत अधिक उच्च आधार पर जो किसी राज्य का विधानमंडल भविष्य की तारीख में उस संबंध में बना सकता है? खंड (3) के अर्थघटन के मामले में, यह तथ्य कि उक्त खंड का पहला भाग भावी कानूनों को संदर्भित करता है जो मौलिक अधिकारों के अधीन होंगे, खंड (3) के उत्तरार्ध भाग की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। कि, संक्षेप में, पहले तीन सामग्री की स्थिति है

अनुच्छेद के प्रावधान। 194 .

अगला सवाल जो हमारे सामने है वह प्रारंभिक से उत्पन्न होता है

श्री सेक्रवई द्वारा यह तर्क दिया गया कि हमारे सामने उनकी उपस्थिति से सदन की ओर से, यह नहीं लिया जाना चाहिए कि सदन ने न्यायालय को अनुच्छेद का अर्थ लगाने की अधिकारिता स्वीकार कर ली है। 194 (3) ताकि उसे बांध सकें। जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, उनका रुख यह है कि विशेषाधिकारों के मामले में सदन सभी चरणों में एकमात्र और अनन्य न्यायाधीश है। यह हो सकता है कि तकनीकी रूप से, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदर्भ पर इस न्यायालय द्वारा दी गई सलाहकार राय ठीक से तथाकथित न्यायिक निर्णय के बराबर नहीं हो सकती है और क्योंकि न्यायालय के समक्ष इस मामले में इस तरह के कोई पक्ष नहीं हैं।

लेकिन अलग से।

संदर्भ, कोई भी हमारे उत्तरों से बाध्य नहीं होगा। मामले के इस तकनीकी पहलू से, यह आवश्यक है कि हम इस मूल प्रश्न का निर्धारण करें कि क्या विशेषाधिकारों के मामले में भी, संविधान सदन को एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है जैसा कि श्री सीरवई ने दावा किया है। यह कॉम है।

इस आधार पर कि शक्तियों को अनुच्छेद में पाया जाना चाहिए। 194 (3) . यह प्रावधान शक्तियों का एकमात्र आधार है, और कोई शक्ति नहीं है।

जो इसमें शामिल नहीं है, सदन द्वारा दावा किया जा सकता है; और इसलिए,

अपनी चर्चा की दहलीज पर, हमें यह तय करना चाहिए

सवाल करते हैं।

इस प्रश्न से निपटने के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है

संघीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता।

इंग्लैंड में, विशेष संदर्भ (गजेंद्रगढ़कर सी. जे.)

445

संसद संप्रभु है; और डाइसी के शब्दों में, संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत की तीन विशिष्ट विशेषताएँ यह हैं कि संसद को कोई भी कानून बनाने या बनाने का अधिकार है; कि इंग्लैंड के कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी व्यक्ति या निकाय को पार्लियामेंट के कानून को ओवरराइड या अलग करने का अधिकार नहीं है; और यह कि संसद का अधिकार या शक्ति रानी के प्रभुत्व के हर हिस्से तक फैली हुई है (1)। दूसरी ओर, संघवाद की मूल विशेषता "उन निकायों के बीच सीमित विशेष, विधायी और न्यायिक प्राधिकरण का वितरण है जो एक दूसरे के साथ समन्वय और स्वतंत्र हैं"। संविधान की सर्वोच्चता एक संघीय राज्य के अस्तित्व के लिए मौलिक है ताकि संघीय इकाई या सदस्य राज्यों के विधानमंडल को शक्ति के उस नाजुक संतुलन को नष्ट करने या बाधित करने से रोका जा सके जो विशेष रूप से राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है जो संघ के इच्छुक हैं, लेकिन अपनी व्यक्तित्व को एकता में विलय करने के लिए तैयार नहीं हैं। संविधान की यह सर्वोच्चता शक्तियों के वितरण की योजना के दुभाषिया के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय के अधिकार द्वारा संरक्षित है। न ही संविधान में कोई बदलाव संभव है।

संघीय या राज्य विधान की प्रक्रिया (2)। इस प्रकार प्रमुख चा ब्रिटिश संविधान के कट्टरपंथी होने का दावा नहीं किया जा सकता है

हमारे जैसे संघीय संविधान।

हमारे विधानमंडलों के पास निस्संदेह पूर्ण शक्तियाँ हैं, लेकिन ये

शक्तियों को लिखित कॉन की बुनियादी अवधारणाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

विधान स्वयं और विधायी क्षेत्रों के भीतर प्रयोग किया जा सकता है

सातवें के तहत तीन सूचियों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र को आवंटित

अनुसूची; लेकिन सूचियों से परे, विधानमंडल यात्रा नहीं कर सकते हैं। वे निस्संदेह अपने पूर्ण विधायी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और

शक्तियों के आधार पर अपने विधायी कार्यों का निर्वहन करना

लेकिन शक्ति का आधार स्वयं संविधान है। इसके अलावा, संसद सहित हमारे विधानमंडलों की विधायी सर्वोच्चता

आम तौर पर भाग III में निहित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है

संविधान। यदि विधायिकाएँ उन्हें सौंपे गए विधायी क्षेत्रों से परे कदम उठाती हैं, या अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर कार्य करती हैं,

वे एक तरह से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं

उक्त फंड से संबंधित प्रासंगिक लेखों द्वारा उचित नहीं ठहराया गया है

मानसिक अधिकार, उनके विधायी कार्यों को निरस्त किया जा सकता है

भारत में अदालतों द्वारा। इसलिए यह याद रखना आवश्यक है कि

यद्यपि हमारे विधानमंडलों के पास पूर्ण शक्तियाँ हैं, वे इसके अंतर्गत कार्य करते हैं।

सामग्री और प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित सीमाएँ

संविधान।

(1) डाइस, द लॉ ऑफ द कांस्टीटचूशन 10 वां संस्करण। rr XXIV, XXXV।

(2) टीबीआईडी पी। आईएक्सएक्सवीआई।

लिखित संविधान द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक देश में, यह

संविधान सर्वोच्च और संप्रभु है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान को स्वयं द्वारा संशोधित किया जा सकता है

संसद, लेकिन यह अनुच्छेद के कारण संभव है। 368 संविधान का स्वयं उस ओर से एक प्रावधान करता है, और संविधान का संशोधन केवल उक्त अनुच्छेद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का

पालन करके ही वैध रूप से किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि जब संसद संविधान में संशोधन करने का इरादा रखती है, तब भी उसे संविधान के प्रासंगिक जनादेश का पालन करना पड़ता है।

विधायक, मंत्री और न्यायाधीश सभी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, क्योंकि संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों से ही वे अपना अधिकार और अधिकार क्षेत्र प्राप्त करते हैं और वे संविधान के प्रावधानों के प्रति निष्ठा रखते हैं। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इंग्लैंड में संसद द्वारा जिस संप्रभुता का दावा किया जा सकता है, भारत में कोई भी विधानमंडल शाब्दिक पूर्ण अर्थों में उसका दावा नहीं कर सकता है।

इस मामले का एक और पहलू भी है जो होना चाहिए

भारतीय संविधान के तहत शक्तियों का विशिष्ट और कठोर पृथक्करण हो या न हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान ने इस देश में न्यायपालिका को संविधान के प्रावधानों का अर्थ लगाने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य सौंपा है। जब ए.

कानून को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि इसे बिना किसी अधिकार के विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है, या अन्यथा असंवैधानिक रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, यह अदालतों को तय करना है कि विवाद का निर्धारण करना है और यह तय करना है कि विधानमंडल द्वारा पारित कानून वैध है या नहीं। जिस तरह विधायिकाओं को विधायी प्राधिकरण प्रदान किया जाता है और उनके कार्य आम तौर पर विधायी कार्यों तक सीमित होते हैं, और कार्यकारी प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर कार्यकारी प्राधिकरण के कार्य और अधिकार, उसी तरह इस देश में न्यायपालिका की अधिकारिता और अधिकार न्यायनिर्णयन के क्षेत्र के भीतर होते हैं। यदि किसी कानून की वैधता को अदालतों के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो यह कभी सुझाव नहीं दिया जाता है कि इस बारे में भौतिक प्रश्न कि क्या विधायी प्राधिकरण का उल्लंघन किया गया है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, विधानसभाओं द्वारा स्वयं तय किया जा सकता है। इस तरह के विवाद का न्यायनिर्णयन पूरी तरह से और विशेष रूप से इस देश की न्यायपालिका को सौंपा गया है और इसलिए, हमें अनुच्छेद के निर्माण के बारे में निर्णय लेने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। 194 (3) अंततः यह विशेष रूप से इस देश की न्यायपालिका के पास होना चाहिए। यही कारण है कि हमें श्री सेक्रवई के इस तर्क को खारिज करना चाहिए कि सदन की शक्तियों की प्रकृति, दायरे और प्रभाव को निर्धारित करने का प्रश्न विशेष रूप से इस न्यायालय के न्यायशास्त्र के भीतर नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, यह निष्कर्ष श्री सेक्रवई के इस तर्क की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा कि सलाहकार की राय विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.) है।

वर्तमान संदर्भ कार्यवाहियों में हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया शब्द सहायक नहीं है।

कैशन ठीक से तथाकथित है और इस तरह से किसी भी पक्ष को बाध्य नहीं करेगा।

इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि अनुच्छेद की सामग्री। 194 (3)

अंततः न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए न कि विधानमंडलों द्वारा, हम उस कार्य की भव्यता और महिमा से बेखबर नहीं हैं जो

संविधान के तहत विधानमंडलों को सौंपा गया है।

मोटे तौर पर कहें तो आज हमारे देश के सभी विधायी सदन

वेल के आदर्श की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं

किराया राज्य जिसे संविधान द्वारा हमारे सामने रखा गया है

देश, और जो स्वाभाविक रूप से विधायी कक्षों को एक उच्च स्तर देता है

आज इतिहास के निर्माण में जगह। उच्च न्यायालयों ने भी

नियम के विकास में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाना कानून और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सफल काम करना

जीवन से। इस संबंध में यह याद रखना आवश्यक है कि इन दोनों संबंधित संस्थानों की स्थिति, गरिमा और महत्व,

विधानमंडल और न्यायपालिका, मुख्य रूप से संविधान द्वारा उनके प्रभार को सौंपे गए संबंधित कारणों की स्थिति, गरिमा और महत्व से प्राप्त होते हैं। ये दोनों

उच्च निकायों के साथ-साथ कार्यपालिका जो एक अन्य महत्वपूर्ण है एक लोकतांत्रिक राज्य का घटक, विरोधी में कार्य नहीं करना चाहिए

न ही शत्रुता की भावना से, बल्कि तर्कसंगत रूप से, सामंजस्यपूर्ण रूप से और अपने-अपने क्षेत्रों में समझ की भावना से, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य के तीन घटकों के इस तरह के सामंजस्यपूर्ण काम करने से ही इस देश में लोकतांत्रिक जीवन शैली के शांतिपूर्ण विकास, विकास और स्थिरता में मदद मिलेगी।

लेकिन जब, वर्तमान मामले की तरह, दोनों के बीच विवाद पैदा होता है।

सदन और उच्च न्यायालय, हमें समस्या से निष्पक्ष और व्यक्तिगत रूप से निपटना चाहिए। आयात करने का कोई अवसर नहीं है

बहस या चर्चा में गर्मजोशी और कठोर भाषा के उपयोग के लिए कोई औचित्य नहीं। वर्तमान संदर्भ द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत समस्या संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों का अर्थ निकालने की है और हालांकि इसके विचार से कुछ कठिन पहलू सामने आ सकते हैं, हमें यथासंभव सर्वोत्तम उत्तर खोजने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान जैसे विवाद से निपटने में, जो किसी राज्य में न्यायपालिका, गरिमा और दो प्रतिष्ठित निकायों की स्वतंत्रता से संबंधित है, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे दृष्टिकोण की वस्तुनिष्ठता संयोग से परीक्षण पर हो सकती है। इसलिए, यह पृथक वस्तुनिष्ठ जांच की भावना है जो न्यायपालिका की विशिष्ट विशेषता है।

प्रक्रिया जिसे हम अपनी सलाहकार राय के लिए तैयार किए गए प्रश्नों का समाधान खोजने के लिए प्रस्तावित करते हैं। यदि अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री सीतलवाड़ द्वारा उच्च न्यायालय के लिए हमारे सामने रखा गया दृष्टिकोण गलत है, तो हम अपना निर्णय [1965] 1 एस. सी. आर. देने में संकोच नहीं करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

448

उस दृष्टिकोण के खिलाफ। दूसरी ओर, यदि हम अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री सीरवई द्वारा सदन के लिए किए गए दावे को कायम नहीं रखा जा सकता है, तो हम तदनुसार अपना निर्णय देने में संकोच नहीं करेंगे। इस महत्व और महत्व की समस्याओं से निपटने के लिए, यह आवश्यक है कि हम बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ें और इस पूरी चेतना के साथ कि इस महत्व को बनाए रखना हमारा गंभीर दायित्व है।

संविधान और कानून।

यह याद किया जाएगा कि अनुच्छेद। 194 (3) इसमें दो भाग होते हैं।

पहला भाग विधानमंडल को समय-समय पर कानून द्वारा अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं को परिभाषित करने का अधिकार देता है, जबकि दूसरा भाग यह प्रावधान करता है

कि जब तक विधानमंडल अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं को परिभाषित करने का विकल्प नहीं चुनता है, तब तक इसकी शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति संविधान के प्रारंभ में यूनाइटेड किंगडम के संसद के सदन और उसके सदस्यों और समितियों की होंगी। श्री सीरवई का

कि सभी शक्तियाँ जो हाउस ऑफ कॉमन्स में निहित हैं प्रासंगिक समय, सदन में निहित करें। यह व्यापक दावा, हालांकि,

इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ शक्तियां हैं जिसका स्पष्ट रूप से सदन द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है। प्राइ ले लो

पहुँच की स्वतंत्रता का अपमान जिसका प्रयोग सदन द्वारा किया जाता है

एक निकाय के रूप में और अपने अध्यक्ष के माध्यम से कॉमन्स को हर समय

याचिका दायर करने, परामर्श देने या अपने संप्रभु के साथ विरोध करने का अधिकार

अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से और उनके पास एक अनुकूल अधिकार है

उनके शब्दों पर दिए गए निर्देश को कॉमन्स द्वारा उचित माना गया था

मौलिक विशेषाधिकार के रूप में (1) "। यह इंगित करने की शायद ही आवश्यकता है

कि सदन इस विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। इसी तरह, प्रिवी प्राप्तकर्ता के कृत्यों और महाभियोग के विशेषाधिकार को पारित करने का अधिकार

लेज को तीन तरीकों से व्यक्त किया जाता है, पहले नए रिट के क्रम से संसद के दौरान कॉमन्स में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरें

दूसरा, विवादित चुनावों के परीक्षण द्वारा; और तीसरा,

संदेह (2) इस विशेषाधिकार का फिर से दावा नहीं किया जा सकता है घर को। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सभी

शक्तियाँ और विशेषाधिकार जो सदन के पास थे

सदन द्वारा प्रासंगिक समय पर कॉमन्स का दावा किया जा सकता है।

अनुच्छेद के प्रासंगिक प्रावधान का अर्थ निकालने में। 194 (3) , हमें करना चाहिए

इस के पिछले निर्णय के आलोक में प्रश्न से निपटें

(1) सर टी. एर्स्किन मे का संसदीय अभ्यास (16 वां संस्करण) पी। 86 .

(2) आई. बी. आई. डी. पी. 175 .

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

449

पंडित शर्मा (1) के मामले में अदालत। इसलिए यह आवश्यक है कि

याद रखें कि उस मामले में बहुमत के निर्णय के अनुसार, अनुच्छेद में निहित प्रावधान की स्थिति क्या है। 194 (3) . उस में

केस, अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के संपादक, सर्च लाइट ऑफ

पटना विधान सभा के सचिव ने पटना से विशेषाधिकार समिति के समक्ष कारण दिखाने के लिए कहा था कि अध्यक्ष और विधानसभा के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

एक सदस्य द्वारा विधानसभा में दिए गए भाषण को पूरी तरह से प्रकाशित किया गया था, जिसके कुछ हिस्सों को अध्यक्ष द्वारा हटाने का निर्देश दिया गया था। वह संपादक जिसने अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय का रुख किया। 32 , उन्होंने तर्क दिया कि उक्त नोटिस और समिति द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई, अनुच्छेद के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। 19 (1) (क), और अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण पर भी अतिक्रमण किया। 21. इन दो आधारों पर उनके द्वारा नोटिस की वैधता पर महाभियोग चलाया गया था। इस दावे का सदन ने अनुच्छेद पर भरोसा करके विरोध किया था। 194 (3) . दो सवाल उठे, एक यह था कि क्या सदन द्वारा दावा किया गया विशेषाधिकार प्रासंगिक समय में इंग्लैंड में एक स्थायी प्रिवी लेज था; और दूसरा था, अनुच्छेद 194 (3) के उत्तरार्ध भाग में निहित समर्थक दृष्टिकोण पर अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 21 के प्रभाव का क्या परिणाम था? प्रमुख निर्णय यह था कि विचाराधीन विशेषाधिकार प्रासंगिक समय पर मौजूद था और इसलिए, इसे अनुच्छेद के उत्तरार्द्ध भाग के तहत शामिल माना जाना चाहिए। 194 (3) . यह उस अनुच्छेद को भी मानता था। 19 (1) (क) लागू नहीं हुआ, क्योंकि सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम के तहत, वर्तमान जैसे मामले में जहां अनुच्छेद है। 19 (1) (क) अनुच्छेद के साथ सीधे संघर्ष में था। 194 (3) , बाद के अनुच्छेद में विशेष

प्रावधान पूर्व में निहित सामान्य प्रावधान पर प्रबल होगा; इसने आगे कहा कि हालांकि अनुच्छेद। 21 लागू किया गया था, इसका उल्लंघन नहीं किया गया था।

दूसरी ओर, अल्पसंख्यक दृष्टिकोण यह था कि विशेषाधिकार

प्रश्न में वास्तव में स्थापित नहीं किया गया था, और वैकल्पिक रूप से, यदि यह माना जाता है कि ऐसा विशेषाधिकार स्थापित किया गया था और था, इसलिए, अनुच्छेद के अंतिम भाग के तहत शामिल किया गया है। 194 (3) , इसे अनुच्छेद द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। 19 (1) (क) इस आधार पर कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार सर्वोपरि थे।

महत्व और अनुच्छेद में निहित इस तरह के प्रावधान पर प्रबल होना चाहिए। 194 (3) जो उनके साथ असंगत हो सकता है।

इस स्तर पर, मोटे तौर पर बिंदुओं को इंगित करना उपयोगी होगा।

उस मामले में बहुमत और अल्पमत दोनों निर्णयों द्वारा निर्णय लिया गया। न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता द्वारा यह आग्रह किया गया था कि हालांकि अनुच्छेद।

(1) [1959] सप. 1 एससीआर 806।

[1

965] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

450 194 (3) यदि संविधान के प्रावधानों के अधीन नहीं किया गया था, तो इसका जरूरी अर्थ यह नहीं है कि यह इतना विषय नहीं है, और यह कि अनुच्छेद के कई खंड। 194 इसे विशिष्ट और अलग प्रावधानों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और सभी खंडों को संविधान के प्रावधानों के अधीन लिया जाना चाहिए, जिसमें निश्चित रूप से अनुच्छेद शामिल होगी। 19 (1) (ए)। इस तर्क को बहुमत और दोनों ने खारिज कर दिया था।

अल्पमत के विचार।

उस मामले में अगला तर्क यह था कि अनुच्छेद। 194 (1)

वास्तव में मौलिक अधिकार के संक्षिप्तकरण के रूप में कार्य करता है

अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 (1) (क) जब राज्य विधानमंडलों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद। 194 (3) संदर्भ में, अनुच्छेद के लिए एक अपवाद होने का तात्पर्य नहीं है। 19 (1) (ए)। यह तर्क भी था बहुमत और अल्पसंख्यक दोनों विचारों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। यह बहुमत के निर्णय द्वारा इंगित किया गया था कि अनुच्छेद (1)। 194 नि:संदिग्ध रूप से उक्त खंड विषय का एक ठोस प्रावधान करता है।

संविधान के प्रावधानों के लिए; लेकिन संदर्भ में, वे प्रावधान अनुच्छेद में नहीं ले जा सकते हैं। 19 (1) (क), क्योंकि यह बाद वाला लेख

विधायिका की प्रक्रिया को विनियमित करना अभिप्रेत नहीं है और यह केवल संविधान के ऐसे प्रावधान हैं जो

विधायिका की प्रक्रिया जो पहले भाग में शामिल हैं अनुच्छेद की। 194 (1) .

याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किया गया तीसरा तर्क यह था कि अनुच्छेद। 19

एक दिव्य दिव्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और प्रबल होना चाहिए

अनुच्छेद के प्रावधानों पर। 194 (3) , विशेष रूप से क्योंकि ये बाद वाले

प्रावधान एक अस्थायी चरित्र के थे। यह विवाद था बहुमत के दृष्टिकोण से अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन अल्पसंख्यक द्वारा बरकरार रखा गया

देखें।

चौथा तर्क यह था कि यदि कोई कानून बनाया जाता है

विधायिका अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करती है, यह

अनुच्छेद के अधीन होगा। 13 संविधान और बन जाएगा

यह इस हद तक अमान्य है कि यह निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

भाग III में। इस तर्क को दोनों दलों के बहुमत ने स्वीकार कर लिया। और अल्पमत निर्णय।

इसने विचार करने के लिए एक और बिंदु छोड़ दिया और इसका संदर्भ था

इस न्यायालय के पूर्व निर्णय में की गई टिप्पणियों के लिए

गुणपति केशवरम रेड्डी बनाम। नफीसुल हसन और राज्य

एक रियायत पर और इसलिए, एक कॉन नहीं माना जा सकता है इस न्यायालय के निर्णय को दरकिनार कर दिया। जैसा कि हम वर्तमान में इंगित करेंगे,

(1) ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 636.

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

451

उक्त निर्णय अनुच्छेद की प्रयोज्यता से संबंधित था। 22 (2) अनुच्छेद के उत्तरार्द्ध भाग के अंतर्गत आने वाले मामले के लिए। 194 (3) . हालाँकि, अल्पमत की राय ने उक्त निर्णय को एक सुविचारित निर्णय के रूप में माना जो न्यायालय के लिए बाध्यकारी था।

हमें यह जोड़ना चाहिए कि बहुमत का निर्णय, संदर्भ में, आयोजित किया गया था

उस अनुच्छेद को। 21 आवेदन किया गया, लेकिन गुण-दोष के आधार पर यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसका कथित उल्लंघन साबित नहीं हुआ था। जिस पर

अल्पसंख्यकों का मानना है कि यह विचार करना अनावश्यक था कि क्या अनुच्छेद है। 21 जैसा कि लागू होता है, क्योंकि उक्त दृष्टिकोण भाग III द्वारा गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि मानता है और इसलिए, उनमें से प्रत्येक अनुच्छेद के प्रावधानों को नियंत्रित करेगा। 194 (3) .

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि पंडित शर्मा (1) के मामले में,

भाग III द्वारा गारंटीकृत। केवल दो अनुच्छेदों के उल्लंघन का अनुरोध किया गया था और वे अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 21 थे। कड़ाई से कहें तो इस पर विचार करना अनावश्यक था। बड़ा मुद्दा यह है कि क्या अनुच्छेद का अंतिम भाग है। 194 (3) यह सामान्य रूप से मौलिक अधिकारों के अधीन था, और वास्तव में, बहुमत के दृष्टिकोण पर भी यह नहीं कहा जा सकता था कि उक्त दृष्टिकोण सभी मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को बाहर करता है, स्पष्ट और सरल कारण के लिए कि अनुच्छेद। 21 लागू होने के लिए आयोजित किया गया था और गुण

उसके कथित उल्लंघन के बारे में याचिकाकर्ता के तर्क का

मामले की जांच की गई और खारिज कर दिया गया। इसलिए, हम ऐसा नहीं सोचते हैं

बहुमत के निर्णय को एक निर्धारित के रूप में पढ़ना सही होगा सामान्य प्रस्ताव है कि जब भी के बीच एक संघर्ष है

अनुच्छेद 194 (3) के उत्तरार्द्ध भाग के प्रावधान और कोई भी प्रावधान

भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की दृष्टि, बाद वाला

यह माना जाना चाहिए कि उस अनुच्छेद का निपटारा हो गया है। 19 (1) (क) लागू नहीं होगा, और अनुच्छेद। 21 करेंगे।

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, बहुमत ने निर्णय लिया है

संयोग से गुणपति केशवरम में निर्णय पर टिप्पणी की गई

रेड्डी का मामला (1)। इस तथ्य के अलावा कि कोई नियंत्रण नहीं था

अनुच्छेद की प्रयोज्यता के बारे में पारंगत। 22 इस मामले में, हमें चाहिए

सम्मान के साथ, इंगित करें कि बहुमत द्वारा की गई टिप्पणी

पहले के निर्णय पर निर्णय आंशिक रूप से सटीक नहीं है। उस में

इस मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ का संबंध था अध्यक्ष द्वारा पारित एक आदेश के तहत श्री मिस्त्री की नजरबंदी

विशेषाधिकार हनन के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा

उक्त सभा से। श्री मिस्त्री की नजरबंदी की वैधता थी इस आधार पर चुनौती दी गई कि इसने अनुच्छेद का उल्लंघन किया है। 22 (2) में से

(1) [1959] सप. 1 एससीआर 806।

(2) ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 636.

[1965] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान। इस याचिका के समर्थन में कथित तथ्यों को महान्यायवादी द्वारा सही माना गया था और उन स्वीकृत तथ्यों पर, अदालत ने माना कि श्री मिस्त्री की नजरबंदी स्पष्ट रूप से अमान्य थी। इस निर्णय का उल्लेख करते हुए, बहुमत के फैसले में कहा गया है कि यह "पूरी तरह से वकील की रियायत पर आगे बढ़ा और इसे इस विषय पर एक सुविचारित राय के रूप में नहीं माना जा सकता है।" इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस टिप्पणी का पहला भाग नहीं है सटीक। महान्यायवादी द्वारा रियायत कानून के उस बिंदु पर नहीं दी गई थी जिसका निर्णय न्यायालय ने किया था, बल्कि तथ्य के एक बिंदु पर दी गई थी; और इसलिए, टिप्पणी के इस हिस्से को सख्ती से उचित नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, यह सच है कि श्री मिस्त्री की ओर से उठाए गए विवाद के गुण-दोष के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है और उस हद तक, बहुमत के फैसले में यह कहना स्वीकार्य हो सकता है कि यह अदालत की सुविचारित राय नहीं थी। लेकिन, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, अनुच्छेद की प्रयोज्यता से संबंधित बिंदु से निपटने के लिए बहुमत के निर्णय की शायद ही आवश्यकता थी। 22 (2) , क्योंकि पंडित शर्मा के (1) मामले में न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में वह मुद्दा नहीं उठा। यही कारण है कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुणपति केशवरम मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसले की वैधता या शुद्धता के बारे में बहुमत के फैसले में की गई स्पष्ट टिप्पणियां।

रेड्डी (2) के मामले को विचाराधीन मुद्दे का निर्णय लेने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद।

22 (2) यदि और जब ऐसा करना आवश्यक हो जाता है तो इस न्यायालय को ऐसे मामले पर विचार करना पड़ सकता है।

इससे पहले कि हम पंडित मामले में इस न्यायालय के फैसले से अलग हों

शर्मा (1) के मामले में, एक अन्य बिंदु का उल्लेख करना आवश्यक है। हम पहले ही देख चुके हैं कि बहुमत के निर्णय ने उस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार कर लिया है कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा अपनी शक्तियों को निर्धारित करते हुए कोई कानून पारित किया गया था, तो अनुच्छेद के पहले भाग द्वारा अधिकृत निजी कानून और उन्मुक्ति। 194 (3) , यह अनुच्छेद के अधीन होगा। 13. श्री सीरवई ने इस निष्कर्ष की शुद्धता को चुनौती देने का प्रयास किया है। उनका तर्क है कि अनुच्छेद के पहले भाग द्वारा विधायिकाओं को प्रदत्त शक्ति। 194 (3) यह एक संवैधानिक शक्ति है, और इसलिए, यदि उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई कानून पारित किया जाता है, तो यह अनुच्छेद के दायरे से बाहर होगा। 13 . हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यह सच है कि इस तरह का कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद के पहले भाग द्वारा विधानसभाओं को प्रदान की गई है। 194 (3) ; लेकिन

जब राज्य विधानमंडल इस शक्ति का प्रयोग करने का इरादा रखते हैं, तो वे निस्संदेह इसके तहत कार्य करेंगे।

अनुच्छेद. 246 सूची II की प्रविष्टि 39 के साथ पढ़ें। इस तरह के कानून के अधिनियमन को एक घटक शक्ति के प्रयोग में नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए, इस तरह के कानून को अर्थ के भीतर एक कानून के रूप में माना जाएगा।

(1) (1959] सप. 1 एससीआर 806।

(2) ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 636.

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

453

अनुच्छेद की। 13. यही वह दृष्टिकोण है जिसे पंडित शर्मा (1) के मामले में बहुमत ने व्यक्त किया है, और हम सम्मानपूर्वक उस दृष्टिकोण से सहमत हैं।

श्री सीरवई ने संदर्भ देकर अपने तर्क का समर्थन करने का प्रयास किया

अनंत कृष्ण बनाम में जे. वेंकटरामा अय्यर द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के लिए। मद्रास राज्य (2)। उस मामले में, विद्वान न्यायाधीश ने कहा है कि "[अनुच्छेद। 13] यह केवल संविधान के प्रारंभ से पहले लागू कानूनों और लागू होने वाले कानूनों पर लागू होता है।

राज्यों द्वारा अधिनियमित, अर्थात भविष्य में। भाग 3 के प्रावधानों के विरुद्ध केवल उन दो वर्गों के कानूनों को ही अमान्य घोषित किया गया है। यह स्वयं संविधान पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियमित नहीं करता है कि संविधान के अन्य भाग भाग III के प्रावधानों के विपरीत शून्य होने चाहिए और यह आश्चर्य की बात होगी यदि ऐसा होता है, यह देखते हुए कि वे सभी एक जैविक संपूर्ण के भाग हैं। यह मूल सिद्धांत स्पष्ट रूप से असाधारण है। इस सिद्धांत को लागू किया जा सकता था अगर हमारे सामने यह आग्रह किया गया होता कि अनुच्छेद का पहला या दूसरा भाग। 194 (3) स्वयं अमान्य है क्योंकि यह भाग III में प्रासंगिक प्रावधानों के साथ असंगत है जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। हालाँकि, यह श्री सीतलवाड़ का तर्क नहीं है, न ही पंडित शर्मा (1) के मामले में इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था। तर्क यह था और है कि यदि अनुच्छेद के पहले भाग द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में। 194 (3) एक कानून विधायिका द्वारा बनाया जाता है, यह अनुच्छेद के अर्थ के भीतर एक कानून है। 13 , और यह तर्क

अनुच्छेद के शब्दों पर आगे बढ़ता है। 13 (2) , स्वयं। अनुच्छेद. 13 (2) यह प्रावधान करता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन ले या कम कर दे और इस खंड का उल्लंघन करते हुए बनाया गया कोई भी कानून, उल्लंघन की सीमा तक, शून्य होगा। जिस कानून के साथ हम काम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य संविधान में संशोधन करना नहीं है और जब इसे पारित किया जाता है तो यह संविधान का हिस्सा नहीं होगा; विधानमंडलों द्वारा उन्हें प्रदत्त विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किए गए अन्य कानूनों की तरह, यह कानून भी अनुच्छेद के अर्थ के भीतर कानून होगा। 13 , और इसलिए, यह तर्क देना अनुचित है कि पंडित शर्मा (1) के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि ऐसा कानून मौलिक अधिकारों के अधीन होगा और अनुच्छेद की शरारत के अंतर्गत आएगा। 13 (2) , राशन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए, स्थिति यह है कि पहले से भेजे गए विवाद से निपटने के लिए हमें अनुच्छेद के उत्तरार्ध के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। 194 (3) अनुच्छेद के अधीन नहीं है। 19 (1) (क), लेकिन अनुच्छेद के अधीन है। 21 .

अगला प्रश्न जिस पर हमें विचार करना चाहिए वह है: क्या यह था

द्वैतवाद को कायम रखने के लिए संविधान का इरादा जो

(2) आई. एल. आर. (1952) पागल। 933 , 951 .

(1) [1959] सप. 1 एस. सी. आर. 806

¦ 1

[1965] 1 एस सी आर।

454

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17 वीं, 18 वीं और 19 वीं ए में इंग्लैंड में सार्वजनिक जीवन को बेरहमी से बाधित किया

सदियों से? संविधान-निर्माताओं को कई अन के बारे में पता था

सुखद परिस्थितियाँ जो दोनों के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुईं

न्यायपालिका और संसद के सदन और वे जानते थे कि ये

सार्वजनिक जीवन में गतिरोध पैदा करने की स्थिति इंग्लैंड। जब उन्होंने अनुच्छेद को लागू किया। 194 (3) , क्या यह उनका इरादा था

इस संघर्ष को बड़े पैमाने पर छोड़ने के लिए, या उन्होंने एक बी अपनाया है उस संघर्ष को हल करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की योजना? द.

इस सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से एक हार्मोन पर निर्भर करेगा। संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों का निर्माण

स्वयं।

आइए पहले अनुच्छेद को लें। 226. यह लेख बहुत व्यापक है

संबंध में सभी क्षेत्रों में प्रत्येक उच्च न्यायालय की शक्तियाँ

जिसे वह किसी व्यक्ति या लेखक को जारी करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है

उचित मामलों में किसी भी सरकार सहित, उन मामलों के भीतर

क्षेत्र निर्देश, आदेश या रिट, प्रकृति में रिट सहित

बंदी प्रत्यक्षीकरण, आदेश, निषेध, यथास्थिति, निश्चित रूप से

रारी, या उनमें से कोई भी किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए

इस बात पर जोर देने के लिए कि अनुच्छेद द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा। 226 प्रदान करने में उच्च न्यायालयों की शक्ति बहुत व्यापक है। अनुच्छेद. 12 परिभाषित करता है कि

" राज्य "के रूप में ऐसे राज्य के विधानमंडल को शामिल करते हुए, और इसलिए, प्रथम

दृश्यतः, अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति। 226 (1)

एक उचित मामले में, विधानमंडल के खिलाफ भी प्रयोग किया जा सकता है। ई.

यदि रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया जाता है

बंदी प्रत्यक्षीकरण का, यह सदन के लिए सक्षम नहीं होगा

प्रारंभिक आपत्ति उठाएँ कि उच्च न्यायालय का कोई न्यायशास्त्र नहीं है

आवेदन पर विचार करने के लिए क्योंकि निरोध सदन के आदेश से है। अनुच्छेद. 226 (1) खुद से पढ़ें, ऐसा नहीं लगता है इस तरह की याचिका को उठाने की अनुमति दें।

अनुच्छेद. 32 जो इस न्यायालय की एफ शक्ति से संबंधित है, मामले को और भी उच्च स्तर पर रखता है; के लिए उचित कार्यवाही द्वारा इस न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार

मौलिक अधिकारों को लागू करना ही एक गारंटी है

मौलिक अधिकार, और इसलिए, हमने अनुच्छेद के बारे में क्या कहा है। 226 (1) अनुच्छेद के बारे में अभी भी अधिक सच है। 32 (1) .

जबकि हम मामले के इस पहलू पर विचार कर रहे हैं, यह है

इस बात पर जोर देना प्रासंगिक है कि उच्च न्यायालय और सदन के बीच जो संघर्ष उत्पन्न हुआ है, वह उच्च न्यायालय और सदन के बीच संघर्ष नहीं है, बल्कि सदन और इस देश के नागरिक के बीच है। केशव सिंह कुछ मौलिक अधिकारों का दावा करते हैं जो संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं और वे अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का रुख करना चाहते हैं। 226 इस आधार पर कि उनके मौलिक अधिकारों का अवैध रूप से उल्लंघन किया गया है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने का तात्पर्य रखता है।

226 (1) , विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.):

455

केशव सिंह द्वारा किए गए दावों के गुण-दोष की जांच करने का प्रयास

और एक अंतरिम आदेश जारी करता है। यह अंतरिम आदेश है जिसने नेतृत्व किया है

वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण विवाद तक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि

न्यायाधीशों के उपस्थित होने की आवश्यकता वाला सदन द्वारा पारित प्रस्ताव

उनके आचरण की व्याख्या करने के लिए सदन के बार के समक्ष, कॉन

अधिकारिता उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच एक में विकसित हो गई है

बी.

सदन; लेकिन यह इसलिए है क्योंकि उच्च न्यायालय अपने कार्य के निर्वहन में कर्तव्यों के रूप में इस तरह के न्यायालय ने आरोपों की जांच के लिए हस्तक्षेप किया

एक नागरिक द्वारा बनाया गया है कि न्यायाधीशों को प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया है

अखाड़ा। मूल रूप से और मूल रूप से, विवाद है

उत्तर प्रदेश के एक नागरिक और उत्तर प्रदेश के विधानमंडलों के बीच

लैटिव असेंबली। यही कारण है कि सवाल से निपटने में

एस.

के मामलों से निपटने में सदन की शक्तियों का विस्तार

इसकी चार दीवारों के बाहर की गई अवमानना, अनुच्छेद के प्रावधान।

226 और अनुच्छेद। 32 महत्व लेते हैं। हम पहले ही संकेत कर चुके हैं

यह बताते हुए कि पंडित शर्मा (1) में इस न्यायालय ने उस अनुच्छेद को अभिनिर्धारित किया है। 21 लागू होता है जहां विधायिका द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है

अनुच्छेद का अंतिम भाग। 194 (3) . यदि कोई नागरिक उच्च न्यायालय जाता है

डी.

इस आधार पर कि अनुच्छेद के तहत उसका मौलिक अधिकार। 21 हो चुका है उल्लङ्घन करने पर, उच्च न्यायालय उसकी जाँच करने का हकदार होगा।

दावा, और यह कि स्वयं पर कुछ सीमा लागू होगी

वर्तमान पक्ष में सदन द्वारा दावा की गई शक्तियों की सीमा

आहार।

ई.

दो अन्य लेख हैं जिनका संदर्भ दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद. 208 (1) यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य के विधानमंडल का एक सदन

विनियमन के लिए नियम बना सकते हैं, इसके प्रावधानों के अधीन

संविधान, इसकी प्रक्रिया और इसके व्यवसाय का संचालन। यह

प्रावधान यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि यदि सदन को

इसके द्वारा निर्धारित कोई भी नियम, वे नियम इसके अधीन होंगे -

एफ.

भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार। दूसरे शब्दों में, जहाँ सदन उत्तरार्द्ध के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियम बनाता है

अनुच्छेद का हिस्सा। 194 (3) , उन नियमों को निधि के अधीन होना चाहिए -

नागरिकों के अधिकार।

1

इसी तरह, अनुच्छेद। 212 (1) एक प्रावधान करता है जो प्रासंगिक है। जी यह निर्धारित करता है कि कानून में किसी भी कार्यवाही की वैधता

प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर किसी राज्य की प्रकृति पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद. 212 (2) आश्वासन देते हैं। विधान-मंडल के उन अधिकारियों और सदस्यों को प्रतिरक्षा, जिनके पास किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होने से विधान-मंडल में प्रो सेडर या कार्य संचालन को विनियमित करने या व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान द्वारा या उसके तहत शक्तियां निहित हैं।

उन शक्तियों के उसके द्वारा प्रयोग के संबंध में। अनुच्छेद. 212 (1) .

(1) [1959] सप. 1 एससीआर 806।

L1

ऐसा प्रतीत होता है कि एक नागरिक के लिए उचित न्यायालय में विधायी कक्ष के भीतर किसी भी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाना संभव हो जाता है यदि उसका मामला यह है कि उक्त कार्यवाही केवल प्रक्रिया की अनियमितता से नहीं, बल्कि एक अवैधता से पीड़ित है। यदि विवादित प्रक्रिया अवैध और असंवैधानिक है, तो इसकी अदालत में जांच की जा सकती है, हालांकि इस तरह की जांच निषिद्ध है यदि प्रक्रिया के खिलाफ शिकायत इससे अधिक नहीं है कि प्रक्रिया अनियमित थी। यह फिर से एक और संकेत है जो अनुच्छेद द्वारा सदन को प्रदत्त शक्तियों के दायरे और विस्तार को समझने में कुछ सहायता प्रदान कर सकता है। 194 (3) . यह हमें अनुच्छेद की ओर ले जाता है। 211. इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के आचरण के संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। यह प्रावधान इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के न्यायिक आचरण के संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी चर्चा के खिलाफ एक पूर्ण संवैधानिक निषेध के बराबर है। न्यायाधीशों की ओर से पेश हुए श्री सीतलवाड़ ने अपना तर्क काफी हद तक इस अनुच्छेद के प्रावधानों पर आधारित किया है। उनका तर्क है कि unquali.ed और पूर्ण शर्तें जिनमें संवैधानिक निषेध को अनुच्छेद में जोड़ा गया है। 211 यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में एक न्यायाधीश का आचरण कभी भी अनुच्छेद के उत्तरार्ध भाग द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों या विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए सदन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का विषय नहीं बन सकता है। 194 (3) . यदि कोई न्यायाधीश अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सदन की अवमानना करता है, तो उसके खिलाफ केवल एक ही कदम उठाया जा सकता है जो अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किया गया है। 121. अनुच्छेद. 121 यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, सिवाय इसके कि उसे संबोधित करने के प्रस्ताव पर। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जैसा कि इसके बाद प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 121 और 211 को एक साथ पढ़ने पर, दो बिंदु स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। न्यायाधीश के न्यायिक आचरण पर राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती है। न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित करने के प्रस्ताव पर ही संसद में इस पर चर्चा की जा सकती है। संविधान निर्माताओं ने इस देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को इतना महत्व दिया कि उन्होंने अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए तरीके को छोड़कर, उन्हें किसी भी विवाद से परे रखना आवश्यक समझा। 121. यदि किसी न्यायाधीश का न्यायिक आचरण अनुचित नहीं हो सकता है

सदन में यह अकल्पनीय है कि एक ही आचरण को वैध रूप से सदन विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.) द्वारा कार्रवाई का विषय बनाया जा सकता है।

अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना। 194 (3) . वास्तव में, यह प्रमुख तर्क है जिसका हमारे समक्ष आग्रह किया गया है

श्री सीतलवाड़।

दूसरी ओर, श्री सीरवई ने तर्क दिया है कि इसका प्रभाव

अनुच्छेद में निहित प्रावधान। 211 अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। वह उस अनुच्छेद की ओर इशारा करते हैं। 211 अध्याय III में दिखाई देता है जो राज्य विधानमंडल से संबंधित है और "सामान्य प्रक्रिया" विषय के तहत आता है, और इसलिए, इसका एकमात्र उद्देश्य जिसे पूरा करना है वह है सदन के अंदर की प्रक्रिया का विनियमन।

विधायिका। उन्होंने अनुच्छेद के प्रावधानों पर भी भरोसा किया है। 194 (2) जो किसी सदस्य के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है

विधानमंडल में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के लिए विधानमंडल। दूसरे शब्दों में, यदि विधानमंडल का कोई सदस्य अनुच्छेद द्वारा निर्धारित पूर्ण निषेध का उल्लंघन करता है। 211 , श्री सीरवई कहते हैं कि अदालत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है और यह दर्शाता है कि अनुच्छेद में निहित निषेध का महत्व है। 211 ओवररेटेड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, निर्माण के मामले में, श्री सीरवई सुझाव देते हैं कि अनुच्छेद में निहित निषेध का पालन करने में विफलता। 211 यह किसी भी संवैधानिक परिणाम की ओर नहीं ले जा सकता है, और इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने यू. पी. बनाम राज्य में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है। मनबोधन लाल श्रीवास्तव (1)। उस मामले में, यह न्यायालय अनुच्छेद में निहित प्रावधानों के प्रभाव पर विचार कर रहा था। 320 संविधान से। अनुच्छेद. 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों को निर्धारित करता है

और खंड 3 (ग) द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, जैसा भी मामला हो, से भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत सिविल क्षमता में सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श किया जाएगा, जिसमें ऐसे मामलों से संबंधित स्मारक या याचिकाएं शामिल हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस खंड के प्रावधान अनिवार्य नहीं थे और किसी लोक सेवक को कोई अधिकार प्रदान नहीं करते थे, ताकि परामर्श का अभाव या परामर्श में कोई अनियमित कमी उसे अदालत में कार्रवाई का कारण नहीं बना सके। श्री सीरवई का तर्क है कि अनुच्छेद में उपयोग

किए गए शब्द। 211 इसी तरह से समझा जाना चाहिए और जिस निषेध पर श्री सीतलवाड़ निर्भर हैं, उसे केवल निर्देशिका माना जाना चाहिए और अनिवार्य नहीं।

हम श्री सीरवई के तर्कों से प्रभावित नहीं हैं। तथ्य यह है

उस अनुच्छेद को। 211 "प्रोसीजर जीन रैली" से संबंधित विषय के तहत प्रकट होने का मतलब यह नहीं हो सकता कि इसके द्वारा निर्धारित निषेध अनिवार्य नहीं है। जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, इस निषेध के पूर्ण महत्व को समझने की कोशिश में, हमें अनुच्छेद 211 को पढ़ना चाहिए।

(1) (1958] एस सी आर 533.

[

1965] 1 एस सी आर।

458

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और 121 एक साथ। यह सच है कि अनुच्छेद। 194 (2) शब्दों में किसी सदस्य द्वारा दिए गए भाषण या विधान सभा में उसके द्वारा दिए गए वोट के संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। लेकिन यह प्रावधान स्वयं इस तथ्य को स्पष्ट रूप से सामने लाता है कि संविधान विधायी कक्ष के भीतर बोलने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उत्सुक था, और इसलिए, इसने यह कहकर बोलने और अभिव्यक्ति की इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक विशिष्ट प्रावधान करने की पूर्व सावधानी बरती कि यह भी अनुच्छेद द्वारा निर्धारित संवैधानिक निषेध का उल्लंघन है। 211 किसी भी कार्रवाई को जन्म नहीं देना चाहिए। निस्संदेह, अध्यक्ष किसी सदस्य को अनुच्छेद का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देंगे। 211 ; लेकिन अगर, अनजाने में, या अन्य ज्ञान से, विधायी कक्ष के भीतर एक भाषण दिया जाता है जो अनुच्छेद को दर्शाता है। 211 , संविधान निर्माताओं ने इस तरह के भाषण को किसी भी अदालत में कार्रवाई से संरक्षण दिया है। सदन स्वयं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

यह भी सच है कि अगर कोई सवाल उठता है कि क्या कोई भाषण है

अनुच्छेद का विरोध करता है। 211 या नहीं, यह अध्यक्ष को इस मुद्दे पर अपना निर्णय देना होगा। ऐसे प्रश्न से निपटने में, अध्यक्ष को इस बात पर विचार करना पड़ सकता है कि क्या कोई

सदस्य जो टिप्पणियां करना चाहता है, वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में न्यायाधीश के आचरण के संबंध में हैं, और उस अर्थ में, यह निर्णय अध्यक्ष को करना है। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य अभी भी बना हुआ है कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद द्वारा एक विशिष्ट प्रावधान करना आवश्यक समझा। 194 (2) और यही वह सीमा है जिस पर संविधान ने विधायी कक्ष की चार दीवारों के भीतर बोलने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के अपने उद्देश्य में कदम रखा है।

अनुच्छेद का अंतिम भाग। 194 (3) ऐसा कोई अपवाद नहीं है, और

इसलिए, यह मानना तर्कसंगत होगा कि यह अनुच्छेद का उल्लंघन करते हुए दिया गया भाषण है। 211 अनुच्छेद द्वारा न्यायालय में कार्रवाई से संरक्षित है। 194 (2) , अनुच्छेद के उत्तरार्द्ध भाग के तहत सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों को निर्धारित करने में ऐसा कोई अपवाद या संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। 194 (3) . यदि कोई न्यायाधीश अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई आदेश पारित करता है या ऐसी टिप्पणियां करता है जो सदन की राय में हों।

अवमानना के बराबर है, और सदन उस ओर से न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ता है, सदन की ओर से ऐसी कार्रवाई को अनुच्छेद के उत्तरार्ध भाग द्वारा किए गए किसी विशिष्ट प्रावधान द्वारा संरक्षित या उचित नहीं ठहराया जा सकता है। 194 (3) . हमारी राय में, अनुच्छेद द्वारा किए गए वास्तविक प्रावधान के विपरीत ऐसा कोई प्रावधान करने में चूक। 194 (2) इसका कोई महत्व नहीं है। दूसरे शब्दों में; यह विरोधाभास इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि संविधान निर्माताओं का विचार था कि विधायी विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.) के भीतर बोलने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जितना संभव हो उतना किया जा सकता है।

459

कक्ष, अनुच्छेद में एक प्रावधान करना होगा। 194 (2) ; और यही सब कुछ है। के निर्वहन के संबंध में एक न्यायाधीश का आचरण

सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग में उसके कर्तव्य कार्रवाई का विषय नहीं हो सकते। इसलिए, स्थिति यह है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में एक न्यायाधीश के आचरण पर सदन के अंदर वैध रूप से चर्चा नहीं की जा सकती है, हालांकि यदि ऐसा है, तो कोई उपाय अदालत में नहीं है। लेकिन इस तरह के आचरण को अनुच्छेद के उत्तरार्ध के तहत किसी भी कार्यवाही का विषय नहीं बनाया जा सकता है। 194 (3) . अगर यह वास्तविक स्थिति नहीं

थी, तो अनुच्छेद। 211 यह एक अर्थहीन घोषणा होगी और यह स्पष्ट रूप से संविधान का इरादा नहीं हो सकता था।

फिर, अनुच्छेद के निर्माण के संबंध में। 211 स्वयं, श्री सीरवई

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यू. पी. बनाम राज्य में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने की स्थिति में है। मनबोधन लाल श्रीवास्तव (1)। लेकिन यह ध्यान दिया जाएगा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि प्रावधान अनुच्छेद में निहित है। 320 (3) (ग) अनिवार्य नहीं था, इस न्यायालय ने कुछ अन्य तथ्यों का उल्लेख किया है जो उक्त निर्माण को निर्धारित करते हैं। यहाँ तक कि

इसलिए, इस न्यायालय ने मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम में प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। नोर्मंडिन (2) जिसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा कि "[टी] वह सवाल करता है कि क्या किसी क़ानून में प्रावधान निर्देशिका हैं या अनिवार्य हैं।

वास्तव में इस देश में उत्पन्न हुआ, लेकिन यह कहा गया है कि कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और हर मामले में क़ानून के उद्देश्य को देखा जाना चाहिए। " सवाल यह है कि क्या

कानून अनिवार्य है या निर्देशिका के इरादे पर निर्भर करता है

विधायिका और उस भाषा पर नहीं जिसमें इरादे कपड़े से लिखे गए हैं। विधायिका के अर्थ और इरादे को नियंत्रित करना चाहिए,

और इनका पता लगाया जाना है, न कि केवल वाक्यांश विज्ञान से

प्रावधान, लेकिन इसकी प्रकृति, इसकी रचना और इसके एक या दूसरे तरीके से अर्थ लगाने से होने वाले परिणामों पर भी विचार करके। (3) ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से उस निर्माण को नकारात्मक बना देंगे जिसके लिए श्री सीरवई तर्क देते हैं। इसकी शायद ही आवश्यकता हो।

संविधान के अन्य प्रावधानों को संदर्भित करने के लिए जो हैं

इस देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रवृत्ति। एक निडर और स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व

कहा जा सकता है कि यह संवैधानिक व्यवस्था की बहुत बुनियादी नींव है भारत में संरचना, और इसलिए, यह बेकार होगा, हमें लगता है, विरोध करने के लिए

कि अनुच्छेद द्वारा विहित पूर्ण निषेध। 211 केवल निर्देशिका के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और इसे कम करने की अनुमति दी जानी चाहिए

सदन को कार्रवाई करने की अनुमति देकर अर्थहीन घोषणा

उसके निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में एक न्यायाधीश के खिलाफ

(1) [1958] एस सी आर 533.

(2) एल. आर. [1917] ए. सी. 170.

(3) लोग वी। डी रेना (2 एन. वाई. एस.) (2) 694,166 विविध। (582) क्रॉफर्ड में उद्धृत,

सांविधिक निर्माण पी। 516 .

[1965] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

460

कर्तव्य। इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि श्री सीतलवाड़ सही हैं जब वे तर्क देते हैं कि शक्तियों की सीमा जो भी हो और

अनुच्छेद के उत्तरार्ध भाग द्वारा सदन को प्रदत्त विशेषाधिकार। 194 (3) , अवमानना के लिए एक न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति, जो कथित रूप से उसके द्वारा की गई थी, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उसके कार्य द्वारा उनमें शामिल नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, श्री सीतलवाड़ का मामला यह है कि जहां तक न्यायाधीशों का संबंध है, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुच्छेद 226 और 211 में निहित प्रावधानों के प्रभाव के परिणामस्वरूप, न्यायिक आचरण कभी भी अनुच्छेद के उत्तरार्ध के तहत अवमानना कार्यवाही का विषय नहीं बन सकता है। 194 (3) , भले ही यह माना जाए कि ऐसा आचरण विषय बन सकता है

इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्राप्त शक्तियों और विशेषाधिकारों के तहत अवमानना कार्यवाही का मामला।

दूसरी ओर, श्री सीरवई श्री सीतलवाड़ के तर्क पर विवाद करते हैं।

अनुच्छेदओं के प्रभाव के बारे में। 226 और 211 अनुच्छेद के अंतिम भाग पर। 194 (3) और आगे आग्रह करते हैं कि भले ही श्री सीतलवाड़ उस विवाद के संबंध में सही हों, वे हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा की गई शक्ति और विशेषाधिकार की वैधता पर विवाद करने के हकदार नहीं होंगे-इसलिए, वर्तमान कार्यवाही में सदन द्वारा दावा किया जा सकता है-कि कोई भी अदालत सामान्य या अनकहे वारंट के पीछे नहीं जा सकती है। इन प्रतिद्वंद्वी विवादों की वैधता को निर्धारित करने के लिए, अब बहुत संक्षेप में विचार करना आवश्यक है कि संविधान के संदर्भ में इस विशेष शक्ति और विशेषाधिकार की स्थिति क्या थी। इस प्रश्न से निपटने में, हम व्यापक रूप से उन शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के व्यापक पहलू का भी उल्लेख करेंगे जो इंग्लैंड में संसद के दोनों सदनों में निहित हैं।

शक्तियों, विशेषाधिकारों के प्रश्न पर विचार करते हुए और

हम समझते हैं कि अंग्रेजी संसद की उन्मुक्तियों के कारण, मे के संसदीय अभ्यास में दिए गए प्रासंगिक बयानों पर खुद को आधारित करना काफी सुरक्षित होगा। इस कृति ने इस विषय पर एक क्लासिक का दर्जा ग्रहण कर लिया है और आमतौर पर इसे संसदीय प्रथा की एक आधिकारिक व्याख्या के रूप में माना जाता है; और इसलिए, हम सोचते हैं कि मई के संदर्भ के अलावा इस प्रश्न से निपटने का प्रयास करना व्यर्थ होगा। मई के अनुसार, संसदीय विशेषाधिकार, प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से संसद के उच्च न्यायालय के एक घटक भाग के रूप में और प्रत्येक सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त विशिष्ट अधिकारों का योग है, जिसके बिना वे अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते थे, और जो अन्य निकायों या व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अधिकारों से अधिक है। इस प्रकार, विशेषाधिकार, हालांकि देश के कानून का हिस्सा है, कुछ हद तक सामान्य कानून से एक उदाहरण है। हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेष विशेषाधिकारों को "मौलिक विशेष संदर्भ (गजेंद्रगढ़कर सी. जे.) के योग" के रूप में परिभाषित किया गया है।

क्राउन के विशेषाधिकारों के विरुद्ध सदन और उसके व्यक्तिगत सदस्यों के अधिकार; कानून के सामान्य न्यायालयों का अधिकार और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के विशेष अधिकार। विशेषाधिकार और कार्य के बीच एक अंतर है, हालांकि यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। कुल मिलाकर, हालांकि, प्रत्येक सदन के कुछ मौलिक अधिकारों के लिए "विशेषाधिकार" शब्द को आरक्षित रखना अधिक सुविधाजनक है, जिन्हें आम तौर पर इसके संवैधानिक कार्यों के प्रयोग के लिए आवश्यक

माना जाता है। विशेषाधिकार का विशिष्ट चिह्न इसका सहायक चरित्र है। संसद के विशेषाधिकार वे अधिकार हैं जो "अपनी शक्तियों के उचित निष्पादन के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं"। वे अलग-अलग सदस्यों द्वारा आनंदित होते हैं, क्योंकि सदन अपने सदस्यों की सेवाओं के निर्बाध उपयोग के बिना अपने कार्यों का पालन नहीं कर सकता है; और प्रत्येक सदन द्वारा अपने सदस्यों की सुरक्षा और अपने अधिकार और गरिमा के समर्थन के लिए (1)।

मई इंगित करता है कि एक मामले को छोड़कर, जीवित व्यक्ति

हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के अपमान आवश्यकता के उसी आधार पर न्यायोचित हैं जो स्व-शासित उपनिवेशों और कुछ ब्रिटिश उपनिवेशों की विधान सभाओं को उनके विधायी प्राधिकरण की कानूनी घटना के रूप में सामान्य कानून के तहत प्राप्त विशेषाधिकार हैं। यह अपवाद अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। कीले बनाम में प्रिवी काउंसिल के निर्णय के बाद से। कार्सन (3) यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह शक्ति हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में निहित है, न कि विधायी निकाय के रूप में।

कार्य करता है, लेकिन संसद के उच्च न्यायालय के वंशज के रूप में और लेक्स एट कॉन्सूटचूडो पार्लियामेंट (1) के आधार पर। ऐतिहासिक रूप से

मूल रूप से कमजोर निकाय के रूप में, कॉमन्स में एक उग्र और अधिक था

अपने विशेषाधिकारों के दावे के लिए लंबे समय तक संघर्ष, नहीं केवल क्राउन और अदालतों के खिलाफ, लेकिन लॉर्ड्स के खिलाफ भी। इस प्रकार विशेषाधिकार की अवधारणा जो विशेष प्रो में उत्पन्न हुई

राजा के खिलाफ आग्रह को कॉमन्स द्वारा प्रथागत अधिकारों के रूप में दावा किया जाने लगा, और इनमें से कुछ दावों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त "प्रिवी" में कठोर होने का दावा करने के लिए बार-बार किए गए प्रयासों के दौरान किया गया। पैर "।

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भयंकर संघर्ष के संबंध में

एक उग्रवादी तरीके से अपने विशेषाधिकारों का दावा करते हुए, मई ने महत्वपूर्ण बना दिया है

टिप्पणी करें कि विशेषाधिकार के ये दावे देर से स्थापित किए गए थे

पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में और सत्रहवीं में राजा के खिलाफ हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा उपयोग किया गया था और-मनमाने ढंग से

-अठारहवीं शताब्दी में लोगों के खिलाफ। तब तक नहीं उन्नीसवीं शताब्दी संतुलन तक पहुँच गई थी और प्री की सीमाएँ थीं

संसद, क्राउन और द्वारा निर्धारित और स्वीकार किया गया अपराध अदालतें)। इस प्रकार दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं -

(2) 4 मूर पी. सी. 63.

(1) मे 'ज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस पीपी। 42-43 .

(3) मे 'ज़ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, पी। 44 .

विशेषाधिकारों के एक सामान्य निकाय का प्रशासन। प्रत्येक सदन, संसद के एक घटक भाग के रूप में, दूसरे के अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करता था। हालाँकि, वे प्रत्येक के लिए विशिष्ट किसी अलग अधिकार से नहीं, बल्कि केवल संसद के कानून और रीति-रिवाजों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। सामान्य तौर पर, सभी विशेषाधिकार जो उचित रूप से तथाकथित हैं, दोनों सदनों के लिए समान रूप से संबंधित हैं। उन्हें प्रत्येक सदन द्वारा घोषित और स्पष्ट किया जाता है; और विशेषाधिकार के उल्लंघनों पर प्रत्येक द्वारा निर्णय लिया जाता है और निंदा की जाती है; लेकिन अनिवार्य रूप से, यह अभी भी संसद का कानून है जो इस प्रकार प्रशासित होता है। यह महत्वपूर्ण है कि

यद्यपि कोई भी सदन संसद के कानून की व्याख्या कर सकता है और अपने विशेषाधिकारों को सही साबित कर सकता है, लेकिन इस बात पर सहमति है कि कोई नया विशेषाधिकार नहीं बनाया जा सकता है। यह स्थिति 1704 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित ऐतिहासिक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप उभरी। इस प्रस्ताव में घोषणा की गई कि "संसद के किसी भी सदन के पास, किसी भी वोट या घोषणा द्वारा, अपने लिए नए विशेषाधिकार बनाने की शक्ति नहीं है, जो संसद के ज्ञात कानूनों और रीति-रिवाजों द्वारा आवश्यक नहीं हैं।" इस प्रस्ताव को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कॉमन्स को सूचित किया गया था और उनके द्वारा सहमति दी गई थी (1)। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अपने प्रस्तावों द्वारा, हाउस ऑफ कॉमन्स अपने विशेषाधिकारों और शक्तियों की सूची में नहीं जोड़ सकता है।

इस स्तर पर व्यापक रूप से मुख्य का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

विशेषाधिकार जिनका दावा हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किया जाता है। बोलने की स्वतंत्रता प्रत्येक स्वतंत्र परिषद या विधायिका के लिए आवश्यक विशेषाधिकार है, और दोनों सदन इसे एक बुनियादी विशेषाधिकार के रूप में दावा करते हैं। यह विशेषाधिकार 1541 से संसद के प्रारंभ में राजा को कॉमन्स की याचिका में स्थापित अभ्यास द्वारा शामिल किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि इस विशेषाधिकार की बार-बार मान्यता के बावजूद, क्राउन और कॉमन्स हमेशा इसकी सीमाओं पर सहमत नहीं थे। 1688 की क्रांति के बाद इस विशेषाधिकार को अंतिम वैधानिक मान्यता मिली। अधिकार विधेयक के 9वें अनुच्छेद द्वारा, यह घोषित किया गया था कि "संसद में बोलने की स्वतंत्रता, और बहस या कार्यवाही पर संसद के बाहर किसी भी अदालत या स्थान पर महाभियोग नहीं चलाया जाना चाहिए या सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए" (*)।

अन्य विशेषाधिकारों में अजनबियों को बाहर करने का अधिकार शामिल है,

वाद-विवाद और कार्यवाहियों के प्रकाशन को नियंत्रित करने का अधिकार, संसद में कार्यवाहियों के अनन्य संज्ञान का अधिकार, सदन की अपनी कार्यवाहियों की वैधता का एकमात्र न्यायाधीश होने का अधिकार और संसद में उनके आचरण के लिए अपने स्वयं के सदस्यों को दंडित करने का अधिकार (3)।

इन विशेषाधिकारों के अलावा, संसद के दोनों सदन थे -

गिरफ्तारी या छेड़छाड़ से मुक्ति का विशेषाधिकार रखने वाला,

(2) आइबीआइडी।, पी। 52 .

(1) मे 'ज़ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, पी। 47 .

(3) आइबीआइडी।, पीपी। 52-53 .

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

463

और आरोपित होने से, जिसका कॉमन्स द्वारा दावा किया गया था

पर्चे के आधार पर। हालाँकि यह विशेषाधिकार दिया गया था

प्रारंभिक तिथि में शाही और वैधानिक मान्यता, विडंबना यह है कि विशेषाधिकार का प्रवर्तन लॉर्ड्स और किंग पर निर्भर था, जो हमेशा कॉमन्स की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं थे। इस संबंध में, मई थोर्प के मामले को संदर्भित करता है जो था

हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष और 1452 में जेल में डाल दिया गया था, राजकोष की अदालत से निष्पादन के तहत, के मुकदमे में

ड्यूक ऑफ यॉर्क। यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के प्रभुत्व और हाउस ऑफ कॉमन्स की कमजोरी का एक स्पष्ट प्रमाण है जो अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों का दावा करने के लिए संघर्ष कर रहा था कि जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कॉमन्स के आवेदन के जवाब में निर्णय दिया कि थोर्प को जेल में रहना चाहिए, तो कॉमन्स ने इस निर्णय को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया कि वे तुरंत दूसरे अध्यक्ष (1) के चुनाव के लिए आगे बढ़ गए।

मई इंगित करता है कि कुछ विशेषाधिकार समय के साथ होते हैं,

बंद कर दिया गया। उनमें से मुक्त गुंबद का उल्लेख किया जा सकता है। इसी तरह, संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम, 1770 द्वारा गिरफ्तारी से स्वतंत्रता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा प्रभावित हुई थी। जूरी सेवा (2) से छूट के विशेषाधिकार के संबंध में कुछ हद तक समान स्थिति उत्पन्न होती है। वास्तव में शुरुआती दिनों में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकारों की सूची एक लंबी और दुर्जेय सूची थी और इससे पता चलता है कि कैसे हाउस ऑफ कॉमन्स अपने और अपने सदस्यों के लिए सभी प्रकार के विशेषाधिकारों का दावा करने के लिए इच्छुक था। हालाँकि, समय के साथ, इनमें से कई विशेषाधिकारों का उपयोग बंद हो गया और उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, कुछ को कानून द्वारा नियंत्रित किया गया था, जबकि प्रमुख विशेषाधिकार जिन्हें सदन के कुशल कार्य के लिए आवश्यक विशेषाधिकारों के रूप में उचित रूप से वर्णित किया जा सकता है, अभी भी लागू हैं।

आम तौर पर इन विशेषाधिकारों की प्रकृति पर विचार करते हुए, और

विशेष रूप से अवमानना के लिए दंडित करने के लिए सदन द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकार की प्रकृति, विशेषाधिकारों के इस सिद्धांत की ऐतिहासिक उत्पत्ति को याद रखना आवश्यक है। इस संबंध में, मे ने इस बात पर जोर दिया है कि आधुनिक संसद की उत्पत्ति इसके न्यायिक कार्यों में शामिल है। मे कहते हैं कि हाल के शोध की प्रमुख पंक्तियों में से एक ने संसद की उत्पत्ति में न्यायिक तत्वों के महत्व को प्रकट किया है। मैटलैंड ने 1305 की संसद सूची की शुरुआत में इस तथ्य के महत्व पर सबसे पहले जोर दिया कि उस समय संसद राजा का "महान दरबार" था और इस प्रकार (अन्य बातों के अलावा) शाही न्याय का सर्वोच्च न्यायालय था। सबसे पहले के चरित्र में मजबूत न्यायिक लकीर को खत्म करने के लिए अब सामान्य सहमति है।

(1) मे 'ज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, पी। 70 .

(2) आइबीआइडी। पीपी।, 75-77 .

[1965] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

464 संसदों और यह तथ्य कि एडवर्ड तृतीय के शासनकाल में भी, यद्यपि संसदों ने अपना काफी समय राजनीतिक और आर्थिक व्यवसाय के लिए समर्पित किया था, राजा की प्रजा की नजर में न्याय का वितरण उनके मुख्य कार्यों में से एक बना रहा। जैसा कि सर्वविदित है, यूनाइटेड किंगडन की संसद बनी है।

संप्रभु, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमिनन्स। ये कई शक्तियाँ सामूहिक रूप से विधानमंडल का निर्माण करती हैं और संविधान के विशिष्ट सदस्यों के रूप में, वे कार्यों का प्रयोग करती हैं और प्रत्येक के लिए विशिष्ट विशेषाधिकारों का आनंद लेती हैं।

हाउस ऑफ लॉर्ड्स, आध्यात्मिक और अस्थायी, एक साथ बैठते हैं, और

संयुक्त रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स () का गठन करता है। विधायिका में एक अलग स्थान पर कॉमन्स के प्रवेश की सटीक तारीख हमेशा विवाद का विषय रही है; लेकिन जैसा कि यह स्वीकार किया जाता है कि वे अक्सर विचार-विमर्श के लिए अलग-अलग बैठते थे, विशेष उदाहरण जिनमें वे अलग-अलग स्थानों पर मिलते थे, यह निर्धारित नहीं करेंगे कि उनका सेपा राशन, उस समय, अस्थायी था या स्थायी। जब

कॉमन्स ने अलग से विचार-विमर्श किया, वे वेस्टमिंस्टर के मठाधीश के चैप्टर हाउस या रेफ़ेक्टरी में बैठे; और उन्होंने अपना काम जारी रखा।

उनके अंतिम अलगाव () के बाद उस स्थान पर बैठकें। द हाउस ऑफ

लॉर्ड्स हमेशा से न्यायिक न्यायालय थे और आज भी हैं।

मई के अनुसार, सबसे विशिष्ट। प्रभुओं की विशेषता उनकी न्यायपालिका है, जिसका वे कई प्रकार से प्रयोग करते हैं।

उनके पास सत्रावसान के दौरान अदालत के रूप में बैठने की शक्ति है।

समाधान; एक अपील न्यायालय का गठन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा किया जाता है।

और अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार उनमें निहित है। मई ने भी अधिनियमों के संबंध में संसद द्वारा दावा की गई शक्ति को संदर्भित किया गया

इंदर और महाभियोग। और उन्होंने वर्णन किया है कि यह कैसे

विशेषाधिकार का प्रयोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा किया गया था कॉमन्स (3)। “ महाभियोग में ", मे कहते हैं", कॉमन्स हैं

कॉमन्स बिना किसी आरोप के खुद को प्रतिबद्ध करते हैं, और न ही उनके अपराधी के खिलाफ निर्देशित शक्तियाँ: लेकिन वे बराबर के न्यायाधीश हैं

अधिकारिता, और प्रभुओं के समान जिम्मेदारी के साथ; और

अभियुक्त की निंदा केवल संयुक्त निर्णय द्वारा की जा सकती है

क्राउन, लॉर्ड्स और कॉमन्स () "। प्राइ का यह पहलू

विलेज ऐतिहासिक विकास की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है।

इंग्लैंड में संवैधानिक कानून। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि

हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा दावा की गई अधिकारिता का एक हिस्सा और साथ ही हाउस ऑफ कॉमन्स का ऐतिहासिक रूप से पता लगाया जा सकता है

आधुनिक संसद की उत्पत्ति, जैसा कि हमने अभी संकेत दिया है, संसद के न्यायिक कार्यों में शामिल थे।

(2) आइबीआइडी।, पीपी। 8-9 .

(1) मे 'ज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, पीपी। 3-4 .

(4) आइबीआइडी।, पीपी। 38-39 .

(3) आइबीआइडी।, पी। 12 .

(6) आइबीआइडी।, पी। 41 .

(5) आइबीआइडी।, पी 40।

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

465

लॉर्ड्स और कॉमन्स द्वारा दिए गए दंडों में अंतर

इस संदर्भ में भी इसका कुछ महत्व है। जबकि दोनों सदन विशेषाधिकार हनन के समान अपराधों के संबंध में सहमत हों ",

मे कहते हैं, "कई महत्वपूर्ण विवरणों में अंतर है।

उनके सजा के तरीकों में। लॉर्ड्स ने दावा किया है कि एक

अभिलेख न्यायालय और, इस प्रकार, न केवल कैद करने के लिए, बल्कि लागू करने के लिए

जुर्माना लगाया। वे एक निश्चित समय के लिए कैद भी करते हैं, और सुरक्षा का आदेश देते हैं अच्छे आचरण के लिए दिया जाएगा; और प्रतिबद्धता का उनका प्रथागत रूप

मन लगाव द्वारा होता है। दूसरी ओर, कॉमन्स

कोई निर्दिष्ट अवधि के लिए नहीं, और पिछली दो शताब्दियों के दौरान जुर्माना नहीं लगाया। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि सदन

लॉर्ड्स, अपनी न्यायिक क्षमता में, रिकॉर्ड का एक न्यायालय है; लेकिन, के अनुसार

लॉर्ड केन्यन के लिए, 'जब एक विधायी क्षमता का प्रयोग किया जाता है, तो यह एक नहीं है रिकॉर्ड की अदालत '। क्या हाउस ऑफ कॉमन्स, कानून में,

अभिलेख न्यायालय, यह निर्धारित करना कठिन होगा; इस दावे के लिए,

एक बार दृढ़ता से बनाए रखने के बाद, बाद में लगभग छोड़ दिया गया है,

हालाँकि कभी स्पष्ट रूप से त्याग नहीं किया गया "(1)। यह अंतिम टिप्पणी की गई

इस सवाल से निपटने के लिए कि क्या विशेषाधिकार का दावा किया गया है श्री सीरवई द्वारा कि एक सामान्य वारंट की जांच नहीं की जा सकती है

अदालतें स्वयं विशेषाधिकार का एक हिस्सा हैं, या परंपरा का परिणाम हैं।

न्यायालयों और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच स्थापित।

आइए हम मई के शब्दों में संक्षेप में इंगित करें कि

हाउस ऑफ कॉमन्स के पास प्रतिबद्धता की शक्ति की विशेषताएं। मे कहते हैं, "प्रतिबद्धता की शक्ति वास्तव में है।"

संसदीय विशेषाधिकार की आधारशिला के रूप में वर्णित "। जैसा कि 1593 में कॉमन्स में कहा गया था, "इस अदालत को अपनी गरिमा और महामहिम के लिए विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसा कि अन्य सभी अदालतों को है। और, जैसा कि यह अन्य सभी न्यायालयों से ऊपर है, वैसे ही इसे अन्य सभी न्यायालयों से ऊपर विशेषाधिकार प्राप्त है और जैसा कि इसके पास विशेषाधिकार और अधिकार क्षेत्र भी है, वैसे ही इसे भी है।

जबरदस्ती और दबाव; अन्यथा न्यायालय में अधिकार क्षेत्र कुछ भी नहीं है, यदि इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। प्रतिबद्धता की इस शक्ति पर मे द्वारा की गई टिप्पणी बहुत ही शिक्षाप्रद है। इस शक्ति की उत्पत्ति जो अपनी प्रकृति में न्यायिक है, संसद की मध्ययुगीन अवधारणा में मुख्य रूप से न्याय की अदालत-"संसद का उच्च न्यायालय" के रूप में पाई जाती है। न्यायिक रूप से कार्य करने वाले न्यायालय के रूप में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास निस्संदेह कम से कम वेस्टमिंस्टर हॉल के किसी भी न्यायालय के रूप में प्रतिबद्धता की शक्ति थी।

लेकिन कॉमन्स, "संसद में नए-आने वाले" के भीतर

न्यायिक स्मृति का समय, आधार पर शक्ति का दावा नहीं कर सका

(2)

आइबीआइडी।, पी। 90 .

(1) मे 'ज़ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, पी। 90 .

[1

965] 1 एस सी आर।

466

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्राचीन काल से। 1399 तक उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया था कि वे पार लाइमेंट के फैसलों में भागीदार नहीं थे, बल्कि केवल याचिकाकर्ता थे। कॉमन्स द्वारा अधिकार के अधिकार को इस आधार पर चुनौती दी गई थी, और उन तर्कों द्वारा बचाव किया गया था जो न्यायिक न्यायशास्त्र के साथ विधायी को भ्रमित करते थे। यह संभवतः मध्ययुगीन अक्षमता के कारण था

कुछ अर्थों में न्याय की अदालत के रूप में अन्यथा एक संवैधानिक प्राधिकरण की कल्पना करें कि कॉमन्स उसी शर्तों पर अपराधियों को करने के अपने अधिकार पर जोर देने में सफल रहे

लॉर्ड्स (1)। यह प्रतिबद्धता के मामले में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकार की उत्पत्ति है।

जैसा कि इंग्लैंड के इतिहास से पता चलता है, हाउस ऑफ कॉमन्स

मान्यता को गिरफ्तार करने के लिए एक भयंकर संघर्ष में संलग्न होना पड़ा राजा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस अधिकार के लिए, और कई में

स्वयं लोगों पर मुकदमा चलाएँ। इस शक्ति को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था

दोनों सदनों के बीच सम्मेलन में प्रभुओं द्वारा,

एशबी बनाम का मामला। सफेद (2), 1704 में और यह बार-बार किया गया है

न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त। वास्तव में यह शक्ति भी वस्तुतः है

कानून द्वारा स्वीकार किया गया, I जेम्स I, c। 13 , एस. 3 , जो प्रदान करता है

कि उसमें कुछ भी किसी के घटते जाने तक नहीं फैलेगा।

इसके बाद संसद में निंदा द्वारा दंड दिया जाएगा

किसी भी व्यक्ति पर (*) "।

अब हम मई की पुस्तक में कानून के कथन का उल्लेख करेंगे।

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बारे में परेशान करने वाले प्रश्न पर

विशेषाधिकार संबंधी मामले। मई का कहना है, इसके लिए एक अलग की आवश्यकता होगी

संयोग से उठाए जाने वाले विषय के साथ पर्याप्त रूप से निपटने के लिए संधि

संवैधानिक कानून के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न। के अनुसार

न्यायालयों की क्षमता और अपवाद के बीच की सीमा किसी भी सदन का अधिकार क्षेत्र एक कठिन प्रश्न है।

न्यायिक कानून जिसने कई उलझन भरे मामले प्रदान किए हैं, विशेष रूप से

सत्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक। यह हो चुका है

सदनों और न्यायालयों के बीच सामान्य आधार जो निजी हैं

कानून "संसद के ज्ञात कानूनों और रीति-रिवाजों" पर निर्भर करता है। और न कि किसी भी सदन के इप्स डिक्सिट पर। सवाल यह है कि

पुटे यह था कि क्या संसद का कानून एक "विशेष" कानून था।

पूर्व मामले में क्या यह एक उच्चतर कानून था जो ओवरराइड करता था सामान्य कानून। इस सवाल से एक और बात निकलती है

न्यायालयों और संसद के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और

कि क्या विशेषाधिकार के मामले को केवल न्याय किया जाना चाहिए

(2) एल. जे. (1701-05), 714।

(1) मे 'ज़ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, पी। 91 .

(3) मे 'ज़ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, पी। 92 .

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

467

उस सदन द्वारा जिसका वह संबंध रखता है, तब भी जब तीसरे पक्ष के अधिकार शामिल थे, या क्या इसका निर्णय कुछ मामलों में अदालतों में किया जा सकता है, और यदि हां, तो किस प्रकार के मामलों में (1)। संसद और अदालतों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण अपरिवर्तनीय प्रतीत होते हैं। अदालतों ने अपने लिए निर्णय लेने के अधिकार का दावा किया जब उनके सामने लाई गई कार्यवाही में ऐसा करना आवश्यक हो गया, इन विशेषाधिकारों के अस्तित्व या पूर्व तम्बू के संबंध में सवाल, जबकि दोनों सदनों ने अपने स्वयं के विशेषाधिकारों के पूर्व न्यायाधीश होने का दावा

किया। अंततः, दोनों दृष्टिकोण व्यवहार में सुलझा लिए गए और धीरे-धीरे दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान विकसित किया गया। यह समाधान जो अदालतों द्वारा चिह्नित किया गया है, वह संसदीय क्षेत्राधिकार के पक्ष में कुछ बड़े अपवादों के साथ, उनके समक्ष मुकदमेबाजी में उत्पन्न होने वाले विशेषाधिकार के सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने के सिद्धांत रूप में उनके अधिकार पर जोर देना है। इनमें से दो अपनी आंतरिक कार्यवाही पर प्रत्येक सदन की अनन्य अधिकारिता हैं, और किसी भी सदन का अवमानना करने और दंडित करने का अधिकार है। मई जोड़ती है कि जबकि यह कर सकते हैं

यह दावा नहीं किया जाता है कि किसी भी सदन ने औपचारिक रूप से इस पर सहमति व्यक्त की है

न्यायालयों द्वारा अधिकारिता की धारणा, किसी की अनुपस्थिति

एक शताब्दी से अधिक समय से चल रहा संघर्ष एक निश्चित पैमाने पर मौनता का संकेत दे सकता है।

स्वीकृति (2)। दूसरे शब्दों में, अस्तित्व के बारे में सवाल और विशेषाधिकार की सीमा को आम तौर पर न्यायसंगत माना जाता है

न्यायालय जहाँ यह किसी भी विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक हो जाता है

अदालतों के सामने लाया गया।

अवमानना के लिए सजा के संबंध में, एक समान प्रक्रिया

परंपरा के अनुसार देना और लेना चलन में है और धीरे-धीरे

व्यवहार में समझौते का एक बड़ा क्षेत्र विकसित किया गया है। थियो

वस्तुतः, हाउस ऑफ कॉमन्स का दावा है कि यह स्वीकृत अधिकार है

विशेषाधिकार के उल्लंघन पर निर्णय का तात्पर्य सिद्धांत रूप में अधिकार से है।

विशेषाधिकारों के अस्तित्व और विस्तार को स्वयं निर्धारित करना।

इसने कभी भी इस दावे को स्पष्ट रूप से नहीं छोड़ा है। दूसरी ओर,

अदालतें संसद के विशेषाधिकारों को कानून का हिस्सा मानती हैं।

उस भूमि का, जिसका वे न्यायिक नोटिस लेने के लिए बाध्य हैं।

वे विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेना अपना कर्तव्य मानते हैं।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक मामले में उत्पन्न होता है जो उनके दायरे में आता है

अधिकारिता, और इसे अपनी व्याख्या के अनुसार तय करना

कानून (3)। स्वाभाविक रूप से, इस द्वैतवाद के परिणामस्वरूप

अदालतों के निर्णयों को सदन द्वारा बाध्यकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है विशेषाधिकार के मामलों में, और न ही सदन के निर्णयों में

अदालतें; और जैसा कि मई बताते हैं, सैद्धांतिक स्तर पर, पुराना द्वैतवाद अभी भी अनसुलझा है। व्यवहार में, हालांकि, "वहाँ है

(2) आइबीआइडी।, पी। 152 .

(1) मे 'ज़ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, पी। 150 .

(3) आइबीआइडी।, पी। 172 .

[1965] आई एस. सी. आर.

468

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिकार क्षेत्र के सवाल पर गतिरोध की तुलना में विशेषाधिकार की प्रकृति और सिद्धांतों पर बहुत अधिक सहमति किसी को उम्मीद करने के लिए प्रेरित करेगी और मई इन सामान्य निष्कर्षों को निम्नलिखित शब्दों में वर्णित करती है:

(1) यह माना जाता है कि, पुर के लिए

विशेषाधिकार के प्रश्नों पर निर्णय लेने की मुद्रा, न ही

सदन अपने आप में सर्वोच्चता का दावा करने का हकदार है।

न्याय की साधारण अदालतें जिनका आनंद लिया जाता था

संसद का अविभाजित उच्च न्यायालय। सर्वोच्चता

संसद, जिसमें राजा और दोनों शामिल हैं

सदन, एक विधायी सर्वोच्चता है जिसके पास कुछ भी नहीं है

सिथर हाउस के विशेषाधिकार क्षेत्राधिकार के साथ कार्य करना

अकेले।

(2) यह दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया जाता है कि, चूंकि

न तो सदन स्वयं कानून में जोड़ सकता है, न ही सदन

अपनी घोषणा से एक नया विशेषाधिकार बना सकते हैं। यह

सक्षम, और इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि यह ज्ञात है अदालतों द्वारा।

दूसरी ओर, अदालतें स्वीकार करती हैं:

(3) कि प्रत्येक सदन का अपने अंतर पर नियंत्रण

एन. ए. एल. कार्यवाही पूर्ण है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

अदालतों के साथ।

(4) कि दोनों में से किसी के द्वारा अवमानना के लिए एक प्रतिबद्ध

सदन अपने अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यवहार में है,

चूंकि कथित अवमानना की आवश्यकता वाले तथ्य समर्पण के वारंट (1) पर नहीं कहा जाएगा।

यह खोज के लिए उल्लेखनीय अंग्रेजी प्रतिभा को एक श्रद्धांजलि है।

समस्याओं के व्यावहारिक तदर्थ समाधान जो प्रतीत होते हैं

देने और लेने की पारंपरिक विधि को अपनाकर अपरिवर्तनीय। इस प्रक्रिया का परिणाम मई के शब्दों में हुआ है, कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने सौ वर्षों से अदालतों के निर्णय के लिए अपने विशेषाधिकारों को प्रस्तुत करने से इनकार नहीं किया है, और इसलिए, यह

कहा जा सकता है कि न्यायशास्त्र को व्यावहारिक मान्यता दी गई है

अपने विशेषाधिकारों के अस्तित्व और विस्तार पर न्यायालयों का गठन।

दूसरी ओर, अदालतों ने हमेशा, किसी भी तरह से

अंतिम उपाय, सदन द्वारा आवेदन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया

इसके किसी भी मान्यता प्राप्त विशेषाधिकार () से। यह व्यापक रूप से कहा गया है,

सदन द्वारा दावा की गई शक्तियों और विशेषाधिकारों की स्थिति

कॉमन्स।

(2)

आइबीआइडी।, पीपी। 173-74 .

(1) मे 'ज़ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, पी। 173 .

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

469

अब जिस पर विचार करना बाकी है, वह इस संबंध में स्थिति है कि

विशेष विशेषाधिकार जिसके बारे में हम चिंतित हैं।, यह निर्धारित करने का विशेषाधिकार कि क्या इसकी अवमानना की गई है और ऐसी अवमानना के लिए दंडित करने का विशेषाधिकार है, और यह दावा करने का विशेषाधिकार है कि किसी व्यक्ति को उसकी अवमानना के लिए सजा देने वाला सामान्य आदेश या वारंट कानून के न्यायालय में जांच योग्य नहीं है। क्या श्री सीरवई द्वारा सदन की ओर से दावा किया गया यह अंतिम अधिकार हाउस ऑफ कॉमन्स में निहित विशेषाधिकार का एक हिस्सा है, या यह अदालतों और सदन के बीच परंपरा द्वारा, या सामूहिकता के सिद्धांत द्वारा, या कानूनी अनुमान के रूप में विकसित समझौते का परिणाम है? इस सवाल की ओर हमें अब मुड़ना होगा।

इस संकीर्ण प्रश्न से निपटने के दौरान भी, यह आवश्यक है,

हम सोचते हैं कि मोटे तौर पर कुछ कठिन मार्ग का उल्लेख करने के लिए जिसके माध्यम से इस प्रश्न पर कानून धीरे-धीरे इंग्लैंड में न्यायिक निर्णयों द्वारा विकसित किया गया है। जिस तरह से व्यवहार में

विशेषाधिकारों का सवाल, सिद्धांत रूप में हमने मुख्य रूप से अपने

स्वयं मई के बयानों पर, इसलिए विकास से निपटने में

इस प्रश्न पर कानून के अनुसार, हम मुख्य रूप से निर्णयों पर भरोसा करेंगे

स्वयं। श्री सीरवई और श्री सीतलवाड़ दोनों ने इसका उल्लेख किया है।

हम बड़ी संख्या में अंग्रेजी निर्णयों के लिए उनका आग्रह करते हुए

हमारे सामने और निष्पक्षता में संबंधित विवाद, हम सोचते हैं कि हम

कुछ महत्वपूर्ण प्रतिनिधि निर्णयों का उल्लेख करना चाहिए।

यह दर्शाने के लिए कि यह सिद्धांत कैसे है। विशेषाधिकार और इसकी संगतियाँ इसे धीरे-धीरे इंग्लैंड में विकसित किया गया है।

हमारे उद्देश्य के लिए, कहानी वर्ष में शुरू होने के लिए कहा जा सकता है

द अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी के मामले में इस समस्या का एक हिस्सा (1) समय-समय पर विकसित होता है जब कुछ पहलू या अन्य

संसदीय विशेषाधिकारों की यह समस्या अदालतों के सामने आई

वेस्टमिंस्टर में जब तक हम 1884 तक नहीं पहुँचे जब ब्रैडलॉफ का मामला आया

वी. गोसेट (2) तय किया गया था।

आइए हम शाफ्ट्सबरी के मामले से शुरू करते हैं। उस मामले में,

शाफ्ट्सबरी के अर्ल लंदन के टावर के लिए प्रतिबद्ध थे।

हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक आदेश के तहत जिसने विपक्ष को निर्देशित किया

उन्हें लेने और रखने के लिए टॉवर ऑफ लंदन की मेज

सदन की खुशी के दौरान सुरक्षित अभिरक्षा "उच्च अधिकार के लिए"

इस सदन के खिलाफ किए गए प्रलोभन; और यह पर्याप्त होगा उस ओर से आदेश "। शाफ्ट्सबरी के अर्ल ने लिया

बंदी प्रत्यक्षीकरण पर राजाओं के न्यायालय की पीठ के समक्ष मामला

कोष और आग्रह किया कि अर्ल का समर्पण अनुचित था

कानून में, क्योंकि "उच्च अवमानना" का सामान्य आरोप था

(1) 86 ई. आर. 792.

(2) एल. आर. 12 क्यू. बी. डी. 721.

अदालत को बनाए रखने के लिए बहुत अनिश्चित। यह भी तर्क दिया गया था कि

उसकी ओर से कि द्वारा प्रयोग की गई अधिकारिता के संबंध में

उक्त अधिकारिता की सीमाएँ लॉर्ड्स द्वारा सीमित थीं

सामान्य कानून और इसका प्रयोग अदालतों में परीक्षण योग्य था। यह याचिका को सर्वसम्मति से न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि

न्यायालय हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले पर सवाल नहीं उठा सका

उच्च न्यायालय के रूप में। रेनफोर्ड सी. जे. ने अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय ने

कारण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, और इसलिए, वापसी का रूप यह महत्वपूर्ण नहीं है "। विद्वान मुख्य न्यायाधीश के अनुसार,

विवादित प्रतिबद्धता फैसले के निष्पादन में थी

अवमानना के लिए प्रभु द्वारा दिया गया; और इसलिए, यदि अर्ल

जमानत हो जाए तो उसे फांसी से मुक्त कर दिया जाएगा; क्योंकि

एक अवमानना प्रत्यक्ष रूप से क्यूरी, निष्पादन के लिए कोई अन्य निर्णय नहीं है

यह। इसलिए इस मामले ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास अवमानना के लिए वारंट जारी करने का अधिकार क्षेत्र था और

कि चूँकि इस प्रकार किए गए व्यक्ति की प्रतिबद्धता हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा दिए गए निर्णय के निष्पादन में थी,

राजा के पीठ विभाग द्वारा उस ओर से जारी सामान्य वारंट की जांच नहीं की जा सकती थी।

इसके पाँच साल बाद, जय ने किंग्स बेंच डिवीजन का रुख किया।

गिरफ्तारी से रिहाई के लिए और टोफम, सार्जेंट एट आर्म्स के खिलाफ उसे गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के लिए कार्रवाई की। टोफम ने अदालत के अधिकार क्षेत्र का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और जय के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इसके सात साल बाद, हाउस ऑफ कॉमन्स ने घोषणा की कि उक्त निर्णय "अवैध, संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन और संसद के अधिकारों के लिए हानिकारक" था। इस दृष्टिकोण पर कार्य करना

दोनों न्यायाधीशों को सदन के बार में बुलाया गया और उनके आचरण के बारे में बताने के लिए कहा गया। बार के सामने पेश होते हुए, सर फ्रांसिस पेम्बर्टन ने सदन में उल्लेख किया कि वह छह साल से अधिक समय से अदालत से बाहर थे और उन्हें ठीक से याद नहीं था कि मामले में क्या हुआ था। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्हें इस बारे में पर्याप्त सूचना दिए बिना बार में बुलाया गया कि उनके खिलाफ क्या आरोप था। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि यदि बचाव पक्ष की चींटी को निवेदन करना चाहिए कि उसने इस सदन के आदेश से उसे गिरफ्तार किया है, और उसे यह अनुरोध करना चाहिए कि राजा की पीठ के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, वह सदन को संतुष्ट करेगा कि इस तरह की याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने अपनी आगे की दलीलें देने के लिए अदालत के फैसलों पर गौर करने के लिए समय मांगा। आखिरकार, दोनों न्यायाधीशों को कैद करने का आदेश दिया गया (1)। इंग्लैंड में संवैधानिक कानून पर सभी प्रमुख लेखकों द्वारा इस घटना की कड़ी आलोचना की गई है और यह कहना काफी सटीक होगा।

(1) 12 राज्य ट्र. 322 .

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

471

कि इसे दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक माना गया है

हाउस ऑफ कॉमन्स के इतिहास में प्रकरण। यह कुछ हद तक

विडंबना यह है कि बहुत पहले 1689 में जो हुआ था, उसका प्रयास किया गया है

वर्तमान कार्यवाहियों में सदन द्वारा किया जाना 14 वर्ष

के बाद इस देश के तहत जीवन के एक लोकतांत्रिक तरीके के लिए इस्तेमाल किया गया है

एक लिखित संविधान!

हालाँकि, इस मामले से अलग होने से पहले, यह महत्वपूर्ण होगा।

संक्षेप में यह इंगित करने के लिए कि सफल न्यायाधीशों ने इस पर कैसे विचार किया है

हाउस ऑफ कॉमन्स का संचालन। सर फ्रांसिस बर्डेट बनाम।

एबॉट (1), लॉर्ड एलेनबरो सी. जे. ने कहा: " आश्चर्य की बात है।

उस मामले में अभिलेख को देखने पर एक न्यायाधीश को कैसे होना चाहिए

पूछताछ की गई, और हाउस ऑफ कॉम द्वारा जेल में डाल दिया गया मॉन्स, एक निर्णय देने के लिए, जो कोई भी न्यायाधीश नहीं बैठता है

इस स्थान पर "से अलग हो सकता है, और उन्होंने कहा कि वकील

बर्डेट में दिखाई देने वाले जनरल ने स्वीकार किया था कि प्रो

शायद उस समय बात इतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आई थी, जहाँ

लॉर्ड एलेनबरो ने देखा कि यह रिवोलू के बाद था

टियन, जो इस तरह के एक कारण के लिए इस तरह की प्रतिबद्धता को थोड़ा सा बनाता है

खतरनाक; और उन्होंने बताया कि यह याद रखना चाहिए कि

लॉर्ड सी. जे., पेम्बर्टन उस समय नुकसान में थे।

उन न्यायाधीशों में से एक होने का जो मुकदमे पर बैठे थे

लॉर्ड रसेल, और इसलिए बाद में लोकप्रियता में उच्च नहीं रहे

क्रांति, जब उसके मामले में निर्णय और प्राप्तकर्ता था

जिसे हाल ही में संसद द्वारा उलट दिया गया था।

इसी तरह, स्टॉकडेल बनाम, हंसार्ड (2) में, इस इंसी का उल्लेख करते हुए

अंत में, लॉर्ड डेनमैन सी. जे. ने घोषणा की: " हमारा सम्मान और आभार

अधिवेशन के लिए संसद को हमें इस तथ्य के प्रति अंधा नहीं करना चाहिए

कि कारावास की यह सजा उतनी ही अन्यायपूर्ण और अत्याचारी थी

मनमाना शक्ति के उन कार्यों में से किसी के रूप में जिनके लिए वे वंचित थे

अपने मुकुट के राजा जेम्स "।

अगला मामला जिसका संदर्भ दिया जा सकता है वह है एशबी बनाम।

सफेद ($)। उस मामले में, वादी आयल्स की बर्गेस थी

दफनाएँ, और इस तरह से पार्लिया के दो सदस्यों के लिए वोट करने का अधिकार है

मन में। चुनाव के दिन उन्होंने प्रतिवादियों से अनुरोध किया,

जो नगर के निर्वाचन अधिकारी थे, उन्हें प्राप्त करने के लिए

वोट करें। यह प्रतिवादियों ने करने से इनकार कर दिया, और वादी था

धोखाधड़ी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपना वोट देने से इनकार करने के लिए अधिकारी, और यह जूरी द्वारा हर्जाने के लिए एक पुरस्कार में समाप्त हुआ। एक कार्रवाई में

फैसले की गिरफ्तारी में रानी की पीठ के समक्ष, यह आग्रह किया गया था कि

(2) 112 ई. आर. 1112,1163।

(1) 104 ई. आर. 501,541।

(3) (1703-04) 92 बी. आर. 126

1 C.I.165-5

:

[1965] 1 एस सी आर।

वादी द्वारा किया गया दावा बनाए रखने योग्य नहीं था। यह कार्रवाई असहमति जताते हुए बहुमत के निर्णय होल्ट सी. जे. के अनुसार सफल रही। न्यायमूर्ति गोल्ड ने अभिनिर्धारित किया कि उनकी राय थी कि प्रतिवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई कायम रखने योग्य नहीं थी, और अपने निष्कर्ष के समर्थन में उन्होंने चार कारण दिए; पहला, क्योंकि प्रतिबादी न्यायाधीश हैं, और इसमें न्यायाधीशों के रूप में कार्य करते हैं;

दूसरा, क्योंकि यह एक संसदीय मामला है, जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है; तीसरा, वादी का मतदान करने का विशेषाधिकार संपत्ति या लाभ का मामला नहीं है, ताकि इसकी बाधा केवल अनुचित नुकसान हो; और चौथा, यह पब चाटने से संबंधित है, और एक लोकप्रिय अपराध है (1)।

हालांकि, होल्ट सी. जे. ने बहुमत की राय से असहमति जताई और

कुछ मजबूत भाषा में उनके विचार। उल्लेख करते हुए

उनके सहयोगियों द्वारा व्यक्त की गई राय कि न्यायालय मामले का न्याय नहीं कर सकता क्योंकि यह एक संसदीय बात थी

चीखते हुए बोला: " अरे! किसी भी तरह से इसके प्रति बहुत कोमल रहें। इसके अलावा, यह जटिल है, और इसके विपरीत राय हो सकती है। लेकिन यह मामला संसद में कभी भी प्रश्न में नहीं आ सकता है; क्योंकि इस बात पर सहमति है कि जिन व्यक्तियों को वादी ने वोट दिया था, वे चुने गए थे; ताकि उनके वोट से वंचित होने के लिए कार्रवाई की जा सके। (2) उन्होंने स्वीकार किया कि अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण या विस्तार नहीं करना चाहिए; लेकिन उन्होंने सोचा कि अदालत को राजा द्वारा दिए गए चार्टर पर, या प्रथा या अनुदेश के मामले पर, जब यह संसद पर अतिक्रमण किए बिना अदालत के समक्ष आता है, तो उसे निर्धारित करना चाहिए। उनका निष्कर्ष था कि यदि यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का मामला है, तो "हम इसका न्याय करने के लिए अपनी शपथ से बाध्य हैं" (*)। हालाँकि, इस निर्णय का अवमानना के सवाल से कोई लेना-देना नहीं है।

अगला मामला जो अवमानना के सवाल से संबंधित है

हाउस ऑफ कॉमन्स आर. वी. है। पैटी (1)। उस मामले में, पैटी और चार अन्य को सदन के अध्यक्ष द्वारा जारी वारंट द्वारा न्यूगेट के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। वारंट एक बोलने वाला युद्ध था और यह दर्शाता था कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों ने सदन के अधिकार क्षेत्र का

प्रलोभन दिया था और इसके ज्ञात विशेषाधिकारों का खुला उल्लंघन किया था। उक्त व्यक्तियों द्वारा इस वारंट की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह कई दुर्बलताओं से पीड़ित था। हालाँकि, मामले में बहुमत का निर्णय यह था कि वारंट कथित दुर्बलताओं के लिए प्रतिवर्ती नहीं था और अदालत को इस मामले से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स अपने स्वयं के उचित न्यायाधीश थे।

विशेषाधिकार। न्यायमूर्ति पॉव्स ने द में पहले के फैसले का उल्लेख किया

(2)

आइबीआइडी।, 137 .

(1) 92 ई. आर. 126,129।

(4)

(1704) 92 ई. आर. 233

(3) आइबीआइडी।, 139 .

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

473

शाफ्ट्सबरी के मामले के अर्ल (1) ने कहा: अगर सभी प्रतिबद्ध हैं

स्कैन किया जाएगा, वे पानी नहीं पकड़ेंगे। हमारे आदेश यहाँ में ऐसे मामले छोटे होते हैं, जैसे कि अवमानना के लिए, या अवमानना के लिए

ऐसा कारण। तो चांसरी में अवमानना के लिए प्रतिबद्धताएँ

पूरी तरह से जवाब नहीं देने आदि में अवमानना के लिए हैं, और नहीं करेंगे

क्या यह प्रतिबद्धता पर्याप्त होगी? उनका मानना था कि "हाउस ऑफ

कॉमन्स एक महान न्यायालय है, और उनके द्वारा किए गए सभी कार्य

संस्कार का उद्देश्य होना चाहिए, और मामला होना आवश्यक नहीं है

उनके वारंटों में विशेष रूप से पढ़ा गया; उसी कारण से जैसे हम

दो पंक्तियों के न्यायालय के एक नियम द्वारा लोगों को प्रतिबद्ध करें, और इस तरह के प्रतिबद्ध

भावनाओं को अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह इरादा किया जाना है, कि हम

हम जो करते हैं, उस पर टिके रहें। (2) इस प्रकार यह देखा जाएगा कि बहुमत

कॉमन्स एक महान न्यायालय था और उच्च न्यायालयों की तरह वेस्टमिंस्टर, इसके लिए एक छोटा सामान्य वारंट जारी करने का हकदार था

इसकी अवमानना के लिए व्यक्तियों को दोषी ठहराना: यदि ऐसा कोई सामान्य आदेश

जारी किया गया था और इसे वेस्टमिन्स में अदालतों के समक्ष चुनौती दी गई थी

इसके अलावा, इसे उसी सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि दिया जाता है

उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए गए इसी तरह के वारंट। होल्ट सी. जे., कैसे

कभी, यह विचार लेने के लिए राजी नहीं किया गया था कि आक्षेपित कारावास ऐसा था जैसे इंग्लैंड के स्वतंत्र व्यक्ति को होना चाहिए

"; और उन्होंने जोड़ा", इसके लिए, जो केवल कर रहा था

एक कानूनी कार्य, जिसे सदन के वोट से अवैध नहीं बनाया जा सकता था

कॉमन्स के; उसके लिए न तो संसद का सदन, न ही दोनों

सदन संयुक्त रूप से, स्वतंत्रता या संपत्ति का निपटान कर सकते थे

विषय; इस उद्देश्य के लिए रानी को शामिल होना चाहिए: और यह कि

इस तरह के कार्यों के लिए उनकी कई सहमति की आवश्यकता थी,

कि विषय की स्वतंत्रता की बड़ी सुरक्षा शामिल थी। (पी। 236)। इसलिए यह मामला यह मानता प्रतीत होता है कि

वेस्टमिंस्टर की अदालतों के लिए जांच करना अनुचित होगा

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी सामान्य वारंट की वैधता।

यह हमें मर्रे के मामले (1) 1750 में निर्णय पर ले जाता है।

मर्रे को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा घुटने टेकने से इनकार करने के लिए जेल में डाल दिया गया था, जब उन्हें हाउस के बार में लाया गया था। सदन द्वारा यह घोषित किया गया था कि मर्रे का घुटने टेकने से इनकार "विशेषाधिकार की सबसे खतरनाक अवमानना" थी। जब बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक याचिका न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, तो इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि "हाउस ऑफ कॉमन्स निस्संदेह एक उच्च न्यायालय था और यह सभी हाथों से सहमत था कि उन्हें अपने विशेषाधिकारों का न्याय करने की शक्ति है, और इसे उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

(2) 92

ई. आर. 232,234।

(1) 86 ई. आर. 792.

(3) 95 ई. आर. 629

[1

965] आई एस. सी. आर.

474

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारे लिए अवमानना क्या थी, क्योंकि अगर यह दिखाई देता, तो हम इसका न्याय नहीं कर सकते थे। यही विचार न्यायमूर्ति राइट द्वारा व्यक्त किया गया है। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स उनके अपने न्यायालय से श्रेष्ठ है, और उनका न्यायालय वेस्टमिंस्टर हॉल में किसी अन्य न्यायालय में अवमानना के लिए किए गए व्यक्ति को जमानत देना स्वीकार नहीं कर सकता है। जे. डेनिसन ने सहमति व्यक्त की और अपनी राय व्यक्त की कि वेस्टमिंस्टर हॉल का न्यायालय उनके विशेषाधिकारों और उनके खिलाफ अवमानना के निर्णय के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स से कमतर था। यह मामला फिर से इस आधार पर आगे बढ़ता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक उच्च न्यायालय है, और इस तरह इसके वारंट की जांच नहीं की जा सकती है।

समय के संदर्भ में अगला प्रासंगिक मामला ब्रास क्रॉस्बी (1) है।

ब्रास क्रॉस्बी लंदन के लॉर्ड मेयर थे और इसके सदस्य थे।

हाउस ऑफ कॉमन्स, और मजिस्ट्रेट के रूप में उन्होंने जमानत स्वीकार की थी

एक व्यक्ति जिसे वारंट के तहत जेल भेजा गया था

सदन के अध्यक्ष द्वारा सदन के आदेशों के तहत जारी किया गया

स्वयं। सदन ने माना कि लॉर्ड मेयर उल्लंघन का दोषी था

सदन के विशेषाधिकार का, और इस तरह वह के लिए प्रतिबद्ध था

लंदन का टावर। इस आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी

पीतल क्रॉस्बी। लेकिन चुनौती जमीनी स्तर पर विफल रही।

कि जब हाउस ऑफ कॉमन्स कुछ भी निर्णय देता है

अवमानना या विशेषाधिकार का उल्लंघन, उनका निर्णय एक दोषपूर्ण निर्णय है

यह, और परिणामस्वरूप उनकी प्रतिबद्धता निष्पादन में है। के रूप में लॉर्ड सी. जे. डी. ग्रे ने कहा, "कोई भी अदालत आरोपमुक्त या जमानत नहीं दे सकती है।

वह व्यक्ति जो किसी अन्य न्यायालय के निर्णय द्वारा निष्पादित किया जा रहा है ",

करने का अधिकार होना, और वह प्रतिबद्धता एक exe होना लेकिन सवाल यह है कि यह अदालत क्या कर सकती है? उन्होंने दिया।

इस टिप्पणी के साथ जवाब दें कि "यह कुछ नहीं कर सकता जब कोई व्यक्ति

निष्पादन में है, एक सक्षम अदालत के फैसले से

अधिकारिता; ऐसे मामले में, यह न्यायालय अपील का न्यायालय नहीं है। (2)

इस दृष्टिकोण से सहमत होते हुए, जे. ब्लैकस्टोन ने कहा कि सदन

कॉमन्स का एक सर्वोच्च न्यायालय है और वे इससे प्रभावित थे

यह तर्क कि "यह अत्यधिक भ्रम पैदा करेगा, यदि प्रत्येक इस कक्ष के न्यायालय को प्रतिबद्धताओं की जांच करने की शक्ति होनी चाहिए।

सदन के अन्य न्यायालयों की अवमानना के लिए; ताकि निर्णय अवमानना के संबंध में प्रत्येक संबंधित न्यायालय की प्रतिबद्धता,

यह अंतिम और बिना नियंत्रण के होना चाहिए। ( ) यह देखा जाएगा

कि यह निर्णय उसी आधार पर आगे बढ़ा जिसके द्वारा

तब मान्यता दी गई कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक श्रेष्ठ था

न्यायालय और इस प्रकार निर्णय किए गए व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार क्षेत्र था

(1) 95 बी. आर. 1005

(2) आइबीआइडी।, 1011 .

(3) आइबीआइडी।, 1014 .

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

475

इसके द्वारा अवमानना का दोषी होना। इस तरह की अवमानना के संबंध में सदन द्वारा जारी एक सामान्य वारंट को वेस्टमिंस्टर हॉल में अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए गए समान वारंट के समान दर्जा दिया गया था।

इस मामले से अलग होने से पहले, हम संयोग से विज्ञापन दे सकते हैं

इस निर्णय पर लॉर्ड डेनमैन सी. जे. द्वारा की गई टिप्पणी। लार्ड डेनमैन ने कहा: अब हम इतिहास की बात के रूप में जानते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स उस समय क्राउन के साथ मिलकर लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों को लागू करने में लगा हुआ था। फिर भी उस विद्वान न्यायाधीश [ब्लैकस्टोन जे.] ने हाउस ऑफ कॉमन्स को बनाए रखने के लिए अपने अयोग्य प्रस्ताव की घोषणा की, भले ही उसे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना चाहिए था (1)।

इस विषय पर अगला महत्वपूर्ण निर्णय सर फ्रांसिस बर का है।

डेट का मामला (2)। यह मामला अतिचार की एक कार्रवाई से उत्पन्न हुआ जिसे सर फ्रांसिस बर्डेट ने हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के खिलाफ उनके घर को तोड़ने और प्रवेश करने और उन्हें टावर में कैद करने के लिए शुरू किया। बचाव पक्ष में दायर याचिका यह थी कि प्रतिवादी का आचरण बर्डेट के समर्पण के लिए सदन के एक आदेश द्वारा उचित ठहराया गया था, जब सदन ने निर्णय दिया था कि वह सदन के न्यायसंगत अधिकारों और विशेषाधिकारों पर प्रतिबिंबित करने वाले एक अपमानजनक और निंदनीय पत्र को प्रकाशित करके सदन की अवमानना का दोषी था। मामले पर विस्तार से बहस की गई और जैसा कि मई बताते हैं: " यह मामला अवमानना (3) करने के लिए कॉमन्स की शक्ति (जैसा कि लॉर्ड शाफ्ट्सबरी का मामला लॉर्ड्स के लिए करता है)

के लिए प्रमुख अधिकारियों में से एक प्रदान करता है। इस मामले में वारंट एक बोलने वाला वारंट था और अवमानना हाउस ऑफ कॉमन्स की अवमानना थी। बर्डेट द्वारा की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था, लेकिन याचिका को अस्वीकार करने के लिए दिए गए कारण महत्वपूर्ण हैं। लॉर्ड एलेनबरो सी. जे. ने इस प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया है। उन्होंने देखा है कि पूर्व के अधिकार पर संसद में, कानून द्वारा मान्यता मिलने पर, और सभी न्यायाधीशों की निरंतर मान्यता मिलने पर, उन्हें यह सोचना चाहिए था कि इस सवाल को शांत करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अधिकार थे, यानी कि क्या हाउस ऑफ कॉमन्स के पास अपने विशेषाधिकारों की अवमानना के लिए प्रतिबद्धता की शक्ति है? सदन के पास निस्संदेह वह शक्ति थी। उस आधार पर मामले से निपटने के लिए आगे बढ़ते हुए, लॉर्ड एलेनबरो ने माना कि सदन दोनों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। उस प्रकाशन के तथ्य और प्रभाव के बारे में, जिसे उसके द्वारा मानहानिकारक माना गया था, और उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णय के अनुरूप (और संसद के किसी भी सदन के निर्णय औचित्य के साथ नहीं हो सकते हैं)।

(1) स्टॉकडेल बनाम. हंसार्ड, 112 ई. आर. 1112,1158

(2) 104 ई. आर. 501

(3) मे 'ज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, पी। 159 .

[1965] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

476

सामान्य न्यायालयों की तुलना में कम आधिकारिक आधार पर रखे जाने पर), सदन को दोनों का निर्णय लेने वाला माना जाना चाहिए, जहां तक उस पर किसी भी प्रश्न का संबंध है जो अन्य न्यायालयों में उत्पन्न हो सकता है।

अगला सवाल जिस पर लॉर्ड एलेनबरो ने विचार किया वह था

यदि वारन स्वयं वचन देने के लिए पर्याप्त आधार का खुलासा करता है, और सदन के अधिकारियों को इसे निष्पादित करने का आदेश देता है, तो इसके तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए औचित्य बनाया जाता है, जब तक कि वारंट को निष्पादित करने के लिए बाद में किसी भी उचित साधन का उपयोग नहीं किया गया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि

उस मामले में न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि यदि जारी किया गया वारंट अनुचित, अवैध या असाधारण प्रतीत होता है, तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए याचिका पर विचार करने और याचिकाकर्ता को राहत देने का हकदार होगा। लॉर्ड एलेनबरो ने इस तर्क पर विचार किया और यह राय व्यक्त की कि यदि कोई प्रतिबद्धता आम तौर पर हाउस ऑफ कॉमन्स की अवमानना के लिए प्रतीत होती है, तो वह न तो उस न्यायालय के मामले में, और न ही किसी अन्य उच्च न्यायालय के मामले में, आगे की जांच करेगा; लेकिन यदि वह अवमानना के लिए प्रतिबद्ध होने का दावा नहीं करता है, लेकिन वापसी पर दिखाई देने वाले कुछ मामले के लिए, जिसे किसी भी उचित इरादे से न्यायालय की अवमानना के रूप में माना जा सकता है, लेकिन प्रतिबद्धता का आधार स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से मनमाना, अन्यायपूर्ण और सकारात्मक कानून या राष्ट्रीय न्याय के प्रत्येक सिद्धांत के विपरीत है, ऐसे मामले में न्यायालय को इसे देखना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए जो भी न्यायालय से न्याय की आवश्यकता हो (पीपी। 558-60) . इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह स्वीकार करते हुए भी कि हाउस ऑफ कॉमंस द्वारा जारी सामान्य वारंट की जांच करना अनुचित या तात्कालिक होगा, लॉर्ड एलेनबरो ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह सम्मेलन इस अपवाद के अधीन होगा कि जहां भी यह वापसी से दिखाई देता है या अन्यथा कि प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से थी।

अन्यायपूर्ण, अदालत पक्ष को राहत देने में असमर्थ नहीं होगी।

यह मामला राजकोष की अदालत के समक्ष अपील में गया और

अपील के तहत निर्णय की पुष्टि की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय निर्णय की घोषणा से पहले, लॉर्ड एल्डन ने उनके लॉर्डशिप्स को प्रस्ताव दिया कि प्रतिवादियों के वकील को तब तक नहीं सुना जाना चाहिए जब तक कि वे उस प्रश्न पर न्यायाधीशों की सलाह प्राप्त न कर लें जो उन्होंने तैयार किया था। यह सवाल था: " क्या, यदि सामान्य याचिकाओं का न्यायालय, किसी अधिनियम को एक अपराध होने का निर्णय देता है

न्यायालय के प्रलोभन ने, एक वारंट के तहत अवमानना के लिए प्रतिबद्ध किया था, जिसमें कहा गया था कि इस तरह का निर्णय आम तौर पर विशेष परिधि रुख के बिना किया जाता है, और मामले को राजा के विशेष संदर्भ न्यायालय (गजेंद्रगडकर सी. जे.) के समक्ष लाया गया था।

पीठ, बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट पर लौटकर, वापसी सेटिंग

अवमानना जीन के इस तरह के निर्णय को बताते हुए वारंट को आगे बढ़ाना

रैली; क्या उस मामले में राजा की पीठ का न्यायालय अलग होगा

कैदी को आरोपित करें, क्योंकि विशेष तथ्य और परिस्थितियाँ,

जिसमें से अवमानना उत्पन्न हुई, युद्ध में निर्धारित नहीं की गई थी

रोते हैं "। इस प्रश्न के बाद न्यायाधीशों को सौंप दिया गया और उन्होंने

कुछ मिनटों के लिए आपस में परामर्श किया, लॉर्ड सीएच। बैरन

रिचर्ड्स ने अपनी सर्वसम्मत राय दी कि ऐसे मामले में राजा की पीठ का न्यायालय मुक्त नहीं होगा। (1) यह राय

स्वीकार कर लिया गया और बर्डेट की अपील को बिना फोन किए खारिज कर दिया गया

उत्तरदाता पर। इस मामले में, लॉर्ड एर्स्किन ने देखा कि "

हाउस ऑफ कॉमन्स, चाहे वह अदालत हो या नहीं, हर एक को पसंद करना चाहिए।

अन्य न्यायाधिकरण, बाधा से खुद को बचाने की शक्ति रखता है

और अपमान करना, और इसकी गरिमा और चरित्र को बनाए रखना। अगर

कानून की गरिमा कायम नहीं रहती, उसका सूर्य अस्त हो जाता है, कभी नहीं होता

फिर से रोशनी। इतना मैंने सोचा कि यह कहना आवश्यक है, महसूस कर रहा हूँ

दृढ़ता से कानून की गरिमा के लिए; और केवल यह जोड़ना है कि मैं

न्यायाधीशों द्वारा दी गई राय से पूरी तरह सहमत हैं। यह मामला ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थिति स्थापित होती है कि सदन द्वारा जारी वारंट

कॉमन्स को एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी वारंट के रूप में माना गया था

और इस तरह, वेस्टमिंस्टर हॉल में अदालतें पीछे नहीं रह सकती थीं यह।

1836-37 में मामलों की एक श्रृंखला शुरू हुई जिसमें जॉन जोसेफ

स्टॉकडेल चिंतित था। मामलों की इस श्रृंखला ने अंततः

मिडलसेक्स के शेरिफ की गिरफ्तारी और कारावास। यह.

ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षकों द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में

हाउस ऑफ कॉमन्स स्टॉकडेल के आदेश के तहत जेलें थीं अपमानजनक तरीके से वर्णित किया गया, और इसलिए, उन्होंने एक कार्रवाई की

मेसर्स के खिलाफ। 1836 में हंसार्ड। बचाव में, हंसार्ड ने गुहार लगाई

विशेषाधिकार और आग्रह किया कि विचाराधीन रिपोर्टें सार्वजनिक थीं

- सदन के आदेश के तहत जारी किया गया। न्यायालय ने कहा कि

सदन के आदेश ने कार्रवाई के लिए कोई बचाव प्रदान नहीं किया। फिर भी,

न्यायपीठ का फैसला स्टॉकडेल के खिलाफ न्याय की याचिका पर गया

गुण-दोष के आधार पर जूरी ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि कथित

स्टॉकडेल का अपमानजनक वर्णन सटीक था। उस समय जब

इस मामले की सुनवाई की गई, लॉर्ड चीफ जस्टिस डेनमैन ने निश्चित किया

हंसार्ड द्वारा दावा किया गया। उन्होंने कहा कि सदन का तथ्य कॉमन्स ने मेसर्स को निर्देशित किया है। हंसार्ड अपने सभी लेख प्रकाशित करेंगे

संसदीय रिपोर्ट उनके लिए या किसी के लिए कोई औचित्य नहीं है।

पुस्तक-विक्रेता जो एक मानहानि वाली संसदीय रिपोर्ट प्रकाशित करता है किसी भी आदमी के खिलाफ (2)। संयोग से, यह जोड़ा जा सकता है कि एक

(1) 3 ई. आर. 1289,1301।

(2) मे 'ज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, पी। 159 .

478 इस विवाद के परिणामस्वरूप, संसद ने अंततः संसदीय पत्र अधिनियम, 1840 पारित किया, जिसने इस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया।

गुण-दोष पर जूरी के प्रतिकूल निर्णय से विचलित नहीं होकर,

स्टॉकडेल द्वारा लाई गई दूसरी कार्रवाई में सदन ने विशेषाधिकार का बचाव करने का फैसला किया। इस बचाव को खारिज कर दिया गया और नुकसान और लागत के भुगतान के लिए एक आदेश पारित किया गया। फिर भी, हाउस ऑफ कॉमन्स ने अपने प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं की और इससे परहेज किया स्टॉकडेल और उनके कानूनी सलाहकारों को मामले को अदालत में ले जाने के लिए दंडित करना; इसके बजाय, यह निर्णय लिया गया कि नुकसान और लागत का भुगतान मामले की विशेष परिस्थितियों में किया जाए।

इस परिणाम से प्रोत्साहित होकर स्टॉकडेल ने तीसरी कार्रवाई की।

उक्त रिपोर्ट के एक और प्रकाशन के लिए। इस बार मेसर्स। हंसार्ड ने दलील नहीं दी; परिणामस्वरूप, निर्णय इसके खिलाफ गया। उन्हें चूक में, और नुकसान का आकलन एक जूरी द्वारा, शेरिफ के न्यायालय में, £ 600 पर किया गया था। मिडिलसेक्स के शेरिफ उस राशि के लिए शुल्क लगाते थे, लेकिन उन्हें सदन द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रतियां दी जाती थीं; और इससे स्वाभाविक रूप से वे इस मामले में सतर्क हो जाते थे। इसलिए, उन्होंने स्टॉकडेल को पैसे के भुगतान में यथासंभव देरी की, लेकिन अंततः उनके द्वारा एक कुर्की के तहत स्टॉकडेल को पैसे का भुगतान किया गया। इस स्तर पर, हाउस ऑफ कॉमन्स ने अखाड़े में प्रवेश किया और स्टॉक डेल को सर्जेंट की हिरासत में सौंप दिया। इसने शेरिफों से पैसे वापस करने का आह्वान किया और उनके इनकार करने पर, उन्हें अवमानना के लिए भी दोषी ठहराया गया। इसके कारण शेरिफों द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट पर उनकी रिहाई के लिए कार्यवाही की गई। हालाँकि, ये कार्यवाही विफल हो गईं और यह मिडलसेक्स के शेरिफ के मामले में निर्णय का प्रभाव है (1)।

स्वाभाविक रूप से श्री सीरवई ने इस पर काफी जोर दिया है।

निर्णय लें। उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि न्यायालय ने मध्य लिंग के शेरिफ को उनके कारावास से बचाने के लिए खुद को शक्तिहीन पाया, हालांकि जिस आचरण ने सदन की अवमानना को जन्म दिया, वह संदर्भ में, न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश का परिणाम था। लॉर्ड डेनमैन सी. जे., जिन्होंने स्वयं इस प्रश्न पर विस्तृत चर्चा की थी और हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसके प्रिवी के संबंध में किए गए दावे की वैधता पर विवाद किया था।

(1) 113 बी. आर. 419

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

479

स्टॉकडेल बनाम के मामले में कानून। हंसार्ड (1), इस निर्णय का एक पक्ष था। उन्होंने यह घोषणा करते हुए अपना निर्णय शुरू किया कि स्टॉकडेल बनाम के मामले में उनका अंतिम निर्णय दिया गया है। हंसार्ड (1) हर तरह से सही था। फिर भी, शेरिफों द्वारा उठाई गई याचिका का उनके खिलाफ जवाब दिया जाना था, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता

एक कानूनी वारंट द्वारा बनाए रखा गया था। लॉर्ड डेनमैन ने तब उन तीन आधारों की जांच की जिन पर वारंट की वैधता पर महाभियोग चलाया गया था और उन्होंने पाया कि उन दलीलों में कोई सार नहीं था। विद्वान मुख्य न्यायाधीश। इस बिंदु पर असर डालने वाले पिछले निर्णयों पर विचार किया और देखा कि बर्डेट बनाम के मामले में लॉर्ड एल्डन द्वारा निर्धारित परीक्षण। एबॉट (3) प्रासंगिक था; और यह परीक्षण, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, आगे बढ़ता है।

यह कि उच्च न्यायालयों द्वारा जारी प्रतिबद्धता के लिए सामान्य वारंट की तरह, अवमानना के आधार पर हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी सामान्य वारंट की बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्यवाही में जांच नहीं की जानी चाहिए। लार्ड डेनमैन सी. जे. के साथ सहमति जताते हुए जे. लिटलडेल ने कहा: " यदि वारंट निर्णय के आधारों की घोषणा करता है, तो यह न्यायालय, कई मामलों में, उनकी वैधता की जांच करेगा; लेकिन, यदि ऐसा नहीं होता है, तो हम ऐसी जांच में नहीं जा सकते। यहाँ हमें यह मान लेना चाहिए कि सदन ने पर्याप्त कारण के साथ निर्णय लिया; और वे उचित न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति विलियम्स, जिन्होंने लॉर्ड डेनमैन के साथ भी सहमति व्यक्त की, ने यह जोड़ना आवश्यक समझा कि "यदि वापसी, इस तरह के मामले में, प्रतिबद्धता का एक तुच्छ कारण दिखाती है, तो एक विशेष पोशाक पहनने के लिए, मुझे बर्डेट वी में लॉर्ड एलेनबरो द्वारा व्यक्त की गई राय से सहमत होना चाहिए। मठाधीश (2), जहाँ वह आम तौर पर अवमानना बताते हुए एक प्रतिबद्धता और स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और बेतुके आधार पर किए जाने वाले वापसी द्वारा दिखाई देने के बीच अंतर करता है। कॉलरिज जे. को वरीयता दी गई

अपना निष्कर्ष इस आधार पर रखने के लिए कि "प्रलोभन के मामलों में इस सामान्य रूप में निर्णय लेने का [हाउस ऑफ कॉमन्स का अधिकार] विशेषाधिकार पर आधारित नहीं है, बल्कि उन्हीं आधारों पर आधारित है जिन पर यह न्यायालय या सामान्य याचिकाओं का न्यायालय प्रतिबद्धता में कोई कारण बताए बिना अवमानना के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है।" यह उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति कोलरिज ने यह स्पष्ट करना आवश्यक समझा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण

कार्यवाही में इसकी वैधता को चुनौती दिए जाने पर सामान्य वारंट की आवश्यकता के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।

अब यह स्वयं विशेषाधिकार का एक हिस्सा है; यह एक परंपरा का परिणाम है जिसके द्वारा अभिलेख के वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा जारी किए गए ऐसे वारंट हैं

आमतौर पर सम्मानित किया जाता है। यह निर्णय 1840 में घोषित किया गया था, और इसे इस विषय पर कानून के विकास में एक मील का पत्थर कहा जा सकता है। इस प्रकार,। यह निर्णय श्री सीरवई को यह तर्क देने में भी सहायता नहीं करता है कि यह उनके विशेषाधिकार का हिस्सा है। (1) 112 ई. आर. 1112.

(2)

104 ई. आर. 501

[1965] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट।

480

सदन इस बात पर जोर देता है कि उसके द्वारा जारी एक सामान्य वारंट को ए माना जाना चाहिए

निर्णायक के रूप में और कानून के न्यायालयों में परीक्षण योग्य नहीं है।

अगला मामला हावर्ड बनाम है। सर विलियम गोसेट (1)। उस में

मामला, बहुमत के निर्णय से अध्यक्ष द्वारा जारी वारंट हावर्ड के खिलाफ सदन को कुछ के परिणामस्वरूप अमान्य माना गया था

वारंट में पाई गई दुर्बलताएँ। केवल विलियम्स जे. ने असहमति जताई। इस मामले में वारंट एक सामान्य वारंट था और जे. विलियम्स ने माना।

कि तकनीकी आपत्तियों की वैधता के खिलाफ उठाया गया

वारंट पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि यह एक सामान्य वारंट था

इस तथ्य के निर्णायक के रूप में माना जाना चाहिए कि पक्ष के खिलाफ

जिनका वारंट जारी किया गया था, उनका उचित निर्णय लिया गया था

और बहुमत के फैसले को कोर्ट ऑफ एक्स्चे द्वारा उलट दिया गया था पूछते हैं। पार्क बी. ने इसके खिलाफ कई तर्कों पर विचार किया

राजकोष न्यायालय के निर्णय के लिए आधार व्यक्त किया गया था इन शब्दों में: " हमारा स्पष्ट मत है कि कम से कम उतना ही

सम्मान दिखाया जाना चाहिए, और जितना अधिक अधिकार दिया जाना चाहिए,

उच्चतम न्यायालयों के बारे में सदन के आदेशों के बारे में

देश में; और, यदि सामान्य न्यायालयों के अधिकारी हैं,

उन्हें दी गई प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य हैं, और इसलिए हैं इसके द्वारा संरक्षित, हाउस ऑफ कॉमन्स का अधिकारी उतना ही है

बाध्य और समान रूप से संरक्षित। हाउस ऑफ कॉमन्स एक ई है

संसद के उच्च न्यायालय का हिस्सा, जो बिना किसी सवाल के है

न केवल एक वरिष्ठ बल्कि इस देश में सर्वोच्च न्यायालय, और से ऊँचा। कानून की साधारण अदालतें (2) "।

इस प्रकार, इस निर्णय का परिणाम यह है कि हाउस ऑफ कॉमन्स

संसद के उच्च न्यायालय का हिस्सा होना एक उच्च न्यायालय है

और इसके द्वारा जारी सामान्य वारंट के अधीन नहीं किया जा सकता है निकट जांच, जैसे अन्य द्वारा जारी किए गए समान वारंट, वरिष्ठ

अभिलेख न्यायालयों को इस तरह की जांच से छूट दी गई है। यह ध्यान दिया जाएगा कि राजकोष न्यायालय ने कहा है कि

यह मामला कि संसद के उच्च न्यायालय के एक भाग के रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स, इस देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है और कानून के सामान्य न्यायालयों की तुलना में उच्च जी है: और यह अपने प्रारंभिक कार्यकाल में संसद के सदन के मूल न्यायिक चरित्र को याद करता है और इस तथ्य पर जोर देता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो संसद के सदन का एक हिस्सा है, अभी भी इंग्लैंड में कानून का सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है।

इस श्रृंखला का अंतिम मामला जिसका हमें उल्लेख करना चाहिए वह है I

ब्रैडलॉफ बनाम में क्वींस बेंच डिवीजन का निर्णय।

(1) 116 ई. आर. 139.

( )

इहिद।, 174 पर।

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

481

गोसेट (1)। यह निर्णय प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक या भौतिक नहीं है, लेकिन चूंकि श्री सीरवई स्टीफन जे. द्वारा प्रतिपादित कानून के कुछ बयानों पर निर्भर प्रतीत होते हैं, इसलिए हम इसे बहुत संक्षेप में संदर्भित करना आवश्यक समझते हैं। ब्रैडलॉफ के मामले में अदालत से इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या हाउस ऑफ कॉमन्स के सार्जेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि सदन के एक प्रस्ताव के पालन में एक सदस्य को सदन से बाहर रखा गया था और जवाब नकारात्मक था। ऐसा प्रतीत होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के भौतिक प्रस्ताव को कानून के विपरीत होने के रूप में चुनौती दी गई थी, और वास्तव में क्वीन बेंच डिवीजन

ब्रैडलॉफ के दावे को इस आधार पर निपटाने के लिए आगे बढ़े कि उक्त प्रस्ताव कानून के प्रासंगिक प्रावधान के सही प्रभाव के अनुसार नहीं हो सकता है; और फिर भी यह माना गया कि विवादित मामला हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रक्रिया के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित है, और इसलिए, क्वीन बेंच के न्यायालय को हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं थी। न्यायालय के समक्ष यह दबाव डाला गया कि प्रस्ताव स्पष्ट रूप से कानून के प्रासंगिक प्रावधान का विरोध करता है। इस तर्क की वैधता को दरकिनार करते हुए, जे. स्टीफन ने कहा कि इसके आंतरिक प्रबंधन से संबंधित अधिकारों और प्रस्तावों के संबंध में, सदन ठीक उसी संबंध में खड़ा है "जैसा कि हम इस न्यायालय के न्यायाधीश उन कानूनों के लिए खड़े हैं जो उन अधिकारों को विनियमित करते हैं जिनके हम संरक्षक हैं, और उन निर्णयों के लिए जो उन्हें विशेष मामलों में लागू करते हैं; अर्थात, वे सबसे गंभीर दायित्वों से बंधे होते हैं जो लोगों को किसी भी आचरण के लिए बाध्य कर सकते हैं।

हमेशा, कानून द्वारा उनके आचरण का मार्गदर्शन करने के लिए जैसा कि वे इसे समझते हैं। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा, "यदि वे इसे गलत समझते हैं, या (मैं अनुमान के लिए माफी मांगता हूं) जानबूझकर इसकी अवहेलना करते हैं, तो वे गलत या अन्यायपूर्ण न्यायाधीशों के समान हैं; लेकिन दोनों ही मामलों में, मेरे फैसले में उनके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं है। देश का कानून ऐसी कोई अपील नहीं देता है; ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया गया है या पेश किया जा सकता है जिसमें किसी भी न्यायालय ने कभी भी संसद के किसी भी सदन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया हो, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें न्यायालयों ने अपनी शक्तियों की सीमाओं को अपने संबंधित सदनों के बाहर घोषित किया है। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि यह उस निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त था जिस पर वह पहुंचा था (2)। श्री सीरवई का तर्क था कि हालांकि प्रस्ताव पार्लिया मेंटरी शपथ अधिनियम का उल्लंघन प्रतीत होता है, लेकिन अदालत ने ब्रैड को कोई राहत देने से इनकार कर दिया, और उन्होंने सुझाव दिया कि हमारे सामने वर्तमान विवाद से निपटने के लिए इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। जाहिर है। इस तर्क का उत्तर यह है कि हम सदन के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित किसी भी मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं।

(1) (1884) एल. आर. 12 क्यू. बी. डी. 271.

(2) आइबीआइडी।, 286 .

कार्यवाही प्रस्तुत करना। हम सदन की शक्ति से निपट रहे हैं।

कथित रूप से की गई अवमानना के लिए नागरिकों को दंडित करना

उनके द्वारा सदन की चार दीवारों के बाहर, और वह अनिवार्य रूप से विभिन्न विचारों को उठाती है।

इस मुद्दे पर प्रासंगिक निर्णयों की जांच करने के बाद,

हम सोचते हैं कि यह अवलोकन करना गलत नहीं होगा कि अधिकार

बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में जांचे गए आरोप आधारित हैं इस विचार पर अधिक कि हाउस ऑफ कॉमन्स में है

रिकॉर्ड के एक उच्च न्यायालय की स्थिति और अन्य की तरह अधिकार है समर्पण के लिए एक सामान्य वारंट जारी करने के लिए अभिलेख की वरिष्ठ अदालतें

अवमानना के दोषी पाए गए व्यक्तियों की सजा। जनरल की तरह

इस प्रकार के संबंध में अभिलेख के वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा जारी वारंट

अवमानना, हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी सामान्य वारंट

इसी तरह की स्थितियों में इसी तरह का इलाज किया जाना चाहिए। यह उस पर है

इस आधार पर कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी सामान्य वारंट

बंदी प्रत्यक्षीकरण में अदालतों की जांच से परे व्यवहार किया गया था

कार्यवाही। इस संबंध में, हमें यह जोड़ना चाहिए कि ऐसे सामान्य वारंटों की वैधता को मान्यता देते हुए, न्यायाधीश

अक्सर देखा है कि अगर वे संतुष्ट थे

लौटाना कि ऐसे सामान्य वारंट तुच्छ के लिए जारी किए गए थे या

असाधारण कारणों से, यह उनके लिए खुला होगा कि वे उनकी जांच करें वैधता।

यह महसूस करते हुए कि अब तक के निर्णयों से प्रकट स्थिति

हमारे द्वारा की गई जांच द्वारा किए गए दावे के लिए बहुत अनुकूल नहीं था कि सामान्य वारंट का निर्णायक चरित्र एक है

विशेषाधिकार के हिस्से के रूप में, श्री सीरवई ने बहुत दृढ़ता से भरोसा किया है प्रिवी काउंसिल के फैसलों पर जो उसका समर्थन करते प्रतीत होते हैं

विवाद, और इसलिए, अब इन निर्णयों की ओर मुड़ना आवश्यक है। इस श्रृंखला में पहला निर्णय विक्टोरिया बनाम की विधान सभा के अध्यक्ष के मामले में है। ह्यूग ग्लास (1)। उस मामले में विक्टोरिया सत्ता की कॉलोनी के लिए संविधान अधिनियम द्वारा था

विक्टोरिया की विधान सभा को उस विधानसभा की अवमानना और विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए एक सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध करने के लिए दिया गया था। उस शक्ति का प्रयोग करते हुए, ग्लास को सदन द्वारा अवमानना करने के लिए घोषित किया गया था और अध्यक्ष के युद्ध के राग के तहत, जो सामान्य शब्दों में था, वह जेल के लिए प्रतिबद्ध था। इसके बाद उनकी ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई और इस याचिका को कॉलोनी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस आधार पर मंजूरी दी कि संविधान संविधि और औपनिवेशिक अधिनियम विधानसभा को प्रदान नहीं करते हैं

समान शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तिएँ जो उनके पास थीं

(1) [1869-71] 3 L.R.P.C. 560.

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

483

हाउस ऑफ कॉमन्स। विधानसभा अध्यक्ष की अपील पर, कॉलोनी में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उलट दिया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रासंगिक क़ानून और अधिनियम ने विधानसभा को वही शक्तियां और विशेषाधिकार दिए जो उक्त अधिनियमों के पारित होने के समय हाउस ऑफ कॉमन्स को थे।

यह मानते हुए कि विधान सभा में भी ऐसा ही था

अवमानना के लिए प्रतिबद्ध होने का; और उस विशेषाधिकार के लिए आनुषंगिक, इस देश में यह अच्छी तरह से स्थापित किया गया है कि हाउस ऑफ कॉमन्स को स्वयं न्यायाधीश बनने का अधिकार है जो प्रलोभन है, और एक वारंट द्वारा उस अवमानना के लिए प्रतिबद्ध है, यह कहते हुए कि प्रतिबद्धता आम तौर पर सदन की अवमानना के लिए है, यह निर्दिष्ट किए बिना कि अवमानना का चरित्र क्या है। फिर उन्होंने इस तर्क के गुण-दोष पर विचार किया कि प्रासंगिक प्रत्यायन अधिनियम विक्टोरिया की विधान सभा को सामान्य वारंट जारी करने की आकस्मिक शक्ति प्रदान नहीं करता है, और इसे खारिज कर दिया। [लॉर्ड कैर्न्स ने कहा, "उनके अधिपति इस बात पर विचार करते हैं कि धोखाधड़ी के लिए प्रतिबद्ध होने के विशेषाधिकार के बीच एक आवश्यक अंतर है।" ऐसा प्रलोभन जो किसी निम्न न्यायालय को प्राप्त होगा, अर्थात् पहले अपने लिए यह निर्धारित करने का विशेषाधिकार कि अवमानना क्या है, फिर किसी वारंट पर अवमानना का चरित्र बताने का, और फिर उस वारंट को किसी उच्च न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षा के अधीन करने का, और इस अवसर को चलाने का कि क्या वह उच्च न्यायाधिकरण निम्न

न्यायालय के निर्धारण से सहमत होगा या असहमत होगा, और एक निकाय का विशेषाधिकार जो समीक्षा के बिना, अवमानना क्या है, और निर्धारण पर कार्य करता है, उस अवमानना के लिए प्रतिबद्ध है, वारंट पर चरित्र या अवमानना की प्रकृति को निर्दिष्ट किए बिना। लॉर्ड कैर्न्स के अनुसार, दो विशेषाधिकारों में से उत्तरार्द्ध पूर्व की तुलना में उच्च और अधिक महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा कि यह वास्तव में अजीब होगा यदि, हाउस ऑफ कॉमन्स के पूरे विशेषाधिकारों और शक्तियों को स्थानांतरित करने की शक्ति के तहत,

यह केवल एक हिस्सा होगा, और इस विशेषाधिकार और शक्ति का एक तुलनात्मक रूप से महत्वहीन हिस्सा हस्तांतरित किया गया था (1)।

दूसरे शब्दों में, यह निर्णय दर्शाता है कि प्रिवी काउंसिल

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि एक सामान्य वारंट जारी करने और उक्त वारंट के निर्णायक चरित्र पर जोर देने की शक्ति स्वयं ही है।

(1) [1869-71] 3 L.R.P.C. 572,573.

सदन की शक्ति और विशेषाधिकार का एक हिस्सा। फिर भी, यह ए है

एक निम्न न्यायालय का विशेषाधिकार और एक की शक्ति और विशेषाधिकार उच्चतर न्यायालय; और इसलिए, बड़ी शक्ति प्रदान की जाती है

के प्रासंगिक प्रावधान द्वारा अभिप्रेत माना गया है

संविधान अधिनियम, क्योंकि जिस स्थिति को प्रदान करने का इरादा है विक्टोरिया की विधान सभा श्रेष्ठ बी की थी

अदालत। दूसरे शब्दों में, विधान सभा को एक उच्च न्यायालय और उसे प्रदत्त शक्ति और विशेषाधिकार के रूप में माना जाता था

इस प्रकार, लॉर्ड केर्न्स ने स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा पहले के अंग्रेजी निर्णयों के लिए जिसमें के बारे में सवाल

इस शक्ति की सीमा और इसकी प्रकृति पर विस्तार से विचार किया गया था।

समय-समय पर।

अगला प्रिवी काउंसिल निर्णय जिस पर श्री सीरवई ने भरोसा किया

फील्डिंग और अन्य बनाम। थॉमस (1)। उस मामले में, नोवा स्कोटिया को प्रदान की गई शक्ति की सीमा के बारे में सवाल

विधानसभा पर विचार किया जाना था और प्रिवी काउंसिल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त विधानसभा के पास यह निर्णय लेने की वैधानिक शक्ति थी कि उसके सदस्यों पर प्रतिबिंबित मानहानि के लिए रेफरी में भाग लेने के उसके आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना विशेषाधिकार और अवमानना का उल्लंघन है, और उस उल्लंघन को कारावास से दंडित करना है। हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, जिस पर तर्क आगे बढ़ा, या उन तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जिन्होंने कार्रवाई को जन्म दिया। यह लॉर्ड हैल्सबरी द्वारा किया गया केवल एक अवलोकन है जिसे उद्धृत किया जाना चाहिए। उस मामले में लॉर्ड हेल्स ने कहा: अधिकारियों ने बर्डेट बनाम में सारांश दिया। एबॉट (2), और द शेरिफ ऑफ मिडिल सेक्स (3) के मामले में, यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सामान्य अदालतों में अपील किए बिना और उन अदालतों द्वारा इसकी प्रक्रिया को बाधित किए बिना अपनी प्रक्रिया द्वारा अपमान और हिंसा से खुद को बचाने के अधिकार को विवाद की सभी संभावनाओं से परे स्थापित करता है। (1) यह इस अवलोकन का अंतिम भाग है जो श्री सीरवई के मामले को कुछ समर्थन देता है। इस अवलोकन के बारे में हमें केवल इतना कहना है कि यह पहले के दो निर्णयों पर आधारित है जिनकी हम पहले ही जांच कर चुके हैं, और यह कि यह कुछ न्यायाधीशों द्वारा किए गए आपत्तियों के साथ आसानी से सामंजस्यपूर्ण नहीं है, जिन्हें 3 याचिकाकर्ता के कारावास की वैधता की जांच करने के लिए अपनी अधिकारिता के संबंध में इस बिंदु से निपटने का अवसर मिला था, जहां यह प्रतीत होता है कि सदन एच द्वारा जारी वारंट

(1) [1896] L.R.A.C. 600.

(2) 104 ई. आर. 501

(3) 113 ER.419।

(4) [1896] L.R.A.C. 600,609।

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

485

ए ऑफ कॉमन्स सदन द्वारा की गई वापसी पर दिखाई दिया

स्पष्ट रूप से तुच्छ या असाधारण या शानदार कारणों पर आधारित।

अंतिम निर्णय जिस पर श्री सीरवई निर्भर हैं, वह मामला है -

रानी वी। रिचर्ड्स (1)। उस मामले में, उच्च न्यायालय

ऑस्ट्रेलिया को एस के प्रावधानों का अर्थ लगाने के लिए कहा गया था। 49 जो अनुच्छेद के प्रावधानों के समान हैं। 194 (3) हमारे संघ के

बी.

टचूशन। धारा 49 इस प्रकार है:

" सीनेट और प्रतिनिधि सभा, और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति वे होंगी जो संसद द्वारा घोषित की जाती हैं, और जब तक यह घोषित नहीं किया जाता है, तब तक राष्ट्रमंडल की स्थापना में यूनाइटेड किंगडम के संसद के कॉमन्स हाउस और इसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां होंगी।

सी.

जिन बिंदुओं पर विचार किया जाना था उनमें से एक यह था कि: एस द्वारा प्राप्त शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं की प्रकृति और विस्तार। 49 ऑस्ट्रेलिया में सीनेट और प्रतिनिधि सभा पर संविधान का? इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है। फिट्जपैट्रिक और ब्राउन को एडवर्ड रिचर्ड्स ने संसद के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी वारंट के अनुसरण में हिरासत में ले लिया था। ये वारंट सामान्य थे और उन्होंने रिचर्ड्स को उक्त दो व्यक्तियों को अपनी हिरासत में लेने के लिए बाध्य किया। 10 जून, 1955 को अभियोजकों के रूप में फिट्ज़पैट्रिक और ब्राउन के आवेदन पर, ऑस्ट्रेलियाई राजधानी टेरी टोरी (जे. सिम्पसन) के सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त एडवर्ड रिचर्ड्स को निर्देशित बंदी प्रत्यक्षीकरण के दो रिटों के लिए एक आदेश निसी प्रदान किया। 15 जून, 1955 को जे. सिम्पसन एस. के अधीन कार्य कर रहे थे। 13 ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र

एफ.

सुप्रीम कोर्ट एक्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले पर ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के समक्ष बहस की जाए। इस तरह मामला उक्त उच्च न्यायालय के समक्ष गया।

उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एस। 49 एस से स्वतंत्र रूप से संचालित। 50 और इसे संविधान की सामान्य संरचना और उसके तहत शक्तियों के पृथक्करण से प्राप्त निहितार्थों द्वारा नहीं पढ़ा जाना था। निर्माण एस। 49 एस से स्वतंत्र रूप से। 50 , उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सामान्य धन की स्थापना में हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति संसद को और उसके बाद से प्रदान की गई थी। संसद ने उक्त धारा के अर्थ के भीतर कोई घोषणा नहीं की थी, एच. आई. इस बात पर विचार करना आवश्यक था कि सदन की क्या शक्तियां हैं

कॉमन्स निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक समय पर थे

(1) 92 सी. एल. आर. 157

[1965] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

486

यह प्रश्न कि क्या संसद द्वारा एक सामान्य वारंट जारी किया जा सकता है या नहीं, और उच्च न्यायालय ने एस के तहत यह अभिनिर्धारित किया। 49 ऑस्ट्रेलियाई संसद क्या निर्णय लेने के विशेषाधिकार का दावा कर सकती है अवमानना है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यदि अध्यक्ष का वारंट एक स्वीकृत विशेषाधिकार के उल्लंघन के अनुरूप है, तो यह निर्णायक है, इसके बावजूद कि विशेषाधिकार का उल्लंघन सामान्य शब्दों में कहा गया है। दूसरे शब्दों में, यह निर्णय निस्संदेह श्री सीरवई के इस तर्क का समर्थन करता है कि वर्तमान मामले में सदन द्वारा जारी एक सामान्य वारंट नहीं है।

उच्च न्यायालय द्वारा जांच योग्य।

इस निर्णय के प्रभाव की सराहना करने के लिए यह आवश्यक है कि

यह इंगित करें कि जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया का संबंध है, मुद्दा पहले से ही डिल बनाम में प्रिवी काउंसिल के निर्णयों द्वारा आधिकारिक रूप से स्थापित किया जा चुका था। मर्फी (1) और साथ ही ह्यूग ग्लास (2) में। वास्तव में, डिक्सन सी. जे. ने मामले के इस पहलू का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। स्वाभाविक रूप से, उन्होंने ह्यूग ग्लास में लॉर्ड केर्न्स द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है और ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दे को तय करने में उक्त टिप्पणियों का पालन किया है। यही वह आधार है जिसे डिक्सन सी. जे. ने इस प्रश्न से निपटने में अपनाया था। इस दृष्टिकोण को अपनाने के बाद, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने इंग्लैंड की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करना अनावश्यक समझा, क्योंकि इंग्लैंड की स्थिति क्या थी, ह्यूग ग्लास (1) में लॉर्ड केर्न्स द्वारा की गई टिप्पणियों द्वारा ऑस्ट्रेलियाई अदालतों के मार्गदर्शन के लिए निर्णायक रूप से निर्धारित किया गया था। फिर भी, उन्होंने देखा है कि हाउस ऑफ कॉम की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति के बारे में सवाल

मोनस एक ऐसा मामला है जिसे इंग्लैंड में कानून की अदालतों ने अपने फैसले के लिए एक मामले के रूप में माना है, हालांकि उन्होंने कहा है कि "इंग्लैंड में अदालतें राजनीतिक विवाद के बिना न्यायिक निर्णय के एक लंबे पाठ्यक्रम के बाद उस स्थिति में पहुंची हैं। इंग्लैंड में कानून अंततः 1840 के आसपास सुलझा लिया गया था। यह अवलोकन स्पष्ट रूप से मिडिलसेक्स के शेरिफ के मामले को संदर्भित करता है (3)।

को।

विद्वान मुख्य न्यायाधीश के शब्दों को उद्धृत करें: " संक्षेप में यह कहा गया है: संसद के किसी भी सदन में किसी विशेषाधिकार के अस्तित्व का न्याय करना न्यायालयों का काम है, लेकिन निस्संदेह विशेषाधिकार दिए जाने पर, यह सदन का काम है कि वह उस अवसर और उसके प्रयोग के तरीके का न्याय करे। सदन का निर्णय उसके संकल्प और अध्यक्ष के आदेश द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि वारंट उस प्रतिबद्धता के आधार को निर्दिष्ट करता है जो अदालत कर सकती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्धारित करता है कि क्या यह विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए एक आधार के रूप में कानून में पर्याप्त है, लेकिन यदि वारंट इसके आधार पर है।

(1) 15 बी आर 784: (1864) 1 मू. पी. सी (एनएस) 487. (2) [1869-71] 3 एल. आर. पी. सी. 560.

(3) 113 ई. आर. 419.

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

एक स्वीकृत विशेषाधिकार के उल्लंघन के अनुरूप सामना करना पड़ता है

निर्णायक और यह कोई आपत्ति नहीं है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन है

सामान्य शब्दों में कहा गया। कानून के इस कथन में प्रतीत होता है

जिन मामलों द्वारा यह अंततः स्थापित किया गया था, अर्थात्

मिडिलसेक्स के शेरिफ का मामला "(1)। अतः इसके अनुसार भी

मुख्य न्यायाधीश डिक्सन, विशेषाधिकार का अस्तित्व और विस्तार एक है

न्यायसंगत मामला और उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा सकता है

अदालत। यदि वारंट एक बोलने वाला वारंट है, तो न्यायालय कर सकता है

यह निर्धारित करें कि क्या यह राशि के आधार के रूप में कानून में पर्याप्त है

विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए, हालांकि, यदि वारंट बोल नहीं रहा है या

सामान्य तौर पर, अदालत इसके पीछे नहीं जा सकती। हमारी राय में यह होगा

इस निर्णय को दावे के समर्थन के रूप में मानना उचित नहीं होगा।

सदन द्वारा बनाया गया कि इसके सामान्य का निर्णायक चरित्र वारंट इसके विशेषाधिकार का एक हिस्सा है। विद्वान प्रमुख

वास्तव में न्याय ने गुण-दोष के आधार पर प्रश्न पर विचार नहीं किया

स्वयं। उन्होंने महसूस किया कि वे की गई टिप्पणियों से बंधे थे

लॉर्ड कैर्न्स द्वारा और उन्होंने केवल यह बताने का इरादा किया है कि उनके लेख में क्या है

राय शेरिफ के मामले में निर्णय का प्रभाव है मिडिलसेक्स (1)।

इसके अलावा, इस मामले का एक और पहलू है जो नहीं हो सकता है।

नजरअंदाज किया जाए। विद्वान सी. जे. डिक्सन कमियों से निपट रहे थे। एस का निर्देशन। 49 ऑस्ट्रेलियाई संविधान, और ग्वायर के रूप में

सी. जे. ने केंद्रीय प्रांत और बरार अधिनियम में अवलोकन किया है।

नहीं। 1938 (2) का XIV, "कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर निर्णय लिया जाता है।

अन्य न्यायालयों के सदस्यों के साथ अधिक सावधानी से व्यवहार करने की आवश्यकता है

संघीय और प्रांतीय शक्तियों की तुलना में, अंतिम विश्लेषण के लिए निर्णय संविधान के शब्दों पर निर्भर होना चाहिए।

जिसकी अदालत व्याख्या कर रही है; और चूंकि कोई दो संविधान नहीं हैं

समान शब्दों में, यह मान लेना बेहद असुरक्षित है कि ए उनमें से किसी एक पर निर्णय बिना योग्यता के लागू किया जा सकता है

एक और "। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने उल्लेखनीय रूप से कहा है कि

यह ऐसा भी हो सकता है जहाँ उपयोग किए गए शब्द या अभिव्यक्तियाँ हैं

किसी शब्द या वाक्यांश के लिए दोनों ही मामलों में एक ही रंग हो सकता है।

इसके संदर्भ से और तदनुसार विभिन्न इंद्रियों को सहन करें (पी। 38)।

ये अवलोकन विशेष रूप से प्रासंगिक और उपयुक्त हैं।

जिस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके संदर्भ में। हालांकि

एस में प्रयुक्त शब्द। 49 ऑस्ट्रेलियाई संविधान के आधार हैं

जिन बिंदुओं पर हमारे संविधान के प्रासंगिक प्रावधान भिन्न हैं ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। उदाहरण के लिए,

अनुच्छेद. 32 हमारा संविधान। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, अनुच्छेद। 32

भारत के नागरिकों को स्थानांतरित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है

(1) 113 ई. आर. 419.

(2)

(1939] एफ. सी. आर. 18.

ऊपर।

C

.I./65-6 (1965) एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

488

यह न्यायालय। दूसरे शब्दों में, उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए इस न्यायालय में जाने का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। इस प्रावधान के साथ-साथ अनुच्छेद में निहित प्रावधानों का प्रभाव। 226 अनुच्छेद 194 (3) के उत्तरार्द्ध भाग के निर्माण पर हम पहले ही जांच कर चुके हैं, यह हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई संविधान में कुछ प्रावधान हैं जो कुछ अधिकारों को ले सकते हैं जो अनुच्छेद के तहत संरक्षित हैं। 226 हमारे कॉन्स टाइटचूशन का। अनुच्छेद. 32 ऑस्ट्रेलियाई संविधान में कोई प्रति-भाग नहीं मिलता है। इसी तरह, ऑस्ट्रेलियाई संविधान में अनुच्छेद के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है। 211 हमारी और इन विशिष्ट विशेषताओं की उपस्थिति दोनों संबंधित प्रावधानों में उपयोग किए गए समान शब्दों के अर्थ और अर्थ में पर्याप्त अंतर बनाने में योगदान देती है। अर्थात्। , एस. 49 ऑस्ट्रेलियाई संविधान और अनुच्छेद। 194 (3) हमारा। इसके अलावा, घोषणा जिस पर एस। 49 संदर्भित आवश्यक रूप से उसी हद तक पीड़ित नहीं हो सकता है

ऐसी सीमा जो किसी कानून को नियंत्रित करती है जब वह भारतीय विधानमंडलों द्वारा अनुच्छेद के पहले भाग के तहत बनाया जाता है। 194 (3) . हमारे संविधान के प्रासंगिक और भौतिक प्रावधानों की इन विशिष्ट विशेषताओं के कारण उन सावधानी और चेतावनी के शब्दों को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाएगा जो ग्वायर सी. जे. ने 1938 में ही दिए थे। इसलिए, हम सोचते हैं कि यह सुरक्षित या कारण नहीं होगा

डिक्सन सी. जे. द्वारा की गई टिप्पणियों पर बहुत अधिक भरोसा करने में सक्षम।

रिचर्ड्स (1) के मामले में विशेषाधिकारों के प्रश्न से निपटने में।

हालाँकि, इस विषय से अलग होने से पहले, हम संयोग से कर सकते हैं

यह इंगित करें कि लॉर्ड पार्कर सी. जे. द्वारा इन रे हंट (*) में की गई हालिया टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि रिकॉर्ड की सर्वोच्च अदालत द्वारा अवमानना के लिए प्रतिबद्धता के संबंध में भी, अदालत अभ्यास करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए दायर याचिका पर उसका अधिकार क्षेत्र उक्त अवमानना की वैधता पर विचार करने के लिए सक्षम होगा, इस तथ्य के साथ कि प्रतिबद्धता का वारंट सामान्य या अनर्गल है। केनेथ द्वारा आग्रह किए गए तर्कों से निपटना

डगलस हंट जो विन द्वारा अवमानना के लिए किया गया था

पैरी जे., पार्कर सी. जे. ने कहा: " यह हो सकता है कि सही दृष्टिकोण

है, और मुझे लगता है कि मामले इसका समर्थन करते हैं, कि हालांकि यह न्यायालय हमेशा

समिति की वैधता की जांच करने की शक्ति है, यह होगा

हालाँकि, उन्होंने कहा कि उनके सामने मामले में, वह काफी संतुष्ट थे कि आवेदन गुण-दोष के आधार पर विफल होना चाहिए। ये अवलोकन

स्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए,

वेस्टमिंस्टर की एक अदालत के पास वैधता की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है।

प्रतिबद्धता का भले ही प्रतिबद्धता का आदेश दिया गया हो

(2) [1959] 1 क्यू. बी. डी. 378.

(1) 92 सी. एल. आर. 157

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

489

अभिलेख के एक अन्य उच्च न्यायालय द्वारा। यदि यह सही स्थिति है, तो यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है कि वेस्टमिंस्टर के न्यायालय आज हाउस ऑफ कॉमन्स को यह दावा करने का अधिकार स्वीकार करेंगे कि उनके सामान्य वारंट उनके द्वारा अप्रमाणित हैं।

फिर भी, आइए हम इस आधार पर आगे बढ़ें कि प्रासंगिक अधिकार

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किया गया या तो इस आधार पर आधारित है कि संसद के उच्च न्यायालय के एक भाग के रूप में, हाउस ऑफ कॉमन्स एक उच्च न्यायालय है और इस तरह, अवमानना के लिए उसके द्वारा जारी प्रतिबद्धता के लिए एक सामान्य वारंट को वेस्टमिंस्टर हॉल में अदालतों द्वारा निर्णायक माना जाता है, या समय के साथ इस तरह के सामान्य युद्ध के लिए एक निर्णायक चरित्र का दावा करने का अधिकार विशेषाधिकार का एक आकस्मिक और अभिन्न अंग बन गया। तुरंत जो सवाल उठता है वह है: क्या यह अधिकार हो सकता है

ऐसा माना जाता है कि अनुच्छेद के उत्तरार्द्ध भाग के तहत वर्तमान प्रावधानों में सदन को सम्मानित किया गया है। 194 (3) ?

आइए पहले हम सदन की स्थिति से संबंधित आधार लें।

एक सुपीरियर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में कॉमन्स। क्या सदन अनुच्छेद द्वारा प्रस्तुत किसी भी कानूनी कल्पना द्वारा ऐसी स्थिति का दावा कर सकता है।

194 (3) ? हमारी राय में, इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है सकारात्मक में। इस मामले में पिछला विधायी इतिहास

यह इस विचार का समर्थन नहीं करता है कि हमारे राज्य विधानमंडल कमजोर थे

1935 के संविधान अधिनियम के तहत अभिलेख न्यायालय। उक्त अधिनियम की धारा 28 जो इसके विशेषाधिकारों से संबंधित है

संघीय विधानमंडल इस मुद्दे पर प्रासंगिक है। एस. 28 (1) कोर

अनुच्छेद के लिए तालाब। 194 (3) वर्तमान संविधान। धारा 28 (2) यह प्रावधान करता है कि अन्य मामलों में, सदस्यों के विशेषाधिकार

कक्ष ऐसे होंगे जिन्हें समय-समय पर परिभाषित किया जा सके -

संघीय विधानमंडल का अधिनियम और, इस प्रकार परिभाषित होने तक, ऐसा होगा

जैसा कि संघ की स्थापना से ठीक पहले हुआ था

भारतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा आनंदित। यह विवादित नहीं है

कि भारतीय विधानमंडल के सदस्य दावा नहीं कर सकते थे पूर्व में उच्च न्यायालय के सदस्य होने की स्थिति

1935 के अधिनियम के अनुसार। धारा 28 (3) में कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया है

किसी भी मौजूदा भारतीय अधिनियम, और, में कुछ भी होने के बावजूद

इस धारा के पूर्वगामी प्रावधान, इस अधिनियम में कुछ भी नहीं,

संघीय विधानमंडल को प्रदान करने या सशक्त बनाने के रूप में समझा जाए दोनों सदनों में से किसी एक को या दोनों सदनों को एक साथ बैठक करने के लिए,

या विधानमंडल की किसी समिति या अधिकारी पर,

एक न्यायालय, या एक शक्ति के अलावा कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक शक्तियाँ

नियमों या स्थिति का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को हटाने या बाहर करने के लिए

आदेश, या अन्यथा अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार करना। अनुभाग

28 (4) यह हमारे उद्देश्य के लिए भी प्रासंगिक है। यह प्रावधान है कि

दंड [1965] आई. एस. सी. आर. के लिए संघीय विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा बनाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

490

अदालत के समक्ष दोषसिद्धि पर, उन व्यक्तियों का जो देने से इनकार करते हैं

समिति के अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने के लिए जब विधिवत आवश्यकता होती है तो चैंबर की समिति के समक्ष साक्षय या दस्तावेज प्रस्तुत करें। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि ये प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि

भारतीय विधानमंडल अपने लेजिस लेटिव चैंबर की चार दीवारों के बाहर की गई अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति का दावा नहीं कर सकता था। इसी अधिनियम की धारा 71 प्रांतीय विधानमंडलों से संबंधित है और इसके खंड (2), (3) और (4) में समान प्रावधान हैं।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (10 और 11 जीईओ) के बाद। VI,

सी। 20) इस स्थिति को भारत सरकार अधिनियम, 1935 में विभिन्न संशोधन आदेशों द्वारा किए गए संशोधनों द्वारा बदल दिया गया था। तृतीय संशोधन आदेश, 1948 सहित संशोधन आदेशों का परिणाम यह हुआ कि उक्त अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (3) और (4) को हटा दिया गया और उप-धारा (2) में संशोधन किया गया। इस संशोधन का प्रभाव यह था कि संघीय विधान मंडल के सदस्य संघीय विधान मंडल के अधिनियम द्वारा अपने विशेषाधिकारों को परिभाषित किए जाने तक हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों का दावा कर सकते थे जो संघ की स्थापना से ठीक पहले अस्तित्व में थे। हालाँकि, यह उल्लेखनीय है कि धारा 71 की संबंधित उप-धाराओं (3) और (4) को बरकरार रखा गया था। यह प्रश्न कि क्या उप-धारा (3) और (4) को हटाने और धाराओं की उप-धारा (2) के संशोधन का परिणाम है। 28

संघीय विधानमंडल को सदन के समान दर्जा प्रदान करना था कॉमन्स के, वर्तमान रेफरी रेन्स में हमारे निर्णय की मांग नहीं करता है। प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत हो सकता है कि संघीय विधानमंडल के सदस्यों को हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के विशेषाधिकारों का प्रदान करना आवश्यक रूप से संघीय विधानमंडल को सभी उद्देश्यों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं बना सकता है; लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिस पर हमें वर्तमान कार्यवाही में चर्चा करने और निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रांतीय के संबंध में स्थिति

हालाँकि, प्रासंगिक समय पर विधान मंडल बिल्कुल स्पष्ट हैं और स्पष्ट रूप से इस तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी कि जिस समय संविधान पारित किया गया था, उस समय प्रांतीय विधान मंडल हाउस ऑफ कॉमन्स और एक उच्च न्यायालय के दर्जे का दावा कर सकते थे। यही अनुच्छेद की संवैधानिक पृष्ठभूमि है। 194 (3) जहाँ तक प्रांतीय विधानमंडलों का संबंध है। इस पृष्ठभूमि के आलोक में, इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि प्रावधानों का परिणाम निहित है।

अनुच्छेद के अंतिम भाग में। 194 (3) इसका उद्देश्य भारत में राज्य विधानमंडलों को एक उच्च न्यायालय का दर्जा प्रदान करना था।

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

491

इस संबंध में इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि

एक उच्चतर अभिलेख न्यायालय का दर्जा जो हाउस ऑफ कॉमन्स को दिया गया था, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है जिनका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। यह अंग्रेजी इतिहास का एक तथ्य है कि संसद अपने शुरुआती कार्यकाल में न्यायिक कार्यों का निर्वहन कर रही थी। यह इंग्लैंड में ऐतिहासिक और संवैधानिक दोनों इतिहास का एक तथ्य है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स अभी भी देश का सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है। यह आज भी संवैधानिक इतिहास का एक तथ्य है कि दोनों सदनों के पास महाभियोग चलाने और उसे लागू करने की शक्तियां हैं। हम सोचते हैं कि यह स्पष्ट है कि इन ऐतिहासिक तथ्यों को भारत में किसी भी कानूनी कल्पना द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है। उचित है।

विधायी प्रावधान कभी-कभी कानूनी कल्पनाओं को पेश करते हैं, लेकिन इस तरह की कल्पनाओं को पेश करने के लिए कानून की शक्ति की एक सीमा है। कानून कानूनी अधिकारों और दायित्वों के बारे में और उस ओर से किए गए प्रावधानों के पूर्वव्यापी संचालन के बारे में

कल्पनाओं को पेश कर सकता है; लेकिन कानूनी कल्पना शायद ही किसी एक से ऐतिहासिक तथ्यों को पेश कर सकती है।

दूसरे देश में।

इसके अलावा, उच्चतम अभिलेख न्यायालय की स्थिति के संबंध में

जो हाउस ऑफ कॉमन्स को दिया गया है, वहाँ है

अंग्रेजी इतिहास का एक और हिस्सा जिसे याद रखना आवश्यक है। हाउस ऑफ कॉमन्स को राजा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के खिलाफ अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा, और न्यायपालिका को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा राजा का एक प्राणी माना जाता था और जूडिका स्वभाव स्पष्ट रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अधीनस्थ था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का मुख्य विरोधी था। इससे एक ओर हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरी ओर राजा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। भारत में ऐसी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है और जिस आधार पर हाउस ऑफ कॉमन्स ने न्यायालय की अधिकारिता से इनकार करने के लिए संघर्ष किया, उसके लिए कोई ऐतिहासिक औचित्य नहीं हो सकता है; यह मामले का एक और पहलू है जो इस सवाल पर विचार करने में प्रासंगिक है कि क्या वर्तमान मामले में सदन उच्च न्यायालय के दर्जे का दावा कर सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदन के पास इसके लिए दंड देने की शक्ति है

अपने कक्ष के बाहर की गई अवमानना, और उस दृष्टिकोण से यह अभिलेख न्यायालय के अधिकार में से एक का दावा कर सकता है। ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जोविट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश के अनुसार कानून, एक ऐसा न्यायालय है जिसमें अधिनियमों और न्यायिक कार्यवाही को स्थायी स्मृति और गवाही के लिए दर्ज किया जाता है, और जिसे अपने अधिकार की अवमानना के लिए जुर्माना लगाने और कैद करने की शक्ति है। सदन और वास्तव में भारत की सभी विधानसभाओं ने कभी भी किसी भी न्यायिक कार्य का निर्वहन नहीं किया और उनकी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि इस दावे का समर्थन नहीं करती है कि वे (1965) आई. एस. सी. आर. हो सकते हैं।

किसी भी अर्थ में अभिलेख न्यायालय माना जाता है। यदि ऐसा है, तो जिस आधार पर अंग्रेजी अदालतें हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी सामान्य वारंट को इस आधार पर मानने के लिए सहमत हुईं कि यह एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी वारंट था, वर्तमान मामले में अनुपस्थित है, और इसलिए, यह तर्क देना अनुचित होगा कि सामान्य वारंट के लिए एक निर्णायक चरित्र का दावा करने की प्रासंगिक शक्ति, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स, समझौते द्वारा, निहित माना जाता है, सदन में निहित है। मामले के इस दृष्टिकोण पर, सदन द्वारा किए गए दावे को खारिज किया जाना चाहिए।

हालाँकि, यह मानते हुए कि सदन द्वारा दावा किया गया अधिकार कर सकता है

हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों के एक अभिन्न अंग के रूप में माना जाए, तो विचार करने वाला प्रश्न यह होगा कि क्या ऐसा अधिकार अनुच्छेद के उत्तरार्ध भाग द्वारा सदन को प्रदान किया गया है। 194 (3) . इस वैकल्पिक परिकल्पना पर, यह विचार करना आवश्यक है कि क्या विशेषाधिकार का यह हिस्सा हमारे संविधान के भौतिक प्रावधानों के अनुरूप है। हम पहले ही अनुच्छेद 32 और 226 का उल्लेख कर चुके हैं। आइए हम अनुच्छेद को लेते हैं। 32 क्योंकि यह भारत के नागरिकों को इस न्यायालय में जाने के लिए प्रदत्त मौलिक अधिकार के महत्व को स्पष्ट रूप से सामने लाता है यदि उनके मौलिक अधिकारों का या तो विधानमंडल या कार्यपालिका द्वारा उल्लंघन किया जाता है। अब, अनुच्छेद। 32 किसी भी अतिक्रमण के संबंध में कोई अपवाद नहीं है, और यह तर्क देना अतार्किक प्रतीत होगा कि भले ही सदन द्वारा दावा किया गया अधिकार नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, पीड़ित नागरिक अनुच्छेद के तहत सफलतापूर्वक इस न्यायालय का रुख नहीं कर सकता है। 32. अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को दिए गए पूर्ण संवैधानिक अधिकार के लिए। 32 इस देश के विधानमंडलों में निहित किसी भी शक्ति या विशेषाधिकार के संदर्भ में कोई अपवाद नहीं किया जा सकता है और संविधान द्वारा कोई अपवाद करने का इरादा नहीं है।

जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि हम इसमें प्रवेश करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

उन मामलों में सभी मौलिक अधिकारों की प्रयोज्यता के बारे में एक सामान्य चर्चा जहां इस देश के किसी भी व्यक्तिगत नागरिक के खिलाफ विधायी शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है, और यह कि हम इस मामले को उस अनुच्छेद के आधार पर निपट रहे हैं। 19 (1) (क) लागू नहीं होता है और अनुच्छेद। 21 डॉक्स। यदि कोई अवसर आता है, तो यह विचार करना आवश्यक हो सकता है कि अनुच्छेद क्या है। 22 विपरीत हो सकता है

अनुच्छेद के तहत शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग से प्रभावित। 194 (3) . लेकिन, अभी हम अनुच्छेद पर विचार कर सकते हैं। 20. अगर अनुच्छेद। 21 लागू होता है, अनुच्छेद। 20 संभवतः लागू हो सकता है, और प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, यदि

नागरिक शिकायत करता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था या अनुच्छेद के तहत। 20 या अनुच्छेद। 21 , क्या वह इसे हिला सकता है या नहीं।

अनुच्छेद के तहत न्यायालय। 32 ? मुद्दा बनाने के उद्देश्य से

जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अनुच्छेद की प्रयोज्यता।

21 स्वयं विशेष संदर्भ (गजेंद्रगढ़कर सी. जे.)

एक पर्याप्त है। यदि कोई नागरिक इस न्यायालय का रुख करता है और शिकायत करता है कि उसका

न्यूनतम

अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार। 21 उल्लंघन किया गया था, यह होगा

स्पष्ट रूप से इस न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह इसके गुण-दोष की जांच करे

कहा गया विवाद, और यह अनिवार्य रूप से सवाल उठाता है कि

क्या नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली गई है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। वास्तव में यह

बी.

प्रश्न पर वास्तव में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था

पंडित शर्मा (1)। यह सच है कि जवाब पक्ष में दिया गया था।

पैन

विधायिका का; लेकिन यह उद्देश्य के लिए पूरी तरह से महत्वहीन है

वर्तमान चर्चा। 1101 यदि किसी मामले में, द्वारा लगाया गया आरोप

डब्ल्यू. डब्ल्यू. डब्ल्यू

नागरिक यह है कि उसे अपनी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया है

कानून के साथ, लेकिन मनमौजी या दुर्भावनापूर्ण कारणों से, यह न्यायालय

एस.

उक्त विवाद की वैधता की जांच करनी होगी, और यह

ऐसे मामले में यह कहने का कोई जवाब नहीं होगा कि वारंट जारी किया गया है। नागरिक के खिलाफ एक सामान्य वारंट है और एक सामान्य वारंट होना चाहिए।

आगे की सभी न्यायिक जांच और जांच को रोकें। हमारी राय में, "

इसलिए, मौलिक संवैधानिक अधिकार का प्रभाव अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों पर फेंका गया। 32 निर्माण के बारे में

डी.

अनुच्छेद का अंतिम भाग। 194 (3) निर्णायक रूप से इस दृष्टिकोण के खिलाफ है कि ए

सदन द्वारा शक्ति या विशेषाधिकार का दावा किया जा सकता है, हालांकि यह हो सकता है

अनुच्छेद के साथ असंगत। 21. इस संबंध में, यह प्रासंगिक हो सकता है

यह याद रखने के लिए कि वे नियम जो सदन को विनियमित करने के लिए बनाने हैं इसकी प्रक्रिया और इसके व्यवसाय का संचालन विषय होना चाहिए।

ई. अनुच्छेद के तहत संविधान के प्रावधानों के लिए। 208 (1) .

फिर, अनुच्छेद का मामला लीजिए। 211 और देखें कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा

जिस सदन के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, उसके दावे पर हो। अगर

सदन के दावे को बरकरार रखा जाता है, इसका मतलब है कि सदन जारी कर सकता है एक न्यायाधीश के खिलाफ सामान्य वारंट और कोई न्यायिक जांच नहीं हो सकती है

ऐसे वारंट की वैधता के संबंध में अभिनिर्धारित। यह वास्तव में होगा

एफ अजीब बात है कि न्यायपालिका को विचार करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए

हमारे विधानमंडलों के विधायी अधिनियमों की वैधता, लेकिन चाहिए

कार्रवाई की वैधता की जांच करने से रोका जाए

विधायिकाओं द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण

नागरिकों को। . यदि सिद्धांत है कि सामान्य वारंट होना चाहिए। निर्णायक के रूप में माना जाता है स्वीकार किया जाता है, तो, जैसा कि हम पहले से ही कर चुके हैं

जी.

केटेड, न्यायिक स्वतंत्रता की मूल अवधारणा पूर्व होगी

बहुत गंभीर खतरे के लिए प्रस्तुत किया; और इसलिए अनुच्छेद का प्रभाव। 211 पर अनुच्छेद की व्याख्या। 194 (3) इस विशेष के संबंध में

शक्ति फिर से निर्णायक रूप से द्वारा उठाए गए विवाद के खिलाफ है

घर।

; .....

यदि अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालयों की शक्ति। 226 और लेखक

एच.

अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय का अधिकार। 32 किसी भी अपवाद के अधीन नहीं हैं,

तब यह तर्क देना व्यर्थ होगा कि एक नागरिक स्थानांतरित नहीं कर सकता है

(1) [1959] सप. 1 एससीआर 806।

सातवाँ

.....

. " [1965] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

494

उच्च न्यायालय या इस न्यायालय में भी अपने अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए

ऐसे मामले जहां उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो। उस ओर से न्यायिक शक्ति की आवश्यकता को अनिवार्य रूप से और अनिवार्य रूप से नागरिक में उस ओर से न्यायालय में जाने के अधिकार के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए; अन्यथा उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति लगभग अर्थहीन हो जाएगी। यह नहीं भूलना चाहिए कि उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय को प्रदत्त न्यायिक शक्ति नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है, और इसलिए, उक्त न्यायिक शक्ति के अस्तित्व में अनिवार्य रूप से नागरिक का अधिकार शामिल है।

किसी उचित मामले में उक्त शक्ति के समक्ष अपील करना।

संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम, 1770 (1) में, प्रिवी काउंसिल को इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या हाउस ऑफ कॉमन्स संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम, 1770 के विपरीत कार्य करेगा, यदि वह संसद में किसी भाषण या कार्यवाही के संबंध में संसद सदस्य के खिलाफ रिट के मुद्दे को अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन के रूप में मानता है। उक्त प्रश्न ने कुछ संदेह को जन्म दिया था, और इसलिए, इसे अपनी राय के लिए प्रिवी काउंसिल को भेजा गया था। प्रिवी काउंसिल द्वारा व्यक्त राय इसके पक्ष में थी

संसद। उक्त सीमित प्रश्न पर अपने उत्तर को सीमित करते हुए, प्रिवी काउंसिल ने यह जोड़ने की सावधानी बरती कि "वे कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं कि क्या परिचयात्मक पैराग्राफ में संदर्भित कार्यवाही 'संसद में एक कार्यवाही' थी, एक ऐसा प्रश्न जो उनके सामने नहीं रखा गया

था, और न ही इस सवाल पर कि क्या केवल एक रिट का मुद्दा किसी भी परिस्थिति में विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा।" " प्रिवी काउंसिल की ओर से बोलने वाले विस्काउंट साइमंड्स ने कहा, "इस मार्ग को अपनाने में, वे महामहिम की प्रजा के अपने गलतियों के निवारण के लिए उसकी अदालतों का सहारा लेने के अपरिहार्य अधिकार के प्रति सचेत रहे हैं और किसी भी कारण की सुनवाई में पूर्वाग्रह नहीं करेंगे जिसमें एक वादी ने राहत मांगी हो।" जिस अविच्छेद्य अधिकार का विस्काउंट साइमंड्स ने उल्लेख किया है, वह अनुच्छेद के प्रावधानों में निहित है। 226 और अनुच्छेद। 32 , और इसका अस्तित्व सदन द्वारा दावा किए गए अधिकार के साथ स्पष्ट रूप से असंगत है कि एक सामान्य वारंट को कानून के सभी न्यायालयों में निर्णायक माना जाना चाहिए; यह सदन द्वारा किए गए दावे के साथ भी समान रूप से असंगत होगा कि केशव सिंह ने अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का रुख करके अवमानना की है। 226 .

इस संबंध में, 1704 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित एक संकल्प का उल्लेख करना दिलचस्प होगा। इस संकल्प से, यह घोषित किया गया था कि निर्वाचकों को कानून की सामान्य अदालतों में मुकदमा चलाने से रोकना, जहां वे अपने मतदान के अधिकार से वंचित हैं, और वकीलों, वकीलों, सलाहकारों और सार्जेंटों को ऐसे मामलों में अनुरोध करने, मुकदमा चलाने और अभिवचन करने से डराना, ऐसा करना उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन है।

(1) (1958) ए. सी. 331

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

495

हाउस ऑफ कॉमन्स, एक मैनिफेस्ट है। कानून को नियंत्रित करने, न्याय के मार्ग में बाधा डालने और अंग्रेजों की संपत्ति को हाउस ऑफ कॉमन्स के मनमाने मतों के अधीन करने की शक्ति ग्रहण करना। यह उसी वर्ष हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित प्रस्ताव के जवाब में था जिसमें संकेत दिया गया था कि सदन के प्रस्ताव द्वारा उल्लिखित मामलों में अनुमोदन के लिए अदालत का रुख करने में किसी भी व्यक्ति के आचरण को सदन की अवमानना के बराबर माना जाएगा। ये प्रस्ताव और जवाबी प्रस्ताव उन अशांत दिनों के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बीच चल रहे भयंकर संघर्ष को केवल दर्शाते हैं; लेकिन इस विवाद का दिलचस्प हिस्सा यह है कि अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सामान्य अदालतों के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स की क्षमता के संबंध में कोई सवाल गया होता, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निस्संदेह इस तरह के दावे को खारिज कर दिया होता, और यह हाउस ऑफ कॉमन्स की बुनियादी आशंका थी।

जो उन न्यायालयों की अधिकारिता को मान्यता देने से इनकार करने के लिए जिम्मेदार था जो अंतिम विश्लेषण में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अधीनस्थ थे।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 30 प्रदान करती है

सभी अधिवक्ताओं पर सभी न्यायालयों में वकालत करने का वैधानिक अधिकार शामिल है

उच्चतम न्यायालय, किसी भी न्यायाधिकरण या व्यक्ति के समक्ष कानूनी रूप से

साक्षय लेने के लिए अधिकृत, और किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष या

समय लागू होने पर अभ्यास करने का अधिकार है। बार की धारा 14 परिषद अधिनियम एक समान अधिकार को मान्यता देता है। अगर किसी नागरिक को अधिकार है

उसके मौलिक अधिकारों का, अधिवक्ता का वैधानिक अधिकार नागरिक को कदम उठाने में सहायता करें और निधि के प्रवर्तन में सहायता करें

नागरिकों के मानसिक अधिकार। इस पर जोर देने की शायद ही आवश्यकता हो

कि गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में

नागरिक कानूनी पेशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,

और इसलिए, मामलों से निपटने के लिए न्यायपालिका के अधिकार के रूप में

अनुच्छेद के तहत उनके सामने लाया गया। 226 या अनुच्छेद। 32 उप नहीं हो सकता है

अनुच्छेद के अधीन सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबद्ध। 194 (3) ,

इसलिए न्यायपालिका और अधिकारों को स्थानांतरित करने के लिए नागरिकों के अधिकार

उस प्रक्रिया में सहायता करने के लिए अधिवक्ताओं को अनियंत्रित रहना चाहिए

अनुच्छेद 194 (3)। यह लागू करने के लिए एक एकीकृत योजना है।

मौलिक अधिकार और इसमें कानून के शासन को बनाए रखने के लिए

देश। इसलिए, हमारा निष्कर्ष यह है कि विशेष अधिकार

जिसे सदन अपनी शक्ति का अभिन्न अंग होने का दावा करता है या

विशेषाधिकार संविधान के भौतिक प्रावधानों के साथ असंगत है शिक्षा और इसके तहत शामिल नहीं माना जा सकता है

अनुच्छेद का अंतिम भाग। 194 (3) .

[

1965] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

496

इस संबंध में, हमें यह जोड़ना चाहिए कि कोई सार नहीं है

श्री सीरवई द्वारा की गई शिकायत में कि केशव सिंह ने लखनऊ पीठ के समक्ष उनके द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में सदन को शामिल करने में अवैध रूप से काम किया। हमारी राय में, यह नहीं कहा जा सकता है कि केशव सिंह अनुचित तरीके से सदन में शामिल हुए थे, क्योंकि उनके लिए इस आधार पर सदन में शामिल होने का अधिकार था कि उनकी प्रतिबद्धता सदन द्वारा पारित आदेश पर आधारित थी, और उस अर्थ में सदन उनकी प्रतिबद्धता के लिए जिम्मेदार था, और उस पर उनका नियंत्रण था (राजा बनाम। द अर्ल ऑफ क्रेव, एक्स पार्ट सेक्गोम (1) और द किंग बनाम। गृह मामलों के राज्य सचिव, पूर्व पक्ष ओ 'ब्रायन (2)। इसके अलावा, यह तथ्य कि केशव सिंह अपनी याचिका में सदन में शामिल हुए, न्यायाधीशों, अधिवक्ता और पक्षकार के खिलाफ उनकी कथित अवमानना के लिए कार्रवाई करने की सदन की शक्ति के मुख्य प्रश्न को निर्धारित करने में कोई प्रासंगिकता या भौतिकता नहीं हो सकती है।

जैसा कि हमने इस राय की शुरुआत में संकेत दिया है,

बात अनुच्छेद के उत्तरार्द्ध भाग की रचना की है। 194 (3) , और उस सहायता के आलोक में जो हमें संविधान के अन्य प्रासंगिक और भौतिक प्रावधानों से प्राप्त करनी चाहिए, यह अभिनिर्धारित करना आवश्यक है कि सदन द्वारा दावा की गई विशेष शक्ति कि उसके सामान्य वारंट को निर्णायक माना जाना चाहिए, अनुच्छेद के उत्तरार्ध का विषय नहीं माना जा सकता है। 194 (3) . इस संबंध में, हम संयोग से देख सकते हैं कि यह कुछ है

क्या संदेह है कि क्या एक सामान्य अनकमिंग जारी करने की शक्ति है

सदन द्वारा दावा किया गया वारंट एस के अनुरूप है। 554 (2) (बी) और एस। 555 दंड प्रक्रिया संहिता। ऐसा प्रतीत होता है कि

इंग्लैंड, अभिलेख की उच्च अदालतों द्वारा अवमानना के लिए प्रतिबद्धता के संबंध में सामान्य वारंट जारी किए जाते हैं, और इस बिंदु पर पूरा विरोध, इसलिए, इस सिद्धांत पर आधारित है कि

एक सामान्य वारंट जारी करने का अधिकार जो इसके संबंध में मान्यता प्राप्त है अभिलेख के वरिष्ठ न्यायालयों को हाउस ऑफ कॉमन्स में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि संसद के उच्च न्यायालय के एक भाग के रूप में यह स्वयं एक उच्चतर अभिलेख न्यायालय है।

इस विषय से अलग होने से पहले, दो सामान्य विचार हैं

जिनका हमें विज्ञापन करना चाहिए। श्री सीरवई ने हमारे समक्ष यह आग्रह किया है कि अवमानना के संबंध में एक भ्रामक सामान्य वारंट जारी करने का सदन द्वारा दावा किया गया अधिकार सदन के प्रभावी कामकाज के लिए एक आवश्यक अधिकार है, और उन्होंने हमें इस मामले से निपटने के लिए कहा है। यह सच है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिकार को इंग्लैंड की अदालतों द्वारा समझौते या परंपरा या सौहार्द के विचारों द्वारा मान्यता दी गई है; लेकिन हम सोचते हैं कि यह कहना पूरी तरह से सही नहीं है कि प्रत्येक

(1) (1910) 2 के. बी. 576.

(2)

[1923) 2 के. बी. 361

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

497

अमेरिकी विधानमंडलों का मामला। अनुच्छेद 1, धारा 5 अमेरिकी संविधान अमेरिकी विधायिका को प्रदान नहीं करता है।

अपने स्वयं के चुनाव, रिटर्न और योग्यताओं का न्यायाधीश सदस्य, और प्रत्येक का बहुमत एक कोरम का गठन करेगा

व्यवसाय; लेकिन एक छोटी संख्या दिन-प्रतिदिन स्थगित हो सकती है,

और अनुपस्थित मेम की उपस्थिति को मजबूर करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है बर्ज़, इस तरह से, और ऐसे दंड के तहत जो प्रत्येक सदन कर सकता है

प्रदान करें। प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही के नियम निर्धारित कर सकता है।

अपने सदस्यों को अव्यवस्थित व्यवहार के लिए दंडित करता है, और

दो-तिहाई की सहमति, एक सदस्य को निष्कासित करें। अवमानना कॉम एक नागरिक द्वारा विधायी कक्ष की चार दीवारों के बाहर बांध दिया गया

जो सदन का सदस्य नहीं है, वह अमेरिकी विधानमंडल के न्यायशास्त्र से बाहर प्रतीत होता है। जैसा कि विलिस ने देखा है,

अवमानना के लिए सजा स्पष्ट रूप से एक न्यायिक कार्य है; फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में, कांग्रेस अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है क्योंकि यह अपने सदस्यों के बीच व्यवस्था बनाए रखने, उनकी उपस्थिति को मजबूर करने, दूसरों द्वारा हमलों या अशांति से बचाने (बदनामी और मानहानि को छोड़कर), चुनाव मामलों और महाभियोग के आरोपों का निर्धारण करने और विधायी कार्य की सहायता के लिए अन्य विभागों के बारे में सटीक जानकारी देने से संबंधित है।

यह (1)। किसी ने कभी यह सुझाव नहीं दिया है कि अमेरिकी कांग्रेस प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है क्योंकि यह नहीं किया गया है

हमारे सामने सदन द्वारा दावा की गई विशेष शक्ति से लैस।

भारत में, इसके अलावा कई राज्य विधानमंडल हैं -

संसद के सदन। यदि हमारे समक्ष सदन द्वारा दावा की गई शक्ति को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि इसके प्रयोग से विसंगत परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। यदि विधानमंडलों के सदस्यों को प्रदत्त पूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर, एक विधानमंडल का कोई सदस्य अपने विधानमंडल में भाषण देता है जिसे दूसरा विधानमंडल सदन अपनी अवमानना के बराबर मानता है, तो स्थिति क्या होगी? बाद वाला विधायी सदन एक सामान्य वारंट जारी कर सकता है और सदस्य को दंडित कर सकता है।

अवमानना में होने का आरोप लगाया जाता है, और इस तरह की शक्ति के स्वतंत्र प्रयोग से बहुत शर्मनाक परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। यही एक कारण है कि संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक समझा कि विधानमंडलों को अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं के संबंध में उचित समय पर कानून बनाना चाहिए, क्योंकि वे जानते थे कि जब ऐसे कानून बनाए जाएंगे, तो वे मौलिक अधिकारों के अधीन होंगे और भारत में अदालतों द्वारा जांच के लिए खुले होंगे। इस तरह के कानूनों के निर्माण तक; अनुच्छेद के उत्तरार्ध भाग द्वारा शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान की गई थी। 194 (3) . जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं।

(1) विलिस, संवैधानिक कानून, पी। 145 .

इस बात पर जोर दिया कि लेख के इस हिस्से का निर्माण इसके भीतर है

इस न्यायालय की अधिकारिता, और इस भाग का अर्थ लगाने में, हमारे पास है

के अन्य प्रासंगिक और भौतिक प्रावधानों को ध्यान में रखना

संविधान। श्री सेक्रवई ने निस्संदेह हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि लोकसभा और राज्य सभा की विशेषाधिकार समितियों ने 22 मई, 1954 को एक रिपोर्ट को स्वीकार किया है, जिसमें विधायी शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग के परिणामस्वरूप किसी भी शर्मनाक या विसंगत स्थितियों से बचने के लिए

संबंधित निकायों के सदस्य, और हमें बताया गया कि लगभग सभी विधानमंडलों द्वारा इसी तरह के प्रस्तावों को अपनाया गया है

भारत। लेकिन ये सहमति के मामले हैं, न कि कानून के मामले, और यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि अगर वही राजनीतिक दल

सभी राज्यों में सत्ता में नहीं होने के कारण, ये समझौते स्वयं पूरी तरह से प्रभावी साबित नहीं हो सकते हैं। मामले के उनके पहलू के अलावा, अनुच्छेद 194 (3) के प्रासंगिक खंड का अर्थ लगाने में, ये समझौते कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते हैं।

श्री सीरवई ने अपनी दलीलों के दौरान काफी कुछ कहा।

इस तथ्य पर जोर देते हुए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में, उच्च न्यायालय को अंतरिम जमानत देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह माना जा सकता है कि इंग्लैंड में यह माना जाता है कि अवमानना के आधार पर हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ शुरू की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही के संबंध में, अदालतों द्वारा जमानत नहीं दी जाती है। बेशक, पिछली शताब्दी के दौरान और इस तरह के बंदी प्रत्यक्षीकरण में आगे बढ़ते हैं। रिटर्न हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा कानून के अनुसार किए जाते हैं, लेकिन "सामान्य नियम यह है कि जो पक्ष अवमानना के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें जमानत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।" लेकिन यह मुश्किल है।

इस तर्क को स्वीकार करें कि भारत में इस मामले में स्थिति बिल्कुल समान है। अगर अनुच्छेद। 226 प्रतिबद्धता के आदेश की वैधता से निपटने के लिए न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, भले ही प्रतिबद्धता का आदेश सदन द्वारा दिया गया हो, यह कैसे कहा जा सकता है कि न्यायालय को ऐसी कार्यवाही में अंतरिम आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है? जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उड़ीसा राज्य बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। मदन गोपाल रूंगटा और अन्य (1), एक अंतरिम राहत केवल मुख्य राहत की सहायता में और सहायक के रूप में दी जा सकती है, जो किसी मुकदमे या कार्यवाही में अपने अधिकारों के अंतिम निर्धारण पर पक्ष को उपलब्ध हो सकती है। वास्तव में, जैसा कि मैक्सवेल ने देखा है, जब कोई अधिनियम कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, तो यह निहित रूप से ऐसे सभी कार्यों को करने या ऐसे साधनों को नियोजित करने की शक्ति भी प्रदान करता है, जो निम्नलिखित हैं -

इसके निष्पादन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक (2)। ऐसा होने पर, तर्क दंड प्रक्रिया के प्रासंगिक प्रावधानों पर आधारित था।

(1) [1952] एस. सी. आर. 28

(2) मैक्सवेल ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स, 11 वां संस्करण।, पी। 350 .

विशेष संदर्भ (गजेंद्रगडकर सी. जे.)

499

लाला जयराम दास और अन्य में संहिता और प्रिवी काउंसिल का निर्णय v. राजा सम्राट (1) की कोई सहायता नहीं है।

हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम प्रश्नों से निपट रहे हैं।

अधिकारिता की स्थिति और ऐसी अधिकारिता के प्रयोग की औचित्य या तर्कसंगतता से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा, किसी उच्चतर अभिलेख न्यायालय के मामले में, यह न्यायालय को विचार करना है कि क्या कोई मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं। सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय के विपरीत, उच्च न्यायालय को अपने लिए अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रश्न निर्धारित करने का अधिकार है। हैल्सबरी कहते हैं, "पहली नजर में कोई भी मामला उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं माना जाता है जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं दिखाया जाता है, जबकि कुछ भी निम्न अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है जब तक कि कार्यवाही के सामने यह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जाता है कि विशेष मामला विशेष अदालत के

संज्ञान में है।" (2)। इसलिए, हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि अंतरिम जमानत के आदेश को पारित करते समय, उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र को पार करने के लिए कहा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप विचाराधीन आदेश अमान्य है। इसके अलावा, आदेश की वैधता का इस सवाल से कोई संबंध नहीं है कि क्या आदेश पारित करते समय न्यायाधीशों ने सदन की अवमानना की है।

इस मामले का एक और पहलू है जिस पर हम विचार कर सकते हैं।

संयोग से संदर्भ लें। हम पहले ही देख चुके हैं कि वर्तमान मामले में, जब 19 मार्च, 1964 को दोपहर 2 बजे लखनऊ पीठ के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत की गई थी, तो दोनों पक्षों ने

उनके संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा पेश किया गया और इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि आवेदन पर उसी दिन दोपहर 3 बजे सुनवाई की जानी चाहिए, और फिर भी जिस सदन को रिट याचिका में शामिल किया गया था और अन्य प्रतिवादी जिनके लिए श्री कपूर पहले चरण में उपस्थित हुए थे, उस समय अनुपस्थित थे। इस प्रकार न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिका पर उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को उन नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए जिनका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है और यह जमानत का यह बाद का आदेश है जिसके कारण बाद के घटनाक्रम हुए हैं। अन्य में

शब्द, वारंट जारी करने की त्वरित कार्रवाई करने से पहले

लखनऊ पीठ के न्यायाधीशों के खिलाफ, सदन ने समझौता नहीं किया

समान अभ्यास के लिए फॉर्म जो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है

एक शताब्दी से अधिक समय तक पालन किया और इसका निर्देश नहीं दिया या तो रिटर्न दाखिल करने के लिए या ऐसा करने के लिए समय मांगने के लिए वकील, और

अनुरोध है कि अदालत को वापसी होने तक अपने हाथों को रोक देना चाहिए

दाखिल किया। यह विवादित नहीं है कि जब भी प्रतिबद्धता आदेश पारित होते हैं

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा एड को इंग्लैंड में पहले चुनौती दी गई है

(1) 72 आई. ए. 120।

(2) हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल्यूम। 9 , पी। 349 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वेस्टमिन्स्टर के न्यायालयों में, सदन हमेशा एक वापसी करता है और यदि उसके द्वारा जारी वारंट सामान्य और अनकहा है, तो इसे वापसी में इस प्रकार कहा जाता है और वारंट प्रस्तुत किया जाता है। यदि वर्तमान कार्यवाहियों में इस मार्ग को अपनाया गया होता, तो यह कहा जा सकता था कि सदन अपनी शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए, उस पैटर्न के अनुसार बना, जो परंपरा के अनुसार, पिछली शताब्दी के दौरान इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स ने हमेशा अपनाया है और उससे भी अधिक; लेकिन ऐसा नहीं किया गया था; और जैसे ही सदन को पता चला कि जमानत देने का आदेश पारित किया गया था, वह इस बात पर सहमत होने के लिए आगे बढ़ा कि क्या न्यायाधीश स्वयं अवमानना में नहीं थे। इन संकीर्ण तथ्यों पर यह विचार रखना संभव होगा कि न्यायाधीशों द्वारा की गई अवमानना का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसे ध्यान में रखते हुए

तथ्य यह है कि श्री कपूर सभी प्रत्यर्थियों की ओर से दोपहर 2 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे और इस बात पर सहमत हुए थे कि मामला दोपहर 3 बजे उठाया जाना चाहिए, यह उनका कर्तव्य था कि वे दोपहर 3 बजे उपस्थित हों और या तो विवरणी दाखिल करें या सदन की ओर से ऐसा करने के लिए समय मांगें। यदि सदन ने श्री कपूर को यह कदम उठाने का निर्देश नहीं दिया और अदालत को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि श्री कपूर क्यों पेश नहीं हुए, तो याचिका पर नोटिस जारी करने और याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए अदालत को दोषी ठहराना शायद ही उचित होगा। इन कार्यवाहियों में हमारे लिए यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि श्री कपूर और सदन के बीच क्या हुआ और श्री कपूर दोपहर 3 बजे सदन और अन्य प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्यों उपस्थित नहीं हुए। श्री कपूर के दोपहर 3 बजे अदालत के समक्ष पेश होने में विफलता ने अदालत के समक्ष कार्यवाही में एक दुर्भाग्यपूर्ण तत्व पेश किया है और अदालत द्वारा पारित आदेश के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है। एक तथ्य स्पष्ट है, और वह यह है कि जब न्यायालय ने नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया, तो उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस वारंट के तहत याचिकाकर्ता को सजा सुनाई गई थी, वह एक सामान्य वारंट था और अदालत को कोई सुझाव नहीं दिया गया था कि ऐसे वारंट के मामले में अदालत को जमानत का कोई आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था। सदन के मामले से निपटने में इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि न्यायाधीशों ने

याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करके अवमानना की है। लेकिन हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम अपने उत्तरों को मामले के इस संकीर्ण दृष्टिकोण पर आधारित करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, क्योंकि प्रश्न 3 और 5 काफी व्यापक हैं और उन्हें व्यापक आधार पर जवाब देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इस व्यापक पहलू से उत्पन्न होने वाले भौतिक प्रश्नों पर हमारे सामने पूरी तरह से बहस की गई है, और यह स्पष्ट है कि वर्तमान संदर्भ देते समय, राष्ट्रपति चाहते हैं कि हम सभी प्रश्नों के अपने उत्तर दें और किसी भी प्रासंगिक पहलू को हमारे विचार से बाहर न करें।

501

कि ये पहलू वर्तमान कार्यवाहियों में अब तक हुए विशेष तथ्यों पर सख्ती से नहीं उठेंगे।

अंत में, हमें इसे अपने पूरे डिस्कस में जोड़ना चाहिए।

क्योंकि हमने लगातार यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जिस मुख्य बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह यह दावा करने का सदन का अधिकार है कि सदन की चार दीवारों के बाहर सदन के सदस्य नहीं होने वाले एक नागरिक द्वारा किए गए अपने प्रलोभन के संबंध में उसके द्वारा जारी एक सामान्य वारंट निर्णायक है, क्योंकि इस दावे पर सदन ने यह विचार रखने का विकल्प चुना है कि न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और पक्ष ने अल्लाह की लखनऊ पीठ के समक्ष लंबित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अपने आचरण के संदर्भ में अवमानना की है। खराब उच्च न्यायालय। चूँकि हमने अभिनिर्धारित किया है कि वर्तमान मामले में क्रमशः न्यायाधीशों, या अधिवक्ता, या पक्षकार द्वारा कोई अवमानना नहीं की गई थी, इसलिए यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए खुला था, और वास्तव में यह उसका कर्तव्य था कि वह दो न्यायाधीशों और अधिवक्ता द्वारा उसके समक्ष दायर याचिकाओं पर विचार करे, और सदन द्वारा पारित विवादित आदेशों के आगे निष्पादन के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में था।

इस विषय से अलग होने से पहले, हम एक का उल्लेख करना चाहेंगे।

अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति के प्रयोग से संबंधित प्रश्न का पहलू। जहाँ तक न्यायालयों का संबंध है, न्यायाधीश हमेशा आंद्रे पॉल बनाम में लॉर्ड एटकिन द्वारा उन्हें संबोधित चेतावनी को ध्यान में रखते हैं। अटॉर्नी-त्रिनिदाद के जनरल (1)। लॉर्ड एटकिन ने कहा, "न्याय एक गुप्त गुण नहीं है; उसे जांच और सम्मान का सामना करने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही ओ. डी. आई. की मुखर टिप्पणियाँ हों।

हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि दंड देने की शक्ति

नेरी पुरुषों "। तिरस्कार जितना बड़ा है, उसका प्रयोग हमेशा सावधानी से, बुद्धिमानी से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। क्रोध या चिड़चिड़ापन में इस शक्ति का बार-बार या अंधाधुंध उपयोग अदालत की गरिमा या स्थिति को बनाए रखने में मदद नहीं करेगा, लेकिन कभी-कभी यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। बुद्धिमान न्यायाधीश यह कभी नहीं भूलते कि अपने पद की गरिमा और स्थिति को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे अपने निर्णयों की गुणवत्ता, निडरता, निष्पक्षता और अपने दृष्टिकोण की निष्पक्षता और अपने न्यायिक आचरण में जो गुण, गरिमा और शिष्टाचार का पालन करते हैं, उससे बड़े पैमाने पर जनता से सम्मान के पात्र हैं। हम यह सोचने का साहस करते हैं कि न्यायपालिका के बारे में जो सच है वह विधानमंडलों के बारे में भी उतना ही सच है।

इस प्रकार पहले तर्क दिए गए सभी प्रासंगिक बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद

हम और उन पर हमारे निष्कर्ष दर्ज किए, हम अब एक स्थिति में हैं

(1) ए. एल. आर. 1936 पी. सी. 141

एडेना उसे देखना

502

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1965] 1 एस. सी. आर.

पी.

ए द्वारा राष्ट्रपति द्वारा हमें संदर्भित पाँच प्रश्नों के उत्तर देने के लिए।

हमारा जवाब है:

(1) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर,

यह उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के लिए सक्षम था।

उत्तर प्रदेश का न्यायालय, जिसमें एन. यू. बेग और जी. डी. सहगल जे. , मनोरंजन करने और उससे निपटने के लिए

की वैधता को चुनौती देने वाली केशव सिंह की याचिका

उस पर लगाए गए कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश विधानसभा की अवमानना के लिए

और इसके विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए और केशव सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने के लिए उनकी उक्त याचिका।

(2) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर,

याचिका प्रस्तुत करवाकर केशव सिंह

उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में उनकी ओर से

श्री बी. सोलोमन अधिवक्ता, उक्त याचिका प्रस्तुत करते हुए, और उक्त दो माननीय न्यायाधीशों द्वारा

सीलैज़कॉन

उक्त याचिका और आदेश से निपटना और निपटना

केशव सिंह की जमानत पर रिहाई का फैसला

उक्त याचिका की अवमानना नहीं की उत्तर प्रदेश विधान सभा।

(3) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर,

यह विधान सभा के लिए सक्षम नहीं था

उत्तर प्रदेश उक्त दोनों के उत्पादन का निर्देश देगा

माननीय न्यायाधीश और श्री बी. सोलोमन अधिवक्ता, इससे पहले

यह अभिरक्षा में है या इसके लिए उनके स्पष्टीकरण की मांग करना - अवमानना।

(4) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर,

यह उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के लिए सक्षम था

उत्तर प्रदेश का न्यायालय मनोरंजन और उससे निपटने के लिए

उक्त दो माननीय न्यायाधीशों और श्री बी. सोलोमन अधिवक्ता, और अंतरिम आदेश पारित करने के लिए प्रतिबंध

उत्तर विधानसभा के अध्यक्ष

उक्त याचिकाओं के लिए प्रदेश और अन्य उत्तरदाता

उक्त विधानमंडल के उपरोक्त निर्देश को लागू करना

लैटिव असेंबली; और

(5) इस सवाल का जवाब देते हुए

जो बहुत व्यापक रूप से शब्दबद्ध है, हमें अपनी प्रस्तावना देनी चाहिए इस अवलोकन के साथ जवाब दें कि जवाब सीमित है

कथित अवमानना के संबंध में मामलों में

एक नागरिक द्वारा किया गया जो सदस्य नहीं है

विधान कक्ष की चार दीवारों के बाहर का सदन।

उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो विशेष संदर्भ से संबंधित कार्य करता है (जे. सरकार)

503

किसी विधिज्ञ के किसी आदेश या निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना लगाने या जारी करने की प्रक्रिया

अवमानना के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी प्रक्रिया,

या इसके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं के उल्लंघन के लिए, या

जो ऐसी याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, प्रतिबद्ध नहीं होता है

उक्त विधानमंडल की अवमानना; और उक्त विधानमंडल

राज्य ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है। अपनी शक्तियों के प्रयोग और प्रवर्तन में एक न्यायाधीश,

विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। इस उत्तर में हमारे पास है

प्रिवी के उल्लंघन के संदर्भ को जानबूझकर हटा दिया गया

सदन के कानून और उन्मुक्ति जिनमें शामिल हो सकते हैं -

उन विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं के अलावा जिनके साथ

हम वर्तमान संदर्भ में चिंतित हैं।

जे. सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ पर यह मामला हमारे पास आया है।

अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति। 143 संविधान से। यह अवसर

क्योंकि संदर्भ एक तीखा संघर्ष था जो उत्पन्न हुआ और अभी भी मौजूद है

उत्तर की विधानसभा (विधान सभा) के बीच प्रदेश राज्य विधानमंडल, जिसे इसके बाद विधानसभा कहा जाता है,

और उस राज्य का उच्च न्यायालय। वह संघर्ष उत्पन्न हुआ क्योंकि

उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की जमानत पर रिहाई का आदेश दिया था जिसे विधानसभा ने अवमानना के लिए जेल की सजा सुनाई थी। सभा

उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने में संबंधित वकील के बराबर था प्रलोभन दिया और उस आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की, और

इसके बाद उच्च न्यायालय ने विधानसभा को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए और

जिसकी ओर से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया गया था प्रलोभन।

बहुत बड़ी संख्या में पक्ष संदर्भ पर उपस्थित हुए और

सार्वजनिक महत्व के कारण यह स्वाभाविक था

प्रश्न शामिल है। इन दलों को दो व्यापक भागों में विभाजित किया गया था।

समूह, एक विधानसभा का समर्थन करता है और दूसरा, उच्च

अदालत।

अब मैं उन वास्तविक तथ्यों को बताऊंगा जिन्होंने संघर्ष को जन्म दिया।

विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि उन्हें फटकार लगाई जाए

अवमानना करने के लिए केशव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज

विधानसभा ने एक निश्चित पर्चे को प्रकाशित करके एक को बदनाम किया

उनके सदस्य। इस प्रस्ताव की वैधता पर कोई सवाल नहीं है।

इस मामले में उत्पन्न होता है और हम केवल इस बात से चिंतित हैं कि इसके बाद क्या हुआ। केशव सिंह जो गोरखपुर के निवासी थे, होने के बावजूद

बार-बार ऐसा करने की आवश्यकता पड़ी, विधानसभा के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे

जिसने फटकार प्राप्त करने के लिए लखनऊ में अपनी बैठकें आयोजित कीं

ऊपर।

C.I

./65-7 [1965] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

504

आवश्यक रेल यात्रा के लिए किराए का भुगतान करने के लिए पैसे खरीदने में असमर्थता का आरोप लगाते हुए। इसके बाद उन्हें उस ओर से अध्यक्ष द्वारा जारी वारंट के निष्पादन में विधानसभा के मार्शल के अधीन लाया गया और 14 मार्च, 1964 को सदन के बार में पेश किया गया। अध्यक्ष ने उनसे बार-बार उनका नाम पूछा, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वे वहाँ खड़े थे और पीठ थपथपाकर अध्यक्ष के सामने खड़े थे।

सदन का सम्मान करते हैं और अध्यक्ष का सामना करने के लिए नहीं मुड़ते हैं, हालांकि ऐसा करने के लिए कहा जाता है। फटकार लगाए जाने के बाद, अध्यक्ष ने विधानसभा के ध्यान में 11

मार्च, 1964 को केशव सिंह द्वारा उन्हें लिखे गए एक पत्र को लाया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने फटकार की सजा का विरोध किया और एक भ्रष्ट व्यक्ति को भ्रष्ट कहने में उन्हें कोई संकोच नहीं था, यह कहते हुए कि उनके पर्चे की सामग्री सही थी और उन पर "नादिरशाही फरमान" (वारंट) जारी करके लोकतंत्र पर एक क्रूर हमला किया गया था। केशव सिंह ने स्वीकार किया कि उन्होंने वह पत्र लिखा था। इसके बाद विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि "केशव सिंह को भाषा में एक पत्र लिखने के लिए सात दिन के कारावास की सजा सुनाई जाए जो सदन की अवमानना और सदन के दृष्टिकोण से उनके दुर्व्यवहार का गठन करता है।" सदन के मार्शल और जिला जेल, लखनऊ के अधीक्षक को एक सामान्य वारंट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था, "जबकि। विधानसभा ने निर्णय लिया है कि श्री केशव सिंह को विधानसभा की अवमानना का अपराध करने के लिए सात दिनों के लिए साधारण कारावास की सजा दी जाए, तदनुसार यह आदेश दिया जाता है कि केशव सिंह को सात दिनों की अवधि के लिए जिला जेल, लखनऊ में रखा जाए। वारंट में उन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है जो अवमानना का गठन करते हैं। केशव सिंह को उसी दिन जेल ले जाया गया और वहां कैद रखा गया। 19 मार्च, 1964 को एक अधिवक्ता बी. सोलोमन ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पीठ के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की, जिसे तब बेग और सहगल जे. जे. द्वारा गठित किया गया था। , जो लखनऊ में बैठा था। केशव सिंह की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट के लिए यह आरोप लगाते हुए कि उन्हें कानून के किसी भी अधिकार के बिना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था और यह नजरबंदी दुर्भावनापूर्ण थी। इस पीठ को लखनऊ पीठ के रूप में संदर्भित किया गया है। इस याचिका को अनुच्छेद के तहत किया गया माना गया था। 226 संविधान और एस। 491 दंड प्रक्रिया संहिता। उसी तारीख को विद्वान न्यायाधीशों ने आदेश दिया कि केशव सिंह को जमानत पर रिहा किया जाए और याचिका को स्वीकार किया जाए और इसमें नामित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए। केशव सिंह को तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया गया। यह आदेश सदन द्वारा पारित कारावास की सजा के साथ-साथ केशव सिंह को अपनी सजा की पूरी अवधि पूरी करने से पहले रिहा करने की अनुमति देता है। 21 मार्च, 1964 को विधानसभा का विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि बेग जे., सहगल जे., बी: सोलोमन और केशव सिंह ने सदन की अवमानना की थी और

केशव सिंह को तुरंत हिरासत में लिया जाए और जेल की शेष अवधि के लिए जिला जेल में रखा जाए और बेग जे., सहगल जे. और बी. सोलोमन को सदन के समक्ष हिरासत में लाया जाए, और यह भी कि केशव सिंह को उनकी शेष सजा पूरी करने के बाद सदन के समक्ष लाया जाए। प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करने के लिए 23 मार्च, 1964 को सदन के मार्शल और लखनऊ के आयुक्त को वारंट जारी किए गए थे। उसी दिन, जे. सहगल ने आर्ट के तहत एक याचिका दायर की। 226 इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में 21 मार्च, 1964 के विधानसभा के प्रस्ताव को निरस्त करने वाले प्रमाण पत्र के लिए और विधानसभा के अध्यक्ष और मार्शल को प्रतिबंधित करने वाले अन्य आवश्यक रिटों के लिए।

विधानसभा और राज्य सरकार इसे लागू करने से संकल्प के अनुसार जारी किए गए आदेशों का संकल्प और निष्पादन। हालाँकि याचिका में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि युद्ध

रेंट जारी किए गए थे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वारंट याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद जारी किए गए थे, या जारी किए गए थे

याचिकाकर्ता को वारंट की जानकारी नहीं थी। यह याचिका थी

सहगल को छोड़कर उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों द्वारा सुना गया और

जे. जे. से प्रार्थना करें। और उन्होंने उसी दिन एक आदेश पारित किया कि

प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर रोक लगाई जाए। इसी तरह की याचिकाएं

बी. सोलोमन और बेग जे. और अन्य लोगों द्वारा भी प्रस्तुत किए गए थे।

अवध बार एसोसिएशन सहित दलों और कुछ पर

ऐसा प्रतीत होता है कि जे. सहगल की याचिका पर भी उनके समान आदेश दिए गए थे। 25 मार्च, 1964 को विधानसभा ने एक ओ. बी. दर्ज किया

यह कि 21 मार्च, 1964 के अपने संकल्प द्वारा यह इसका नहीं था

यह तय करने का इरादा कि बेग जे., सहगल जे., बी. सोलोमन और केशव सिंह ने उन्हें दिए बिना सदन की अवमानना की थी

एक सुनवाई, लेकिन इसके लिए सदन के समक्ष उनकी उपस्थिति की आवश्यकता थी

उन्हें अपनी स्थिति समझाने का अवसर देना और यह हल हो गया

ताकि उपरोक्त नाम वाले व्यक्तियों को नियमों के अनुसार अपनी शंकाओं को समझाने का अवसर देने के बाद प्रश्न का निर्णय लिया जा सके।

डक्ट। इस प्रस्ताव के अनुसार, नोटिस जारी किए गए थे

पर

26 मार्च, 1964 से बेग जे., सहगल जे. और बी. सोलोमन ने सूचित किया उन्हें यह कहते हुए कि वे समिति के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं

. अपनी उपज

बनाने के लिए

10 6 अप्रैल, 1964 को ए. एम.

सायंस "। 23 मार्च, 1964 को जारी किए गए वारंट, जो कभी जारी नहीं हुए थे। निष्पादित किया गया, इन नोटिसों को देखते हुए वापस ले लिया गया। द.

वर्तमान संदर्भ 26 मार्च को दिया गया था। 1964 और उसके बाद

विधानसभा ने 26 मार्च, 1964 के नोटिस को यह कहते हुए वापस ले लिया कि संदर्भ को देखते हुए दो न्यायाधीश और सोलोमन और केशव

सिंह को आवश्यकतानुसार विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

[

1965] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

506

ये तथ्य संदर्भ के क्रम में निहित पाठों में दिए गए हैं। हालाँकि, गायन में तथ्यों के कथन के बारे में एक विवाद है। यह कहा गया है कि विधानसभा ने 21 मार्च, 1964 को संकल्प लिया कि दो न्यायाधीशों, सोलोमन और केशव सिंह ने "अपने कार्यों से, सदन की अवमानना की।" "उपरोक्त कार्य" शब्द 19 मार्च, 1964 की केशव सिंह की याचिका और उस पर दिए गए आदेश की प्रस्तुति का उल्लेख करते हैं। विधानसभा की ओर से यह बताया गया है कि प्रस्ताव में यह नहीं कहा गया है कि अवमानना क्या थी। यह तर्क सही है।

इस संदर्भ में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विधानसभा को एक सामान्य वारंट द्वारा अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को जेल में डालने का विशेषाधिकार है, यानी उन तथ्यों को बताए बिना जो अवमानना को दर्शाते हैं, और यदि ऐसा करता है, तो अदालतों को इस तरह के समर्पण की वैधता की जांच करने की शक्ति है? अन्य में

शब्दों में, यदि ऐसा कोई विशेषाधिकार है, तो क्या यह हिरासत में लिए गए नागरिक के मौलिक अधिकारों पर वरीयता लेता है। विधानसभा की ओर से कहा जाता है कि उसे ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त है और वर्तमान मामले में अदालत का हस्तक्षेप अधिकार क्षेत्र के बाहर था। यह प्रश्न तब विधानसभा के विशेषाधिकार का है, क्योंकि यदि उसके पास आवश्यक विशेषाधिकार नहीं है, तो यह विवादित नहीं है कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में जो किया है वह वर्तमान उद्देश्यों के लिए असाधारण होगा।

सबसे पहले विधानसभा के विशेषाधिकारों के बारे में। सभा उद्देश्य के लिए सी. एल. पर निर्भर करती है। (3) अनुच्छेद की। 194 संविधान से। उस लेख के पहले तीन खंड इस स्तर पर निर्धारित किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद. 194 (1) इस संविधान के प्रावधानों और विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में बोलने की स्वतंत्रता होगी।

विधानमंडल या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के बारे में, और कोई भी व्यक्ति ऐसे विधानमंडल के किसी सदन द्वारा या उसके अधिकार के तहत किसी भी रिपोर्ट के प्रकाशन के संबंध में इतना उत्तरदायी नहीं होगा, कागज, वोट या कार्यवाही।

(3) अन्य मामलों में, किसी राज्य के विधानमंडल के सदन की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति,

और ऐसे विधान-मंडल के सदन के सदस्यों और समितियों के सदस्य और समितियाँ ऐसी होंगी जो समय-समय पर विधान-मंडल द्वारा विधि द्वारा परिभाषित की जाएं, और जब तक कि विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

इस प्रकार परिभाषित, हाउस ऑफ कॉमन्स के होंगे

यूनाइटेड किंगडम की संसद, और इसके सदस्य

इस अधिनियम के प्रारंभ में सदस्य और समितियाँ

संविधान।

अनुच्छेद 105 में केंद्रीय विधानमंडल के संबंध में समान प्रावधान हैं। यह विवाद में नहीं है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अपने दोनों सदनों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति को परिभाषित करने वाला कोई कानून नहीं बनाया है। इसलिए विधानसभा का दावा है कि उसके पास वे विशेषाधिकार हैं जो 25 जनवरी, 1950 को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स को थे।

मैं इस स्तर पर कुछ सामान्य शब्द कहना चाहूंगा

" हाउस ऑफ कॉमन्स या उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। सबसे पहले मैं यह ध्यान रखना चाहता हूं कि यह हमारे लिए आवश्यक नहीं है। "विशेषाधिकार", "शक्तियाँ" और "उन्मुक्ति" के बीच अंतर करने का उद्देश्य। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अपनी-अपनी विषय-वस्तु के मामले में अलग हैं, लेकिन शायद अन्यथा नहीं। इस प्रकार अपनी आंतरिक कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण रखने के सदन के अधिकार को उसका विशेषाधिकार माना जा सकता है, अवमानना के लिए किसी को दंडित करने के उसके अधिकार को उसकी शक्ति के रूप में अधिक उचित रूप से वर्णित किया जा सकता है, जबकि यह अधिकार कि कोई भी सदस्य सदन में कही गई किसी भी बात के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, वास्तव में एक प्रतिरक्षा हो सकती है। हालाँकि ये सभी अधिकार एक कानून द्वारा बनाए गए हैं और एक ही मानक द्वारा न्याय किए जाते हैं। मैं सुविधा के लिए उन सभी को "विशेषाधिकार" के रूप में वर्णित करूंगा। इसके बाद मैं ध्यान देता हूं कि यह मामला केवल हाउस ऑफ कॉमंस के विशेषाधिकारों से संबंधित है, न कि इसके सदस्यों और इसकी समितियों के विशेषाधिकारों से। हालांकि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि बाद के दो के विशेषाधिकार हैं

उनके अलावा पूर्व के लोगों से अलग सम्मान

सामग्री।

हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों की प्रकृति कर सकती है

मई की संसदीय प्रथा का उल्लेख करके सबसे अच्छी तरह से चर्चा की जाए, जो अंग्रेजी संसद से संबंधित मामलों पर अधिकार का एक स्वीकृत कार्य है। यहाँ यह देखने में मदद मिल सकती है कि लंबे समय से कॉमन्स के विशेषाधिकारों की प्रकृति के बारे में कोई विवाद नहीं है।

मैं इंगित करके विशेषाधिकारों की प्रकृति को समझाना शुरू करता हूं।

उनके और सदन के कार्यों के बीच अंतर। इस प्रकार हाउस ऑफ कॉमन्स की कराधान कानून शुरू करने की वित्तीय शक्तियों को अक्सर इसके विशेषाधिकार के रूप में वर्णित किया जाता है। हालाँकि, यह हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार नहीं है जिसके लिए सी. एल. (3) अनुच्छेद की। 194 संदर्भित करता है। अंग्रेजी संसदीय कानून में हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों का तकनीकी अर्थ है।

और लेख केवल उसी अर्थ में शब्द का उपयोग करता है। उस तकनीकी भावना को इन शब्दों में वर्णित किया गया है: " [ग) मौलिक [1965] आई. एस. सी. आर.

508

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्येक सदन के अधिकार जिन्हें आम तौर पर आवश्यक माना जाता है

अपने संवैधानिक कार्यों का प्रयोग करना। (1) एक बात जिस पर मैं अब जोर देना चाहूंगा वह यह है कि विशेषाधिकारों की प्रकृति का सार यह है कि वे हाउस ऑफ कॉमन्स के मुख्य कार्यों के सहायक हैं। एक और बात जो मैं इस स्तर पर देखना चाहता हूं वह यह है कि अन्य विशेषाधिकार पूरी तरह से संसद के कानून और रीति-रिवाजों पर निर्भर करते हैं, जबकि अन्य को क़ानून द्वारा परिभाषित किया गया है। केवल इन्हीं आधारों पर सभी विशेषाधिकार जो भी स्थापित किए गए हैं "(2)। इस मामले में हम केवल पूर्व प्रकार के विशेषाधिकार से संबंधित होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषाधिकार की यह विविधता संसद के कानून और रीति-रिवाजों से अपना अधिकार प्राप्त करती है। इस कानून को लेक्स पार्लियामेंट का नाम दिया गया है। इसकी उत्पत्ति संसद की प्रथा से हुई है। इसलिए, यह इंग्लैंड के सामान्य कानून से अलग है, जो हालांकि प्रथा पर आधारित है, लेकिन एक सेपा पर आधारित है।

प्रथा का दर सेट, अर्थात्, जो शेष क्षेत्र में प्रचलित है। मूल में इस अंतर ने संसद और न्यायालयों के बीच गंभीर मतभेदों को जन्म दिया था, लेकिन वे कई वर्षों से वहां सुलझाए गए हैं और सिद्धांत के रूप में एक विवाद को छोड़कर, किसी भी व्यावहारिक विवाद की पुनरावृत्ति को एक संभावना नहीं माना जाता है। इसलिए लॉर्ड कॉलरिज सी. जे. ने ब्रैडलॉफ बनाम में कहा। गोसेट (1)।

" चाहे सभी मामलों में और सभी परिस्थितियों में

सदन अपने विशेषाधिकारों के एकमात्र न्यायाधीश हैं।

इस अर्थ में कि किसी भी सदन का संकल्प

कानून की अदालत के लिए विषय का वही प्रभाव पड़ता है जो एक

संसद का अधिनियम, एक ऐसा प्रश्न है जो अब नहीं है

निर्धारित करना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी समीक्षा की अनुमति देने के लिए

बहुत गंभीर जटिलताओं का कारण बना है, और कई में हो सकता है अनुमेय मामले कॉमन्स के विशेषाधिकारों में समाप्त होते हैं

प्रभुओं द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। लेकिन, रेसो को पकड़ने के लिए

किसी भी सदन का प्रलोभन पूरी तरह से जांच से परे है

कानून की अदालत हमें ऐसे निष्कर्ष पर ले जा सकती है जो इससे मुक्त नहीं हैं गंभीर जटिलताएँ भी। इतना कहना ही काफी है

कि मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धांत रूप में प्रश्न अतिरिक्त है

हल करना मुश्किल है; व्यवहार में यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और किसी भी तरह से अब उत्पन्न नहीं होता है। "

यह परिच्छेद विवाद की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

यह बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होगा, और वास्तव में मुझे लगता है कि उस विवाद की चर्चा में प्रवेश करना 'अनुचित होगा', क्योंकि यह केवल अशुद्धियों को ऊपर उठाने का काम करेगा जो बस गई हैं, एक धारा जो अब वर्षों से साफ हो गई है। इसके अलावा

(

2) आई. बी. आई. डी. पी. 44 .

(1) मे 'ज़ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, 16 वाँ संस्करण। पी। 42 .

(3) (1884) एल. आर. 12 क्यू. बी. डी. 271,275।

विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

यह विवाद इस देश में कभी पैदा नहीं हो सकता है क्योंकि यहां निस्संदेह अदालतों को संविधान की व्याख्या करनी है और इसलिए, अनुच्छेद। 194 (3) . यह इस प्रकार है कि जब इस देश में उस अनुच्छेद के तहत कोई प्रश्न उठता है कि क्या संविधान के प्रारंभ में हाउस ऑफ कॉमन्स को कोई विशेष विशेषाधिकार प्राप्त था, तो उस प्रश्न का निपटारा केवल अदालतों द्वारा किया जाना चाहिए और उसका निपटारा किया जाना चाहिए। भयानक "द्वैतवाद" के यहाँ प्रकट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी अदालतें विधानमंडल के सदन के साथ विवाद में प्रवेश करती हैं कि इसके विशेषाधिकार क्या हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो कहा है वह वर्तमान संदर्भ के उद्देश्यों के लिए विशेषाधिकारों की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए और अब मैं इस मामले में विधानसभा के विशेषाधिकारों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ूंगा, उस शब्द का उपयोग विधायिका के मुख्य कार्य के सहायक अधिकारों के अर्थ में करूंगा।

जिस विशेषाधिकार को मैं सबसे पहले लेता हूं, वह है समर्पण करने की शक्ति।

अवमानना। यह विवादित नहीं है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास यह है

शक्ति। सभी निश्चित मामले और पाठ्य-पुस्तकें ऐसी शक्ति की बात करती हैं। प्रतिबद्धता की शक्ति को वास्तव में 'संसदीय विशेषाधिकार की आधारशिला' के रूप में वर्णित किया गया है. इसके बिना पार्लिया के विशेषाधिकार

वे आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे, लेकिन, अगर वे नहीं होते

व्यपगत, पीड़ा पर जीवित रहता "। (1) बर्डेट बनाम में। एबॉट (2) लॉर्ड एलेनबरो सी. जे. ने कहा,

" क्या इसकी उम्मीद की जा सकती है?

.....कि स्पीकर

उसकी गदा के साथ जाने की आवश्यकता होनी चाहिए के लिए अभियोग के एक विधेयक को प्राथमिकता देने के लिए एक भव्य जूरी के सामने

सदन का अपमान? उन्हें निश्चित रूप से

आत्म-पुष्टि और आत्म-सुरक्षा की शक्ति रखें

अपने हाथों में..

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इस शक्ति का अधिकार निस्संदेह है।

यह करने की शक्ति की प्रकृति की सराहना करने में मदद करेगा

अवमानना के लिए इसकी तुलना विशेषाधिकार हनन के साथ करने के लिए जो स्वयं

अवमानना हो सकती है। इस प्रकार इसके आदेशों के खिलाफ हाउस ऑफ कॉमन्स की कार्यवाही का प्रकाशन इसके विशेषाधिकार का उल्लंघन है और अवमानना के बराबर है। हालाँकि, सभी अवमाननाएँ हैं

विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं। गरिमा या अधिकार के खिलाफ अपराध

यद्यपि सदन को "विशेषाधिकार का उल्लंघन" कहा जाता है, लेकिन इसे अवमानना के रूप में अधिक उचित रूप से अलग किया जाता है। अवमानना के लिए जेल जाना अपने आप में हाउस ऑफ कॉमन्स का एक विशेषाधिकार है चाहे अवमानना उसके विशेषाधिकार के सीधे उल्लंघन से की गई हो या उसके विशेषाधिकार का उल्लंघन करके की गई हो।

(2) 104

ई. आर. 501,559

(1) मई, पी। 90 .

[

1965] 1 एस. सी. आर

510

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गरिमा या अधिकार। (1) "इस प्रकार एक विधायी निकाय के कार्य, विशेषाधिकार और अनुशासनात्मक शक्तियां निकटता से जुड़ी हुई हैं। द.

विशेषाधिकार कार्यों और विशेषाधिकारों की अनुशासनात्मक शक्तियों के आवश्यक पूरक हैं। (2) मैं यह जोड़ सकता हूं कि यह विवाद में नहीं है कि अवमानना करने की शक्ति का प्रयोग न केवल सदन के किसी सदस्य के खिलाफ किया जा सकता है, बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति के खिलाफ भी किया जा सकता है। (1)

उच्च न्यायालय की ओर से यह तर्क दिया गया कि शक्ति

हाउस ऑफ कॉमन्स को अवमानना के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए सी. एल. द्वारा प्रेरित नहीं किया गया था। (3) अनुच्छेद की। 194 राज्य विधानमंडल के सदनों पर क्योंकि हमारे संविधान को शक्तियों के विभाजन और अवमानना के लिए जेल जाने की शक्ति प्रदान करने वाली इसकी मूल योजना के साथ पढ़ा जाना चाहिए, हमारे संविधान के तहत केवल एक न्यायिक निकाय, अर्थात् अदालतों के पास हो सकता है, न कि विधानसभा जैसे विधायी निकाय के पास। इसलिए यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद। 194 (3) कोन के रूप में पढ़ा नहीं जा सका

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्राप्त न्यायिक शक्तियों को प्राप्त करना

इंग्लैंड एक विधायी निकाय पर अपने विशेषाधिकारों में से एक के रूप में और इसलिए

विधानसभा के पास इसका अधिकार नहीं था।

उच्च न्यायालय का यह तर्क, मेरे विचार में, पूरी तरह से है।

आधार के बिना; सिद्धांत और अधिकार दोनों इसके खिलाफ हैं।

इस न्यायालय ने पहले के अवसरों पर यह मत व्यक्त किया है कि

शक्तियों का पृथक्करण हमारे संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है:

उदाहरण के लिए रे में देखें। दिल्ली विधि अधिनियम (1)। फिर से संविधान

बेशक सर्वोच्च है और भले ही यह सिद्धांत पर आधारित था

शक्तियों का पृथक्करण, संविधान को रोकने के लिए कुछ भी नहीं था राष्ट्र-निर्माता, यदि वे चाहते हैं, तो न्यायिक शक्तियों को प्रदान करने से

शक्तियों का विभाजन। इस तरह का विवाद निश्चित रूप से बेतुका होगा। इसलिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या हमारा संविधान निर्माता हैं?

विधानमंडलों को वचनबद्ध होने की शक्ति प्रदान की है। सवाल यह हैं

अपनी शक्तियों को सीमित करें। संविधान निर्माताओं ने क्या किया था हालाँकि, उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों से ही इसका पता लगाया जा सकता है।

उनके द्वारा बनाए गए संविधान में। अगर वे शब्द सरल हैं,

उन्हें प्रभाव दिया जाना चाहिए, चाहे हमारा संविधान कुछ भी हो।

यह शक्ति के विभाजन पर आधारित है या नहीं। यह मुझे ले जाता है

सी. एल. में प्रयुक्त भाषा। (3) अनुच्छेद की। 194. वहाँ शब्द दिखाई देते हैं

"किसी सदन की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तिएँ हैं।

(1) मई, पी। 43 .

(2) एलबी आईडी।

(4) (1951) एस. सी. आर 747,883

(3) आइबीआइडी। , पी।

91 विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

511

वे हाउस ऑफ कॉमन्स के हों "। मैं इससे अधिक सरल भाषा की कल्पना नहीं कर सकता। उस भाषा का केवल एक ही अर्थ हो सकता है। और वह यह है कि इसका उद्देश्य राज्य विधानमंडलों को वे शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान करना था जो हाउस ऑफ कॉम

इंग्लैंड में मोन थे। एक के प्रति निष्ठा का दावा करके शब्दों को उनके स्पष्ट अर्थ से इनकार करने में चतुराई का कोई अवसर नहीं है। शक्तियों के विभाजन का कथित सिद्धांत। जहाँ तक शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के अनुप्रयोग के संबंध में सिद्धांत का संबंध है।

इस निर्णय से यह प्रश्न पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।

इस न्यायालय के पं. एम. एस. एम शर्मा बनाम श्री श्री कृष्ण सिन्हा (1)। मुझे बाद में इस मामले का विस्तार से उल्लेख करना होगा। वहाँ दास सी. जे. ने पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का बहुमत निर्णय दिया और जे. सुब्बा राव ने अपनी असहमति व्यक्त की। दास सी. जे. ने इस आधार पर कार्यवाही की कि राज्य विधानमंडल के सदनों को अवमानना करने की शक्ति थी। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी विधायी निकाय को न्यायिक शक्तियों से रोक सके। इस मुद्दे पर जे. सुब्बा राव ने कोई असहमति व्यक्त नहीं की। इसके अलावा, इंग्लैंड में न्यायिक समिति ने दो मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रावधानों के तहत, अनुच्छेद के प्रावधानों के समान है। 194 (3) हमारे संविधान

के अनुसार, हाउस ऑफ कॉमन्स की अवमानना करने की शक्ति कुछ ब्रिटिश उपनिवेशों के कुछ विधायी निकायों को प्रदान की गई थी। विक्टोरिया की विधान सभा के अध्यक्ष बनाम।

ग्लास (2) यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक क़ानून "। विधान परिषद

विक्टोरिया से। . . . . . इस तरह की चीज़ों को पकड़ेंगे, आनंद लेंगे और अभ्यास करेंगे विशेषाधिकार, उन्मुक्ति और शक्तियाँ। . . . आयोजित किया गया, आनंद लिया गया और

ग्रेट ब्रिटेन की संसद के कॉमन्स हाउस द्वारा प्रयोग किया गया

और आयरलैंड "के विधानमंडल के सदनों को सम्मानित किया गया

विक्टोरिया की ऑस्ट्रेलियाई कॉलोनी के लिए प्रतिबद्ध करने की न्यायिक शक्ति

अवमानना। रानी वी. रिचर्ड्स (3) यह माना गया था कि एस। 49 में से

ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल संविधान अधिनियम, 1901 जो

प्रतिनिधि सभा ऐसी होगी जो इसके द्वारा घोषित की जाए। संसद, और घोषित होने तक, कॉमन्स की होगी।

यूनाइटेड किंगडम की संसद का सदन "., को सम्मानित किया गया

किसी व्यक्ति को जेल में डालने की सदन की न्यायिक शक्तियाँ

अवमानना। यह डिक्सन सी. जे. द्वारा देखा गया था।

" यह ऐतिहासिक चर्चा करने का अवसर नहीं है।

जिन आधारों पर ये शक्तियाँ और विशेषाधिकार संलग्न हैं

हाउस ऑफ कॉमन्स में। कहने के लिए पर्याप्त है

(2) (1869-71) 3 एल. आर. पी. सी. 560.

(1) [1959] सप. 1 एससीआर 806।

(3) 92 सी. एल. आर. 157

कि उन्हें कई अधिकारियों द्वारा उचित माना जाता था

विधायी कार्य की घटनाओं के बावजूद,

तथ्य जो अधिक सैद्धांतिक रूप से माना जाता है-शायद एक

यह भी कहा जा सकता है, वैज्ञानिक रूप से-वे जूडी से संबंधित हैं

कि संविधान और पृथक का एक सामान्य दृष्टिकोण देने के लिए शक्तियों का होना पर्याप्त कारण नहीं है

ये शब्द, जो हमें इतने स्पष्ट लगते हैं, एक प्रतिबंध

तीव या द्वितीयक अर्थ जो वे ठीक से नहीं करते हैं

भालू "। (1)

ऑस्ट्रेलियाई में प्रावधानों की भाषा में समानता

संविधान और हमारा संविधान चौंकाने वाला है। हालाँकि यह कहा गया था कि वे अंडर एस के लिए समान नहीं थे। 49 ऑस्ट्रेलियाई सदन प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकारों की घोषणा कर सकते हैं जबकि हमारे मामले में विशेषाधिकारों को कानून द्वारा परिभाषित किया जाना था और ऑस्ट्रेलिया में कोई मौलिक अधिकार नहीं थे। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस तर्क का बिल्कुल भी पालन नहीं करता। सवाल यह नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में विशेषाधिकारों की घोषणा कैसे की जाती है या मौलिक अधिकारों का विशेषाधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन

उन शब्दों के अर्थ के बारे में जो दोनों विधियों में स्पष्ट हैं। रिचर्ड के मामले (2) में डिक्सन सी. जे. के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए न्यायिक समिति को एक आवेदन दिया गया था।

लेकिन इस तरह की अनुमति से इनकार कर दिया गया था, विस्काउंट साइमंड्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय का निर्णय "अक्षम्य है": रानी वी. रिचर्ड्स (3)। फील्डिंग वी का भी संदर्भ दिया जा सकता है। थॉमस (1) कनाडा में नोवा स्कोटिया के विधानमंडल को कॉमन्स के विशेषाधिकार प्रदान करने वाले समान प्रावधान की व्याख्या के लिए। इसलिए, यह अनुच्छेद प्रतीत होगी। 194 (3) विधानसभा को अवमानना करने की शक्ति प्रदान की गई और उसके पास वह शक्ति है।

अगला सवाल एक जनरल द्वारा किए गए विशेषाधिकार के बारे में है।

आदेश दिया। इंग्लैंड में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यदि हाउस ऑफ कॉमन्स अवमानना का गठन करने वाले तथ्यों को बताए बिना एक सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होता है, तो अदालतें उस आदेश (*) की समीक्षा नहीं करेंगी। हालाँकि, उच्च न्यायालय की ओर से यह कहा गया था कि अंग्रेजी हाउस ऑफ कॉमन्स की यह शक्ति इसकी निजी शक्तियों में से एक नहीं थी।

लेकिन यह उस सदन के कब्जे में था क्योंकि यह एक श्रेष्ठ था

न्यायालय और इसलिए, वह शक्ति, विशेषाधिकार नहीं होने के कारण, अनुच्छेद द्वारा राज्य विधानमंडलों को प्रदान नहीं की गई है। 194 (3) हमारे संविधान का। विधानसभा द्वारा यह दावा नहीं किया जाता है कि यह एक उच्च न्यायालय है

और इसलिए, एक जनरल द्वारा अवमानना करने की शक्ति है

आदेश दिया। अगर ऐसा होता तो मुझे इस तरह के दावे को सही ठहराने के लिए कुछ नहीं मिलता।

8 (3)

92 सी. एल. आर. 157 (4) [1896] ए. सी. 600

(1) 92 सी. एल. आर. 157,167

(3) 92 सी. एल. आर. 157,171

(5) बर्डेट वी. देखें। मठाधीश 3 ई. आर. 1289; मई का संसदीय अभ्यास 16वां संस्करण। पी।

173 विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

513 .

बनाया गया। यह मुझे इस सवाल पर ले जाता है, क्या एक सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होने की शक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों में से एक है, या, क्या यह कुछ ऐसा है जो इंग्लैंड के सामान्य कानून के तहत सदन के पास था क्योंकि यह एक उच्च न्यायालय था?

मुझे इस तर्क का समर्थन करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है कि

उस समर्पण के संबंध में कानून के न्यायालयों की अधिकारिता के परिणामी वंचित होने के साथ एक सामान्य वारंट द्वारा समर्पण कुछ ऐसा है जो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास था क्योंकि यह एक उच्च न्यायालय था। सबसे पहले, मुझे नहीं लगता कि हाउस ऑफ कॉमन्स अपने आप में कभी एक अदालत थी। उस सदन का इतिहास इस तरह के विवाद का समर्थन नहीं करता है। आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि यह अवलोकन करना आवश्यक है कि हम एक अलग निकाय के रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों से संबंधित हैं, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह ब्रिटिश संसद का एक घटक हिस्सा है जिसमें राजा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी शामिल हैं। हालाँकि जिन विशेषाधिकारों के साथ हम जुड़े हुए हैं, वे वे हैं जिनका हाउस ऑफ कॉमन्स अकेले एक स्वतंत्र निकाय के रूप में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कब्जे वाले विशेषाधिकारों के अलावा दावा करता है। वास्तव में यह स्पष्ट है कि दोनों सदनों के विशेषाधिकार समान नहीं हैं: मई च। III. यह हो सकता है कि अंग्रेजी इतिहास के शुरुआती दिनों में संसद एक अदालत थी। द.

हालाँकि, हाउस ऑफ कॉमन्स इस न्यायालय का हिस्सा नहीं प्रतीत होता है। मध्ययुगीन काल में कानूनी अवधारणा यह थी कि राजा सभी चीजों का स्रोत था; न्याय को उसी से प्रवाहित माना जाता था और इसलिए, न्याय का न्यायालय राजा से जुड़ा हुआ था। राजा का न्यायालय इस प्रकार कानून का एक न्यायालय था और यही "संसद का उच्च न्यायालय" कहा जाता है। संसद के उच्च न्यायालय के इतिहास का सारांश पॉटर की आउटलाइन ऑफ इंग्लिश लीगल हिस्ट्री (1958 संस्करण) में दिया गया है और इसे निम्नानुसार निर्धारित किया जा सकता है: राजा की परिषद, अपने पुराने शीर्षक क्यूरिया रेजिस के तहत, सामान्य कानून अदालतों की जननी थी, लेकिन सामान्य कानून अदालतों के अच्छी तरह से स्थापित होने के बाद भी कुछ न्यायिक कार्यों को बनाए रखा। (पी। 78)। हालांकि बाद में 14 वीं और 15 वीं शताब्दी में यह माना गया कि राजा की पीठ की अपील संसद में होती है न कि परिषद में। लेकिन संसद को बहुत काम करना था और याचिकाओं को सुनने या यहां तक कि राजा की पीठ से त्रुटि के नियमों को सुनने के लिए बहुत कम समय मिल सकता था और यह अधिकार क्षेत्र 15 वीं शताब्दी में स्थगित हो गया। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसद का कॉमन्स कोई हिस्सा नहीं था। 1485 में सभी न्यायाधीशों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि त्रुटि का अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स का है न कि पूरी संसद का। प्रोफेसर होल्ड्सवर्थ इस तथ्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह पूरी तरह से नहीं भुलाया गया था कि अधिकार क्षेत्र संसद में राजा और उनकी परिषद के लिए था जबकि कॉमन्स [1965] 1 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कभी भी अपनी परिषद का हिस्सा नहीं, संसद में अपनी परिषद में राजा का अर्थ है केवल राजा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स; पी। 95. यह भी है

यह बताना दिलचस्प है कि जब कॉमन्स ने अलग-अलग विचार-विमर्श किया, तो वे पश्चिम मंत्री के मठाधीश के चैप्टर-हाउस या रेफक्टरी में बैठे; और उन्होंने अपनी बैठकों के बाद उस स्थान पर अपनी बैठकें जारी रखी।

अंतिम अलगाव; मई पी। 12. जिस अलगाव का उल्लेख किया गया है वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच अलगाव है। यह भी बताया जा सकता है कि जब यह कहा जाता है कि इंग्लैंड में कानून संसद में राजा द्वारा बनाए जाते हैं, तो क्या होता है कि कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बार में जाते हैं जहां राजा या तो व्यक्तिगत रूप से, या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो उनसे कमीशन लेता है।

एक अधिनियम को मंजूरी देता है। यह सब दिखाएगा कि हाउस ऑफ कॉम जब यह एक अलग निकाय के रूप में बैठता है तो यह संसद में नहीं बैठता है। इसलिए यह संसद का उच्च न्यायालय नहीं है। मैं यहाँ चाहता हूँ

इस बात पर जोर दें कि हम इस मामले में हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों से संबंधित हैं जो एक अलग निकाय के रूप में काम कर रहे हैं, यानी संसद में नहीं बैठ रहे हैं। पी पर अवलोकन किया जा सकता है। 90 , “ क्या हाउस ऑफ कॉमन्स, कानूनी रूप से, रिकॉर्ड की अदालत है, यह निर्धारित करना मुश्किल होगा: " एनसन के संविधान के कानून में, 5 वां संस्करण। खण्ड. 1 पी पर। 197 , यह कहा गया है कि "सदन चाहे या न हो

कॉमन्स की अदालत अभिलेख की एक अदालत है, जिसके पास न केवल अवमानना के लिए प्रतिबद्धता द्वारा अपमान से खुद को बचाने की समान शक्ति है, बल्कि उच्च न्यायालयों ने इस मामले में उसी तरह से निपटा है जैसे वे एक दूसरे के साथ करेंगे, और इसके निर्णय को निर्णायक के रूप में स्वीकार किया है।

पूछते हैं

बयान कि एक अवमानना की गई है, उसके बिना वह अवमानना क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि अधिकारियों की इस स्थिति में कम से कम यह मानना खतरनाक होगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स रिकॉर्ड की अदालत थी। यदि ऐसा नहीं था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास रिकॉर्ड की अदालत के रूप में एक सामान्य वारंट द्वारा अपनी अवमानना करने की शक्ति थी।

अब मैं यह बताने के लिए आगे बढ़ रहा हूं कि हाउस ऑफ कॉमन्स का यह अधिकार कैसे है

इंग्लैंड में आधिकारिक पाठ्यपुस्तक लेखकों द्वारा एक सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होने से निपटा गया है। पी. 173 , चर्चा करने के बाद पूर्व के विशेषाधिकारों के संबंध में कॉमन्स और न्यायालयों के बीच संघर्ष और यह कहते हुए कि सिद्धांत रूप में मुद्दे पर वास्तविक बिंदु को हल करने का कोई तरीका नहीं है, यदि दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। मई ने कहा, "व्यवहार में, हालांकि, बहुत कुछ है।

अधिकार क्षेत्र के सवाल पर गतिरोध की तुलना में विशेषाधिकार की प्रकृति और सिद्धांतों पर अधिक सहमति किसी को उम्मीद करने के लिए प्रेरित करेगी। " इसके बाद वे कहते हैं, "अदालतें स्वीकार करती हैं: - (3) कि प्रत्येक का नियंत्रण

सदन अपनी आंतरिक कार्यवाही पर निरपेक्ष है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

अदालतों के साथ खिलवाड़। (4) कि किसी भी सदन द्वारा अवमानना के लिए एक समर्पण व्यवहार में इसके अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर है, क्योंकि विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

515

कथित अवमानना का गठन करने वाले तथ्यों को समर्पण के वारंट पर बताए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मई हाउस ऑफ कॉमन्स के सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होने के अधिकार को अपने विशेषाधिकारों में से एक के रूप में मानता है न कि कुछ ऐसा जिसके लिए वह सामान्य कानून के तहत रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में अधिकार का हकदार है। संवैधानिक कानून के मामलों में

कीर और लॉसन द्वारा, (चौथा संस्करण) पी। 126 , यह कहा गया है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के निस्संदेह विशेषाधिकारों में से "की शक्ति है

संसद के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति को सदन के प्रलोभन के लिए कारावास में डाल कर विशेषाधिकार के मामलों पर निर्णयों को निष्पादित करना। मिडिलसेक्स के शेरिफ के मामले में इसका उदाहरण दिया गया है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक सामान्य युद्ध विवाद द्वारा अवमानना के लिए मिडिलसेक्स के शेरिफ को प्रतिबद्ध किया था, शेरिफ ने सदन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए किंग्स बेंच डिवीजन के एक आदेश को लागू किया, जो वह करने

के लिए बाध्य था और उस अदालत ने कहा कि सदन द्वारा किए गए समर्पण की वैधता के सवाल पर जाने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था: मिडिलसेक्स के शेरिफ (1) देखें। हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, वॉल्यूम। 28 पी। 467 , यह कहा गया है कि कानून की अदालतें उन कारणों की जांच नहीं करेंगी जिनके लिए किसी व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराया जाता है और किसी भी सदन द्वारा एक वारंट द्वारा किया जाता है जो उसकी गिरफ्तारी के कारणों को नहीं बताता है। यह अवलोकन हाउस ऑफ कॉमन्स और न्यायालयों के बीच पूर्व के विशेषाधिकारों से संबंधित संघर्ष से निपटने में किया जाता है और स्पष्ट रूप से एक सामान्य वारंट जारी करने की शक्ति को सदन के विशेषाधिकार के मामले के रूप में मानता है। अंत में, डाइस के संवैधानिक कानून (10 वां संस्करण) में पी। 58 फुटनोट में यह बताया गया है।

" संसदीय विशेषाधिकार की प्रकृति से है

चीजें कभी भी सटीक कानूनी परिभाषा का विषय नहीं रहीं।

एक या दो बिंदु स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य हैं। स्थापित किया गया।

(1) संसद का कोई भी सदन इसके लिए प्रतिबद्ध हो सकता है

अवमानना; और अदालतें इसके पीछे नहीं जाएंगी।

मित्तल और कथित तथ्यों की जांच करना

अवमानना बशर्ते कि अवमानना का कारण

नहीं बताया गया "।

इस प्रकार मैं पाता हूँ कि निस्संदेह प्राधिकार के लेखकों ने इस शक्ति को एक सामान्य वारंट द्वारा करने के लिए माना है, जिसके परिणामस्वरूप कारावास की वैधता पर निर्णय लेने के लिए अदालत की अधिकारिता से वंचित किया गया है, न कि सदन के विशेषाधिकार के मामले के रूप में और एक उच्च न्यायालय के रूप में उसके अधिकार के रूप में।

अब मैं न्यायिक आयोग के हाल के फैसलों का उल्लेख करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं।

समिति जिसने हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकार को भी कम कर दिया

(1) 113 ई. आर. 419.

विशेषाधिकार के आधार पर एक सामान्य वारंट द्वारा। पहला ए केस जिस पर मैं विचार करूँगा वह ग्लास का (1) केस है। वहाँ विक्टोरिया कॉलोनी की विधान सभा ने एक सामान्य वारंट द्वारा ग्लास को अवमानना के लिए जेल भेज दिया और मामले को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अदालत के समक्ष लाया गया। मैंने पहले कहा है कि कुछ कानूनों के तहत विधानसभा ने उन्हीं विशेषाधिकारों का दावा किया है जो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास थे। बी विक्टोरिया के सर्वोच्च न्यायालय ने ग्लास के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद मामले को न्यायिक समिति के पास ले जाया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि वहां यह तर्क दिया गया था कि "विशेषाधिकार अवमानना के लिए मूर्खतापूर्ण तरीके से कार्य करने का विशेषाधिकार है; कि बिना अपील के अवमानना का निर्णय लेना, और एक जनरल वारटेंट द्वारा कार्य करने की शक्ति, केवल इस देश में लागू होने वाली घटनाएं या दुर्घटनाएं हैं, और कॉलोनी को हस्तांतरित नहीं की गई हैं।" "यह देश" शब्द इंग्लैंड को संदर्भित करता है। लॉर्ड केर्न्स ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ इस तर्क को खारिज कर दिया: अवमानना का न्याय करने और एक सामान्य-वारंट द्वारा करने के तत्व शायद उन विशेषाधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो इस देश में हाउस ऑफ कॉमन्स के पास हैं और यह वास्तव में अजीब होगा यदि हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी विशेषाधिकारों और शक्तियों को स्थानांतरित करने की शक्ति के तहत, जो इस विशेषाधिकार और शक्ति का केवल एक हिस्सा और तुलनात्मक रूप से महत्वहीन हिस्सा होगा, उसे स्थानांतरित कर दिया गया। (पी। 573)। उन्होंने यह भी कहा, (पृ. 572) "सभी संदेहों से परे, विशेषाधिकारों में से एक और हाउस ऑफ कॉमन्स के सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकारों में से एक है -

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस देश में यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि हाउस ऑफ कॉमन्स को स्वयं न्यायाधीश बनने का अधिकार है जो अवमानना है, और एक वारंट द्वारा उस अवमानना के लिए यह कहते हुए कि प्रतिबद्धता आम तौर पर सदन के प्रलोभन के लिए है, यह निर्दिष्ट किए बिना कि अवमानना का चरित्र एफ क्या है। इसलिए, यह लगभग आवश्यक होगा कि कॉलोनी के विधानमंडल को कॉलोनी को हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों, उन्मुक्तिओं और शक्तियों को सौंपने की अनुमति दी गई है, और क़ानून की तारीख में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्रयोग किए गए सभी विशेषाधिकारों और शक्तियों को लागू करने के संदर्भ में, कॉलोनी की विधान सभा को अवमानना से जुड़े हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार या शक्ति-विशेषाधिकार या शक्ति, अर्थात्, अवमानना करने के लिए, अवमानना के बारे में खुद को न्याय करने के लिए, और एक वारंट द्वारा अवमानना करने के लिए आम तौर पर

यह कहते हुए कि अवमानना हुई थी। रिचर्ड के मामले में (2) एक सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होने की शक्ति पर विचार किया गया था।

सदन के विशेषाधिकार और लॉर्ड कैर्न्स (1) (1869-71) एल. आर. 3 पी. सी. 560 की टिप्पणियों के रूप में।

(2) 92 सी. एल. आर. 157, विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

517

ग्लास के (1) मामले में उस दृष्टिकोण के समर्थन में उद्धृत किया गया था। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस विचार को न्यायिक समिति द्वारा बरकरार रखा गया था:

रानी वी. रिचर्ड (2)। यह ध्यान देने योग्य है कि डिक्सन सी. जे. की राय थी, जैसा कि मैंने पहले दिखाया है, कि प्रतिबद्ध होने की शक्ति वैज्ञानिक रूप से अधिक उचित रूप से एक न्यायिक शक्ति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पाया कि यह तकनीकी रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स का एक विशेषाधिकार था और इसलिए एस द्वारा ऑस्ट्रेलियाई सदनों को हस्तांतरित किया गया था। 49 1901 का ऑस्ट्रेलियाई संविधान अधिनियम। यह.

यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि यह मामला वर्ष 1955 का था और यह दर्शाता है कि उस समय यह विचार था कि अपराध करने का अधिकार

एक सामान्य वारंट द्वारा सदन का विशेषाधिकार था। मैं यह केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह सुझाव दिया गया है कि भले ही यह एक विशेषाधिकार था, लेकिन यह त्याग से खो गया था। ये मामले बताते हैं कि

ऐसा नहीं है। फील्डिंग वी. थॉमस (3) भी यही विचार रखते हैं।

यह कहा गया था कि न्यायिक समिति के निर्णय थे

हम पर बाध्य नहीं। ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ।

यह दर्शाता है कि वे गलत हैं और इसलिए, वे कम से कम मूल्यवान हैं

प्रेरक अधिकारियों के रूप में। तथ्य यह है कि न्यायिक के निर्णय

समिति हम पर किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के रूप में बाध्यकारी नहीं है

क्या हाउस ऑफ कॉमन्स को कोई विशेष विशेषाधिकार प्राप्त था। हम. या तो उस विशेषाधिकार का न्यायिक संज्ञान लेना पड़ सकता है या इसका निर्णय लेना पड़ सकता है

विदेशी कानून के मामले के रूप में अस्तित्व। निर्णय लेना अनावश्यक है।

जो सही दृष्टिकोण है। यदि पूर्व, एस के तहत। 57 ईवीआई का

इन रिपोर्टों के संदर्भ में कार्य करना उचित होगा। तो दोनों में हम इन रिपोर्टों को देखने के हकदार हैं और क्योंकि उनमें शामिल हैं

इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालयों में से एक के निर्णय, हम नहीं हैं

यह कहने का अधिकार है कि जिसे वे हाउस ऑफ कॉम का विशेषाधिकार कहते हैं

उनके देश के राजा तब तक विशेषाधिकार नहीं हैं जब तक कि अन्य समान रूप से उच्च न हों

एक विपरीत दृष्टिकोण रखने वाला प्राधिकरण आने वाला है।

अब मैं कुछ अंग्रेजी मामलों पर आता हूं जिन पर प्रस्ताव दिया गया है

कि एक सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होने का अधिकार एक मामला नहीं है

हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार लेकिन एक अधिकार जो उसके पास था

एक उच्च न्यायालय है, जैसा कि मैंने विद्वान अधिवक्ता के तर्क को समझा है

उच्च न्यायालय के लिए, आधारित। मैं मामलों को क्रम में लूंगा

तिथि. इन मामलों के तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा।

और यह कहना पर्याप्त होना चाहिए कि उनमें से प्रत्येक ने अधिकार के साथ व्यवहार किया

हाउस ऑफ कॉमन्स का एक सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होना। सबसे पहले,

बर्डेट वी है। एबॉट (1)। इस मामले में, पहले अदालत के फैसले में

(1) (1869-71) एल. आर., 3 पी, सी, 560,

(2) 92 सी. एल. आर. 171

(3) [1896] ए. सी. 600

(4

) 104 ई. आर. 501 [1965] 1 एस. सी. आर.

518

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस मामले के संबंध में एलेनबरो सी. जे. और जे. बेले द्वारा सुझाव दिए गए थे। 189 वे कहते हैं, "यह ध्यान देने योग्य है कि बर्डेट बनाम के मामले में। एबॉट जबकि बेली जे. आराम कर रहे हैं

न्यायपालिका के न्यायालयों के साथ अपनी स्थिति की समानता पर प्रतिबद्ध होने का सदन का दावा, लॉर्ड एलेनबरो सी. जे. ने अपने निर्णय को समीचीनता के व्यापक आधार और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसी शक्ति की आवश्यकता पर आधारित किया है। इसलिए, एनसन के अनुसार, एलेन बरो सी. जे. स्पष्ट रूप से यह विचार नहीं रखता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक अदालत है और यह सब बे है। ली जे., उनके अनुसार, हाउस ऑफ कॉमन्स को सुपीरियर कोर्ट के साथ समानता में रखना है। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स एक अदालत थी, तो वहाँ। बेशक, इसे एक के साथ समानता में रखने का कोई सवाल ही नहीं था। इस निर्णय से सदन में एक अपील की गई थी

सलाह, "क्या, यदि सामान्य याचिकाओं का न्यायालय, निर्णय दे चुका है न्यायालय की अवमानना होने वाला कार्य, एक वारंट के तहत अवमानना के लिए किया गया था, जिसमें आम तौर पर विशेष परिस्थितियों के बिना इस तरह के निर्णय का उल्लेख किया गया था, और मामले को बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट पर लौटकर राजा की पीठ के समक्ष लाया गया था, जिसमें वारंट की स्थापना की गई थी, जिसमें आम तौर पर प्रलोभन के इस तरह के निर्णय का उल्लेख किया गया था; क्या उस मामले में राजा की पीठ का न्यायालय कैदी को रिहा कर देगा। क्योंकि जिन विशेष तथ्यों और संदर्भों से अवमानना उत्पन्न हुई थी, वे वारंट में नहीं दिए गए थे। बर्डेट वी। एबॉट (1)। न्यायाधीशों ने इस सवाल का जवाब नकारात्मक में दिया। उस पर लॉर्ड एल्डन ने उसे सौंप दिया

निर्णय जिसके साथ न्यायालय के अन्य सदस्य सहमत हुए, यह कहते हुए कि हाउस ऑफ कॉमन्स को एक द्वारा प्रतिबद्ध करने की शक्ति थी

सामान्य आदेश। मैं यह मानने में असमर्थ हूं कि यह मामला दर्शाता है कि

मोनस एक उच्च न्यायालय था। मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड एल्डन सोचा कि हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए

जिस तरह से एक उच्च न्यायालय ने दूसरे के साथ व्यवहार किया और पता लगाना चाहता था

अदालतें एक-दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करती थीं। मैं बाद में दिखाऊंगा कि यह है

अन्य में लॉर्ड एल्डन के निर्णय के बारे में लिया गया दृष्टिकोण

मामले। लेकिन अब मैं उल्लेख करूँगा कि अगर लॉर्ड एल्डन का मानना था कि

एनसन की श्रेष्ठता ने इस मामले को इस तरह से नहीं रखा होगा कि मैंने अभी-अभी उनके काम से पढ़ा है।

फिर मैं स्टॉकडेल बनाम के मामले पर आता हूं। हंसार्ड (2)। कि

मामले की सुनवाई लॉर्ड डेनमैन सी. जे., लिटलडेल जे., पैटसन जे. और

कोलरिज जे. लॉर्ड डेनमैन ने कहा, (पी। 1168),

(2) 112 ई. आर. 1112.

(1) 3 ई. आर. 1289.

विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

519

" इससे पहले कि मैं अंत में इस मुख्य तर्क से विदा ले लूं

लेकिन, मैं इस धारणा का निपटारा करूंगा कि सदन

कॉमन्स एक अलग न्यायालय है, जिसका विशिष्ट न्यायशास्त्र है। विषय-वस्तु पर, जिस पर, उस कारण से,

इसका निर्णय अंतिम होना चाहिए। तर्क दिया गया

आध्यात्मिक न्यायालय के स्तर पर सदन और

नौसेना का न्यायालय। इसे अपनाना। सादृश्य, यह

मुझे लगता है कि रक्षा के प्रयास को नष्ट करने के लिए

वर्तमान कार्रवाई। अब हम पूछ रहे हैं कि क्या विषय-वस्तु के अधिकार क्षेत्र में आता है

हाउस ऑफ कॉमन्स। यह तर्क दिया जाता है कि वे ला सकते हैं इसे उनके अधिकार क्षेत्र में घोषित करके। इसके लिए

दावा, उनके विशेषाधिकारों से उत्पन्न होने के रूप में, मैं पहले से ही है

मेरा जवाब दिया: यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी

न्यायालय निर्णय देकर स्वयं को अधिकार क्षेत्र दे सकते हैं

कि वे इसका आनंद लें। "

स्पष्ट रूप से लॉर्ड डेनमैन इस आधार पर आगे नहीं बढ़े कि कॉम मोनस एक अदालत थी। वास्तव में वह "से उत्पन्न होने वाले अधिकार" का उल्लेख करता है।

यह विशेषाधिकार "। फिर मुझे लगता है कि जे. लिटलडेल पी. पर देख रहे हैं। 1174 : " लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स में यह कार्यवाही उत्पन्न नहीं होती है

प्रतिकूल दावे; न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होती है।

वादी पक्षों के बीच निर्णय करने के लिए न्यायाधीश; लेकिन यह सदन है

कॉमन्स जो एकमात्र दल हैं जो क्या घोषणा कर रहे हैं

वे कहते हैं कि वे उनके हैं। इसलिए जे. लिटलडेल ने भी विचार नहीं किया।

एक अदालत के रूप में कॉमन्स। फिर पैटसन जे. आए जिन्होंने कहा कि

पी। 1185 , " हाउस ऑफ कॉमन्स अपने आप में न्यायालय नहीं है

संसद "। फिर पी पर। 1185 वह देखता है:

" मैं इस बात से इनकार करता हूं कि केवल हाउस ऑफ लॉर्ड्स का संकल्प

.....कानून के न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। . . . . .

हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव बहुत कम हो सकता है,

जो निर्णय के लिए न्यायिक न्यायालय नहीं है

वादी के बीच कानून या तथ्य का कोई प्रश्न

दल, अपने सदस्यों के चुनाव के संबंध में छोड़कर,

कानून के न्यायालयों पर बाध्यकारी होना।

अंत में मैं कॉलरिज जे. के पास आता हूँ। उन्होंने पी. 1196 :

" लेकिन यह कहा जाता है कि यह और अन्य सभी न्यायालय

कानून हाउस ऑफ कॉमन्स की गरिमा से कमतर है।

और इसलिए हमारे लिए इसकी समीक्षा करना असंभव है

निर्णय लें। यह तर्क मुझे एक पर आधारित प्रतीत होता है

कई विवरणों की गलतफहमी; सबसे पहले, किस में यह समझ में आता है कि यह न्यायालय सदन से कमतर है

कॉमन्स; अगला किस अर्थ में सदन एक न्यायालय है

सब कुछ "।

पी।

C.I./6

5-8 [1965] 1 एस. सी. आर.

20

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फिर पी। 1196 उन्होंने कहा:

" वास्तव में, सदन कानून का न्यायालय बिल्कुल नहीं है,

जिस अर्थ में केवल वह शब्द ही ठीक से हो सकता है

यहाँ लागू किया गया; न तो मूल रूप से, न ही अपील द्वारा, यह कर सकता है

दो पक्षों के बीच मुकदमेबाजी में किसी मामले का फैसला करना;

ऐसा करने का कोई साधन नहीं है; यह ऐसी किसी शक्ति का दावा नहीं करता है; शक्तियाँ

इसकी जांच और आरोप है, लेकिन यह नहीं तय करता है

न्यायिक रूप से, सिवाय इसके कि वह स्वयं एक पक्ष है,

अवमानना का मामला। उनके लिए डिग्री का कोई सवाल ही नहीं है। न्यायालयों के बीच उत्पन्न होता है; "

जे. कॉलरिज की टिप्पणियों का विशेष महत्व है

आसन्स इसके बाद दिखाई देंगे। यह स्पष्ट है कि न तो पैटसन जे।

या जे. कॉलरिज ने सोचा कि हाउस ऑफ कॉमिनन्स एक अदालत थी

उनके पास इस तरह की कोई भी शक्तियाँ थीं।

तारीख के क्रम में अगला मामला मिडिलसेक्स के शेरिफ (1) का है।

ऑर्ड डेनमैन, सी. जे. ने पी. 426 :

" प्रतिनिधि निकायों को अनिवार्य रूप से पुष्टि करनी चाहिए

अपने स्वयं के माध्यम से उनका अधिकार; और उन माध्यमों से अवमानना के लिए समर्पण की प्रक्रिया में झूठ बोलना। यह

केवल संसद के सदनों पर लागू नहीं होता है, लेकिन [के रूप में

बर्डेट वी में देखा गया था। मठाधीश (14 पूर्व, 138)],

न्याय के न्यायालयों को, जो, साथ ही सदनों को,

निरंतर बाधा और अपमान के लिए उत्तरदायी होना चाहिए यदि वे

उन्हें ऐसी शक्तियाँ नहीं सौंपी गई थीं। यह अनावश्यक है।

इस सवाल पर चर्चा करने के लिए कि क्या कैच हाउस ऑफ पार्लिया

न्यायालय नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए; यह स्पष्ट है कि वे नहीं कर सकते शक्ति के बिना अपने उचित कार्यों का प्रयोग करें

हस्तक्षेप से खुद को बचाएँ। का परीक्षण इस संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स का प्राधिकरण,

लार्ड एल्डन द्वारा बर्डेट v में न्यायाधीशों को प्रस्तुत किया गया।

एबॉट (5 डाउ, 199) ने कहा कि क्या, यदि न्यायालय ने

सामान्य याचिकाओं ने एक कार्य को अवमानना करार दिया था न्यायालय का, और इसके लिए प्रतिबद्ध, निर्णय बताते हुए

आम तौर पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण पर राजा की पीठ का न्यायालय वारंट जारी करना, कैदी को रिहा कर देगा

क्योंकि अवमानना के तथ्य और परिस्थितियाँ नहीं बताया गया। एक नकारात्मक जवाब दिया जा रहा है, भगवान

एल्डन, लॉर्ड एर्स्किन की सहमति से (जिनके पास था अधिकारिता के प्रयोग के प्रतिकूल होने से पहले),

और सदन से असहमति की आवाज के बिना, पुष्टि करें नीचे दिए गए निर्णय को संपादित करें। और हमें यह मान लेना चाहिए कि

(1) 113 ई. आर. 419.

विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

521

क्या कोई अदालत, बहुत अधिक क्या पार्लिया के सदन

मेंट, महान कानूनी अधिकार पर कार्य करते हुए, इसे लेता है अवमानना का उच्चारण करें, ऐसा ही है। "

यह अवलोकन उस बात का समर्थन करेगा जो मैंने इसके बारे में कहा है

बर्डेट बनाम में लॉर्ड एल्डन का निर्णय। एबॉट (1)। डेनमैन सी. जे. ने यह नहीं सोचा था कि लॉर्ड एल्डन हाउस ऑफ कॉमन्स को एक अदालत मानते थे क्योंकि उन्होंने स्वयं इस प्रश्न पर चर्चा करना अनावश्यक पाया था। जिस आधार पर उन्होंने सोचा कि हाउस ऑफ कॉमन्स को एक

सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होने का अधिकार होना चाहिए, वह उस कद के निकाय में समीचीनता और विश्वास का एक आधार था। कोलरिज जे. पी. पर अवलोकन करता है। 427 ,

" यह उदाहरणों से प्रतीत होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स

इस तरह से। इस सामान्य मामले में निर्णय लेने का उनका अधिकार अवमानना के मामलों में प्रपत्र विशेषाधिकार पर आधारित नहीं है,

लेकिन यह उन्हीं आधारों पर आधारित है जिन पर यह न्यायालय या

सामान्य याचिकाओं का न्यायालय एक समझौते के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है

प्रतिबद्धता में कोई कारण बताए बिना प्रलोभन दें। प्रभु।

एल्डन ने मामले को बर्डेट बनाम में इस तरह से रखा है। मठाधीश

(5 डाउ, 165,199)।"

जे. कॉलरिज के इस अवलोकन पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक गलत धारणा के कारण है। कोलरिज जे. पी. 427 एक्स प्रेसली स्टॉकडेल बनाम में उनके और अन्य न्यायाधीशों द्वारा कही गई सभी बातों की पुष्टि करता है। हंसार्ड (2)। · जैसा कि मैंने पहले दिखाया है, उन्होंने वहाँ कहा था कि "वास्तव में, सदन कानून का न्यायालय बिल्कुल नहीं है"। इससे पहले जब उन्होंने कहा कि सामान्य रूप में निर्णय लेने का अधिकार विशेषाधिकार पर आधारित नहीं था, उनका जो भी मतलब था, उनका मतलब यह नहीं था कि यह हाउस ऑफ कॉमन्स के एक अदालत होने पर स्थापित किया गया था। मुझे लगता है कि उनका मतलब यह था कि यह एक ऐसा अधिकार था जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स को अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करने के लिए प्राप्त करना था और इसलिए, इसे सम्मान और सम्मान के संकेत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। उनका यह भी मतलब हो सकता था कि शक्ति सदन के लिए कुछ विशिष्ट नहीं थी क्योंकि यह अदालतों के पास भी इसी कारण से थी, और इसलिए, यह एक विशेषाधिकार नहीं था, एक ऐसा शब्द जिसका उपयोग संसद के पास कुछ के अर्थ में किया गया है और जो अन्य निकायों या व्यक्तियों के पास से अधिक है: सी. एफ. 42 मई।

इसके बाद हावर्ड बनाम का मामला आता है। गोसेट (*)। यह होगा।

राजकोष न्यायालय के फैसले को संदर्भित करने के लिए पर्याप्त है अपील में कक्ष जो पी से शुरू होता है। 158. यह निर्णय पार्क बी. द्वारा दिया गया था, जिन्होंने पी. 171 :

(2)

112 ई. आर. 1112.

(1) 3 ई. आर. 1289.

(3) 116 ई. आर. 139.

522

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1965] 1 एस सी आर।

" अध्यक्ष का आदेश, हमारी राय में, वैध है,

ताकि सदन के अधिकारी को सुरक्षा मिले,

संसद के उच्च न्यायालय को केबल और इसकी प्रत्येक शाखा। ”

यहाँ फिर से सदन को समान सम्मान का हकदार माना जाता है।

एक उच्चतर न्यायालय के रूप में, लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि सदन एक उच्चतर न्यायालय है।

अंत में, मैं ब्रैडलॉफ वी. पर आता हूं। गोसेट (1) जिसमें पी। 285

स्टीफन जे. ने कहा, "हाउस ऑफ कॉमन्स न्याय का न्यायालय नहीं है। मैं यह देखने में असमर्थ हूं कि इन अधिकारियों के बारे में यह कैसे कहा जा सकता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स की सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होने की शक्ति उसके पास है क्योंकि यह एक उच्च न्यायालय है।

यह तब कहा गया था कि भले ही एक जनरल द्वारा करने का अधिकार हो

यह नहीं कहा जा सकता है कि वारंट हाउस ऑफ कॉमन्स के पास था क्योंकि यह उच्च न्यायालय था, इस विषय पर मामलों में टिप्पणियाँ, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें मैंने पहले ही संदर्भित किया है, यह स्थापित करेंगी कि अधिकार अदालतों के सामूहिकता के किसी नियम, या अनुमानित साक्षय या अदालतों और सदन के बीच एक समझौते से या अंत में पूर्व द्वारा बाद वाले को दिए गए किसी समझौते से उत्पन्न होता है। मैं तुरंत देखता हूं कि ये मामले विवाद का समर्थन नहीं करते हैं और न ही कोई पाठ्य-पुस्तक है

यह विचार लिया कि वे करते हैं या कि अधिकार एक विशेषाधिकार के अलावा कुछ भी है। मुझे आगे यह विवाद स्पष्ट रूप से गलत लगता है और

हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार की मूल प्रकृति को नजरअंदाज करता है। मैंने पहले विशेषाधिकार की प्रकृति बताई है लेकिन मैं इसे दोहराऊंगा। यहाँ। हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी विशेषाधिकार कानून पर आधारित हैं। उस कानून को लेक्स पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। अतः विशेषाधिकार हैं -

वे मामले जो हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकार में हैं। में।

स्टॉकडेल बनाम. हंसार्ड (2) सभी न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकार लेक्स पार्लियामेंट और उस कानून पर आधारित हैं जैसे

कोई अन्य कानून, देश का एक कानून है जिसका अदालतें हकदार हैं

प्रबंध करें।

अब अगर एक सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होने का विशेषाधिकार एक है

कानून में प्रवर्तनीय अधिकार जो हाउस ऑफ कॉमन्स से संबंधित है,

यह न्यायालयों के समिति के नियम द्वारा नियंत्रित मामला नहीं हो सकता है।

अदालतों की समिति केवल एक स्व-अधिरोपित प्रतिबंध है। यह कुछ है। जिसे अदालत अपने दम पर नहीं करने का फैसला करती है। यह वास्तव में एक नहीं है

कानून का शासन बिल्कुल भी। यह कोई लागू करने योग्य अधिकार नहीं बनाता है। एक 'अधिकार' विशेषाधिकार इसके आधार पर नहीं हो सकता है। इसके अलावा कोई सवाल नहीं है।

(2)

112 ई. आर. 1112.

(1) (1884) एल. आर. 12 क्यू. बी. डी. 271.

विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

न्यायालयों की समिति जब तक कि दो न्यायालय न हों, जिनमें से प्रत्येक दूसरे को सभ्यता या विचार प्रदान करता है। यहाँ हमारे पास हाउस ऑफ कॉमन्स और अदालतें हैं। पहला न्यायालय नहीं है और बाद वाले को अपने उचित कामकाज के लिए सदन से सभ्यता या विचार की आवश्यकता नहीं है। यहाँ न्यायालयों के सामूहिकता के किसी भी सिद्धांत को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

विशेषाधिकार के बारे में अगला वास्तव में एक नियम से ज्यादा कुछ नहीं है

यह अनुमान लगाते हुए कि हाउस ऑफ कॉमन्स का एक सामान्य वारंट किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से कैद करता है, ताकि समर्पण की वैधता के प्रश्न की अदालत द्वारा जांच करने की आवश्यकता न हो, मुझे लगता है कि यह कहा जाता है कि यह एक धारणा है जिसे कानून द्वारा बनाए जाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं है, तो सदन का अधिकार संबंधित न्यायाधीश के अनुग्रह पर निर्भर करेगा और इसलिए यह कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता और न ही ऐसा कहा जाता है कि ऐसा है। फिर क्या? यदि यह कानून का अनुमान है, तो वह कौन सा कानून है जिस पर अनुमान आधारित है? किसी का भी उल्लेख नहीं किया गया है और जहाँ तक मुझे पता है, कोई भी मौजूद नहीं है जब तक कि यह लेक्स पार्लियामेंट न हो। एक बार ऐसा कहने के बाद, यह वास्तव में लेक्स पार्लियामेंट के लिए विशेषाधिकार का विषय बन जाता है, यह धारणा एक विशेषाधिकार स्थापित करने के अलावा पैदा नहीं होगी। लेक्स पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया अधिकार एक विशेषाधिकार है। यह बात मैंने विशेषाधिकारों की प्रकृति पर चर्चा करते हुए पहले भी कही है।

अंत में, सदन के बीच समझौते में अपने मूल का अधिकार है

कॉमन्स और कानून की अदालतों की, या बाद वाले द्वारा पूर्व को दी गई रियायत में? यह एक नया तर्क है। मुझे किसी भी उदाहरण के बारे में पता नहीं है जहां एक अधिकार, और इसलिए, जिस कानून पर यह आधारित है, अदालतों के साथ एक समझौते द्वारा बनाया गया है। अदालतें कानून बिल्कुल नहीं बनाती हैं, कम से कम समझौते से; वे उनका पता लगाते हैं और उन्हें प्रशासित करते हैं। इसी कारण से, अदालतें रियायत से कानून नहीं बना सकती हैं। अदालत को कानून के सवाल को स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि कानून पहले से मौजूद न हो। मुझे यह कल्पना करना असंभव लगता है कि कोई भी संसदीय विशेषाधिकार जो एक प्रवर्तनीय अधिकार पैदा करता है, समझौते द्वारा अस्तित्व में लाया जा सकता है।

अदालतों के साथ या उनके द्वारा दी गई रियायत से।

इससे पहले कि मैं वर्तमान विषय के साथ भाग लेता, मैं स्वतंत्रता लूंगा

यह देखते हुए कि हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों के बारे में नए विचार शुरू करना हमारे लिए नहीं है, ऐसे विचार जिनकी इंग्लैंड में कभी कल्पना नहीं की गई थी। हमारा काम अपने स्वयं के शोधों द्वारा विशेषाधिकारों के बारे में एक नवाचार शुरू करना नहीं है। इन नए विचारों को अंग्रेजी मामलों में निर्णयों में विषम टिप्पणियों पर आधारित करना असुरक्षित होगा, जो उनके संदर्भ से बाहर हैं और जिस उद्देश्य के लिए उन्हें बनाया गया था, उसकी अवहेलना करते हैं। इन मामलों से मैंने जो उद्धृत किया है, वह कम से कम एक विराम लाएगा और सोचेगा कि ये मामले 524 के सदन के अधिकार के बारे में एक नए सिद्धांत के लिए कोई निश्चित आधार प्रदान नहीं कर सकते हैं।

कॉमन्स को एक सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होना है। अंग्रेजी के पुराने इतिहास पर किए गए शोध वर्तमान संदर्भ में पूरी तरह से अनुचित हैं और जो अधिक है, वह गलत धारणाओं को जन्म दे सकता है। प्राचीन वस्तुओं में शोध पर विशेषाधिकारों के बारे में हमारे निष्कर्ष को आधार बनाने के लिए, इस सवाल के लिए एक गलत प्रक्रिया होगी कि 1950 में हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों को क्या मान्यता दी गई थी। 1950 में उस अवधि के शोध जब ये विशेषाधिकार बी आकार ले रहे थे, उनकी सामग्री और प्रकृति का कोई जवाब नहीं दे सकते। इस प्रश्न का उत्तर केवल यह सुनिश्चित करके दिया जा सकता है कि क्या चर्चा के तहत अधिकार को 1950 से पहले के वर्षों में इंग्लैंड में आधिकारिक राय द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार के रूप में माना गया था।

फिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि एक सामान्य वारंट द्वारा प्रलोभन के लिए प्रतिबद्ध होने का अधिकार जिसके परिणामस्वरूप वंचित किया जाता है उस समिति की जांच करने के लिए कानून की अदालतों की अधिकारिता हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार है। यह विशेषाधिकार, मेरे विचार में, पहले बताए गए कारणों से, उत्तर प्रदेश के पास है।

अनुच्छेद के कारण सभा। 194 (3) संविधान से।

तब यह कहा जाता है कि विधानसभा के विशेषाधिकार का प्रयोग वह केवल एक नागरिक के मौलिक अधिकारों के अधीन ही कर सकता है

संविधान द्वारा गारंटीकृत। यह मुझे शर्मा के मामले (1) पर ले जाता है। जैसे ही मैंने उस मामले में बहुमत के फैसले को पढ़ा, मुझे लगता है कि वे हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों को मानते हैं

जो अनुच्छेद द्वारा राज्य विधानमंडल के सदनों को प्रदान किए गए थे।

194 (3) , मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दें। तथ्य ये थे। बिहार विधानमंडल का एक सदन जिसने भी कोई गलती नहीं की अनुच्छेद के तहत अपने विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाली कानून। 194 (3) , इसकी कार्यवाही के कुछ हिस्सों को हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद

याचिकाकर्ता ने अपने एफ में कार्यवाही का पूरा विवरण प्रकाशित किया

कागज जिसमें वह भी शामिल है जिसे हटा दिया गया था। इसके बाद नोटिस जारी किया गया था।

सदन द्वारा उन्हें कारण दिखाने के लिए जारी किया गया कि कदम क्यों नहीं उठाए जाने चाहिए

सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। द.

उस मामले में दावा किया गया विशेषाधिकार प्रकाशन को प्रतिबंधित करने का अधिकार था

उसकी कार्यवाही के बारे में। याचिकाकर्ता, अखबार का संपादक, तब

अनुच्छेद के तहत एक याचिका दायर की। 32 संविधान का कहना है कि जी

विशेषाधिकार ने स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार को नियंत्रित नहीं किया

अनुच्छेद के तहत भाषण। 19 (1) ((क) और इसलिए सदन ने

उसके खिलाफ कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी विवाद किया कि

हाउस ऑफ कॉमन्स को वह विशेषाधिकार प्राप्त था जो बिहार विधानसभा को था

दावा किया। बहुमत का मानना था कि सदन को विशेषाधिकार प्राप्त है

इसकी कार्यवाहियों के प्रकाशन को प्रतिबंधित करना और वह विशेषाधिकार था

जो अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के मौलिक अधिकार के अधीन नहीं है।

(1) [1959) सप. 1 एससीआर 806।

विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

525

19 (1) (ए)। जे. सुब्बा राव ने एक असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि

सदन को जनता को प्रतिबंधित करने का विशेषाधिकार नहीं था इसकी कार्यवाहियों का विवरण। बाद के सवाल के साथ हम सहमत नहीं हैं।

वर्तमान मामले में। परिणामस्वरूप शर्मा की (1) याचिका थी बर्खास्त कर दिया।

उच्च न्यायालय की ओर से दो बिंदु लिए गए हैं।

इस मामले को ध्यान में रखें। पहले यह कहा गया था कि बहुमत का फैसला

पुनर्विचार की आवश्यकता थी और फिर यह कहा गया कि किसी भी स्थिति में,

उस फैसले में केवल यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वहाँ दावा किया गया विशेषाधिकार पूर्व में लिया गया था

ऐसा नहीं है कि किसी अन्य विशेषाधिकार को मौलिक से अधिक प्राथमिकता दी गई है अधिकार। मैं इनमें से किसी भी तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

विधानसभा की ओर से यह बताया गया है कि

अनुच्छेद के तहत संदर्भ। 143 हमारे पास अलग रखने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

इस न्यायालय का पूर्व निर्णय, क्योंकि हमें अपना उत्तर देना होगा

कानून पर निर्दिष्ट प्रश्न और इस न्यायालय का निर्णय जब तक यह निश्चित रूप से कानून निर्धारित करता है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह विवाद व्यर्थ है। उच्च न्यायालय की ओर से यह कहा गया था कि पुनः। दिल्ली विधि अधिनियम (2) एक प्रश्न उठा

क्या संघीय न्यायालय का निर्णय, जिसे हमारे संविधान के तहत हमारे निर्णयों के समान अधिकार प्राप्त है, सही था। यह तर्क दिया जा सकता है कि यह मामला मदद नहीं करता है, क्योंकि पूछे गए प्रश्न के लिए पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी। मुझे नहीं।

इस विषय पर आगे चर्चा करने का प्रस्ताव है, क्योंकि मैं सभा के तर्क के पक्ष में इतनी दृढ़ता से महसूस नहीं करता कि मुझे इस प्रश्न पर अपने विद्वान भाइयों के दृष्टिकोण से अलग होना चाहिए।

हालाँकि, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुमत में निर्णय

शर्मा का मामला (1) पूरी तरह से सही था जब उसने माना कि विशेषाधिकार मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं थे। मैंने पहले अनुच्छेद के पहले तीन खंड निर्धारित किए हैं। 194. पहला खंड स्पष्ट रूप से संविधान के प्रावधानों के अधीन बनाया गया था-चाहे जो भी प्रावधानों पर विचार किया गया हो-जबकि तीसरा खंड ऐसा विषय नहीं बनाया गया था। बहुमत और अल्पमत दोनों निर्णय इस बात पर सहमत हैं कि तीसरे खंड को इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता है जैसे कि इसे स्पष्ट रूप से संविधान के प्रावधानों के अधीन बनाया गया हो। अपने लिए, मुझे नहीं लगता कि कोई और पढ़ना संभव है। अनुच्छेद का खंड (3)। 194 इस प्रकार स्पष्ट रूप से संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन नहीं किए जाने के कारण, इसके और संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान के बीच संघर्ष, जो मौजूद पाया जा सकता है, को कैसे हल किया जा सकता है? बहुमत ने माना कि

(2)

[1951] एससीआर 747।

(1) [1959] सप. 1 एससीआर 806।

{

1965] 1 3. सी. आर.

526

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को दोनों और अनुच्छेद के पुनर्मिलन के लिए लागू किया जाना चाहिए। 194 (3) एक विशेष प्रावधान होना चाहिए

अनुच्छेद में उल्लिखित मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दें। 19 (1) (क) जो एक सामान्य प्रावधान था: (पी। 860)। हालांकि जे. सुब्बा राव ने कहा कि कोई अंतर्निहित विसंगति शर्त नहीं थी

वेन आर्ट। 19 (1) ((क) और अनुच्छेद। 194 (3) , फिर भी उन्होंने सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को लागू किया। उन्होंने महसूस किया कि जब से विधायिका

यदि शक्तियों और विशेषाधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है और उन विशेषाधिकारों का उपयोग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना किया जा सकता है, तो विशेषाधिकार मौलिक अधिकार को दिया जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि इस निर्माण ने दोनों लेखों को पूरा प्रभाव दिया: (पीपी। 880-1) . विद्वान न्यायाधीश के प्रति बहुत सम्मान के साथ, मुझे यह अनुसरण करना मुश्किल लगता है कि कैसे इस व्याख्या ने दोनों लेखों के प्रभाव का परिणाम दिया और इस प्रकार एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण प्राप्त किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेदओं के बीच कोई टकराव नहीं है। 194 (3) और

19 (1) (क), क्योंकि वे अलग-अलग मामलों से निपटते हैं। पूर्व में कहा गया है कि राज्य विधानमंडलों के पास अंग्रेजी हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे जबकि अनुच्छेद। 19 (1) (क) में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को बोलने की पूरी स्वतंत्रता होगी। संघर्ष

हालाँकि यह तब सामने आता है जब हम अनुच्छेद के तहत दावा किए गए विशेष विशेषाधिकारों पर विचार करते हैं। 194 (3) . जब अनुच्छेद। 194 (3) यह कहता है कि राज्य विधानमंडलों के पास कुछ विशेषाधिकार होंगे, यह वास्तव में उन विशेषाधिकारों को अपने आप में शामिल करता है। इसलिए, अनुच्छेद का उचित अध्ययन। 194 (3) यह है कि यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडलों को अन्य विशेषाधिकारों के अलावा, इसकी किसी भी कार्यवाही के प्रचार को प्रतिबंधित करने का विशेषाधिकार है। तभी अनुच्छेदओं के बीच संघर्ष होता है। 194 (3) और 19 (1) (ए) देखा जा सकता है; एक कुछ प्रकाशित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है जबकि दूसरा कहता है कि सभी चीजें हो सकती हैं

प्रकाशित हुआ। मेरा मानना है कि शर्मा के मामले (1) में सभी न्यायाधीशों द्वारा लेखों को इसी तरह पढ़ा गया था। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो दोनों प्रावधानों के बीच टकराव या उनके बीच सुलह का कोई सवाल ही नहीं होता।

अब अगर अनुच्छेद। 19 (1) (क) प्राथमिकता होनी चाहिए, तो एक नागरिक के पास है

उन्हें जो भी पसंद हो उसे प्रकाशित करने की पूरी स्वतंत्रता है; वह सदन में प्रो सीडिंग प्रकाशित कर सकते हैं, भले ही सदन ने उनके पब लाइसेंस पर प्रतिबंध लगा दिया हो। लेकिन उस पढ़ने का परिणाम अनुच्छेद के उस हिस्से को मिटा देना है। 194 (3) जिसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडलों को अपनी कार्यवाही के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने की शक्ति और

विशेषाधिकार होगा। इसे शायद ही प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण पठन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, एक ऐसा पठन जो दोनों प्रावधानों को प्रभावी बनाता है। यह एक ऐसा पठन है जो प्रावधानों में से एक को प्रभावी बनाता है और दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि यह मौजूद नहीं था।

(1) (1959) सप. 1 एससीआर 806।

विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

527

यह सच है कि अगर अनुच्छेद। 19 (1) (ए) प्रबल, यह मिटा नहीं होगा

हाउस ऑफ कॉमन्स के अन्य सभी विशेषाधिकार जिन्हें होना था अनुच्छेद में पढ़ें। 194 (3) . इस प्रकार सदन का बहिष्कृत करने का अधिकार

प्रकाशन को प्रतिबंधित करने का अधिकार होने पर भी अजनबी बरकरार रहे कार्यवाही को अनुच्छेद द्वारा नष्ट कर दिया गया था। 19 (1) (ए)। लेकिन ऐसा नहीं है।

अजनबियों और बोलने की स्वतंत्रता और सुलह का कोई सवाल नहीं सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम से दोनों का उदय हुआ। जब एक

केवल एक प्रावधान का एक हिस्सा दूसरे प्रावधान के साथ संघर्ष में है,

दोनों को क़ानून की पुस्तक से मिटा कर सुलझा नहीं लिया जाता है यह कहते हुए कि दोनों प्रावधान इस प्रकार किए गए हैं

सामंजस्यपूर्ण क्योंकि इस तरह के विलोपन के बाद बाकी पहले और पूरे दूसरे काम करते हैं। हम सामंजस्य के बारे में चिंतित हैं

दोनों को सर्वोत्तम संभव प्रभाव देकर दो परस्पर विरोधी प्रावधान और यह गॉर्डियन गाँठ को काटकर नहीं किया जाता है

कानून से बाहर विरोधाभासी भाग।

मैं इस बात से सहमत हूं कि अनुच्छेद के बीच संघर्ष को देखते हुए। 194 (3) और

अनुच्छेद. 19 (1) (क), जो पहले बताए गए तरीके से उत्पन्न होता है, उसे सामंजस्यपूर्ण निर्माण द्वारा हल किया जाना चाहिए। जैसा कि मैं समझता हूँ

सिद्धांत, यह है। जब विधानमंडल-यहाँ संविधान

निर्माता-उन दोनों प्रावधानों को अधिनियमित किया जिन्हें वे दोनों प्रभावी बनाने का इरादा रखते थे। यदि संयोग से ऐसा होता है कि दोनों का पूर्ण प्रभाव नहीं हो सकता है, तो विधायिका के इरादे को उन प्रावधानों को देकर सबसे अच्छी तरह से पूरा किया जाएगा जो उन दोनों को सबसे अधिक प्रभाव देने का प्रभाव डालेंगे। मेरा मानना है कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम के पीछे यही सिद्धांत है। आवेदन करना

शर्मा के मामले में वह नियम (1), यदि अनुच्छेद के तहत विधायिका द्वारा दावा किया गया विशेषाधिकार। 194 (3) कार्यवाहियों के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने का पूर्ण प्रभाव दिया गया था, अनुच्छेद। 19 (1) (क) संविधान से पूरी तरह से मिटा नहीं दिया जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी

अंतिम उल्लिखित अनुच्छेद अन्य मामलों के संबंध में लागू रहेगा। यदि, इसके विपरीत अनुच्छेद। 19 (1) (क) पूर्ण प्रभाव रखने के लिए था, अर्थात, एक नागरिक को कुछ भी कहने और प्रकाशित करने की स्वतंत्रता थी। जिसे वह पसंद करता था, फिर अनुच्छेद का वह हिस्सा। 194 (3) जो कहता है कि सदन अपनी कार्यवाही के प्रकाशन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकता है

नष्ट कर दिया गया, यह ऐसा है जैसे इसे संविधान में कभी नहीं रखा गया था। यह, मेरे विचार से, शायद ही संविधान का उद्देश्य या उचित पठन हो सकता है। मैं इन कारणों से कहूंगा कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण का नियम शर्मा के मामले (1) में बहुमत द्वारा की गई व्याख्या का समर्थन करता है।

जे. सुब्बा राव ने एक और कारण बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा

मानसिक अधिकारों को विशेषाधिकारों पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए

(1) [1959] सप. 1 एससीआर 806।

सुपर

न्यायालय

रि

पोर्टें

विधानमंडल और इस पर भी विद्वान वकील ने वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ए पर भरोसा किया। जे. सुब्बा राव ने कहा कि 194 (3) किस अनुच्छेद के तहत है।

राज्य विधानमंडल ने इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के समान प्रिवी लेज का दावा किया, जिसे कहा गया है

इस खंड का दूसरा भाग, स्पष्ट रूप से एक अस्थायी दृष्टि थी क्योंकि इसका प्रभाव तब तक होना था जब तक कि विधानमंडल एक परिभाषित कानून नहीं बनाता।

संविधान निर्माताओं के रूप में विशेषाधिकारों के लिए बी का इरादा होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि और जब उस कानून विधानमंडल ने ऐसा किया

यह मौलिक अधिकारों के अधीन होगा और यह अजीब होगा यदि इसके अस्थायी प्रावधानों को स्वतंत्र माना जाए।

उन अधिकारों को। शर्मा के मामले में बहुमत (संदेह के बिना कहा गया 1) अनुच्छेद 194 (3) के तहत बनाई गई कोई चर्चा नहीं। सभी मौलिक अधिकारों के अधीन होगा। हालाँकि सभा के लिए जाने-माने अधिवक्ता ने हमारे सामने तर्क दिया कि

दृष्टिकोण उचित नहीं था। वर्तमान मामले में मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो भी दृष्टिकोण लिया जाता है। मान लीजिए कि कानून ने बनाया है

अपने विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाले विधानमंडल को मौलिक मानसिक अधिकारों के अधीन होना चाहिए। लेकिन ऐसा केवल आर्ट रियली के कारण होगा। 13 ऐसा कहते हैं।

अनुच्छेद के तहत बनाया गया कानून। 194 (3) इसे उप के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए

मौलिक अधिकारों के बारे में; स्थिति यह है कि यदि वह कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ संघर्ष करता है, तो यह उतना ही अच्छा है जितना कि बिल्कुल नहीं बनाया गया है।

यही अनुच्छेद का प्रभाव है। 13. तर्क है कि चूंकि अनुच्छेद के तहत बनाए गए कानून। 194 (3) मौलिक अधिकारों के अधीन हैं, इसलिए सी. एल. के दूसरे भाग द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों को भी होना चाहिए। (3) हो, क्या वहाँ है-ई एक गलत धारणा पर आधारित है। अनुच्छेद 13 किसी कानून को खराब बनाता है यदि वह

मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष। यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि क्योंकि अनुच्छेद। 13 सी. एल. के तहत बनाए गए कानून बना सकते हैं। (3) अनुच्छेद की। 194 शून्य, उस खंड के दूसरे भाग द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार भी शून्य होने चाहिए। अनुच्छेद 13 संविधान के किसी प्रावधान पर लागू नहीं होता है। यह केवल राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को नियंत्रित करता है। 194 (3) नहीं है। इसलिए, मुझे समझ नहीं आता कि यह क्यों माना जाना चाहिए कि विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाला कानून यदि बनाया जाता है, तो यह अमान्य हो जाएगा यदि मौलिक अधिकारों के साथ टकराव में, विशेषाधिकारों में शामिल हैं।
अनुच्छेद. 194 (3) —मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अनुच्छेद का दूसरा भाग ऐसा ही है। 194 (3) पढ़ा जाना चाहिए-मौलिक अधिकारों के अधीन होने का भी इरादा होना चाहिए। अगर ऐसा इरादा था, तो जी

सी. एल. (3) इसकी शुरुआत इस प्रावधान के साथ हुई होगी कि यह संविधान के अधीन होगा। तथ्य यह है कि सीएल में। (1) 'इस संविधान के प्रावधानों के अधीन' शब्द तब आते हैं जब उन्हें सी. एल. से हटा दिया जाता है। (3) यह एक मजबूत संकेत है कि बाद वाला खंड इस तरह के विषय होने का इरादा नहीं था। इसके अलावा, यह इरादा नहीं हो सकता था क्योंकि तब वह विशेषाधिकार जिसके साथ वर्तमान मामला संबंधित है, अर्थात्, एक जनरल द्वारा अवमानना के लिए प्रतिबद्ध होना।

1. [1959] सप. 1 एससीआर 806।

विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

529

अदालत की समीक्षा के अधीन किए बिना वारंट का संविधान से सफाया कर दिया जाएगा क्योंकि एक मानसिक अधिकार की आवश्यकता होती है कि अदालतों में स्वतंत्रता के प्रत्येक अभाव की वैधता की जांच की जाएगी।

यह भी कहा गया था कि मौलिक अधिकार दिव्य हैं। आई.

पता नहीं इसका क्या मतलब है। यदि वे दिव्य हैं तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि संविधान ने उन्हें ऐसा बनाया है। अनुच्छेद द्वारा संविधान में कोई संदेह नहीं है। 13 यह विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के अधीन बनाता है, लेकिन मुझे नहीं पता, और न ही हमें यह बताया गया है कि संविधान किस अन्य तरीके से मौलिक अधिकारों को दिव्य बनाता है। हम उन चीजों को संविधान में पढ़ने के हकदार नहीं हैं जो वहां नहीं हैं। हम निश्चित रूप से यह कहने के हकदार नहीं हैं कि संविधान में एक विशिष्ट प्रावधान का कोई प्रभाव केवल इसलिए नहीं है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के साथ टकराव में है, या क्योंकि बाद वाले अपनी प्रकृति से हैं, हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं।

ऐसा किया गया, दिव्य।

फिर अनुच्छेद के दूसरे भाग के बारे में। 194 (3) अस्थायी होने के नाते,

यह इस बात पर निर्भर करता है कि संविधान निर्माताओं की मंशा क्या थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्रावधान किया गया था कि जब कानून बनाया गया था

अनुच्छेद के पहले भाग के तहत विधानमंडल। 194 (3) उस प्रावधान के उत्तरार्ध के तहत प्राप्त हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे यह पता चलता है कि दूसरा भाग अस्थायी था। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि संविधान निर्माताओं का इरादा था कि विधानमंडल को अपने विशेषाधिकारों को परिभाषित करने के लिए अपना कानून बनाना चाहिए। संविधान निर्माताओं के समक्ष 1950 में जब उन्होंने संविधान बनाया था, ऑस्ट्रेलियाई संविधान अधिनियम, 1901 में कमोबेश इसी तरह के प्रावधान थे और वे जानते थे कि पचास वर्षों के दौरान, ऑस्ट्रेलिया में वहां के विधानमंडलों के सदनों के विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाले कानून नहीं बनाए गए थे, लेकिन सदन अपने संविधान द्वारा उन्हें प्रदान किए गए हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों को जारी रखने के लिए संतुष्ट थे। उनके सामने इस उदाहरण के साथ मेरे पास यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हमारे संविधान में इसी तरह का प्रावधान किया था, तो वे चाहते थे कि हमारे विधानमंडल अपने विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाले कानून बनाए और अनुच्छेद के दूसरे भाग द्वारा उन्हें प्रदान किए गए हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों से छुटकारा पाए। 194 (3) . मुझे लगता है कि यह कहना भी सही है कि भले ही अनुच्छेद के दूसरे भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार हों। 194 (3) अस्थायी थे, जो एक पठन को उचित नहीं ठहराएंगे, जिसका परिणाम संविधान से किसी भाग या उसे हटाना होगा।

इस स्तर पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि गणपति केशव में

राम रेड्डी बनाम। नफीसुल हसन (1) उनकी अदालत ने गिरफ्तारी का फैसला सुनाया

(1) ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 636.

[

1965] 1 एस सी आर।

530

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद द्वारा आवश्यक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए बिना उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेषाधिकार हनन के लिए अध्यक्ष के आदेश के तहत एक नागरिक। 22 (2) संविधान का उल्लंघन वहां उल्लिखित मौलिक अधिकार का उल्लंघन था। रेड्डी के मामले (1) में कहा गया है कि नहीं

लिए गए दृष्टिकोण के समर्थन में कारण। जे. सुब्बा राव, हालाँकि उन्होंने इसे देखा, फिर भी वे इससे बंधे हुए महसूस करते थे। बहुमत ने यह देखते हुए ऐसा नहीं किया कि वहां का निर्णय वकील द्वारा रियायत पर आगे बढ़ा। इस न्यायालय में उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पहले के मामले में कोई रियायत नहीं थी। मैंने देखा कि दास सी. जे., जिन्होंने शर्मा के मामले (1) में बहुमत का फैसला सुनाया, उस बीच के सदस्य थे जिसने रेड्डी के मामले (1) का फैसला किया। यदि रेड्डी के मामले (1) में निर्णय कम से कम इस अर्थ में नहीं था कि विद्वान अधिवक्ता इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई तर्क देने में असमर्थ था कि विशेषाधिकार मौलिक अधिकार का स्थान लेता है, तो यह अजीब होगा कि निर्णय में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई थी। हालाँकि यह सब इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि निर्णय से ऐसा नहीं लगता कि रेड्डी के मामले (1) में यह तर्क दिया गया है कि यह अनुच्छेद का दूसरा भाग है। 194 (3) उन्होंने ऐसे विशेषाधिकार सृजित किए जिन्हें मानसिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई, क्योंकि निर्णय में लिए गए दृष्टिकोण के समर्थन में कोई कारण नहीं बताया गया है, अपने लिए मुझे रेड्डी के मामले का पालन नहीं करने में कोई कठिनाई नहीं है (1) विशेष रूप से शर्मा के मामले (1) में बहुमत ने इसका पालन नहीं किया।

यह भी कहा गया था कि विशेषाधिकारों का उद्देश्य केवल विधानमंडलों को सुचारू रूप से और बिना किसी बाधा के संचालित करना था। द. यह बताया गया कि विधानमंडलों का मुख्य कार्य कानून बनाना था और विशेषाधिकारों का उद्देश्य उस कार्य के उचित निर्वहन में सहायता करना था। यह तर्क दिया गया था कि यदि किसी विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, जिनके निर्माण के लिए वे मुख्य रूप से मौजूद हैं, मौलिक अधिकारों के अधीन हैं, तो यह उत्सुक है कि कुछ ऐसा जो उस प्राथमिक कार्य के लिए सहायक है, उनसे मुक्त होना चाहिए। मुझे इसमें कुछ

भी अजीब नहीं लगता। विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून मौलिक अधिकारों के अधीन हैं क्योंकि संविधान ऐसा कहता है। विशेषाधिकार विषय नहीं हैं क्योंकि वे स्वयं संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं और न तो उन्हें विषय बनाया गया है और न ही ऐसी उचित व्याख्या पर पाया गया है।

मेरा मानना है कि मैंने अब आगे बढ़े सभी कारणों पर चर्चा की है।

इस विचार का समर्थन कि शर्मा के मामले (3) में बहुमत का निर्णय गलत था। जैसा कि मैंने कहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कारण सही हैं।

(2) (1959) सप. 1 एससीआर 806।

1 ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 636.

विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

531

आर. के. करंजिया बनाम माननीय श्री एम. अनंतसायनम

अयंगर, अध्यक्ष, लोकसभा (1961 का डब्ल्यू. पी. संख्या 221 अप्रकाशित संस्करण), जो अनुच्छेद के तहत एक याचिका थी। 32 संविधान के अनुसार, इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ को शर्मा के मामले (1) में बहुमत के निर्णय की शुद्धता पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने उस निर्णय को सही माना और याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह अभिनिर्धारित करने का एक और कारण है कि शर्मा के मामले (1) का सही निर्णय लिया गया था।

अब मैं शर्मा के बारे में दूसरे विवाद पर आता हूं।

मामला (1)। यह कहा गया था कि बहुमत के फैसले में यह सब हुआ

वह मामला यह था कि सी. एल. के दूसरे भाग द्वारा किसी विधानमंडल को प्रदत्त अपने पक्षकारों के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने का विशेषाधिकार। (3) अनुच्छेद की। 194 यह अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अधीन नहीं था। 19

(1) (ए)। यह इंगित किया गया था कि उस मामले में यह नहीं कहा गया था कि के दूसरे भाग के तहत सभी विशेषाधिकार

अनुच्छेद. 194 (3) सभी मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात पर जोर दिया गया कि दास सी. जे. ने उस मामले में दिए गए तर्क से निपटा कि अनुच्छेद। 21 के अभ्यास द्वारा उल्लंघन किया जाएगा

सदन का यह कहते हुए अवमानना करने का विशेषाधिकार कि वहाँ यह अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होगा। 21 गिरफ्तारी के अनुसार होगा

गिरफ्तारी और निरोध के कारण कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के लिए

सदन द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार होगा

अनुच्छेद के तहत। 208. यह तर्क दिया गया था कि इसलिए बहुमत ने माना

कि अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार। 21 पहले ले लेंगे प्रतिबद्ध होने के विशेषाधिकार पर समर्पण।

यह तर्क मुझे भी स्वीकार्य नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि शर्मा

मामला (1) अनुच्छेद के बीच संघर्ष से संबंधित था। 19 (1) (अ)

और अनुच्छेद के दूसरे भाग के तहत सदन का विशेषाधिकार।

194 (3) इसकी कार्यवाहियों के प्रकाशन को प्रतिबंधित करना और इसलिए,

अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लेख करना अनावश्यक था। द.

कारण, हालांकि, जिसके कारण बहुमत ने माना कि संघर्ष

दोनों के बीच को प्राथमिकता देकर हल करना था

कई लोगों के बीच संघर्ष की स्थिति में विशेषाधिकार उपलब्ध होगा।

अन्य विशेषाधिकार और कई अन्य मौलिक अधिकार। अब कि कारण यह था कि संघर्ष को हल करने के लिए, सामंजस्य का नियम

निर्माण को लागू करना पड़ा और उसका परिणाम यह होगा कि मौलिक अधिकार, जो उनके स्वभाव में सामान्य थे, को

उन विशेषाधिकारों को स्वीकार करें जो विशेष थे। पूरा फैसला

उस मामले में बहुमत यह था कि जब एक संघर्ष शर्त थी

अनुच्छेद के दूसरे भाग द्वारा सृजित एक विशेषाधिकार। 194 (3) और ए

मौलिक अधिकार, उस संघर्ष को सामंजस्य बनाकर हल किया जाना चाहिए उन दोनों को। यह निर्णय निश्चित रूप से संघर्ष पर लागू होगा

(1) [1959] सप. 1 एससीआर 806।

[1965] 1 एस सी आर।

532

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक द्वारा अवमानना के लिए जेल के लिए समर्पण के विशेषाधिकार के बीच

उस वारंट की वैधता की समीक्षा किए बिना सामान्य वारंट कानून की अदालत और द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों द्वारा

अनुच्छेदएँ। 21 , 22 और 32. बहुमत का निर्णय प्राधिकरण होगा। यह मानने के लिए कि संघर्ष को एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए

निर्माण। वास्तव में अल्पसंख्यकों का भी यही दृष्टिकोण था। द.

अंतर वास्तविक निर्माण के बारे में था।

दास सी. जे. ने निस्संदेह कहा कि अनुच्छेद का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। 21 में

शर्मा का मामला (1) क्योंकि स्वतंत्रता से वंचित करना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार था। यह, मेरे दिमाग में, केवल एक था

वैकल्पिक कारण, क्योंकि वह उस बिंदु पर उसी कारण से विचार कर सकते थे जिस पर उन्होंने कहा था कि यह अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है। 19 (1) (क) पब को प्रतिबंधित करने के सदन के विशेषाधिकार के आगे झुकना चाहिए।

एकर कार्यवाहीक अनुज्ञप्ति, अर्थात्, सामंजस्यपूर्ण निर्माणक नियमक प्रयोग द्वारा। वह उसी तर्क से कह सकते थे जिसका उन्होंने कार्लियर का उपयोग किया था, कि मौलिक अधिकार की

गारंटी अनुच्छेद. 21 सामान्य था और एक सामान्य युद्ध राग द्वारा हिरासत में लेने का विशेषाधिकार एक विशेष प्रावधान था और इसलिए, प्रबल होना चाहिए। मैं अनुच्छेद पर आधारित तर्क से निपटने में असमर्थ हूं। 21 जिस तरह से उन्होंने किया, दास सी. जे. ने माना कि अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है। 21 सी. एल. के दूसरे भाग के तहत विधानमंडल के पास एक सामान्य वारंट द्वारा समर्पण के विशेषाधिकार को प्राथमिकता दी गई। (3) अनुच्छेद की। 194. यदि उन्होंने ऐसा किया होता, तो कोई कारण नहीं होता कि उन्हें यह मानना चाहिए था कि बोलने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सदन की कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने के विशेषाधिकार के अधीन होना चाहिए। यह कहने का एक और कारण है कि दास सी. जे. उस अनुच्छेद को नहीं मानते थे। 21 विशेषाधिकार पर वरीयता ली

एक सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध होना यह तथ्य है कि उन्होंने माना कि रेड्डी के मामले (2) का गलत निर्णय लिया गया था। उस मामले में उस अनुच्छेद को माना गया था। 22 समर्पण के विशेषाधिकार पर वरीयता थी। अगर अनुच्छेद। 22 जैसा कि दास सी. जे. ने माना होगा कि उन्होंने रेड्डी के मामले (2) की शुद्धता को स्वीकार नहीं किया था, वे उस अनुच्छेद को और अधिक नहीं मान सकते थे। 21 विशेषाधिकार पर वरीयता होगी

अवमानना के लिए प्रतिबद्ध।

सी. एल. एस. का कुछ संदर्भ दिया गया था। (1) और (2) अनुच्छेद। 194 को

दिखाएँ कि शर्मा के मामले (1) ने उस अनुच्छेद का फैसला किया। 19 (1) (क) केवल सी. एल. के दूसरे भाग द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार के आगे झुकना पड़ता था। (3) अनुच्छेद की। 194 , लेकिन मुझे नहीं लगता कि शर्मा के मामले (1) में बहुमत का निर्णय उन खंडों पर आधारित था। यह याद रखा जाएगा कि ये खंड सदन में बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। दास सी. जे. ने उनका उल्लेख केवल इसलिए किया क्योंकि कुछ तर्क, जिनका उल्लेख करना अब आवश्यक नहीं है, इनके आधार पर दिए गए थे।

(2) ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 636.

(1) (1959] सप. 1 एससीआर 806।

विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

यह दिखाने के उद्देश्य से खंड कि विशेषाधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अधीन थे। अल्पमत और बहुमत दोनों निर्णय इन तर्कों को स्वीकार करने में असमर्थ थे। वास्तव में उस मामले में प्रश्न सदन के बाहर एक नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने की शक्ति से संबंधित था। (1) और (2) केवल सदन में ही किसी सदस्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऐसी स्वतंत्रता से संबंधित है जिसका मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

एहि न्यायालयमे एकर अर्थ पर किछु चर्चा भेल।

सी. एल. में "संविधान के प्रावधानों के अधीन" शब्द। (1) अनुच्छेद की। 194. ये शब्द, मेरे विचार में, केवल संविधान के समर्थक दृष्टिकोण को संदर्भित कर सकते हैं जो अन्यथा सी. एल. एस. के लिए सदन में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। (1) और (2) एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे। अब मैं एक विषयांतर करूँगा और कहूंगा कि विधानसभा के विद्वान अधिवक्ता ने अनुच्छेद में यह बताया है। 194 संविधान निर्माताओं ने एक सदस्य की बोलने की स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से सी. एल. एस. में प्रदान करके अलग तरीके से व्यवहार किया। (1) और (2) और सदन में बोलने की स्वतंत्रता के अलावा अन्य विशेषाधिकारों का प्रावधान करके। (3) . उन्होंने कहा कि इसका कारण यह था कि यदि सदन में बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी

सी. एल. (3) यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और

तब सत्ता में पार्टी संभवतः उस स्वतंत्रता को नष्ट कर सकती है। इरादा यह था कि सदन में बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए स्वयं संविधान द्वारा गारंटी दी जाएगी ताकि विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा किसी भी हानि की पहुंच से बाहर हो। मुझे लगता है कि यही एकमात्र कारण है कि उस स्वतंत्रता को संविधान में सी. एल. एस. में समान रूप से माना गया था। (1) और (2) अनुच्छेद। 194. वहाँ

उन खंडों का हाथ में मामले से कोई लेना-देना नहीं है। न ही उनका शर्मा के मामले में फैसले से कोई लेना-देना था। द.

परिणाम यह है कि मेरे फैसले में शर्मा का मामला वर्तमान मामले को शामिल करता है।

और इससे अलग नहीं किया जा सकता है।

पहले बताए गए कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि

जब अनुच्छेद के दूसरे भाग द्वारा किसी सदन को प्रदत्त विशेषाधिकार के बीच टकराव हो। 194 (3) और एक मौलिक अधिकार, कि

दोनों प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करके संघर्ष का समाधान करना होगा। यह. यह कहना गलत होगा कि मौलिक अधिकार का अधिकार होना चाहिए।

विशेषाधिकार पर केवल इसलिए कि यह एक मौलिक अधिकार है

या किसी अन्य कारण से। वर्तमान मामले में संघर्ष के बीच है अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिबद्ध करने का सदन का विशेषाधिकार

उस समर्पण को कानून की अदालत द्वारा जांच किए जाने के लिए उत्तरदायी होना

अनुच्छेद के तहत उस अधिकार को लागू करने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार। 32 या अनुच्छेद। 226. यदि प्रवर्तन में अदालतों को स्थानांतरित करने का अधिकार

मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जाती है, विशेषाधिकार जो 534 प्रदान करता है।

[1965] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय

रिपोर्टें

कि यदि कोई सदन किसी व्यक्ति को एक सामान्य वारंट द्वारा प्रतिबद्ध करता है

मित्तल की अदालतों द्वारा समीक्षा नहीं की जाएगी, इसके सभी नुकसान होंगे

प्रभाव और यह ऐसा होगा जैसे कि वह विशेषाधिकार अनुच्छेद के दूसरे भाग द्वारा किसी सदन को नहीं दिया गया था। 194 (3) . यह, मेरे विचार में,

नहीं हो सकता। ऐसा होने पर, यह होगा कि जब एक हाउस कॉम

किसी व्यक्ति को एक सामान्य वारंट द्वारा अवमानना के लिए सूचित करता है कि व्यक्ति को अदालतों से संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही अदालतें इस तरह के समर्पण के आदेश पर निर्णय में बैठ सकती हैं। यह कहना मेरा इरादा नहीं है कि नियम में अपवाद नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं वर्तमान मामले में इन अपवादों, यदि कोई हों, पर चर्चा करने का प्रस्ताव नहीं करता हूं। उन अपवादों के अस्तित्व का समर्थन बर्डेट बनाम में लॉर्ड एलेनबरो सी. जे. की टिप्पणियों से किया जा सकता है। एबॉट (1)। मई में पी। 159 मामला इस प्रकार है: " लॉर्ड

एलेनबरो सी. जे. ने इस संभावना को खुला छोड़ दिया कि ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं जिनमें अदालतों को अवमानना के लिए एक समर्पण की वैधता पर निर्णय लेना होगा, जहां वापसी में प्रदर्शित तथ्यों को किसी भी उचित व्याख्या द्वारा अवमानना के रूप में नहीं माना जा सकता है।

मुझे लगता है कि मैंने अब इस विषय पर कानून पर पर्याप्त चर्चा की है।

और संदर्भ क्रम में बताए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

प्रश्न संख्या 1. - क्या, तथ्यों और संदर्भ पर

मामले की जटिलताओं के लिए, यह सक्षम था

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ। इसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति एन. यू. बेग और

माननीय श्री न्यायमूर्ति जी. डी. सहगल, मनोरंजन और कल्याण के लिए!

श्री केशव सिंह की याचिका के साथ

अधिरोपित कारावास की सजा की वैधता उत्तर प्रदेश की विधान सभा द्वारा इसके लिए

श्री केशव सिंह को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए उसकी उक्त याचिका का निपटान।

इस सवाल का जवाब, मेरी राय में, एफ़ायर में दिया जाना चाहिए।

मैटिव। लखनऊ पीठ निश्चित रूप से आम तौर पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं से निपटने के लिए सक्षम थी। विधानसभा द्वारा उठाया गया एकमात्र मुद्दा यह है कि जब हिरासत की शिकायत अध्यक्ष द्वारा जारी सामान्य वारंट के तहत की जाती है तो ऐसी याचिकाओं से निपटने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन लखनऊ पीठ को यह पता लगाना था कि क्या केशव सिंह की नजरबंदी इस तरह के वारंट द्वारा की गई थी, इससे पहले कि वह अधिकार क्षेत्र के अभाव के आधार पर याचिका को खारिज कर सके। याचिका में यह नहीं दिखाया गया कि हिरासत सामान्य वारंट के तहत थी। यह तब प्रकट हुआ होगा जब विधानसभा के अध्यक्ष और जेलर जो याचिका के प्रतिवादी थे

(1) (1811) 14 ईस्ट I. 152: 104 ई. आर. 501

विशेष संदर्भ (जे. सरकार)

535

उनकी वापसी। वह अवस्था तब नहीं आई थी जब लखनऊ पीठ ने याचिका का निपटारा किया और उस पर आदेश दिए। लखनऊ तक

पीठ को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि हिरासत ने शिकायत की थी

एक सामान्य वारंट के तहत था, इससे निपटने की पूरी क्षमता थी याचिका दायर करें और उस पर आदेश दें। कहा गया है कि आदेश

जमानत अवैध थी क्योंकि कानून में जमानत पर रिहाई की अनुमति नहीं है जब

कारावास अवमानना के लिए है। मुझे नहीं लगता कि यह एक उपयुक्त अवसर है।

कानून के उस प्रश्न को तय करने के लिए भले ही जमानत का आदेश था

कानून में न्यायोचित नहीं है जो अन्यथा प्रतिस्पर्धा को प्रभावित नहीं करेगा आदेश देने के लिए पीठ की पीठ। मुझे नहीं लगता कि यह

संदर्भ का उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था कि क्या

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में जहां कारावास धोखाधड़ी के लिए है

अन्यथा, कानून जमानत पर रिहाई की अनुमति देता है।

प्रश्न संख्या 2. - क्या, तथ्यों और संदर्भ पर

श्री केशव सिंह के कारण मामले की जटिलताएँ

उनकी ओर से उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली याचिका

उपरोक्त उत्तर प्रदेश का न्यायालय, श्री बी. सोलोमन, अधिवक्ता, उक्त याचिका प्रस्तुत करते हुए और उक्त

दो माननीय न्यायाधीशों का मनोरंजन और उनसे निपटना

कहा याचिका और श्री केशव की रिहाई का आदेश

सिंह उक्त याचिका के निपटारे तक जमानत पर हैं। उत्तर विधानसभा की अवमानना

प्रदेश।

पहली बात जो मैं देखता हूं वह यह है कि सवाल यह है कि क्या कोई

विधानसभा की अवमानना का निर्धारण विधानसभा को करना है। अगर कि निर्धारण तथ्यों को नहीं बताता है, कानून की अदालतें नहीं कर सकती हैं इसकी वैधता की समीक्षा करें। यह अवलोकन करने के बाद, मैं आगे बढ़ता हूँ

सवाल का जवाब देने के लिए। सवाल का जवाब नकारात्मक होना चाहिए। मुझे लगता है। अवमानना के रूप में किसी कार्य के लिए, यह न केवल अवैध होना चाहिए, बल्कि जानबूझकर अवैध भी। अब वर्तमान मामले में यह दिखाई नहीं देता है

कि उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी को भी कोई जानकारी थी कि कारावास एक सामान्य वारंट के तहत था। ऐसा होने पर, मेरे पास है यह कहने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि याचिका की प्रस्तुति एक थीअवैध कार्य बहुत कम एक जानबूझकर अवैध कार्य है। कोई अवमानना नहीं थी, इसलिए, माननीय न्यायाधीशों या बी. सोलोमन या केशव सिंह ने इस संबंध में उनके द्वारा लिए गए संबंधित भागों के लिए याचिका के साथ।

प्रश्न संख्या 3. - चाहे तथ्यों और संदर्भों पर हो मामले की जटिलताओं, यह लेजिस के लिए सक्षम था उत्तर प्रदेश की स्थानीय विधानसभा उत्पाद का निर्देशन करेगीउक्त दो माननीय न्यायाधीशों और श्री बी. सोलोमन का कथन,

अधिवक्ता, हिरासत में उसके सामने या उनके स्पष्टीकरण के लिए बुलाने के लिए

राष्ट्र अपनी अवमानना के लिए; यह याद रखा जाएगा कि, गायन के अनुसार, रेसो

21 मार्च, 1964 का ल्यूशन जिसने उत्पादन का निर्देशन किया हिरासत में मौजूद माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि उन्होंने 19 मार्च, 1964 की केशव सिंह की याचिका के संबंध में क्रमशः जो किया था, उससे उन्होंने सदन की अवमानना की थी और विधानसभा इस प्रस्ताव पर विवाद करती है। लेकिन हमें करना है

संदर्भ क्रम में बताए गए तथ्यों पर प्रश्न का उत्तर दें और इस बात से कोई सरोकार न रखें कि सही तथ्य क्या हो सकते हैं। एक बात यह है कि सभा के लिए यह सक्षम नहीं होगा कि वह माननीय न्यायाधीशों और बी. सोलोमन को सुनवाई किए बिना अवमानना का दोषी पाए। दूसरा, वर्तमान मामले में मैं पहले ही दिखा चुका हूं कि वे इतने दोषी नहीं थे। ऐसा होने के कारण, विधानसभा के लिए यह सक्षम नहीं था कि वह उन्हें हिरासत में पेश करने का निर्देश दे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में विधानसभा ने माननीय न्यायाधीशों को अवमानना के सवाल पर सुनवाई के उद्देश्य से नहीं बल्कि इस आधार पर पेश करने का निर्देश दिया था कि

उन्होंने अवमानना की थी। इसलिए, "पक्षकार पं. के आरोपों का जवाब देने के लिए व्यक्तियों को बार में हिरासत में लाने" के सदन के विशेषाधिकार के सवाल पर चर्चा करना अनावश्यक है। मई पी. देखें। 94. इसके अलावा, विधानसभा ने इसे संशोधित किया था

न्यायाधीश सोलोमन और केशव सिंह को लाने का प्रस्ताव

हिरासत में लिया गया और केवल माननीय से स्पष्टीकरण मांगा गया

न्यायाधीशों और बी. सोलोमन को उनके आचरण के लिए। इसलिए, कड़ाई से बोलते हुए, उन्हें हिरासत में लाने का सवाल

सदन मामले के तथ्यों पर नहीं उठता है।

स्पष्टीकरण मांगने के लिए सभा की क्षमता के बारे में दो न्यायाधीशों और बी. सोलोमन से, मुझे लगता है कि ऐसा था। वह एक है। सदन के विशेषाधिकारों का। क्योंकि उसके पास वचन देने की शक्ति है अवमानना से संबंधित तथ्यों का पता लगाने की शक्ति होनी चाहिए

प्रलोभन।

प्रश्न संख्या 4. - क्या, तथ्यों और संदर्भ पर

मामले की जटिलताओं, यह पूर्ण के लिए सक्षम था उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ ने विचार करने के लिए और उक्त दो माननीय की याचिकाओं पर विचार करें। न्यायाधीश और श्री बी. सोलोमन, अधिवक्ता और अंत में पारित करने के लिए रिम ने विधानसभा अध्यक्ष को रोकने का आदेश दिया उत्तर प्रदेश की विधानसभा और अन्य उत्तरदाताओं को उपरोक्त निर्देश को लागू करने से उक्त याचिकाएं

उक्त विधान सभा का गठन; मैं इस सवाल का जवाब हां में दूंगा। पूर्ण बेंच

इसके समक्ष दो न्यायाधीशों और बी. सोलोमन विशेष संदर्भ (जे. सरकार) द्वारा याचिकाएं दायर की गई थीं। उन्हें अवमानना का दोषी पाते हुए विधानसभा के प्रस्ताव की शिकायत करना। मैंने पहले कहा है कि इस मामले के तथ्यों पर, उन्हें इतना दोषी नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद पूर्ण पीठ के पास अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति थी जो उसने किया था।

प्रश्न संख्या 5. - चाहे किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो न्यायालय जो किसी याचिका को चुनौती देता है या उस पर विचार करता है किसी विधानमंडल का कोई आदेश या निर्णय लागू करना याचिकाकर्ता पर जुर्माना या उसके खिलाफ कोई प्रक्रिया जारी करना याचिकाकर्ता को उसकी अवमानना या उसके उल्लंघन के लिए विशेषाधिकार और उन्मुक्ति या जो कोई आदेश पारित करता है

ऐसी याचिका उक्त विधानमंडल की अवमानना करती है। और क्या उक्त विधानमंडल लेने के लिए सक्षम है अभ्यास में ऐसे न्यायाधीश के खिलाफ कार्यवाही और अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं का प्रवर्तन। यह एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है और एक भी करने में सक्षम नहीं है उत्तर; परिस्थितियों के अनुसार उत्तर अलग-अलग होंगे, और परिस्थितियों के सभी समूहों की कल्पना करना संभव नहीं है। न ही मुझे लगता है कि हमें ऐसा करने के लिए कहा गया है। जैसा कि पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर इसके तथ्यों पर दिया जाना चाहिए।

मामला। उन तथ्यों पर सवाल का जवाब नकारात्मक में दिया जाना चाहिए।

मैं अब मामले के एक पहलू का उल्लेख करने का प्रस्ताव करता हूं जिस पर

बार में बहुत सारे तर्क दिए गए थे। यह अवमानना के लिए एक न्यायाधीश के दायित्व से संबंधित है। अगर मैंने पहले जो कहा है, उसमें मैं सही हूं, तो एक न्यायाधीश को सामान्य वारंट के तहत एक सदन द्वारा की गई प्रतिबद्धता में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यदि वह ऐसा आदेश देता है जो इस तरह की प्रतिबद्धता में हस्तक्षेप करता है, तो उसकी कार्रवाई अधिकार क्षेत्र के बिना होगी। यह तब एक शून्य होगा। उस आदेश को निष्पादित करने वाला कोई भी अधिकारी सदन की प्रतिबद्धता में हस्तक्षेप करेगा और इस तरह का हस्तक्षेप अवैध होगा क्योंकि आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है और इसलिए यह अमान्य है। यदि सदन अवमानना में उनके खिलाफ कार्यवाही करता है, तो कानून की अदालत किसी भी स्थिति में उन्हें इसके आधार पर कोई राहत नहीं दे सकती थी। आदेश दें। ऐसा हो सकता है कि न्यायाधीश इस तरह का आदेश देकर सदन की अवमानना करेगा क्योंकि इसके द्वारा वह अवैध रूप से और पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना सदन के आदेश में हस्तक्षेप करेगा। हालाँकि अब मैं जिस प्रश्न का उल्लेख करना चाहता हूँ वह यह है कि क्या न्यायाधीश को यह मानते हुए कि उसने अवमानना की है, सदन द्वारा इसके लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, सवाल यह है कि क्या न्यायाधीश को अपने द्वारा की गई अवमानना के लिए सदन द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ छूट है? यदि उनका आदेश वैध होता, तो निश्चित रूप से, उन्होंने अवमानना नहीं की होती और उनके लिए प्रतिरक्षा का सवाल ही पैदा नहीं होता।

यह उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया था कि यह मानते हुए भी कि कि कोई न्यायाधीश किसी सदन की अवमानना कर सकता है, उसे पूरी छूट है। इसे संविधान की योजना पर सबसे पहले रखा गया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह पूर्ण न्यायिक स्वतंत्रता का पक्षधर है। इसके बाद यह बताया गया कि हमारे संविधान के तहत न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता है

अनुच्छेद के तहत। 124 (4) , अर्थात्, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा एक निश्चित बहुमत द्वारा समर्थित एक संबोधन पर राष्ट्रपति के आदेश से। रिलायंस को तब आर्ट पर रखा गया था। 211 कॉन्स्टिटचूशन की

कानून जो संसद के विधानमंडल में चर्चा को प्रतिबंधित करता हैअपने कर्तव्यों के निर्वहन में एक न्यायाधीश की धारा और यह कहा गया था कि यह इंगित करता है कि एक न्यायाधीश अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे इतना उत्तरदायी बनाने के लिए उसके आचरण पर चर्चा की जानी चाहिए। यह था। हालाँकि उस अनुच्छेद को स्वीकार किया। 211 लागू करने योग्य नहीं दिया अनुच्छेद की दृष्टि से सही। 194 (2) लेकिन यह कहा गया था कि संविधान निर्माताओं का इरादा है कि एक न्यायाधीश को छूट दी जाए विधानसभा की अवमानना के दायित्व से।

इन दलीलों की शुद्धता को उनकी ओर से चुनौती दी गई थी।

सभा से। न्यायिक स्वतंत्रता के मुद्दे के संबंध में अन्यथा, यह कहा गया था कि यह शायद ही इरादा किया गया होगा कि

एक न्यायाधीश को प्रतिरक्षा होनी चाहिए, भले ही वह जानबूझकर ऐसा करता हो एक सदन की अवमानना। यह बताया गया कि अवमानना

जानबूझकर किया जाएगा, क्योंकि न्यायाधीश को पता होगा कि एक सामान्य वारंट का मामला जिसे आगे बढ़ाने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था आगे।

जहां तक अपरिवर्तनीयता पर आधारित तर्क का संबंध है न्यायाधीशों ने उपबंधित तरीके को छोड़कर, यह कहा गया था किअवमानना के लिए प्रतिरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। यह बताया गया था कि संविधान राज्य की स्वायत्तता प्रदान करता है और यह कर सकता है ऐसा इरादा नहीं किया गया है कि जब किसी न्यायाधीश ने अवमानना की हो किसी राज्य विधानमंडल का, उस निकाय का एकमात्र उपाय होगा -कदम उठाने के अनुरोध के साथ केंद्रीय संसद से संपर्क करें न्यायाधीश को हटाना। यह भी गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाएगा

राज्य विधानमंडल की गरिमा। ऐसे में राहत का अनुदान मामला केंद्रीय संसद की इच्छा पर निर्भर करेगाऔर राहत मिलने की संभावना नहीं होगी, विशेष रूप से जब राज्य और केंद्र में सत्ता में रहने वाले दल, जितना हो सके थे होता है, अलग। न्यायाधीशों की अपरिवर्तनीयता नहीं थी, यहकहा गया था, उनके जानबूझकर गलत कार्य को बचाने का इरादा था लेकिन केवल अवैध हस्तक्षेप के खिलाफ उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिएशक्तिशाली प्रभाव। यह

तर्क दिया गया था कि एक न्यायाधीश की प्रतिरक्षा अदालत के उन अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाएगा जो विशेष संदर्भ (सरकार 1) के लिए बाध्य होंगे।

उसके सभी आदेशों को असहाय और अनिश्चित स्थिति में निष्पादित करें, क्योंकि उन्हें न्यायाधीशों के अवैध आदेशों का भी पालन करना पड़ता है और इस तरह वे विधानसभा द्वारा वैध रूप से लगाए गए दंड के जोखिम के लिए खुद को उजागर करते हैं। अंत में यह कहा गया कि यदि देश की भलाई के लिए न्यायाधीशों का स्वतंत्र होना आवश्यक था, तो विधानमंडलों की स्वतंत्रता भी आवश्यक थी।

अनुच्छेद के बारे में। 211 , यह देखा गया कि यह बिल्कुल नहीं था एक इरादे को इंगित करें कि न्यायाधीश स्वयं द्वारा किए गए प्रलोभन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कोन था। अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देना था। 194 (1) एक निश्चित तरीके से नियंत्रित किया जाना। इसके अलावा यह

उस अनुच्छेद को इंगित किया गया था। 211 चर्चा को तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि सबसे पहले यह निर्णय लिया गया कि उस चर्चा के संचालन से संबंधित अपने कर्तव्यों के निर्वहन में एक न्यायाधीश, एक निर्णय जो

अक्सर करना मुश्किल होता है और किसी भी मामले में निर्णय विधानमंडल ने अनुच्छेद के तहत प्राप्त किया है। 194 (3) कि यह निरपेक्ष है इसकी आंतरिक कार्यवाहियों का नियंत्रण: (ब्रैडलॉफ वी. देखें। गोसेट)।

इन सभी आधारों पर यह तर्क दिया गया था कि हमारे संविधान ने

एक न्यायाधीश को एक स्वीकृत अवमानना के लिए कोई प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है

उसके द्वारा प्रतिबद्ध। यह बताया गया था कि इंग्लैंड में न्यायिक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित अधिकारियों के पास यह नहीं था कि प्रतिरक्षा और संदर्भ जय बनाम को दिया गया था। टोफम (1) और पीतल क्रॉसबी का मामला (1)। मुझे यकीन नहीं है कि मैंने इस पर सभी तर्क दिए हैं। सवाल लेकिन मैंने जो कहा है वह प्रतिस्पर्धा का एक उचित विचार देगा वाद-विवाद। इस मामले के उद्देश्य के लिए, मुझे नहीं लगता उन विवादों के गुणों में जाना आवश्यक है। द. संदर्भ के तथ्यों पर जो प्रश्न उठते हैं, वे मेरे में हो सकते हैं देखें, इम के सवाल पर उच्चारण किए बिना जवाब दिया जाए

न्यायाधीशों की सामूहिकता। यह अक्सर सैद्धांतिक से बहुत बेहतर होता है।

विवादों को विद्वानों के लेखों में दफन होने दिया जाना चाहिए और अभ्यास की परिस्थितियों में बचने के लिए बहुत अधिक तनाव जो जन्म देते हैं उन विवादों के लिए। इंग्लैंड में उन्होंने ऐसा किया है और वहाँ है

हमारे देश में भी ऐसा न होने का कोई कारण नहीं है। आई. दृढ़ता से महसूस करते हैं कि यह हमारे देश के हित की बहुत सेवा करेगा विशेष रूप से इस प्रश्न का उत्तर न देना बेहतर है क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं है। उभरा। मुझे उम्मीद है कि यह कभी नहीं होगा।

मुझे लगता है कि यह उल्लेख करना सही है कि श्री वर्मा ने

यह कहते हुए कि संविधान के संशोधनों पर विचार करना राष्ट्रपति का काम नहीं था और यह अनुच्छेद का उद्देश्य नहीं था। 143 कि शुरू करने के उद्देश्य से इस न्यायालय से परामर्श किया जाना चाहिए कानून। मैं यह कहने में असमर्थ हूं कि श्री वर्मा का तर्क पूरी तरह से निराधार है, लेकिन मैं वर्तमान मामले में उस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करता।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मुझे कहना होगा कि मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं

कि परिस्थितियों को वही मोड़ लेना चाहिए था जो उन्होंने लिया था और राष्ट्रपति द्वारा इस न्यायालय को संदर्भित करना आवश्यक बनाया जाना चाहिए था। थोड़ी अधिक चतुराई, संयम और दूसरों के लिए विचार के साथ, जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे बचा जा सकता था। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेग और सहगल जे. जे. उनके पास पूरे तथ्य होने के बाद 19 मार्च, 1964 की याचिका को खारिज कर दिया जाता। मुझे खेद है कि उस संयम को दिखाने के बजाय, जिसकी इस अवसर पर मांग की गई थी, विशेष रूप से जेल के आदेश को स्पष्ट रूप से विधानसभा के कद के एक निकाय द्वारा अवमानना के लिए पारित किया गया था, एक त्वरित कार्रवाई की गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रतीक्षा करने के लिए ज्यादा समय नहीं था, लेकिन केशव सिंह अंतिम समय में आकर अदालत के हाथों को मजबूर नहीं कर सके। माननीय न्यायाधीशों के आदेश का परिणाम एक ऐसे मामले में विधानसभा की पूरी तरह से वैध कार्रवाई में हस्तक्षेप करना था जहां हस्तक्षेप उचित नहीं था और निश्चित रूप से टालने योग्य था। दूसरी ओर, विधानसभा भी संयम बरतकर और न्यायाधीशों के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं करके संकट से बच सकती थी।

एक बार। यह ध्यान में रखा जा सकता था कि न्यायाधीशों को कठिन कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था, कि अक्सर उन्हें अपूर्ण सामग्रियों पर कार्य करना पड़ता था, और इसलिए त्रुटियां संभव थीं। यह हो सकता है

यह महसूस किया कि जब उसने न्यायाधीशों के समक्ष तथ्यों को रखा, तो उसके दृष्टिकोण की सराहना की जाएगी और उचित आदेश विशेष संदर्भ (जे. सरकार) दिए जाएंगे।

पूर्ण साथी रियाल की अनुपस्थिति में जो किया गया था उसे पूर्ववत करने के लिए बनाया गया। विधानसभा की इस तरह की कार्रवाई से उसका कद और प्रतिष्ठा बढ़ती और राज्य के विभिन्न अंगों के सामंजस्यपूर्ण कामकाज में मदद मिलती।

मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो महसूस करते हैं कि

विधान सभा पर अवमानना करने की पूर्ण शक्ति के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता है। संविधान द्वारा विधानमंडलों को स्पष्ट रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण चीजें सौंपी गई हैं। संविधान के लागू होने के चौदह वर्षों के दौरान, विधानमंडलों ने इस विचार को सही ठहराने के लिए कुछ नहीं किया है कि वे सत्ता पर भरोसा करने के लायक नहीं हैं। हालांकि मैं अनुच्छेद की ओर इशारा करूंगा। 211 यह लागू करने योग्य नहीं है, विधानमंडलों ने संयम की सराहनीय भावना दिखाई है और इन सभी वर्षों में एक बार भी न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की है। हमें अपने लोगों में विश्वास नहीं खोना चाहिए, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि विधानमंडल संविधान द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे या यह सुरक्षा केवल न्यायिक सुधार में निहित है। इस तरह के सुधार घर्षण पैदा कर सकते हैं और कारण बन सकते हैं

अच्छे से ज्यादा नुकसान। एक आधुनिक राज्य में देश की भलाई के लिए अक्सर यह आवश्यक होता है कि समानांतर शक्तियां विभिन्न प्राधिकरणों में मौजूद हों। यह अपरिहार्य नहीं है कि ऐसी शक्तियों का टकराव होगा। यह दृष्टिकोण रखना पराजयवाद होगा कि हमारे देश में

पुरुष इन शक्तियों को सुचारू रूप से और लोगों के सर्वोत्तम हित में और टकराव पैदा किए बिना काम करने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हुआ है वह फिर कभी नहीं होगा और हमारा संविधान विभिन्न अंगों द्वारा काम करेगा।

राज्य सौहार्दपूर्ण ढंग से, समझदारी से, साहसपूर्वक और उस भावना से जिस भावना से संविधान निर्माता उनसे कार्य करने की अपेक्षा करते थे।

आई.